December 2022

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

ChatGPT

Private Member's Bill
for Women's Reservation.

DNA Technology
Regulation Bill

Ratnagiri's
pre-historic rock art

GAGAN
(GPS Aided Geo Augmented Navigation)

Role of Micro Financial
Institutions in financial Inclusion

State of Finance
for Nature report

PM SVANIDHI SCHEME

TOPPER'S RECOMMENDED
BEST CHOICE

हिंदी

IAS BABA

UPSC/IAS 2023

(BILINGUAL)

PRELIMS PINNACLE

YOUR ROADMAP TO SUCCESS IN PRELIMS 2023

56 High-Quality Prelims Tests

Exclusive CSAT (Classes & Tests)

Exclusive Current Affairs (Classes, Tests & Handouts)

Detailed & Crisp Handouts for Easy Revision

Comprehensive Classes (Static & Current Affairs) - Full Syllabus

UPSC PRELIMS 2023

ONLINE

ADMISSION OPEN

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

विषय-सूची

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

- स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP)
- मोबाइल ऐप 'प्रहरी'
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन
- कंगारू कोर्ट
- एग्जिट पोल
- राज्यसभा के सभापति
- पीएम स्वनिधि योजना
- लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को पूरा करना
- छठी अनुसूची
- एग्रीस्टैक परियोजना
- क्षेत्रीय परिषद
- भारतीय रेलवे के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना
- विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS)
- अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिककरण (पीएमएफएमई योजना)
- जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम

अर्थव्यवस्था

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002
- बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम
- पेरिस क्लब
- 'रूह अफज़ा' ट्रेडमार्क का निर्णय
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)
- कोल इकॉनमी
- समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 (मैरीटाइम एंटी-पायरेसी बिल, 2022)
- रक्तसे कार्पो खुबानी (Raktsey Karpo Apricot), तंदूर रेडग्राम और अलीबाग सफेद प्याज - नए जीआई टैग जोड़े गए

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- एशिया-पेसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन
- वासेनार अरेंजमेंट
- सिंगापुर घोषणा

इतिहास, कला और संस्कृति

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- महापरिनिर्वाण दिवस
- संगाई महोत्सव
- सिलहट-सिलचर महोत्सव
- पं. मदन मोहन मालवीय
- रत्नागिरी की पूर्व-ऐतिहासिक रॉक कला
- तानपुरा/तंबूरा
- मैतेई लिपि
- 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन
- गोवा मुक्ति दिवस
- पाणिनि की 'अष्टाध्यायी'
- बेट्टा-कुरुबा जनजाति
- श्रीशैलम मंदिर
- भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार
- श्री गुरु गोबिंद सिंह
- मलिक अहमद और अहिल्याबाई होल्कर
- मुहम्मद इकबाल
- धनु यात्रा
- तेल त्साफ (Tel Tsaf)
- श्रीमुखलिंगम मंदिर

भूगोल

- तटीय लाल रेत के टीले/एरा मैटी डिब्बालू
- शीत लहर (Cold Wave)
- फ़िजी
- कैक्टस रोपण और इसका आर्थिक उपयोग
- ओकावांगो डेल्टा और मर्चिसन फॉल्स

- कलासा-बंदूरी परियोजना
- बराक नदी

पर्यावरण

- मंकीपॉक्स / एमपॉक्स
- स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट
- भारत के शीतलन क्षेत्र की रिपोर्ट में जलवायु निवेश के अवसर: विश्व बैंक
- स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट
- फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन (FGD)
- ज़ोंबी वायरस
- भोपाल गैस त्रासदी
- महुआ का पेड़/मधुका लोंगिफोलिया
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क
- नेवादा वाइल्डफ्लावर' (Nevada wildflower)
- ओरण (Orans)
- नीलगिरी तहर परियोजना
- एशियाई विशालकाय कछुए
- सैंड बैटरी
- अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन (Emperor penguin)
- डाइबैक रोग (Dieback Disease)

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

- खानाबदोश मलमपदंद्रम जनजाति
- तलाक अधिनियम 1869

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- डार्क पैटर्न
- विश्व एड्स दिवस
- ज्वारीय व्यवधान घटनाएं (TDE)
- भारत की पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना
- विक्रम एस रॉकेट
- एथिलीन ग्लाइकोल
- ओपन स्टैंडर्ड डिजिटल ट्रंकिंग रेडियो सिस्टम
- SHE STEM 2022
- न्यूरालिंक
- ChatGPT
- GAGAN (जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन)
- एंथ्रेक्स
- NavIC
- पनडुब्बी वागीर
- कार्बनिक सौर सेल
- ग्रीन मेथनॉल
- नेगलेरिया फाउलेरी या ब्रेन-ईटिंग अमीबा
- सेप्सिस
- दुर्लभ बीमारी 'जीएनबी1 इन्सेफेलोपैथी'

MAINS

राजव्यवस्था और शासन

- जनजातीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करना
- न्यायपालिका में महिलाएं
- लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्षम करना
- भारत के लिए प्रेषण
- भारत में असमानता रिपोर्ट 2022: एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया द्वारा डिजिटल डिवाइड
- सतत विकास की सहायता में ग्रीन टैक्स
- भारत में खाद्य सुरक्षा
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
- विरासत संरक्षण की आवश्यकता

अर्थव्यवस्था

- बड़े व्यवसायों पर न्यूनतम कर
- ई-रूपी (E-Rupee)
- भारत का सहकारी क्षेत्र
- भारत की ब्लू कार्बन क्षमता
- भारत में कपड़ा उद्योग
- वित्तीय समावेशन में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की भूमिका
- कार्बन ट्रेडिंग
- भारत में उर्वरक क्षेत्र
- पुनर्योजी कृषि
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कृषि कमोडिटी पर व्यापार प्रतिबंध का विस्तार किया

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
- भारत और G20 अध्यक्षता
- मुक्त व्यापार समझौता शासन

इतिहास, कला और संस्कृति

- बी आर अम्बेडकर और महिला अधिकारिता

पर्यावरण

- अमेज़न बेसिन में वनों की कटाई
- मृदा संरक्षण और प्रबंधन का महत्व
- आर्कटिक महासागर का गर्म होना और इसके प्रभाव
- क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

- स्वास्थ्य एक अधिकार के रूप में: राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक
- राष्ट्रीय पर्यटन नीति
- भारत की भाषाएँ
- ST सूची में जनजातियों को जोड़ना

सुरक्षा समस्याएं

- भारत में साइबर हमले
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- डीपफेक तकनीक और चीन
- क्वांटम कम्प्यूटिंग

नीति शास्त्र

- भारत में भ्रष्टाचार

PRACTICE QUESTIONS

ANSWER KEY

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP)	**चर्चा में क्यों :** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि एसआईपीपी योजना के तहत पेटेंट दाखिल करने के लिए आईपी सुविधा शुल्क में वृद्धि हुई है। सुविधा शुल्क में कम से कम 100% की वृद्धि की गई है। **योजना के बारे में:** • यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। • संशोधित योजना 02-12-2022 से लागू है। • यह योजना महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क CGPDTM (DPITT-MoCI के तहत) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। **पात्रता:** • स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत DPIIT द्वारा कंपनियों को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी जाती है। • इसकी अस्तित्व की अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं है। • स्थापना के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपयेहै।
मोबाइल ऐप 'प्रहरी'	**संदर्भ:** केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मोबाइल ऐप 'प्रहरी' और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का मैनुअल लॉन्च किया। यह इससे संबंधित जानकारी भी देता है: • "केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली" (CP-GRAMS) पर बायोडाटा या शिकायत निवारण। • विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी • यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा। **BSF के बारे में:** • सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा पर भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है। • यह भारत के सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces -CAPF) में से एक है। • इसे 1965 के युद्ध के मद्देनजर उठाया गया था। • यह एकमात्र सीएपीएफ है जिसके पास वाटर विंग, एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। • यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। • यह वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	**संदर्भ:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हाल ही में वीर बाल दिवस के स्मरणोत्सव को और अधिक सार्थक बनाने के लिए सुझाव/सलाह आमंत्रित करने के लिए सिख बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। • हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने अंतिम सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के चार पुत्रों, "साहिबजादों " के साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 26 दिसंबर को "वीर बाल दिवस" के रूप में घोषित किया है। • जबकि चारों शहीद हो गए थे, यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह दिन साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया था, जो मुगल सेना द्वारा सरहिंद (पंजाब) में छह और नौ साल की उम्र में मारे गए थे। **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में:** • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। • छह धार्मिक समुदाय, जैसे; मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, पारसियों (पारसियों) और जैनों को पूरे भारत में केंद्र

	सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। (जैन समुदाय 2014 में जोड़ा गया था)। • 2001 की जनगणना के अनुसार, इन छह समुदायों में देश की आबादी का 18.8% हिस्सा है। **संरचना :** अधिनियम में कहा गया है कि आयोग में शामिल होंगे: • एक अध्यक्ष, • एक उपाध्यक्ष और • प्रतिष्ठित, क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले 5 सदस्य; • इसमें अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।
सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन	**संदर्भ:** हाल ही में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2 प्रमुख पहलें शुरू की हैं: सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन। **सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के बारे में** • सभी भाग लेने वाले शहरों का मूल्यांकन तीन प्रमुख नगरपालिका वित्त मूल्यांकन मापदंडों में 15 संकेतकों पर किया जाएगा, अर्थात्: ○ संसाधन जुटाना, ○ व्यय प्रदर्शन, ○ राजकोषीय शासन • निम्नलिखित चार जनसंख्या श्रेणियों में से किसी एक के तहत शहरों को उनके स्कोर के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर रैंक प्रदान किया जाएगा: ○ 4 मिलियन से अधिक ○ 1-4 मिलियन के बीच ○ 100,000 से 1 मिलियन ○ 100,000 से कम • प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों को राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ प्रत्येक राज्य/राज्य क्लस्टर में पहचाना और पुरस्कृत किया जाएगा। **शहर सौंदर्य प्रतियोगिता (City Beauty Competition) के बारे में:** • सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन का उद्देश्य सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए भारत में शहरों और वार्डों द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को पहचानना और प्रोत्साहित करना है। • सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन के तहत, शहरों के वार्डों और सार्वजनिक स्थानों को पहुंच, सुविधाओं, गतिविधियों, सौंदर्यशास्त्र और पारिस्थितिकी के पांच व्यापक स्तंभों के खिलाफ आंका जाएगा। • शहरों में सबसे खूबसूरत सार्वजनिक स्थलों को पहले राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। • शहर सौंदर्य प्रतियोगिता में भागीदारी स्वैच्छिक है।
कंगारू कोर्ट	**संदर्भ :** तमिलनाडु की एक कंगारू कोर्ट ने एक जोड़े को उनके प्रेम विवाह के लिए जुर्माना लगाया। **कंगारू कोर्ट के बारे में:** • ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसे "अच्छे सबूत के बिना किसी पर मुकदमा चलाने के लिए लोगों के एक समूह द्वारा आयोजित एक अनौपचारिक अदालत" के रूप में परिभाषित करती है। • इसका उपयोग कार्यवाही या गतिविधियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जहां एक निर्णय इस तरह से किया जाता है जो अनुचित, पक्षपाती और वैधता का अभाव है। • कुछ शब्दकोशों का कहना है कि जानवर के साथ जुड़ाव का ऑस्ट्रेलियाई लोगों से संबंध हो सकता है, हालांकि यह अवधारणा शायद अमेरिका में उत्पन्न हुई थी।

एग्जिट पोल	**खबरों में क्यों :** गुजरात राज्य विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल हाल ही में जारी किए गए थे। **एग्जिट पोल क्या होते हैं:** ● एग्जिट पोल से यह संकेत मिलता है कि वे किस राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं। ● यह मतदाताओं द्वारा चुनाव में वोट डालने के बाद होता है; जबकि ओपिनियन पोल चुनाव से पहले होता है। ● एक एग्जिट पोल से यह संकेत मिलता है कि चुनाव में हवा किस तरफ बह रही है. साथ ही उन मुद्दों, व्यक्तित्वों पर भी चर्चा होती है, जो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। ● आज देश में एग्जिट पोल कई संगठनों द्वारा किए जाते हैं, जो अक्सर मीडिया संगठनों के साथ गठजोड़ में कराए जाते हैं. एग्जिट पोल का सर्वेक्षण आमने-सामने या ऑनलाइन किया जा सकता है। **भारत में एग्जिट पोल का इतिहास:** ● 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने इस तरह का पहला सर्वेक्षण कराया था। ● भारत में, किसी विशेष चुनाव के एग्जिट पोल के परिणामों को अंतिम वोट डाले जाने तक प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। ● अंतिम चरण समाप्त होने तक मतदान शुरू होने से पहले एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जा सकता है।
राज्यसभा के सभापति	**संदर्भ:** हाल ही में, राज्यसभा ने अपने नए सभापति श्री जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। **राज्यसभा के सभापति के बारे में:** ● उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। **संवैधानिक प्रावधान:** ● अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। ● संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति (भारत के उप-राष्ट्रपति) और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है। **शक्तियां और कार्य:** ● राज्यसभा के सभापति को कोरम (गणपूर्ति) न होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक स्थगित करने का अधिकार है। ● संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल-बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है। ● सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिये सभापति की सहमति आवश्यक है। ● संसदीय समितियाँ, चाहे वह सभापति द्वारा गठित हों या सदन द्वारा, सभापति के निर्देशन में काम करती हैं। ● वह सदस्यों को विभिन्न स्थायी समितियों और विभाग-संबंधित संसदीय समितियों में नामित करता है। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। ● जहाँ तक सदन में या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, संविधान और नियमों की व्याख्या करना सभापति का कर्तव्य है और कोई भी ऐसी व्याख्या पर सभापति के साथ शामिल नहीं हो सकता है। **सभापति को पद से हटाना:** ● राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। ● जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, वह सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता हालाँकि वह सदन में उपस्थित हो सकता है।
पीएम स्वनिधि योजना	**संदर्भ:** हाल ही में भारत सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को मार्च, 2022 से आगे बढ़ा दिया है। **पीएम स्वनिधि के बारे में:** ● आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए न केवल उन्हें ऋण देकर, बल्कि उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना

	शुरू की। • इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों और उसके आसपास के अर्द्ध-शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी वाले छोटे व्यापारियों) को कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से अपना कारोबार शुरू करने के लिए बिना किसी की गारंटी के एक साल की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देना है। • इसके तहत ऋण के नियमित पुनर्भुगतान करने पर प्रोत्साहन के रूप में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी, निर्धारित डिजिटल लेनदेन करने पर सालाना 1,200रुपये तक का कैशबैक और आगे फिर से ऋण पाने की पात्रता भी प्रदान की गई है। • इस योजना के तहत करीब 20 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 752191 स्वीकृत किए गए हैं और 218751 ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। **पात्रता मानदंड:** पीएम स्वनिधि योजना उन सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है जो 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे हुए हैं। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की गई है: • शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी किए गए वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र वाले स्ट्रीट वेंडर्स। • यूएलबी को प्रोत्साहित किया जाता है कि ऐसे वेंडरों को वेंडिंग का स्थायी प्रमाण पत्र और पहचान पत्र तुरंत और निश्चित रूप से एक महीने की अवधि के भीतर जारी करना। • स्ट्रीट वेंडर, यूएलबी के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से छूटे हुए या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद बिक्री शुरू कर दी है और जिन्हें यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है। • यूएलबी की भौगोलिक सीमा में आसपास के विकास/परिनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता और यूएलबी/टीवीसी द्वारा उस प्रभाव के लिए सिफारिश पत्र (एलओआर) जारी किए गए हैं। **नए विस्तार के बारे में:** • दिसंबर 2024 तक ऋण देने की अवधि का विस्तार। • देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक का विस्तार करना।
लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को पूरा करना	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने कम बोझिल और यहां तक कि "आउट-ऑफ-द-बॉक्स" विचार का सुझाव दिया है, जिसमें लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के लिए वरिष्ठ वकीलों को शामिल करना है। • उच्च न्यायालयों में वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी आकर्षक कानूनी प्रथाओं को स्थायी रूप से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, लेकिन दो साल की सीमित अवधि के लिए संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत बेंच में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में शामिल होने के इच्छुक हो सकते हैं। • सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में खंडपीठ में वापस आने के इच्छुक थे, बकाया से निपटने में अपने अनुभव को लेकर आते है। **पृष्ठभूमि:** अप्रैल 2021 में दिए गए फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 5 ट्रिगर पॉइंट निर्धारित किए थे जो अनुच्छेद 224A के तहत प्रक्रिया को सक्रिय कर सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट एकवचन नहीं हो सकता है और एक से अधिक घटनाएं हो सकती हैं जहां यह उत्पन्न होती है - • यदि रिक्तियां स्वीकृत शक्ति के 20% से अधिक हैं। • एक विशेष श्रेणी के मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। • लंबित मामलों के 10% से अधिक बैकलॉग पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं। • निपटान की दर का प्रतिशत किसी विशेष विषय में या आम तौर पर न्यायालय में मामलों की संस्था से कम है। • भले ही कई पुराने मामले लंबित न हों, लेकिन अधिकार क्षेत्र के आधार पर, बढ़ते बकाया की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है यदि निपटान की दर एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि में दाखिल करने की दर से लगातार कम है।

	• हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले एडहॉक जजों की नियुक्ति पहली बार नहीं हो रही है। वे पहले सेवा कर चुके हैं और इस प्रकार उनके पास भारी काम के बोझ से निपटने की विशेषज्ञता है। इसलिए, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया नियमित नियुक्तियों की तुलना में सरल होनी चाहिए। • यदि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की प्रशंसा के कुछ दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं की जाती है, तो मेधावी उम्मीदवारों की रुचि समाप्त हो जाती है और न्याय वितरण प्रणाली को भारी नुकसान होता है। **टिप्पणी:** **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224A** • उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। • इसका प्रयोग बहुत कम होता है। • इसमें कहा गया है, "किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से अनुरोध कर सकता है, जिसने उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभाला हो और उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर किया हो "। • मुख्यमंत्री राज्यपाल से परामर्श के बाद अपनी सिफारिश केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को भेजते है। **मामलों का लम्बित होना** • उच्च न्यायालयों में 22 जुलाई तक 59 लाख से अधिक मामले लंबित थे। • इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक 10 लाख से अधिक लंबित मामले हैं। • इसके बाद राजस्थान के उच्च न्यायालय (6 लाख से अधिक) और बॉम्बे (6 लाख से कम) हैं।
छठी अनुसूची	**चर्चा में क्यों:** लद्दाख में कई राजनीतिक समूह जम्मू और कश्मीर की तर्ज पर संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संभावित रूप से शामिल करने की मांग कर रहे हैं। **छठी अनुसूची के बारे में :** • यह असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों पर लागू होता है। • यह स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADCs) के गठन का प्रावधान करता है जिनके पास राज्य के अंदर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है। • एडीसी में पांच साल की अवधि के साथ 30 सदस्य होते हैं, और भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम परिषदों, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव और शहर-स्तरीय पुलिसिंग आदि के संबंध में कानून, नियम और विनियम बना सकते हैं। • असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद 40 से अधिक सदस्यों के साथ एक अपवाद है और 39 मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है।
एग्रीस्टैक परियोजना	**संदर्भ:** एग्रीस्टैक बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने 'इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (आईडीईए)' की मूल अवधारणा को अंतिम रूप दिया है, जो एग्रीस्टैक के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। • एग्रीस्टैक एक संघबद्ध संरचना है और डेटा का स्वामित्व केवल राज्यों के पास है। • संघीय किसानों के डेटाबेस तक पहुंच केवल सरकार के पास है। संघीय किसानों के डेटाबेस को विकसित करने में कोई निजी कंपनी शामिल नहीं है। **एग्रीस्टैक क्या है?** • एग्रीस्टैक प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है जो किसानों और कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है। • एग्रीस्टैक किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में शुरू से अंत तक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच तैयार करता है। • यह केंद्र के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भूमि के शीर्षक से लेकर मेडिकल रिकॉर्ड तक, भारत में डेटा को डिजिटाइज़ करने के लिए व्यापक पुश प्रदान करना है। • प्रत्येक किसान के पास एक अद्वितीय डिजिटल पहचान (किसान आईडी) होगी जिसमें व्यक्तिगत विवरण होगा।

	• प्रत्येक आईडी को व्यक्ति के डिजिटल राष्ट्रीय आईडी आधार से जोड़ा जाएगा। **संभावित लाभ:** • क्रेडिट और सूचना तक अपर्याप्त पहुँच, कीट संक्रमण, फसल की बर्बादी, फसलों की कम कीमत और उपज की भविष्यवाणी जैसी समस्याओं से डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से पर्याप्त रूप से निपटा जा सकता है। • यह नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ाएगा। **प्रमुख बिंदु:** • 100 गांवों में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके किसान को सशक्त बनाने के लिए मूल्य श्रृंखला (खेत से कांटे तक) में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। • "नेशनल एग्रीकल्चर जिओ हब" की स्थापना और लॉन्च तथा किसानों के डेटाबेस पर जीआईएस परत को सक्षम करने के लिए उनके 'ArcGIS' प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। • कृषि मूल्य श्रृंखला में डिजिटल सेवाएं और डिजिटल कृषि के आसपास एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। • एक अनुकूलित 'साइट विशिष्ट फसल सलाहकार' सेवा का निर्माण और डेयरी मूल्य श्रृंखला का डिजिटलीकरण और गेहूं की फसल के संचालन का समर्थन करना। • किसानों, प्रशासन, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच प्रभावी ज्ञान साझा करना। • किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की दक्षता/दक्षता में सुधार करने की दिशा में प्रभावी योगदान देने के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस बनाना। • AI/ML समाधान बनाना।
क्षेत्रीय परिषद	**चर्चा में क्यों:** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। **क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य:** • अंतर्राज्यीय समस्याओं को हल करना और संबंधित क्षेत्रों के संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। • इन राज्यों में सहकारी कार्य करने की आदत विकसित करना। **क्षेत्रीय परिषद के बारे में :** • क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार 1956 में भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिया गया था। • राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य शामिल है। • उत्तर पूर्वी राज्य यानी (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिजोरम (vi) मेघालय और (vii) नागालैंड क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं। • उनकी प्रमुख समस्याओं को उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत गठित उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा देखा जाता है। • पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से सिक्किम राज्य को भी उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल किया गया है। **संगठनात्मक ढाँचा :** • **अध्यक्ष**: केन्द्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होता है। • **उपाध्यक्ष:** प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिये उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। • **सदस्य:** मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित दो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य।

	• प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसमें संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। • आवश्यकता के आधार पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है। **भूमिका और उद्देश्य:** • राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना। • तीव्र राज्यक संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना। • केंद्र एवं राज्यों को विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिये सक्षम बनाना। • विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिये राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना। **कार्य:** • प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकार निकाय है और किसी भी ऐसे मामले पर चर्चा कर सकती है जिसमें राज्यों का साझा हित हो और सरकार को सलाह दे सके • विशेष रूप से, एक क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित के संबंध में चर्चा कर सकती है और सिफारिशें कर सकती है: • आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई भी मामला; • सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों या अंतर-राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई भी मामला; • राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई भी मामला।
भारतीय रेलवे के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना	**उद्देश्य:** • इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं (MEA) सहित सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन और लंबी अवधि के समय में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और शहर के केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य है। • नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ-साथ मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन और प्रतिस्थापन करना। • यह योजना उन स्टेशनों को भी कवर करती जहां विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं। **कार्य क्षेत्र :** • इस योजना का उद्देश्य बेकार/पुरानी इमारतों को लागत प्रभावी तरीके से स्थानांतरित करना है। • अच्छा कैफेटेरिया/खुदरा सुविधाएं प्रदान करना। • कार्यकारी लाउंज और छोटी व्यावसायिक बैठकों के लिए स्थान भी बनाए जाएंगे। • लैंडस्केपिंग, ग्रीन पैच और स्थानीय कला और संस्कृति के तत्वों का उपयोग होना • सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म (760-840 मिमी) प्रदान किए जाएंगे। • प्लेटफार्म क्षेत्रों की जल निकासी अत्यंत महत्वपूर्ण है। • ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं कि स्टेशन अपने उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क वाई-फ़ाई एक्सेस प्रदान करे। • महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग प्रावधानों के साथ सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर पर्याप्त शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे। • धन की उपलब्धता और मौजूदा परिसंपत्तियों की स्थिति के अनुसार स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल समाधानों की ओर धीरे-धीरे बदलाव।
विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS)	**संदर्भ:** हाल ही में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री से विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) प्रदान करने का अनुरोध किया। **SCS के बारे में:** • इस अवधारणा को पहली बार 1969 में प्रस्तुत किया गया था जब 5वें वित्त आयोग ने कुछ वंचित राज्यों को बेहतर

	उपचार प्रदान करने की मांग की थी। • इस अवधारणा का नाम डॉ गाडगिल मुखर्जी (तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष) के नाम पर रखा गया था और यह विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता के हस्तांतरण से संबंधित है। • विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) वाले राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। • भारत में किसी भी राज्य को 'विशेष श्रेणी' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। • हालांकि, प्रावधानों की एक विस्तृत श्रृंखला 10 राज्यों के लिए उपलब्ध है जिन्हें अनुच्छेद 371, 371-A से 371-H, और 371-J के तहत सूचीबद्ध किया गया है। • योजना आयोग के विघटन और नीति आयोग के गठन के बाद, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, जिसका अर्थ था गाडगिल फॉर्मूला-आधारित अनुदानों को बंद करना। • 14वें वित्त आयोग ने 2015 में इसकी सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद विशेष श्रेणी की स्थिति की अवधारणा को प्रभावी ढंग से हटा दिया। **विशेष श्रेणी की स्थिति के लिए मानदंड:** • पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र। • कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा। • पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थान। • आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन। • राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति।
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र	**खबरों में क्यों:** नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक 14 दिसंबर 2022 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। • यह बिल नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया है। **पृष्ठभूमि** • नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत 2019 में सेटअप। • **उद्देश्य:** भारत में मध्यस्थता के बेहतर प्रबंधन के लिए। • अधिनियम ने NDIAC को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया। • अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (ICADR) को प्रतिस्थापित किया गया, जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। **संघटन:** **NDIAC में सात सदस्य शामिल हैं:** • इसमें का अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या मध्यस्थता के संचालन या प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है; • संस्थागत मध्यस्थता में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्ति; • वित्त मंत्रालय के एक नामिती और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एनडीआईएसी के दैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार) सहित तीन पदेन सदस्य; • वाणिज्य और उद्योग के एक मान्यता प्राप्त निकाय से एक प्रतिनिधि, जिसे रोटेशनल आधार पर अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हो। **कार्यकाल और अधिवर्षिता:** • एनडीआईएसी के सदस्य तीन साल तक पद पर बने रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

	• इसके अध्यक्ष के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष है और अन्य सदस्यों की आयु 67 वर्ष होती है। **मध्यस्थता के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में भारत** • भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी हम मध्यस्थता के अंतरराष्ट्रीय केंद्र नहीं हैं, जबकि छोटे देश और शहर मध्यस्थता के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे हैं। • वर्तमान में, सिंगापुर, लंदन और हांगकांग जैसे स्थान मध्यस्थता के लिए पसंदीदा केंद्र हैं। • NDIAC उन केंद्रों की तुलना में अधिक किफायती शुल्क पर मध्यस्थता पुरस्कार प्रदान कर सकता है। **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र** • एडीआर विवाद समाधान का एक तंत्र है जो गैर-विरोधाभासी है, अर्थात सभी के लिए सर्वोत्तम समाधान तक पहुंचने के लिए सहकारी रूप से मिलकर काम करना। • एडीआर अदालतों पर मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में सहायक हो सकता है, जबकि शामिल पार्टियों के लिए एक पूर्ण और संतोषजनक अनुभव प्रदान करता है। **मध्यस्थता (Arbitration):** विवाद एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है जो विवाद पर फैसला करता है (एक "पुरस्कार") जो ज्यादातर पार्टियों पर बाध्यकारी होता है। **बिचवई (मीडिएशन/Mediation):** मीडिएशन में, एक निष्पक्ष व्यक्ति जिसे "मध्यस्थ" कहा जाता है, पक्षकारों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने का प्रयास करने में मदद करता है। • मध्यस्थता और मीडिएशन का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। • हाल ही में उन्होंने विवाद समाधान के तरीकों के रूप में दुनिया भर में प्रमुखता हासिल की है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिककरण (पीएमएफएमई योजना)	**संदर्भ:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने सूचित किया है कि पीएमएफएमई योजना के तहत प्रदान की जाने वाली क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी में केंद्र के हिस्से की कुल राशि 110.86 करोड़ रुपये है। **पीएमएफएमई योजना के बारे में:** • देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' और 'वोकल फॉर लोकल' अभियानों के तहत प्रधानमंत्री औपचारिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना शुरू की गई थी। • सरकार इस योजना के तहत लगभग 200,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का इरादा रखती है। **योजना के उद्देश्य:** • प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण व्यवसायों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तक क्रेडिट पहुंच होना। • 200,000 मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उनके विपणन और ब्रांडिंग को मजबूत करके और औपचारिक इकाइयों के साथ आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत करके संगठित इकाइयों में बदलने के लिए सहायता करना। • भंडारण, ऊष्मायन सुविधाओं और पैकेजिंग जैसी साझा सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि। • खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए पेशेवर और तकनीकी सहायता। • व्यक्तिगत या समूह के स्वामित्व वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए उचित प्रशिक्षण और अनुसंधान। PMFME योजना ने एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाया है। • इस दृष्टिकोण के तहत, राज्य जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान और चयन करते हैं, जो एक खराब होने वाली कृषि फसल हो सकती है, जैसे कि अनाज, या एक खाद्य उत्पाद जो जिले में बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है।
जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम	**चर्चा में क्यों:** जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम-2022 के तहत नए भूमि नियमों को अधिसूचित किया और जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम-1960 को प्रतिस्थापित किया, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में लीज पर सरकारी भूमि देने के लिए विशेष नियमों से संबंधित था।

पहले का नियम:

- अतीत में श्रीनगर, जम्मू, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे प्रमुख स्थानों को होटलों, वाणिज्यिक संरचनाओं और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए खोल दिया गया था।
- इन भूमि कानूनों को जम्मू-कश्मीर के उच्च मध्य वर्ग की रीढ़ माना जाता था और इसने प्रमुख स्थानों पर होटलों और वाणिज्यिक संरचनाओं की एक नई श्रृंखला की अनुमति दी।

संशोधन की आवश्यकता:

- क्योंकि पिछले भूमि कानून "प्रतिगामी" थे।
- वर्तमान भूमि धारकों ने 100 करोड़ रुपये की संपत्ति से लाभ प्राप्त करने के लिए 5 रुपये का भुगतान किया।

नए नियम:

- वर्तमान भू-स्वामियों के लीज समाप्त होने की स्थिति में विस्तार नहीं किये जायेंगे।
- समाप्त हो चुके लीज का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और निर्धारित किया जाएगा।
- लीज की अवधि को घटाकर 40 वर्ष (पहले 99 वर्ष) कर दिया गया है।
- बाहर जाने वाले लीज धारकों को संपत्ति खाली करनी होगी अन्यथा बेदखली का सामना करना पड़ सकता है।
- एक विशेषज्ञ समिति उन सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करेगी जहां पट्टा समाप्त हो गया था।
- इसकी नए सिरे से ई-नीलामी की जाएगी।
- नियम "भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के तहत कानूनी रूप से सक्षम किसी भी व्यक्ति" के लिए खुली बोली लगाते हैं।
- ये नियम जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम, 1960 के तहत सरकार को अर्जित सरकारी राजस्व के डिफ़ॉल्ट में एक व्यक्ति या एक इकाई मानते हैं या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दोषी सरकार नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- अब निरसित भूमि कानूनों के अनुसार, ऐसी कोई भूमि उस व्यक्ति को लीज पर नहीं दी जाएगी, जो राज्य का स्थायी निवास नहीं है; उन मामलों को छोड़कर जहां सरकार, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, औद्योगिक या वाणिज्यिक विकास के हित में या एक पंजीकृत धर्मार्थ समाज के पक्ष में इस प्रतिबंध को शिथिल करती है।

नए नियमों का प्रभाव:

- सैकड़ों संपत्तियां नई नीलामी के लिए खुलेंगी, जहां बाहरी लोग भी भाग ले सकते हैं।
- पर्यटक आकर्षण के केंद्र गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर और जम्मू के पटनीटॉप नीलामी के लिए जाएंगे।

अर्थव्यवस्था

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम	**खबरों में क्यों :** अभिनेता विजय देवरकोंडा हाल ही में बहुभाषी फिल्म, 'लाइगर' के निर्माण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए, जिसमें बॉक्सिंग के दिग्गज माइक टायसन का कैमियो था। **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा):** • यह भारत की संसद का एक अधिनियम है। • 1999 में सख्त FERA (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) को बदलने के लिए प्रस्तुत किया गया। • फेमा भारत में सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन के व्यवहार की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। • इन विदेशी मुद्रा लेनदेनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - पूंजी खाता लेनदेन और चालू खाता लेनदेन। • यह अधिनियम विदेशी मुद्रा से संबंधित अपराधों को नागरिक अपराध बनाता है। • इसने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को लागू करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। • सिद्धांत - सभी चालू खाता लेन-देन की अनुमति है जब तक कि स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो और सभी पूंजीगत खाता लेनदेन तब तक निषिद्ध हैं जब तक कि स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002	**खबरों में क्यों:** वित्त मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 में परिवर्तनों को अधिसूचित किया। **PMLA 2002 में परिवर्तन:** प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 15 और एजेंसियों के साथ आर्थिक अपराधियों के बारे में आपत्तिजनक जानकारी और सामग्री साझा करने की अनुमति दी। इसमे शामिल है • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) • गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) • विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) • राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड • केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) • वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो • विदेश मंत्रालय, राज्य पुलिस विभाग, विभिन्न अधिनियमों के तहत नियामक, रक्षा खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, सैन्य खुफिया, केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत जांच प्राधिकरण। • इससे पहले ईडी को सीबीआई, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) सहित केवल 10 एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति थी। • सामाजिक कुरीतियों को पहचानना और उन्हें कानून की अदालत में न्याय के कटघरे में लाना। **धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के बारे में :** • यह 2002 में एनडीए सरकार द्वारा पारित भारत की संसद का एक आपराधिक कानून है। • PMLA कानून बना और 1 जुलाई, 2005 को लागू हुआ। • इसके पास संपत्तियों को जब्त करने, निवेश करने, तलाशी लेने और कुर्की करने के लिए पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपे गए व्यापक अधिकार हैं। • मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वियना कन्वेंशन में भारत की प्रतिबद्धता के कारण पेश किया गया।

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम

संदर्भ: क्लस्टर विकास कार्यक्रम में बागवानी उपज के कुशल और समय पर निकासी तथा परिवहन के लिये मल्टीमॉडल परिवहन के उपयोग के साथ अंतिम-मील कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) बनाकर संपूर्ण बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की एक बड़ी क्षमता है।

- इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** CDP का उद्देश्य लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% की वृद्धि करना और क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिये क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है।

प्रमुख विशेषताएं:

- CDP लक्षित समूहों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एकीकृत हस्तक्षेपों का समर्थन करेगा।
- हस्तक्षेपों को निम्नलिखित तीन कार्यक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:
  I. पूर्व-उत्पादन, उत्पादन
  II. कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्यवर्धन
  III. रसद, विपणन और ब्रांडिंग
- MoA&FW ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है।
- यह पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, रसद, ब्रांडिंग और मार्केटिंग गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देगा।

महत्व:

- सीडीपी से मूल्य श्रृंखला के साथ लगभग 10 लाख किसानों और संबंधित हितधारकों को लाभ होगा।
- इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मदद से देश में बागवानी के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पेरिस क्लब

खबरों में क्यों: पेरिस क्लब ने श्रीलंका को मौजूदा कर्ज पर 10 साल की मोहलत (Moratorium) और मौजूदा वित्तीय संकट को हल करने के लिए एक फार्मूले के तहत 15 साल के ऋण पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया है।

- इस साल की शुरुआत में, श्रीलंका ने बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच अपने 51 बिलियन डॉलर के बाहरी ऋण का भुगतान नहीं किया था।
- पेरिस क्लब ने भी वैश्विक उत्तर और दक्षिण से श्रीलंकाई ऋण के पुनर्गठन में समान कटौती करने का आह्वान किया है।

पेरिस क्लब के बारे में :

- यह 22 अमीर देशों के आधिकारिक लेनदारों का एक अनौपचारिक समूह है जो कर्जदार देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का स्थायी समाधान ढूंढता है।
- यह वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही सरकारों को उनके ऋण चुकौती को कम करने और फिर से बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

	• 1956 में गठित, इसने अब तक 400 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 100 देशों के लिए आधा ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। • "G20 कॉमन फ्रेमवर्क" पेरिस क्लब के साथ मिलकर G20 द्वारा समर्थित एक पहल है। • अन्य लेनदार राष्ट्रों को मामला-दर-मामला आधार पर बातचीत की बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, यदि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। • इसके सदस्य फरवरी और अगस्त को छोड़कर बाकी महीने में एक बार पेरिस में मिलते हैं। • आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के साथ एक उपयुक्त कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पेरिस क्लब देनदार देशों को अपने लेनदारों के साथ बैठक के लिए आमंत्रित करता है, जो दर्शाता है कि देश अपने बाहरी ऋण दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता है, और इसलिए अपने विदेशी लेनदारों के साथ एक नई भुगतान व्यवस्था की आवश्यकता है। • विश्व बैंक, आईएमएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि, साथ ही प्रासंगिक क्षेत्रीय विकास बैंक भी पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में भाग ले सकते हैं। • देनदार देश का प्रतिनिधि आमतौर पर इसका वित्त मंत्री होता है, जो अपने मंत्रालय और केंद्रीय बैंक के अधिकारियों वाली टीम का नेतृत्व करता है।
'रूह अफ़ज़ा' ट्रेडमार्क का निर्णय	**संदर्भ:** हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) बनाम सदर लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड, ने सदर प्रयोगशालाओं को आपत्तिजनक ट्रेडमार्क 'दिल अफज़ा' के तहत पेय पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है। • रूह अफजा' के निर्माताओं ने दावा किया कि उत्पाद 'दिल अफजा' का डिजाइन भ्रामक रूप से 'रूह अफजा' के ट्रेडमार्क के समान है, जो एक अत्यधिक प्रतिष्ठित शरबत (मीठा पेय) है। **ट्रेडमार्क के बारे में:** • ट्रेडमार्क वस्तुओं या सेवाओं के चित्रमय प्रतिनिधित्व को दूसरों से अलग करने के लिए संदर्भित करता है। • यह शब्द, प्रतीक, ध्वनि, रंग, वस्तुओं का आकार, ग्राफिक्स प्रतिनिधित्व या पैकेजिंग आदि हो सकते हैं। • यह मालिक को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाता है, मालिक की प्रतिष्ठा और उपभोक्ता कल्याण को नुकसान से बचाता है। • भारत में, ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत ट्रेडमार्क शासित होते हैं (यह ट्रेडमार्क के संबंध में अधिकारों की सटीक प्रकृति से संबंधित है), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP), वाणिज्य मंत्रालय के तत्वावधान में। • इसके कार्यान्वयन निकाय पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक होते है।
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना	**खबरों में क्यों:** RoDTEP योजना को रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और आयरन एंड स्टील के लेखों तक बढ़ाया गया था। **योजना के बारे में:** • RoDTEP का मतलब निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट है। • यह योजना 1 जनवरी 2021 से लागू की जा रही है। • इसने MEIS (मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम) का स्थान लिया। • RoDTEP विश्व स्तर पर स्वीकृत सिद्धांत पर आधारित है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए, और निर्यात किए गए उत्पादों पर लगने वाले करों और शुल्कों को या तो छूट दी जानी चाहिए या निर्यातकों को भेज दी जानी चाहिए। • RoDTEP योजना उन निर्यातकों को एम्बेडेड केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों में छूट/धनवापसी करती है जिन्हें अब तक छूट/वापसी नहीं दी जा रही थी।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)	**खबरों में क्यों:** भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (MSO) पंजीकरण का नवीनीकरण' पर अपनी सिफारिशें जारी कीं। **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के बारे में** • यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा स्थापित किया गया था।

	• TRAI में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। • TRAI को संचार और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सचिव की अध्यक्षता वाले सचिवालय के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। • ट्राई अधिनियम को 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया था, जिसने ट्राई से न्यायिक और विवाद कार्यों का नियंत्रण ग्रहण करने के लिए एक दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) की स्थापना की। • ट्राई ने Mycall ऐप, MySpeed ऐप और डू नॉट डिस्टर्ब (DND 2.0) ऐप लाया हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता जो भुगतान कर रहे हैं और जो टेलीकॉम ऑपरेटर एक निश्चित दर पर प्रदान करने का वादा कर रहे हैं, उसके बीच पारदर्शिता है।
कोल इकॉनमी	**खबरों में क्यों:** आईईए का कोयला 2022: 2025 की रिपोर्ट का विश्लेषण और पूर्वानुमान कहता है कि कोयला वैश्विक कोयले की मांग का विकास इंजन बना रहेगा। • वैश्विक कोयले की मांग इस साल आठ अरब टन तक पहुंच गई। • निकट अवधि में लौह और इस्पात क्षेत्र में कोयले की जगह ले सकने वाले कम उत्सर्जन वाले विकल्पों के अभाव में, वैश्विक कोयले की मांग पूर्वानुमान अवधि के दौरान सपाट रहने के लिए तैयार है। **भारत:** • भारत, चीन के साथ, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसका अपना कोयला उत्पादन 2025 तक एक बिलियन टन को पार कर जाएगा। • भारत में कोयले की खपत 2007 के बाद से 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से दोगुनी हो गई है। • भारत और चीन, विश्व स्तर पर केवल दो देश हैं जहां कोयला खदानों की संपत्ति में निवेश में वृद्धि हुई है क्योंकि बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए दोनों देशों में घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है।
समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 (मैरीटाइम एंटी-पायरेसी बिल, 2022)	**खबरों में क्यों :** संसद ने मेरीटाइम एंटी-पायरेसी बिल 2022 को राज्यसभा की मंजूरी के साथ पारित कर दिया है। 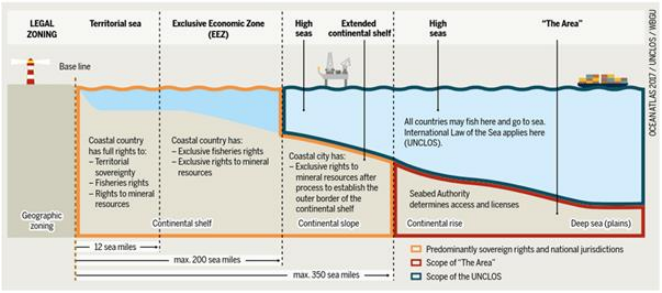 **विधेयक के बारे में:** • यह समुद्री डकैती को एक निजी जहाज़ या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिये किसी जहाज़, विमान, व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ की गई हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। • एंटी-मैरीटाइम पाइरेसी बिल, 2019 भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। • यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से परे समुद्र पर लागू होता है। • ईईजेड भारत के समुद्र तट से 200 समुद्री मील से परे है।
रक्तसे कार्पो खुबानी (Raktsey Karpo Apricot),	**संदर्भ:** जीआई के वर्तमान संग्रह में भारत के विभिन्न राज्यों जैसे तेलंगाना के तंदूर रेडग्राम, लद्दाख के रक्तसे कारपो खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज जैसे 03 नए आइटमों को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है।

तंदूर रेडग्राम और अलीबाग सफेद प्याज - नए जीआई टैग जोड़े गए

रक्तसे कार्पो खुबानी के बारे में:

- रक्तसे कारपो, खुबानी (apricot) के परिवार से संबंधित है। विटामिन और कम कैलोरी से भरपूर, यह सोर्बिटोल से भरपूर है – एक प्राकृतिक ग्लूकोज विकल्प जो मधुमेह रोगियों द्वारा सेवन किया जा सकता है।
- इसके बीजों का तेल कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने के लिए जाना जाता है।
- इन खुबानी को किसी भी रासायनिक उर्वरक का उपयोग किए बिना पेड़ों पर या गुच्छों में व्यवस्थित रूप से उगाया जाता है।
- लद्दाख में इसे स्थानीय रूप से 'चूली' के नाम से जाना जाता है।
- लद्दाख के देशी खुबानी जीनोटाइप में अद्वितीय विशेषताएं हैं, जैसे उच्च टीएसएस (कुल घुलित ठोस) सामग्री, देर से और विस्तारित फूल और फल परिपक्वता, और सफेद बीज स्टोन फेनोटाइप।

खुबानी को दो श्रेणी में बांटी गई है –

- स्वाद के आधार पर :-
    - कड़वी गुठली वाले -इसे खंते भी कहते हैं यह कड़वा होता है।
    - मीठी गुठली वाले – इसे न्यारामो कहते हैं यह मीठा होता है।
- बीज के रंग के आधार पर
    - सफेद बीज वाले- इसे रक्तसे कार्पो कहा जाता है, इसे ही GI टैग प्राप्त हुआ, इसमें रक्तसे का अर्थ बीज तथा karpo का अर्थ सफेद है।
    - भूरे बीज वाले – इसे रक्तसे नाकापो कहा जाता है, इसका बीज काला रंग का होता है।
- ये खुबानी लद्दाख की पहली जीआई टैग उत्पाद है, जिसकी खेती को अब कारगिल में 'एक जिला-एक उत्पाद' के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
- भारत में, यह जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में एक सीमित सीमा तक उगाया जाता है।
- पेड़ सर्दियों के तापमान को -30 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान को सहन कर सकता है यदि वह स्वस्थ अवस्था में हो।

तेलंगाना के तंदूर लाल ग्राम के बारे में:

- यह अरहर की एक स्थानीय किस्म है जो मुख्य रूप से राज्य के तंदूर और आस-पास के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, विशेष रूप से तंदूर क्षेत्र में मिट्टी के खनिजों के साथ उपजाऊ गहरी काली मिट्टी के साथ-साथ विशाल चूना पत्थर के भंडार को तंदूर लाल चना को विशिष्ट गुणवत्ता व् लक्षण प्रदान करते हैं
- इसमें लगभग 24 प्रतिशत प्रोटीन होता है, जो अनाज के लगभग तीन गुना है, और अपने बहुत अच्छे स्वाद और बेहतर खाना पकाने की गुणवत्ता के लिए लोकप्रिय है।

महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज के बारे में:

- यह अपने अनोखे मीठे स्वाद, बिना आंसू वाले कारक और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है।
- अलीबाग तालुका की मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम है और इसकी भू-जलवायु स्थितियां इसे अन्य सफेद प्याज उत्पादक क्षेत्रों की तुलना में अद्वितीय बनाती हैं।
- सफेद प्याज एंटीऑक्सिडेंट का एक उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें 25 से अधिक विभिन्न प्रकार के फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के विकास के जोखिम को कम करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

एशिया-पेसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन

खबरों में क्यों : प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक, 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन 25 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ।

- **थीम -** इस वर्ष की महासभा की थीम यह है: 'लोगों की सेवा करना: संकट की घड़ी में मीडिया की भूमिका।

ABU:

- एबीयू की स्थापना 1964 में एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी, गैर-राजनीतिक, पेशेवर संघ के रूप में की गई थी
- यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारण संघ है।
- इसमें लगभग 70 देश और 5 महाद्वीप शामिल हैं और इसके 250 सदस्य हैं।

भारतीय सदस्य:

- अखिल भारतीय रेडियो / प्रसार भारती (AIR)
- दूरदर्शन/प्रसार भारती (DD)

कार्य:

	• एबीयू विचारों, अनुभवों और प्रथाओं के आदान-प्रदान के मंच के रूप में प्रमुख उद्योग, क्षेत्रीय और वैश्विक सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों का आयोजन करता है। • ABU मीडिया अकादमी उत्कृष्टता और सीखने का एक केंद्र है, जो सालाना सैकड़ों पाठ्यक्रम और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ प्रदान करता है। • यह विकासशील देशों के लिए अधिकार-मुक्त सामग्री अधिग्रहण प्रदान करता है, प्रमुख खेल आयोजनों के लिए अधिकारों की बातचीत करता है और क्षेत्र के लिए कवरेज का आयोजन करता है। • यह संकट के समय में मीडिया व्यवसायियों को मीडिया की भूमिका के बारे में प्रशिक्षित और सुसज्जित करता है। • यह इस विशाल क्षेत्र से पत्रकारिता समुदाय और शिक्षाविदों के सदस्यों को एक साथ लाने और उन्हें गहन सीखने, चर्चाओं, विचारों के आदान-प्रदान और नेटवर्किंग में शामिल करने के लिए नवीनतम रुझानों और चुनौतियों का भी पता लगाता है।
वासेनार अरेंजमेंट	**खबरों में क्यों :** भारत 1 जनवरी 2023 को वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। • भारत ने UNSC की अध्यक्षता भी ग्रहण की है। **वासेनार अरेंजमेंट के बारें में** • यह 1996 में स्थापित किया गया। • यह एक स्वैच्छिक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। • सदस्य देश पारंपरिक हथियारों के हस्तांतरण और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों जैसे विभिन्न मुद्दों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। • दोहरे उपयोग का मतलब किसी वस्तु या तकनीक की क्षमता को कई उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से है - आमतौर पर शांतिपूर्ण और सैन्य। • वासेनार अरेंजमेंट का सचिवालय ऑस्ट्रिया के विएना में है। • इसके 42 सदस्य देश हैं। • भारत 2017 में व्यवस्था का इसका सदस्य बना। **भारत के लिए महत्व:** • भारत आतंकवादियों या आतंकवाद का समर्थन करने वाले संप्रभु राष्ट्रों को हथियारों के उपयोग को रोकने में सक्षम होगा। • भारत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो भारत में नए उभरते रक्षा और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम कर सकते हैं। • भारत धीरे-धीरे डब्ल्यूए की नियंत्रण सूची में कई वस्तुओं के कम लागत वाले उत्पादक के रूप में उभर रहा है।
सिंगापुर घोषणा	**खबरों में क्यों :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक (APRM) सिंगापुर में आयोजित की गई। **सिंगापुर घोषणा के बारे में:** • सिंगापुर घोषणा का उद्देश्य श्रम बाजार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने और COVID-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक अनिश्चितता जैसे संकटों का समाधान खोजने के लिए सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना है। • यह घटती मजदूरी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए ILO के सदस्यों की राष्ट्रीय कार्रवाई की 10-सूत्रीय प्राथमिकताओं का एक साझा दृष्टिकोण प्रदान करता है। • इसने माना कि श्रम बाजार संस्थान में विश्वास और लचीलापन हासिल करने, स्थायी सुधार और समावेशी वैश्विक प्रगति के लिए सामाजिक संवाद महत्वपूर्ण है। • मजदूरों और नियोक्ताओं के मजबूत और प्रतिनिधि संगठन स्थायी और समावेशी समाजों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं और सामाजिक न्याय और अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए मौलिक हैं।

- जिन देशों में नीति विकास और चर्चा में योगदान करने के लिए अपर्याप्त क्षमता, तंत्र या स्वतंत्रता है, वहां नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों और सरकारों के लिए क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए।
- सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संघ की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और सीमांत श्रमिकों और अनौपचारिक कार्यबल सहित पूरे क्षेत्रों में सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की मान्यता के माध्यम से श्रमिक हितों की रक्षा की जाती है।
- नौकरी के बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर, समान मूल्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देकर, काम और जिम्मेदारियों में संतुलन बनाकर और महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देकर दुनिया भर में लैंगिक अंतर को दूर किया जाना चाहिए।
- अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में एक सहज और निरंतर परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- शासन के ढांचे को मजबूत करके और संघ बनाने की स्वतंत्रता का सम्मान करके प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। भेजने और प्राप्त करने वाले देशों के बीच बढ़े हुए द्विपक्षीय श्रम प्रवासन समझौते के माध्यम से, उनके आवास में सुधार करने, उनके वेतन की रक्षा करने और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- सरकारों को संकट के समय में शांति, सुरक्षा और अच्छे काम के लिए सुगम संक्रमण की सुविधा देनी चाहिए।
- सार्थक और प्रभावी सामाजिक संवाद के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के निर्माण के लिए बस बदलाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

इतिहास, कला और संस्कृति

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

संदर्भ: भारत के प्रधान मंत्री ने 3 दिसंबर 2022 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

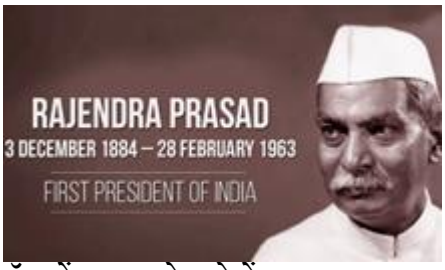

डॉ राजेंद्र प्रसाद के बारे में:

व्यक्तिगत जीवन:

- **जन्म :** उनका जन्म 3 दिसंबर, 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था।
- **शिक्षा:** उन्होंने 1902 में कलकत्ता प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। 1907 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने कलकत्ता लॉ कॉलेज में कानून का अध्ययन किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभ्यास किया।
- उन्होंने 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में डॉक्टरेट पूरा किया।
- 1920 के दशक की शुरुआत में, वह एक हिंदी साप्ताहिक देश और एक अंग्रेजी द्विसाप्ताहिक, सर्चलाइट के संपादक बने।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन:

- प्रसाद ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया।
- वह 1911 में पार्टी में शामिल हुए और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए चुने गए जिसके बाद उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई।
- वह महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने बिहार के चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी का समर्थन किया था।
- उन्होंने बाद में 1920 में एक वकील के रूप में अपने आकर्षक कैरियर को छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए और असहयोग आंदोलन में भाग लिया।
- उन्होंने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, बैठकें कीं, राज्य का दौरा किया और भाषण दिए। उन्होंने लोगों से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, नौकरियों का बहिष्कार करने का आग्रह किया।
- उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 1921 में पटना में नेशनल कॉलेज की शुरुआत की और लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा।
- उन्होंने 1935 के क्वेटा भूकंप (Quetta Earthquake) के बाद अपनी अध्यक्षता में सिंध और पंजाब में क्वेटा केंद्रीय राहत समिति की स्थापना की।
- अक्टूबर 1934 में प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
- 1939 में सुभाष चंद्र बोस के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद और 1947 में जब जे.बी. कृपलानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तब उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था।
- राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसाद को कई बार गिरफ्तार किया गया और 1931 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कैद किया गया।

	संविधान निर्माण में योगदान: • 1946 में, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भारत की अंतरिम सरकार में शामिल हुए। **डॉ प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की समितियों में शामिल हैं:** • राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति • प्रक्रिया के नियमों पर समिति • वित्त और कर्मचारी समिति • संचालन समिति **साहित्यिक कार्य:** • चंपारण में सत्याग्रह (1922) • भारत विभाजित (1946) • आत्मकथा (1946) बांकीपुर जेल में 3 साल की जेल की अवधि के दौरान लिखी गई उनकी आत्मकथा। • महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें (1949) • बापू के कदमों में (1954) • स्वतंत्रता के बाद से (1960)
महापरिनिर्वाण दिवस	**खबरों में क्यों:** हाल ही में भारत रत्न डॉ. बीआर अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस या पुण्यतिथि मनाई गई। **बीआर अंबेडकर के बारे में:** • डॉ अंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और एक समाज सुधारक थे जिन्होंने दलितों, महिलाओं और मजदूरों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। • उनका जन्म 1891 में महू सेना छावनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। • वे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। • उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। **शिक्षा:** • उन्होंने एलफिंस्टन हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। • उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। • उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक और डॉक्टरेट पूरा किया - उनकी थीसिस "दी प्राब्लम आफ दि रुपी: इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन" (रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान) पर थी। • उन्होंने अपनी पीएच.डी. कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। **योगदान:** • 1919 में, भारत सरकार अधिनियम की तैयारी में साउथबरो समिति के समक्ष अपनी गवाही में अम्बेडकर ने कहा कि दलितों और अन्य समुदायों के लिए एक अलग चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। • 1920 में, अम्बेडकर ने कोल्हापुर के महाराजा, शाहजी द्वितीय की सहायता से "मूकनायक" (मूकनायक) नामक एक समाचार पत्र शुरू किया। • 1923 में, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा (बहिष्कृत कल्याण संघ) की स्थापना की।

	• अम्बेडकर ने 1927 तक दलित अधिकारों के लिए पूर्ण आंदोलन शुरू किया और सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को सभी के लिए खोलने और सभी जातियों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार देने की मांग की। • 1932 में, अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। • उन्होंने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। • 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और उनकी पार्टी ने 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा। • 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। • 1947 में डॉ. अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। • 1950 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। • 1956 में अम्बेडकर ने अपने लगभग पांच लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। • 2 दिसंबर, 1956 तक उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि, "द बुद्धा या कार्ल मार्क्स" को पूरा किया। • 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने घर पर उनका निधन हो गया। **किताबें और पत्रिकाएँ:** • बहिष्कृत भारत (1927) • समता (1929) • जनता (1930) • मूक नायक (साप्ताहिक) • जाति का संहार • हिंदू धर्म का दर्शन • हिन्दू धर्म की पहेलियां • शूद्र कौन थे?
संगाई महोत्सव	**संदर्भ:** हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से मणिपुर संगई महोत्सव को संबोधित किया। **संगाई महोत्सव के बारे में:** • इस त्योहार का नाम राजकीय पशु, संगाई के नाम पर रखा गया है, जो केवल मणिपुर में पाया जाने वाला हिरन है। • संगाई उत्सव मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। • इस महोत्सव के कई संस्करण पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन महोत्सव के नाम से मनाए गए हैं, 2010 से इसका नाम बदलकर संगाई महोत्सव कर दिया गया है। • मणिपुर को विश्व स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। **यह राज्य के योगदान को दर्शाता है:** कला और संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, ललित कला, स्वदेशी खेल, व्यंजन, संगीत और साहसिक खेल, प्राकृतिक पर्यावरण।
सिलहट-सिलचर महोत्सव	**संदर्भ:** भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए असम की बराक घाटी में 7 दिसंबर, 2022 को सिलहट-सिलचर महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया गया। • इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। **सिलहट-सिलचर महोत्सव के बारे में:** • इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा असम सरकार द्वारा बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप सोसाइटी और भारत-बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से समर्थित है।

	• यह त्योहार भारत और बांग्लादेश के बीच समानताओं को रेखांकित करता है, विशेष रूप से बंगाली भाषा का सिलहटी संस्करण और सिलहटी संस्कृति। **महत्व:** • इस महोत्सव का उद्देश्य दोनों शहरों और उनके लोगों को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से अलग करने के सामान्य मूल्यों और साझा विरासत को पुनर्जीवित करना है। • इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति, व्यंजन, साहित्य, कला और शिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। • यह उत्सव सार्वजनिक और सामाजिक जीवन के प्रतिष्ठित लोगों, उद्योगपतियों, कलाकारों, विद्वानों और दोनों पक्षों के चिकित्सकों को आपसी विकास और अवसर के मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाएगा। • इसके अलावा, महोत्सव स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बहु-विषयक व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा।
पं. मदन मोहन मालवीय	**खबरों में क्यों :** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने शिक्षा क्षेत्र को समृद्ध बनाने में पंडित मदन मोहन मालवीय के यादगार योगदान को याद किया। 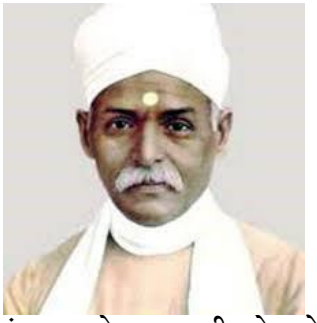 **पं. मदन मोहन मालवीय के बारे में** • 25 दिसंबर, 1861 को इलाहाबाद में जन्मे मालवीय ने प्रारंभिक शिक्षा 'पाठशाला' प्रणाली के तहत ली, और संस्कृत में निपुण थे। • 1879 में, उन्होंने मुइर सेंट्रल कॉलेज (वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय) से स्नातक किया और एक स्थानीय हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया। **योगदान:** • 1906 में हिंदू महासभा की स्थापना की। • 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की स्थापना की। • मालवीय जी 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। • वह 1909, 1918, 1932 और 1933 में चार बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। • वह एक समाज सुधारक और एक सफल लेगिज़लेटर (legislator) थे, जिन्होंने 11 वर्षों (1909-20) तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया। • मालवीय ने मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का समर्थन किया, ब्रिटिश साम्राज्य में अनुबंधित श्रम प्रणाली का विरोध किया और रेलवे के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया। • 1930 में, जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने इसमें भाग लिया और गिरफ्तारी दी। • उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव पर दो प्रसिद्ध भाषण दिए- एक 1922 में लाहौर में और 1931 में कानपुर में। • उन्होंने गाय के कल्याण के लिए वृंदावन में श्री मथुरा वृंदावन हसनानंद गोचर भूमि नाम से एक गैर-सरकारी संगठन बनाया। **उपलब्धियां:**

	• उन्हें 'महामना' कहा जाता है। • 2015 में, सरकार ने मालवीय को उनकी मृत्यु के 68 साल बाद भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। • 2016 में, भारतीय रेलवे ने नेता के सम्मान में वाराणसी-नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस शुरू की। • **पुस्तकें -** भारतीय संवैधानिक सुधार, भाषणों और लेखन के मोंटागु-चेम्सफोर्ड प्रस्तावों की आलोचना।
रत्नागिरी की पूर्व-ऐतिहासिक रॉक कला	**संदर्भ:** हाल ही में पुरातत्व संरक्षणवादियों ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी (Ratnagiri) जिले के बारसू (Barsu) गांव में एक मेगा ऑयल रिफाइनरी की प्रस्तावित अवस्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञों का दावा है कि यह रिफाइनरी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रागैतिहासिक ज्योग्लिफ्स (prehistoric geoglyphs) को नुकसान पहुंचा सकती है। **कला के बारे में:** • इसे रत्नागिरी में स्थानीय रूप से कटल शिल्पा के नाम से भी जाना जाता है। • ये स्थल राज्य पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित हैं। • रत्नागिरी स्थित गैर-लाभकारी संगठन निसर्ग यात्री संस्था (Nisarga Yatri Sanstha) पिछले कुछ वर्षों से कोंकण क्षेत्र में ज्योग्लिफ्स को खोजने और संरक्षित करने के लिए काम कर रही है। • इसमें 1500 से अधिक पेट्रोग्लिफ हैं। • **पेट्रोग्लिफ्स:** यह रॉक आर्ट के रूप में इन्साइजिंग, पिकिंग, नक्काशी और एब्रेडिंग का उपयोग करके चट्टान की सतह पर बनाई गई एक छवि है। • यूनेस्को कार्बन और भूवैज्ञानिक डेटिंग का उपयोग करके इन साइटों को 12,000 साल से अधिक पुराना बताता है। • यूनेस्को की सूची में "कोंकण ज्योग्लिफ्स" का उल्लेख है। **ज्योग्लिफ्स के बारे में:** • यह प्रागैतिहासिक रॉक कला का एक रूप है। • इसे लेटराइट पत्थर पर उकेरा गया है। • यह शैल चित्रों, नक़्क़ाशी, कप के निशान और अंगूठी के निशान के रूप में हो सकता है। • रत्नागिरी जिले के कशेली में भारत का सबसे बड़ा रॉक उत्कीर्णन या ज्योग्लिफ़ है। • इसमें एक हाथी की 18X13 मीटर बड़ी आकृति है। • इनमें से कुछ समूहों में जीवन से बड़े पैमाने के एक या दो स्टैंडअलोन आंकड़े हैं और अन्य एक साथ एकत्रित कई आंकड़े दिखाते हैं। **रॉक आर्ट का महत्व:** • यह मेसोलिथिक (मध्य पाषाण युग) से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग तक मानव बस्तियों के निरंतर अस्तित्व का प्रमाण है। • यह विश्व विरासत स्थल बनने के लिए तीन संभावित स्थलों में से एक है। • अन्य दो में मेघालय में जीवित मूल पुल जिंगकींग जरी और आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर शामिल हैं। • इसमें दर्शाया गया है कि कैसे लोग शुष्क पठार में उथले रॉक पूल, धाराओं और जलकुंडों में आर्द्रभूमि के लिए अनुकूलित हुए।

	• इसके समूह रॉक कला में नक़्क़ाशी और स्कूपिंग की तकनीकों के विकास को दर्शाने वाले उन्नत कलात्मक कौशल के उदाहरण हैं। • इसमें मनुष्यों और जानवरों जैसे हिरण, हाथी, बाघ, बंदर, जंगली सूअर, गैंडा, दरियाई घोड़ा, मवेशी, सुअर, खरगोश और बंदर की नक्काशी है। • इसमें बड़ी संख्या में सरीसृप और उभयचर जीव जैसे कछुआ और घड़ियाल, जलीय जानवर जैसे शार्क और स्टिंग रे, और पक्षी जैसे मोर शामिल हैं।
तानपुरा/तंबूरा	**संदर्भ:** संकटग्रस्त तानपुरा निर्माताओं को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से कुछ समर्थन मिलता है। • शास्त्रीय भारतीय वाद्य वाद्ययंत्रों के पारंपरिक निर्माता अपनी कला के विलुप्त होने की चिंतित रहते हैं, यह युवा पीढ़ी के बीच बहुत कम रुचि है, और उनके अधिकांश ग्राहक अब विदेशों में स्थित हैं। **तानपुरा/तंबूरा के बारे में:** • तानपुरा, जिसे तंबूरा और तानपुरी के रूप में भी जाना जाता है, भारत में उत्पन्न होने वाला एक लंबी गर्दन वाला प्लक तार वाद्य यंत्र है। • यह राग नहीं बजाता है, बल्कि किसी अन्य वाद्य या गायक की धुन को निरंतर सुरीला बौरन या ड्रोन प्रदान करके सहयोग और समर्थन करता है। • एकलवादक या तालवादक के साथ ताल में तानपुरा नहीं बजाया जाता है। • हिंदुस्तानी संगीतकार तानपुरा शब्द के पक्ष में हैं जबकि कर्नाटक संगीतकार तंबूरा कहते हैं। • तानपुरों को दो अलग-अलग शैलियों में डिज़ाइन किया गया है: **I. मिराज शैली:** यह हिंदुस्तानी कलाकारों के लिए तानपुरा का पसंदीदा रूप है। **II. तंजौर शैली:** यह तंबूरा की एक दक्षिण भारतीय शैली है, जिसका कर्नाटक कलाकारों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बारे में:** • भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। • यह अन्य देशों और उनके लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों में शामिल है। • इसकी स्थापना 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। • **मुख्यालय:** नई दिल्ली। • यह परिषद विभिन्न देशों में स्थापित सांस्कृतिक केंद्रों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मिशन संचालित करती है। • भारत और विदेशों में सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन के अलावा, ICCR पूरे भारत में कई सांस्कृतिक संस्थानों का वित्तीय समर्थन करता है, और नृत्य, संगीत, फोटोग्राफी, थिएटर और दृश्य कला में व्यक्तिगत कलाकारों को प्रायोजित करता है। • यह 1965 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का भी संचालन करता है, जिसका अंतिम पुरस्कार 2009 में था।

मैतेई लिपि

संदर्भ: लिपि, जिसे कभी मेइतेई शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त था, लेकिन जो हिंदू धर्म के आने से अनुपयोगी और अंततः गायब हो गई, यह अब अपने पुनरुद्धार के लिए एक दशक पुराने आंदोलन के बाद जीवन के एक नए लीज का आनंद ले रही है।

मेइतिलोन लिपि के बारे में:

- मेइतिलोन (मणिपुरी भाषा) लिपि काफी पुरानी है।
- लिपि का सबसे पहला पुरालेखीय रिकॉर्ड खोइबु गांव का एक पत्थर का शिलालेख है जिसे मेइडिंगु कियांबा (1467-1508) के आदेश पर बनाया गया था।
- 'मेडिंगु' वे राजा हैं जो निंगथौजा वंश के हैं जिनका शासन 33 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक फैला हुआ है।
- मेइतेई मयेक या मैतेई लिपि समय के साथ विकसित हुई और इसके कारण विभिन्न समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ।
- 7वीं और 8वीं शताब्दी के सिक्कों पर शिलालेख शायद 18-अक्षरों की लिपि में थे, जो 17वीं शताब्दी में मेइडिंगु पम्हीबा (1709-1748) के शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म के आगमन के साथ, शायद 36-अक्षरों की लिपि में विस्तारित हो गया था।
- हिंदू धर्म के आगमन के साथ, बंगाली लिपियाँ इतनी लोकप्रिय हो गईं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में शिलालेख बंगाली लिपि में थे।
- मैतेई मयेक को पुनर्जीवित करने का आंदोलन 1930 के दशक में शुरू हुआ और 1950 के दशक में इसने मजबूती हासिल की।
- 18 मई, 2005 को लिए गए कैबिनेट के एक फैसले से, मैतेई मयेक में लिखी गई मणिपुरी को स्कूलों में प्रस्तुत किया गया था और अब तक, इसे बंगाली लिपि की जगह विश्वविद्यालय स्तर पर भी पढ़ाया जाता है।

1925 काकोरी ट्रेन एक्शन

संदर्भ: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चार क्रांतिकारियों को 17 दिसंबर (राजेंद्रनाथ लाहिड़ी) और 19 दिसंबर (अशफाकउल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह) को 1927 में फांसी दी गई थी।

- यह काकोरी ट्रेन डकैती के दो साल बाद हुआ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्यों ने ब्रिटिश खजाने में पैसे ले जाने वाली एक ट्रेन को लूट लिया था।

1925 काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में:

- काकोरी षडयंत्र (या काकोरी ट्रेन डकैती) एक ट्रेन डकैती थी जो लखनऊ के पास हुई थी। यह डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) द्वारा आयोजित की गई थी।
- 9 अगस्त 1925 को, शाहजहाँपुर से लखनऊ जाने वाली 8 नंबर डाउन ट्रेन काकोरी शहर के पास आ रही थी, जब एक क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोकने के लिए आपातकालीन चैन खींच दी और बाद में गार्ड पर काबू पा लिया।
- लखनऊ में जमा करने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों से एकत्र किए गए धन को ले जाने वाला गार्ड केबिन इनका लक्ष्य था। क्रांतिकारियों ने केवल इन थैलियों (जिनमें 100,000 रुपये से अधिक थे) को लूटे और लखनऊ से भाग निकले।
- हालांकि क्रांतिकारियों ने किसी भी यात्री को निशाना नहीं बनाया, लेकिन गार्ड और क्रांतिकारियों के बीच हुई गोलीबारी में अहमद अली नाम का एक यात्री मारा गया। जिससे यह हत्या का मामला बना।
- डकैती की योजना को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, स्वर्ण सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशब चक्रवर्ती, मन्मथनाथ गुप्ता, मुकुंदि लाल, बनवारी लाल, कुंदन लाल और प्रणवेश मुखर्जी ने अंजाम दिया था।

	• आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मुकदमे के दौरान 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। • इनमें से अधिकांश बंदियों को पंडित गोबिंद बल्लभ पंत, मोहनलाल सक्सेना, चंद्रभानु गुप्ता, अजीत प्रसाद जैन, गोपीनाथ श्रीवास्तव, आर. एम. बहादुरजी और बी. के. चौधरी द्वारा कानूनी राहत दिया गया था। • राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने मामले का बचाव किया। • स्वर्ण सिंह (भगत सिंह के चाचा), राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह सहित 5 सदस्यों को मौत की सुनाई गई। • उर्दू कविता सरफ़रोशी की तमन्ना को इसी दौरान राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लोकप्रिय हुई। यह कविता वास्तव में बिस्मिल अज़ीमाबादी द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखी गई थी। • चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें पकड़ा नहीं जा सका, ने HRA को पुनर्गठित किया और 1931 तक संगठन चलाया।
गोवा मुक्ति दिवस	**संदर्भ:** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर राष्ट्र को अपनी शुभकामनाएं ट्वीट कीं, जो पुर्तगाली औपनिवेशिक ताकतों को हराने और 1961 में गोवा को आजाद कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन विजय' की सफलता को चिह्नित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। **गोवा मुक्ति दिवस के बारे में:** • 18 और 19 दिसंबर, 1961 को 'ऑपरेशन विजय' नामक एक पूर्ण सैन्य अभियान चलाया गया, जिसे थोड़े प्रतिरोध के साथ अंजाम दिया गया और आत्मसमर्पण के एक साधन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके कारण भारत द्वारा गोवा का विलय किया गया। **गोवा का इतिहास:** • गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक उपस्थिति 1510 में शुरू हुई, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने एक स्थानीय सहयोगी तिमय्या की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर के राजा को हराया और बाद में वेल्हा गोवा (या पुराना गोवा) में एक स्थायी समझौता स्थापित किया। • नेपोलियन युद्धों के दौरान, 1812 और 1815 के बीच गोवा पर अंग्रेजों का संक्षिप्त कब्जा था। • 1843 में, राजधानी को वेल्हा गोवा से पणजी में स्थानांतरित कर दिया गया था। • पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन ने गोवा में ईसाई धर्म के आगमन और विकास को भी देखा। **गोवा की स्वतंत्रता:** • बीसवीं शताब्दी के अंत तक, गोवा ने पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासन के विरोध में राष्ट्रवादी भावना के उभार को देखना शुरू कर दिया था। • गोयन राष्ट्रवाद के पिता के रूप में मनाए जाने वाले ट्रिस्टाओ डी ब्रागांका कुन्हा जैसे नेताओं ने 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। • 1946 में, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गोवा में एक ऐतिहासिक रैली का नेतृत्व किया जिसने नागरिक लिबर्टीज और स्वतंत्रता, और अंततः भारत के साथ एकीकरण का आह्वान किया, जो गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बन गया। • 1947 के बाद, पुर्तगाल ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संप्रभुता के हस्तांतरण पर स्वतंत्र भारत के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। • 1949 में पुर्तगाल अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) का हिस्सा बनने के बाद, गोवा भी विस्तार से सोवियत विरोधी गठबंधन का हिस्सा बन गया। • गोवा पर संभावित हमले की सामूहिक पश्चिमी प्रतिक्रिया के डर से, भारत सरकार ने कूटनीति पर जोर देना जारी रखा। • जैसा कि भारत ने अपनी नीति के स्तंभों के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उपनिवेशीकरण और साम्राज्यवाद विरोधी आक्रामक रूप से समर्थन किया, पुर्तगाल में औपनिवेशिक शासन की निरंतरता तेजी से अस्थिर हो गई।
पाणिनि की	**संदर्भ:** हाल ही में कैम्ब्रिज के विद्वान ने संस्कृत की सबसे बड़ी पहेली को हल करने का दावा किया है- एक व्याकरण की

'अष्टाध्यायी'	समस्या जो 'अष्टाध्यायी' में पायी जाती है, यह विद्वान पाणिनि द्वारा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। **पाणिनि, 'भाषा विज्ञान के जनक' के बारे में:** • पाणिनि संभवत: चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में थे, जब सिकंदर की विजय और मौर्य साम्राज्य की स्थापना का युग था। • वे संभवतः सलातुरा (गांधार) में रहते थे, जो वर्तमान में उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। • पाणिनि संभवत: तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय से जुड़े थे, जिसने कौटिल्य और चरक को भी दिया था, जो क्रमशः राज्यकला और चिकित्सा के प्राचीन भारतीय स्वामी थे। **अष्टाध्यायी के बारे में:** • 'अष्टाध्यायी', या 'आठ अध्याय' - एक भाषाई पाठ है जो इस बात के लिए मानक निर्धारित करता है कि संस्कृत को कैसे लिखा और बोला जाना चाहिए था। • पाणिनि की टिप्पणियों में पतंजलि का महाभाष्य (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व) और जयादित्य और वामन की काशिका वृत्ति (7वीं शताब्दी ईस्वी) शामिल हैं।
बेट्टा-कुरुबा जनजाति	**संदर्भ:** हाल ही में लोकसभा ने बेट्टा-कुरुबा को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया। **बेट्टा-कुरुबा के बारे में:** • बेट्टा कुरुबा (बेट्टा का अर्थ 'पहाड़ी', कुरुबा का अर्थ 'चरवाहा') जनजाति कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, और नीलगिरी के कुछ स्वदेशी समुदायों में से एक है। • परंपरागत रूप से, कुरुबा के लोग शिकार करके, जंगली शहद इकट्ठा करके अपना भरण-पोषण करते थे। • स्थानांतरण के कारण, बेट्टा कुरुबा के लोगों को अपनी पारंपरिक आजीविका छोड़ने और कॉफी, मसाले (जैसे काली मिर्च, अदरक, इलायची) और चाय के बागानों में खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। • ये बेट्टा कुरुम्बा भाषा बोलते हैं जो एक द्रविड़ भाषा है जो तमिल से निकटता से संबंधित है। • इन्हें आमतौर पर पल्लवों का वंशज माना जाता है। • कुरुंबों के बीच सगोत्रीय विवाह (Consanguineous marriages) जैसे क्रॉस-कजिन विवाह पसंद किए जाते हैं।
श्रीशैलम मंदिर	**संदर्भ:** हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम मंदिर के परियोजना विकास का उद्घाटन किया है। **मंदिर के बारे में:** • इसे भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। • यह आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले के श्रीशैलम में स्थित है। • मंदिर नल्लामाला पहाड़ियों की चोटी पर और कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। • यह भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को समर्पित है। • यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो शैववाद और शक्तिवाद दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। • लिंगम के आकार में प्राकृतिक पत्थर की संरचनाओं में देवी ब्रह्मरम्बा देवी और भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी हैं। • देवताओं की मूर्ति को 'स्वयंभू' या स्वयं प्रकट माना जाता है। • इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और देवी पार्वती के 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। **श्रीशैलम मंदिर का इतिहास:**

	• श्रीशैलम मंदिर का उल्लेख पहली शताब्दी ईस्वी में सातवाहन राजा वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के नासिक शिलालेख में मौजूद है। • रेड्डी राजाओं- प्रोले वेम्मा और अनावेमा रेड्डी ने मंदिर में रास्ते और मंडप बनवाए। • मंदिर में आधुनिक परिवर्धन विजयनगर साम्राज्य के हरिहर प्रथम के शासनकाल के दौरान किए गए थे। **मल्लिकार्जुन मंदिर की वास्तुकला:** • मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। • इसमें ऊंची मीनारें और विशाल आंगन हैं। • त्रिपुरंतकम, सिद्धावतम, आलमपुरा और उमामहेश्वरम के मंदिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आसपास श्री सैलम के चार प्रवेश द्वार के रूप में स्थित हैं।
भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार	**खबरों में क्यों :** भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) के पास 1962, 1965 और 1971 के युद्धों और हरित क्रांति के रिकॉर्ड नहीं हैं। • सभी 151 मंत्रालय और विभाग हैं, और एनएआई के पास केवल 64 एजेंसियों का रिकॉर्ड है - कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने एनएआई के साथ अपने रिकॉर्ड साझा नहीं किए हैं। **एनएआई:** • NAI संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। • यह सभी गैर-वर्तमान सरकारी अभिलेखों का भंडार है, जो उन्हें प्रशासकों और विद्वानों के उपयोग के लिए रखता है। • मूल रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में स्थापित, NAI अब दिल्ली में स्थित है। • यह केवल सरकार और उसके संगठनों के रिकॉर्ड रखता और संरक्षित करता है, और वर्गीकृत दस्तावेज़ प्राप्त नहीं करता है। • NAI में होल्डिंग्स वर्ष 1748 से शुरू होने वाली एक नियमित श्रृंखला में हैं, और अभिलेखों की भाषाओं में अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत और उर्दू शामिल हैं। • हाल ही में, एनएआई ने नए बनाए गए अभिलेख पाताल पोर्टल पर सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया है। **यह दस्तावेज़ कैसे प्राप्त करता है:** • सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम, 1993 के अनुसार, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को 25 वर्ष से अधिक पुराने रिकॉर्ड को एनएआई को स्थानांतरित करना है, जब तक कि वे वर्गीकृत जानकारी से संबंधित न हों। • हालांकि, यह पता लगाने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों पर निर्भर है कि वर्गीकृत जानकारी क्या है, और यहीं पर व्यक्तिपरक राय आ सकती है। • विभिन्न मंत्रालय और प्रशासन अपनी-अपनी परिभाषाएँ देते हैं कि क्या वर्गीकृत है और क्या गैर-वर्तमान है।
श्री गुरु गोबिंद सिंह	**खबरों में क्यों :** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। **श्री गुरु गोबिंद सिंह:**

- गुरु गोबिंद सिंह (5 जनवरी, 1671 - 21 अक्टूबर, 1708) पटना साहिब, बिहार, भारत में "गोबिंद राय" पैदा हुए थे।
- वह सिख धर्म के दसवें और अंतिम गुरु थे।
- गुरु गोबिंद सिंह अपने पिता 'गुरु तेग बहादुर' यानी नौवें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने।

योगदान:

- वह एक दिव्य दूत, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे।
- उन्होंने 1699 में खालसा बिरादरी की संस्था के साथ सिख धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप में बनाया।
- उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अंतिम रूप में पूर्ण किया, जो आज हमें मिलता है।
- अपने नश्वर शरीर को छोड़ने से पहले, गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के अगले और शाश्वत गुरु के रूप में घोषित किया।
- उन्हें सर्बंस दानी (दयालु दाता, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया), मर्द आगमरा (बिना किसी समानता के व्यक्ति), शाह-ए-शहंशाह (सम्राटों के सम्राट), बार दो आलम शाह (दोनों दुनिया के शासक) और अन्य के रूप में विभिन्न रूप से सम्मानित किया जाता है।
- वह फ़ारसी, अरबी और संस्कृत के साथ-साथ अपने मूल पंजाबी से परिचित भाषाविद् थे।
- उन्होंने आगे सिख कानून को संहिताबद्ध किया, मार्शल कविता और संगीत लिखा, और दसम ग्रंथ ("दसवां खंड") नामक सिख कार्य के प्रतिष्ठित लेखक थे।
- गुरु गोबिंद सिंह की आत्मकथा को विचित्र कथा कहा जाता है।

मलिक अहमद और अहिल्याबाई होल्कर

संदर्भ: महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद को बताया कि उन्होंने 18 वीं शताब्दी की मालवा रानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर पश्चिमी महाराष्ट्र शहर अहमदनगर का नाम बदलकर 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर' करने के लिए जिला प्रशासन से एक प्रस्ताव मांगा है।

अहिल्याबाई होल्कर के बारे में:

- उनका जन्म अहमदनगर के चोंडी गाँव में ग्राम प्रधान मानकोजी शिंदे के यहाँ 1725 में हुआ था।
- 1754 में भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की लड़ाई में अपने पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने मालवा पर अधिकार कर लिया।
- उनके शासनकाल में मालवा पर एक बार भी आक्रमण नहीं हुआ।

	• होल्कर के अधीन, महेश्वर शहर एक साहित्यिक, संगीतमय, कलात्मक और औद्योगिक केंद्र बन गया, और उन्होंने वहाँ एक कपड़ा उद्योग स्थापित करने में मदद की, जो अब प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ियों का घर है। **हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार:** • 1780 में, उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, मुगल राजा औरंगजेब द्वारा इसे नष्ट करने का आदेश देने के लगभग एक सदी बाद। • बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकारेश्वरी, गया और रामेश्वरम जैसे पवित्र स्थलों के अलावा, होल्कर ने यात्रियों के लिए विश्राम गृहों और सार्वजनिक घाटों के निर्माण का भी समर्थन किया। **मलिक अहमद निजाम शाह के बारे में:** • 1486 में, मलिक अहमद निज़ाम शाह बहमनी सल्तनत के प्रधान मंत्री बने। • वे राजा द्वारा उन्हें सत्ता से बेदखल करने के प्रयास का मुकाबला किया और मई 1490 में अहमदनगर के पास बहमनी साम्राज्य की सेना को हराया। • 1494 में उन्होंने सीना नदी के बाएं तट पर, जहां उन्होंने सेना को हराया था, के करीब एक शहर की नींव रखी और उसका नाम अपने नाम पर अहमदनगर रखा। • अहमदनगर महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। • कुछ समय बाद, अहमदनगर (तब निजामशाही के नाम से जाना जाता था) बहमनी साम्राज्य से उभरने वाले पांच स्वतंत्र राज्यों में से एक बन गया।
मुहम्मद इकबाल	**संदर्भ:** हाल ही में विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र के खिलाफ मुहम्मद इकबाल द्वारा लिखित प्रार्थना 'लब पे आती है दुआ' के पाठ से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। **मुहम्मद इकबाल के बारे में:** • उनका जन्म कश्मीरी पंडित वंश के एक परिवार में हुआ था जिसने 17 वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म अपना लिया था। • उनका जन्म सियालकोट, पंजाब (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। • उन्हें आमतौर पर अल्लामा (इस्लामी विद्वानों को दी गई उपाधि) कहा जाता था। • एक वकील के रूप में वे कई मामलों में लाहौर उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए। • उन्हें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी, जिन्होंने उन्हें 1922 में "सर" की उपाधि दी थी। • उनकी 60 वर्ष की आयु में लाहौर में निधन हो गया। • उनका मकबरा लाहौर के हजूरी बाग में स्थित है। **राजनीतिक कैरियर और विचारधारा:** • अपने बचे जीवन में, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के विचार का समर्थन किया। • वह मुहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के एक अलग राष्ट्र के दृष्टिकोण से प्रभावित थे। **प्रमुख कार्य:** • उन्होंने उर्दू ग़ज़ल 'सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा' लिखी। • उनकी पहली पुस्तक, असर-ए खुदी (द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ), 1915 में प्रकाशित हुई थी। • इसके बाद 1918 में रामुज-ए-बेखुदी (निःस्वार्थता का रहस्य) का आयोजन किया गया।

	• इसे उनके काव्य दर्शन का आधार माना जाता है।
धनु यात्रा	**संदर्भ:** सबसे बड़ा ओपन-एयर थिएटर फेस्टिवल 'धनु यात्रा' उत्सव दो साल के अंतराल के बाद ओडिशा राज्य के बरगढ़ में शुरू हुआ। **धनु यात्रा के बारे में:** • यह 1947-48 में देश की आजादी का जश्न मनाने के हिस्से के रूप में बरगढ़ में अस्तित्व में आया। • यह सालाना 7-11 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। • यह धान की कटाई के अंत में किया जाता है जो इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। • उत्सव में नाटक वासुदेव के साथ अपनी बहन देवकी के विवाह पर कंस द्वारा मथुरा के सम्राट उग्रसेन को गद्दी से उतारने के साथ शुरू होता है। • यह राक्षस राजा कंस की मृत्यु और उग्रसेन को सिंहासन की बहाली के साथ समाप्त होता है। • जीरा नदी धनु यात्रा उत्सव के दौरान यमुना का प्रतिनिधित्व करती है जब 5 वर्ग किमी में फैली पूरी बारगढ़ नगरपालिका सीमा एक मंच में बदल जाती है और प्रत्येक नागरिक एक भूमिका निभाता है। • इस नदी को कभी बरगढ़ की जीवन रेखा माना जाता था।
तेल त्साफ (Tel Tsaf)	**संदर्भ:** हाल ही में, इज़राइल के तेल त्साफ से नए पुरातात्विक निष्कर्षों ने 5200 ईसा पूर्व या 7,200 साल पहले सिंधु घाटी से उत्पन्न होने वाले कपास के रेशों की उपस्थिति दिखाई है। **निष्कर्षों के बारे में:** • Tel Tsaf, मध्य ताम्रपाषाण स्थल, मध्य जॉर्डन घाटी में स्थित है। • Tel Tsaf में पाए जाने वाले कपास के रेशे मेहरगढ़ में पाए जाने वाले कपास के रेशों से छोटे होते हैं। • खोजे गए कपास के रेशों और बास्ट के अन्य रेशों को कई रंगों से रंगा गया है जो इस क्षेत्र में जटिल सामाजिक गतिविधियों को इंगित करता है। • उत्खनन से पता चला है कि चार वास्तुशिल्प परिसर हैं जिनमें से प्रत्येक में गोल या आयताकार कमरे और कई गोलाकार साइलो के साथ एक बंद प्रांगण है। • अंत्येष्टि साइलो के भीतर या उसके आस-पास पाए गए।
श्रीमुखलिंगम मंदिर	**खबरों में क्यों:** केंद्र सरकार ने यूनेस्को से श्रीमुखलिंगम मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का आग्रह किया है। **मंदिर के बारे में:** • श्रीमुखलिंगम मंदिर को कलिंगनगरम के नाम से भी जाना जाता है। • यह प्रारंभिक पूर्वी गंग राजवंश की राजधानी थी। • आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जालुमुरु मंडल में वामसाधारा नदी के पास स्थित है।

- 9वीं शताब्दी सीई में निर्मित, यह कलिंग स्थापत्य शैली में बनाया गया है।
- यह भगवान श्रीमुख लिंगेश्वर (शिव का एक रूप) को समर्पित है।
- यहाँ, शिव लिंगम में चेहरे की नक्काशी नहीं है और इसलिए मंदिर अन्य शिव मंदिरों से अलग है।
- इसे दक्षिणा काशी के नाम से भी जाना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जाने और नदी में डुबकी लगाने से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है।

भूगोल

तटीय लाल रेत के टीले/एरा मैटी डिब्बालू

संदर्भ : हाल ही में वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश सरकार से विजाग के ग्लेशियल-काल के तटीय लाल रेत के टीलों की रक्षा करने का आग्रह किया।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु इस साइट को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि एरा मैटी डिब्बालू ने हिमनद और गर्म अवधि दोनों को देखा है।

तटीय लाल रेत के टीलों/एरा मैटी डिब्बालू के बारे में:

एरा मैटी डिब्बालु का गठन:

- यह लगभग 12,000 साल पहले समुद्र-भूमि संपर्क के कारण बना।
- अद्वितीय लाल रंग प्रदान करने वाले ऑक्सीकरण के साथ रेत (40-50%), गाद और मिट्टी (अन्य 50%) का मिश्रण शामिल है।

एरा मैटी डिब्बालु का महत्व:

- ये भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उत्तर चतुर्धातुक काल के भूवैज्ञानिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं और समुद्र के स्तर के गिरने और इसके बाद के उठने, जलवायु, मानसून और तलछट पर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रभाव के निशान रखते हैं।
- ये मानवशास्त्रीय और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें संभवतः मेसोलिथिक और नवपाषाण सांस्कृतिक सामग्री भी शामिल है।

एरा मैटी डिब्बालु की मान्यता:

- इसे 2014 में एक राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल के रूप में और 2016 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।
- अन्य समान स्थान: देश में लाल रेत के टीलों के समान विस्तार वाला एकमात्र अन्य स्थान तमिलनाडु है, जिसमें टेरी टिब्बा परिसर है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में:

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है।
- यह 1851 में स्थापित किया गया था, यह भारत सरकार के खान मंत्रालय का संगठन है, जो दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है और भारतीय सर्वेक्षण (1767 में स्थापित) के बाद भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करने के लिए दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण है।

	• जीएसआई के मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन के निर्माण और अद्यतन से संबंधित हैं। • इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में स्थित हैं। प्रत्येक राज्य की एक राज्य इकाई होती है। • 1951 एम.एस. कृष्णन भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक बनने वाले पहले भारतीय बने।
शीत लहर (Cold Wave)	**संदर्भ:** हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भीषण शीत लहर की स्थिति का अनुमान लगाया था। 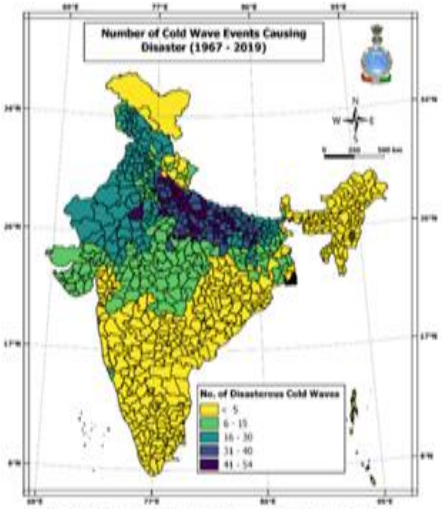 Fig.2: Number of Cold wave events causing disaster 1967-2019 (Source – IMD, New Delhi) **आईएमडी द्वारा शीत लहर के लिए मानदंड:** • शीत लहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और लगातार दो दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस (C) कम हो। • 'अत्यंत' ठंडा दिन तब माना जाता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से कम-से-कम 6.5 डिग्री कम होता है। **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:** • यह खांसी और सर्दी, ब्रोंकाइटिस और सांस की बीमारियों, रक्तचाप के मामलों, त्वचा की समस्याओं और यहां तक कि धूप की कमी के कारण हड्डी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द से भिन्न होता है। **भारत में शीत लहर के लिए जिम्मेदार कारक:** • उत्तर पश्चिम एशिया के ऊपर जेट स्ट्रीम में एक रिज (अपेक्षाकृत उच्च वायुमंडलीय दबाव का एक विस्तारित क्षेत्र) का निर्माण। • ऊपरी-स्तर की हवाओं द्वारा स्टीयरिंग के जवाब में ठंडी हवा का संचलन। • उत्तर और मध्य भारत के ऊपर सतही उच्च दाब का निर्माण। • दक्षिण पूर्व की ओर ठंडी हवा के परिवहन के लिए हवाओं को बढ़ाने के लिए उत्तर-पश्चिम भारत की ओर आने वाली एक मजबूत पछुआ लहर की तरह ट्रिगरिंग तंत्र। • उत्तर-पश्चिमी हिमालय पर व्यापक हिमपात।
फ़िजी	**संदर्भ:** हाल ही में पूर्व सैन्य कमांडर और दो बार के तख्तापलट नेता सित्विनी राबुका ने फिजी के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली।

फिजी के बारे में:

- यह ओशिआनिया का एक हिस्सा है।
- यह 1874 से लगभग सौ वर्षों तक एक ब्रिटिश उपनिवेश था।
- यह 1970 में स्वतंत्रता हुआ।
- **राजधानी:** सुवा
- **मुख्य नदियाँ:** रीवा, नवुआ, सिगाटोका (सिंगाटोका) और Ba (Mba)।
- **सबसे ऊँची चोटी:** तोमनिवि (विक्टोरिया पर्वत)- 4,344 फीट (1,324 मीटर)।
- यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल: लेवुका ऐतिहासिक पोर्ट टाउन।
- इसका सबसे बड़ा द्वीप विटी लेवु (Viti Levu) कहलाता है।
- यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के उत्तर में कोरो सागर को घेरे हुए है।
- ये द्वीप बड़े पैमाने पर ज्वालामुखीय क्रिया, तलछटी जमाव और प्रवाल के गठन के माध्यम से बनते हैं।

कैक्टस रोपण और इसका आर्थिक उपयोग

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने 'कैक्टस रोपण और इसके आर्थिक उपयोग' विषय पर एक परामर्श बैठक आयोजित की।

- बैठक में जैव-ईंधन, खाद्य और जैव-उर्वरकों के लिए कैक्टस के उपयोग के लाभों को साकार करने के लिए निम्नीकृत भूमि पर कैक्टस के पौधे लगाने के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई।
- भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% निम्नीकृत भूमि की श्रेणी में आता है।

कैक्टस के बारे में:

- कैक्टस पौधे कैक्टैसी परिवार के सदस्य होते है।
- हालांकि कुछ प्रजातियाँ काफ़ी नम वातावरण में रहती हैं, अधिकांश कैक्टि ऐसे आवासों में रहते हैं जहां कम से कम कुछ सूखा रहता है।
- कई अत्यंत शुष्क वातावरण में रहते हैं, यहाँ तक कि अटाकामा रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, जो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक है।
- इस वजह से कैक्टि पानी के संरक्षण के लिए कई अनुकूल होते है।

	• उदाहरण के लिए, लगभग सभी कैक्टि रसदार होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे गाढ़े, मांसल हिस्से पानी जमा करने के लिए अनुकूलित होते हैं। • कई अन्य रसीलों के विपरीत, तना अधिकांश कैक्टि का एकमात्र हिस्सा है जहां यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। • कैक्टि की अधिकांश प्रजातियों में केवल रीढ़ होती है, जो अत्यधिक संशोधित पत्तियां होती हैं। • कांटे कैक्टस के पास वायु प्रवाह को कम करके और कुछ छाया प्रदान करके पानी के नुकसान को रोकने में मदद करते हैं। • सही पत्तियों की अनुपस्थिति में कैक्टि के बढ़े हुए तने प्रकाश संश्लेषण करते हैं। **संरक्षण:** • सभी कैक्टि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट II में शामिल हैं। • कुछ कैक्टि, जैसे कि सभी एरियोकार्पस और डिस्कोकैक्टस प्रजातियाँ, अधिक प्रतिबंधात्मक परिशिष्ट I में शामिल हैं। **उपयोग:** • कैक्टस अपने पोषक तत्वों के साथ-साथ अपने औषधीय महत्व के लिए जाने जाते हैं। • कैक्टस के पैड और फल दोनों ही संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं और हैंगओवर से लेकर उच्च कोलेस्ट्रॉल तक किसी भी चीज के लक्षणों को कम कर सकते हैं। • कैक्टस के पैड और फल दोनों ही फाइबर से भरपूर होते हैं, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं। • इनका सजावटी पौधों के रूप में उपयोग किया जाता है। • इनके चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। • कैक्टस के फल विशेष रूप से विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं, जो कि सबसे अच्छे प्रतिरक्षा बूस्टर में से एक है। • **पोषण:** कैक्टस के फल और पैड विटामिन और पोषक तत्वों की खुराक प्रदान करते हैं जिनमें सूजन-रोधी गुण होते हैं और मधुमेह और हृदय रोग जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।
ओकावांगो डेल्टा और मर्चिसन फॉल्स	**चर्चा में क्यों :** तेल कंपनियां अफ्रीका के दो सबसे प्रतिष्ठित जैव विविधता हॉटस्पॉट को तेल के लिए ड्रिल करने के प्रयास में धमकी दे रही हैं जो अंततः एक वैश्विक अभिजात वर्ग के लिए अपनी राह बनाएगी और अफ्रीकियों को लाभ नहीं पहुंचाएगी, एक जर्मन गैर-लाभकारी संस्था की हालिया रिपोर्ट ने इसको प्रकाश डाला है। • दोनों स्थानों पर चल रही तेल अन्वेषण परियोजनाओं का प्रभाव वन्यजीवों के लिए मौत की घंटी बजा सकता है और वहां रहने वाले समुदायों को बेघर कर सकता है। • ReconAfrica, एक कनाडाई कंपनी, Kavango Zambezi Transfrontier Nature Conservation Area (KAZA) में तेल के लिए ड्रिलिंग कर रही है। **ओकावांगो डेल्टा:** • ओकावांगो डेल्टा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। • यह बोत्सवाना में है। • यह सैन जैसे स्वदेशी लोगों की मातृभूमि है। • यह ओकावांगो नदी द्वारा बनाई गई है - जो अंगोला के ऊंचे इलाकों से निकलती है। • यह नदी दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में बहती है और चौड़ी है, जिसे 'फैन' कहा जाता है। • यह बहुत कम प्रमुख आंतरिक डेल्टा प्रणालियों में से एक है जो समुद्र में नहीं बहती है। • इस डेल्टा में स्थायी दलदली भूमि और मौसमी बाढ़ वाले मैदान शामिल हैं।

ओकावांगो डेल्टा का महत्व:

- ओकावांगो का पानी अतिरिक्त शुष्क क्षेत्र को जलभराव वाली आर्द्रभूमि बनाता है जो जानवरों, पौधों और दस लाख से अधिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण जल संसाधन प्रदान करता है।
- यह अफ्रीका की पांच बड़ी वन्यजीव प्रजातियों का घर है: सवाना हाथी, केप भैंस, गैंडा, शेर और तेंदुआ।
- जिराफ़, जेब्रा, मृग, पैंगोलिन, पक्षियों की 400 प्रजातियाँ और 1,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ भी हैं।
- 200,000 से अधिक लोग इस क्षेत्र में रहते हैं जो रेकॉन अफ्रीका के अन्वेषण लाइसेंस के अंतर्गत आता है।

मर्चिसन जलप्रपात:

- यह युगांडा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह प्रतिष्ठित अफ्रीकी वन्यजीव प्रजातियों का घर है।
- यह झील अल्बर्ट के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो रिफ्ट वैली ग्रेट लेक्स में से एक है, जो युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच की सीमा पर स्थित है।
- नील नदी पार्क से होकर बहती है और इसके किनारों पर हाथी, हिप्पो, नील मगरमच्छ, भैंस और माराबौ स्टॉर्क हमेशा देखे जा सकते हैं।

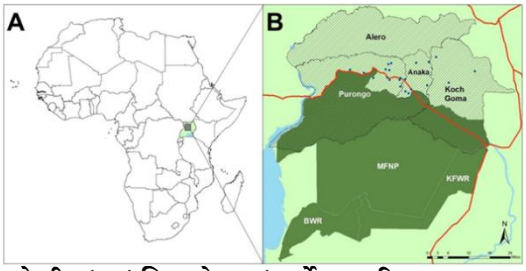

कवांगो ज़म्बेजी ट्रांसफ़्रंटियर नेचर कंज़र्वेशन एरिया (काज़ा):

- KAZA दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रकृति और परिदृश्य संरक्षण क्षेत्र है।
- यह अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं में फैला हुआ है।

बोत्सवाना के बारे में:

- राजधानी – गेबोरोने
- यह दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध देश है।
- इसका 70% क्षेत्र कालाहारी रेगिस्तान से आच्छादित है।
- बोत्सवाना में दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 130,000 है।
- यह अफ्रीका का सबसे पुराना निरंतर लोकतंत्र है।

कलासा-बंदूरी परियोजना

संदर्भ: भारत सरकार ने हाल ही में कर्नाटक की कलसा-बंदूरी पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे गोवा और महाराष्ट्र के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

- केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने कलसा बांध से 1.72 टीएमसी और भंडुरा बांध से 2.18 टीएमसी पानी के डायवर्जन को मंजूरी दे दी है।

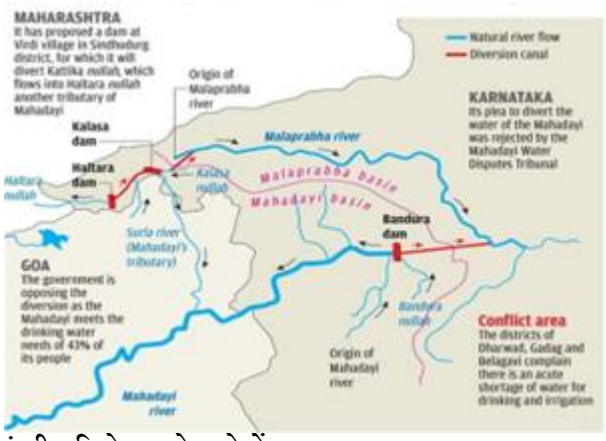

कलासा-बंदुरी परियोजना के बारे में:

- यह एक बांध है जिसे महादयी बेसिन से मलप्रभा नदी के घाटे वाले बेसिन में पानी मोड़ने के लिए बनाया किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य सूखाग्रस्त उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना है। इन क्षेत्रों में धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट और गदग शामिल हैं।

महादयी नदी के बारे में:

- कर्नाटक के बेलगावी जिले के खानापुर तालुक में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से महादयी नदी कर्नाटक (पश्चिमी घाट) में निकलती है।
- पश्चिम की ओर बहते हुए, यह उत्तरी गोवा जिलों में प्रवेश करती है।
- मंडोवी बनाने के लिए कई धाराएँ नदी के प्रवाह में शामिल हो जाती हैं जो गोवा से होकर बहने वाली दो प्रमुख नदियों में से एक है।
- यह पणजी में अरब सागर में मिलती है।
- **वितरण:** कुल क्षेत्रफल का 375 वर्ग किमी कर्नाटक में, 77 वर्ग किमी महाराष्ट्र में और शेष 1580 वर्ग किमी गोवा में है।

केंद्रीय जल आयोग (CWC) के बारे में:

- केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।
- आयोग को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास, जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाएं शुरू करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने की सामान्य जिम्मेदारी सौंपी गई है।

	• यह आवश्यकतानुसार ऐसी किसी भी योजना की जांच, निर्माण और निष्पादन भी करता है। • केन्द्रीय जल आयोग के प्रमुख एक अध्यक्ष हैं जिनका पद भारत सरकार के पदेन सचिव के स्तर का होता है। • आयोग के कार्य को 3 विंगों में विभाजित किया गया है, अर्थात् डिजाइन और अनुसंधान (डी एंड आर) विंग, नदी प्रबंधन (आरएम) विंग और जल योजना और परियोजनाएं (डब्ल्यूपी एंड पी) विंग।
बराक नदी	**चर्चा में क्यों:** बदरपुर से भंगा (10.5 किमी) तक बराक नदी के सुनिश्चित गहराई वाले ड्रेजिंग कार्य का ठेका ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। • असम में जलमार्गों के सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा धनराशि का वितरण किया गया है। **बराक नदी:** • बराक नदी दक्षिण असम की प्रमुख नदियों में से एक है। • यह मणिपुर से निकलती है। मणिपुर के बाद यह मिजोरम और असम से होकर बहती है। • 564 किलोमीटर लंबी यह नदी सूरमा-मेघना नदी प्रणाली का हिस्सा है। • यह बाद में बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां यह सूरमा और कुशियारा नदियों में बंट जाती है। • बराक की प्रमुख सहायक नदियाँ जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई, सोनाई और कटखल हैं। • बराक उप-बेसिन भारत, बांग्लादेश और बर्मा में नालियों का क्षेत्र है। • भारत में जल निकासी क्षेत्र 41723 वर्ग किमी है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.38% है। • उप-बेसिन मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों में स्थित है। 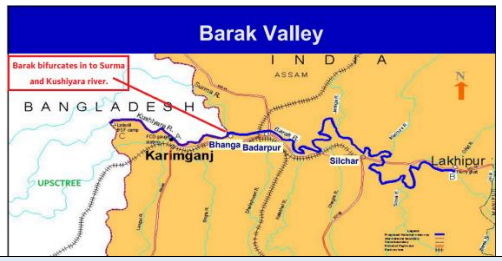

पर्यावरण

मंकीपॉक्स / एमपॉक्स	**संदर्भ:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में घोषणा की कि वह मंकीपॉक्स के लिए "mpox" शब्द का उपयोग करना शुरू करेगा, जिसने इस गर्मी की शुरुआत में अफ्रीका के बाहर वायरल बीमारी के पहले बड़े प्रकोप में लगभग 80,000 लोगों को संक्रमित किया है। विश्व स्तर पर 90 प्रतिशत से अधिक मामले एमएसएम (पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले) नेटवर्क में पाए गए हैं। **एमपॉक्स के बारे में:** • यह एक वायरल जूनोटिक रोग है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है। • मंकीपॉक्स वायरस पॉक्सविरिडे परिवार में ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस का सदस्य है। • मंकीपॉक्स की नैदानिक प्रस्तुति चेचक से संबंधित ऑर्थोपॉक्सवायरस संक्रमण से मिलती-जुलती है जिसे 1980 में विश्व भर में समाप्त घोषित कर दिया गया था।

लक्षण:

- बुखार
- लाल चकत्ते और सूजी हुई लिम्फ नोड्स
- सिरदर्द और मतली

संचरण:

- मंकीपॉक्स वायरस ज्यादातर जंगली जानवरों जैसे कि रोडेंट्स (rodents) यानी चूहों, बंदरों और प्राइमेट्स से लोगों में फैलता है।
- इसका मानव-से-मानव संचरण भी होता है।
- मंकीपॉक्स वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में घावों, शरीर के तरल पदार्थों, खांसने-छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के संपर्क में आने से फैलता है।

प्रकोप:

- मंकीपॉक्स का पहला मामला 1958 में बंदरों में और मनुष्यों में 1970 में पश्चिमी अफ्रीका में दर्ज किया गया था।
- 2017 में नाइजीरिया में इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया।
- इसके बाद अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन समेत कई देशों में इस बीमारी की जानकारी मिली है।

चेचक से अंतर:

- चेचक और मंकीपॉक्स के लक्षणों के बीच मुख्य अंतर यह है कि मंकीपॉक्स के कारण लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं (लिम्फैडेनोपैथी) जबकि चेचक में नहीं होता है।

स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया तथा प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) द्वारा प्रकाशित एशिया 2021 में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- वर्ष 2021 में भारत को बाढ़ से कुल 3.2 बिलियन डॉलर और तूफान से 4.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने इन घटनाओं को और अधिक बढ़ा दिया है।
- 2021 के दौरान, भारत ने ≥ 34 समुद्री मील की अधिकतम निरंतर हवा की गति के साथ पांच चक्रवाती तूफानों का अनुभव किया।
- प्री-मॉनसून सीज़न के दौरान अरब सागर के ऊपर बना अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते (मई) सबसे विनाशकारी था।
- भयंकर चक्रवाती तूफान यास (मई) ने पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा में दस्तक दी, जिससे क्रमशः 20,000 करोड़ रुपये और 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
- आंध्र प्रदेश और ओड़िशा के तटीय इलाकों से चक्रवाती तूफान गुलाब टकराया, जिससे 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
- गुलाब के अवशेषों से चक्रवात शाहीन का निर्माण हुआ और गुजरात में भारी वर्षा हुई।
- चक्रवाती तूफान जवाद, जिसके कारण पूर्वी तट पर भारी वर्षा हुई।

	• देश में आंधी-तूफान और बिजली गिरने से करीब 800 लोगों की मौत हो गई। • भारत एशिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। बाढ़ के बाद चीन को एशिया में सबसे अधिक आर्थिक नुकसान ($18.4 बिलियन) हुआ। • 2021 में एशिया में आई कुल प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ और तूफान की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत थी। • रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि महासागर के गर्म होने से समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, तूफान के रास्ते और समुद्री धाराएं बदल सकती हैं और स्तरीकरण बढ़ सकता है। • ऊपरी महासागर का गर्म होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संवहन, हवाओं, चक्रवात आदि के रूप में सीधे वातावरण को प्रभावित करता है। • गहरा महासागर सीधे वातावरण को प्रभावित नहीं करता है। • अरब सागर में वार्मिंग विशेष रूप से अद्वितीय है क्योंकि इसमें वायुमंडलीय सुरंगों और पुलों के माध्यम से अतिरिक्त गर्मी प्राप्त करने के रास्ते हैं। विभिन्न महासागरों से मिश्रित गर्म पानी इसमें पंप (डाला) किया जाता है। • ये क्षेत्र वैश्विक औसत ऊपरी-महासागर वार्मिंग दर की तुलना में तीन गुना अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं। • कुरोशियो करंट सिस्टम के मामलों में, मौजूदा सिस्टम ट्रॉपिक्स से गर्म पानी लेता है और तेज हवाएं अधिक गर्मी को करंट में धकेलती हैं। • ला नीना के कारण अत्यधिक वर्षा - इस समय के दौरान, भारत में स्थापित दबाव पैटर्न उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, जो यूरेशिया और चीन से परिसंचरण को संचालित करता है। • पूर्वोत्तर मानसून के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वोत्तर मानसून की वर्षा असाधारण रूप से सामान्य (दीर्घकालिक औसत का 171 प्रतिशत) से अधिक थी और 1901 के बाद से सबसे अधिक (579.1 मिलीमीटर) थी।
भारत के शीतलन क्षेत्र की रिपोर्ट में जलवायु निवेश के अवसर: विश्व बैंक	**संदर्भ:** विश्व बैंक द्वारा 2030 के बाद से जारी की गई "भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर" रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल 160 से 200 मिलियन से अधिक लोग घातक गर्मी की लहर के संपर्क में आ सकते हैं, और गर्मी के तनाव से संबंधित उत्पादकता में गिरावट के कारण भारत में लगभग 34 मिलियन लोगों को नौकरी के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:** • विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2037 तक कूलिंग की मांग मौजूदा स्तर से 8 गुना ज्यादा होने की संभावना है। • इस परिदृश्य में, भारत के लिए स्थानों को ठंडा रखने के लिए वैकल्पिक और नवीन ऊर्जा कुशल तकनीकों को तैयार करना अनिवार्य है। • रिपोर्ट के अनुसार, यह 2040 तक 1.6 ट्रिलियन डॉलर का निवेश अवसर खोल सकता है, इसके अलावा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम कर सकता है और 3.7 मिलियन नौकरियां उत्पन्न कर सकता है। • रिपोर्ट में कहा गया है कि कूलिंग शूटिंग की मांग के साथ, हर 15 सेकंड में एक नए एयर कंडीशनर की मांग होगी, जिससे अगले दो दशकों में वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 435% की वृद्धि होने की उम्मीद है। **भारत में हीट वेव्स घोषित होने के मानदंड:** • हीट वेव माना जाता है यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। • यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक है, तो सामान्य तापमान से 4°C से 5°C की वृद्धि को हीट वेव स्थिति माना जाता है। • इसके अलावा, 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को भीषण गर्मी की लहर की स्थिति माना जाता है।
स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और भूमि क्षरण के कई वैश्विक संकटों से निपटने के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों (NbS) के लिए वित्तपोषण को दोगुना करने की आवश्यकता है।

	रिपोर्ट के बारे में: • यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme- UNEP) द्वारा जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (BMZ) की द इकोनॉमिक ऑफ लैंड डीग्रेडेशन पहल, 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD) और यूरोपीय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:** • मुख्य फोकस एनबीएस के लिए वित्त प्रवाह को दोगुना करने और ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए इसे कम करने पर होना चाहिए। • रिपोर्ट के मुताबिक, एनबीएस में मौजूदा वैश्विक निवेश प्रति वर्ष करीब 154 अरब डॉलर (12,49.44 करोड़ रुपये) है, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 384 अरब डॉलर करने की जरूरत है। • रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है, "ऊर्जा क्षेत्र में हानिकारक सब्सिडी सबसे अधिक है, जिसका अनुमान $340 बिलियन/वर्ष से $530 बिलियन/वर्ष तक है और कृषि क्षेत्र में लगभग $500 बिलियन/वर्ष है,"। • रिपोर्ट ने इन निवेशों को धीरे-धीरे समाप्त करने की सिफारिश की। • रिपोर्ट की एक अन्य विशेषता प्रकृति-आधारित समाधानों में निजी निवेश की आवश्यकता थी, जो वर्तमान में केवल 17 प्रतिशत है। • रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि निजी क्षेत्र के अभिकर्त्ताओं को 'नेट ज़ीरो' को 'नेचर पॉजिटिव' के साथ जोड़ना होगा।
फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन (FGD)	**संदर्भ:** सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, दिसंबर 2015 से, पश्चिम बंगाल में एक भी बिजली स्टेशन ने SO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए फ़्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) तकनीक स्थापित नहीं की है। • उत्सर्जन मानकों को भारत में पहली बार दिसंबर 2015 में कोयला आधारित बिजली स्टेशनों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), और मरकरी (Hg) के उत्सर्जन को सीमित करने के साथ-साथ पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन मानकों को सख्त करने और पानी की खपत सीमा निर्धारित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। **फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) के बारे में:** • फ़्लू-गैस डीसल्फ़राइज़ेशन (FGD) जीवाश्म-ईंधन बिजली संयंत्रों के निकास से सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों का एक सेट है। • फ़्लू गैस एक फ़्लू के माध्यम से वायुमंडल में निकलने वाली गैस है, जो चिमनी, ओवन, भट्टी, बॉयलर या भाप जनरेटर से निकास गैसों को संप्रेषित करने के लिए एक पाइप या चैनल है। • FGD सिस्टम में वेट स्क्रबिंग या ड्राई स्क्रबिंग शामिल हो सकती है। • गीले FGD सिस्टम में, फ़्लू गैसों को एक शोषक के संपर्क में लाया जाता है, जो या तो तरल या ठोस सामग्री का घोल हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड शोषक के साथ घुल जाता है या प्रतिक्रिया करता है और उसमें फंस जाता है। • शुष्क FGD सिस्टम में, शोषक शुष्क चूर्णित चूना या चूना पत्थर होता है; इसमें एक बार अवशोषण हो जाने पर, ठोस कणों को बैगहाउस फिल्टर के माध्यम से हटा दिया जाता है।

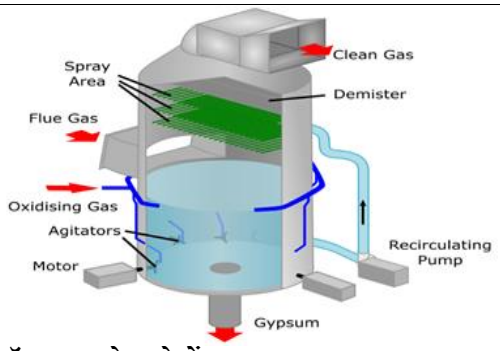

सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में:

- यह एक अकार्बनिक यौगिक, भारी, रंगहीन और जहरीली गैस है।
- इसमें तीखी, जलन पैदा करने वाली गंध होती है, जो माचिस की तीली के जलने वाली गंध के समान होती है।
- प्रकृति में, यह ज्वालामुखीय गैसों और कुछ पानी के गर्म झरनों के घोल में होता है।
- आमतौर पर, यह औद्योगिक रूप से हवा में जलाकर तैयार किया जाता है या
- सल्फर युक्त ईंधन के दहन से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है।
- यह वायुमंडल में जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है जो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख घटक है।

सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग

- इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फाइट बनाने में किया जाता है।
- इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है।
- यह मुख्य रूप से सूखे मेवों में रेफ्रिजरेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीच और खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाता है।

सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और वायु प्रदूषण:

- वायु प्रदूषण में SO2 उत्सर्जन का महत्वपूर्ण योगदान है। हवा में SO2 की उच्च सांद्रता आम तौर पर अन्य सल्फर ऑक्साइड (SOx) के गठन की ओर ले जाती है।
- छोटे कण बनाने के लिए SOx वातावरण में अन्य यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। ये कण पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) प्रदूषण में योगदान करते हैं।
- छोटे कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और काफी ज्यादा स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं।
- वातावरण में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं में जीवाश्म ईंधन का जलना है।
- अन्य स्रोतों में औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे कि अयस्क से धातु निकालना, प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी, और लोकोमोटिव, जहाज और अन्य वाहन तथा भारी उपकरण जो उच्च सल्फर सामग्री के साथ ईंधन जलाते हैं।

ज़ोंबी वायरस

चर्चा में क्यों : फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 साल पुराने जोंबी वायरस को जिंदा करने का दावा किया है, और अब इससे होने वाली महामारी की आशंका भी जताई है।

- जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में स्थायी जमी हुई भूमि (पर्माफ्रॉस्ट) का विगलन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक नया खतरा पैदा कर सकता है।

ज़ोंबी वायरस के बारे में:

- ज़ोंबी वायरस एक ऐसे वायरस को दिया गया शब्द है जो बर्फ में जम जाता है और इसलिए निष्क्रिय रहता है।
- जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, वायरस पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण उभरा है।
- यह विषाणुओं का समूह है जो हजारों वर्षों से सुप्त अवस्था में है।
- इसे पैंडोरावायरस येडोमा कहा जाता है जो 48,500 साल पुराना है और इसमें अन्य जीवों को संक्रमित करने की क्षमता है।

	• यह रूस के याकुटिया में युकेची अलास में एक झील के नीचे खोजा गया था। **ज़ोंबी वायरस का प्रमुख कारण:** • उत्तरी गोलार्द्ध का एक चौथाई भाग स्थायी रूप से जमी हुई भूमि से घिरा है जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहा जाता है। • जलवायु के गर्म होने के कारण, स्थायी रूप से पिघले हुए पर्माफ्रॉस्ट एक मिलियन वर्षों तक जमे हुए कार्बनिक पदार्थों को छोड़ रहे हैं और जिनमें से अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में विघटित हो जाते हैं जो ग्रीनहाउस प्रभाव को और बढ़ाते हैं। • इस कार्बनिक पदार्थ के हिस्से में पुनर्जीवित कोशिकीय रोगाणु (प्रोकैरियोट्स, एककोशिकीय यूकेरियोट्स) के साथ-साथ वायरस भी शामिल हैं जो प्रागैतिहासिक काल से निष्क्रिय रहे हैं।
भोपाल गैस त्रासदी	**संदर्भ:** संभावना ट्रस्ट के मुताबिक, 38 साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले कीटनाशक संयंत्र से 27 टन घातक मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस का रिसाव अभी भी शहर पर कहर बरपा रहा है। इससे जीवित बचे लोगों में फंगल संक्रमण की घटनाओं में नयी वृद्धि हुई है। **भोपाल गैस त्रासदी के बारे में:** • 3 दिसंबर, 1984 के शुरुआती घंटों में भोपाल (मध्य प्रदेश) में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा संचालित एक संयंत्र से मिथाइलिसोसाइनेट (एमआईसी) गैस का रिसाव हुआ। • इसमें अंतिम मरने वालों की संख्या 15,000 और 20,000 के बीच होने का अनुमान लगाया गया था। • जहरीली गैस के संपर्क में आने के कारण जीवित बचे करीब पांच लाख लोगों को सांस की समस्या, आंखों में जलन या अंधापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अन्य विकृतियों का सामना करना पड़ा। • अध्ययन में पाया गया कि गैस के संपर्क में आने वाली महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों में गैस के संपर्क में न आने वाली महिलाओं की तुलना में "जन्मजात विकृति" होने की संभावना अधिक होती है। **भोपाल गैस त्रासदी पर सरकार की प्रतिक्रिया:** • सरकार ने मार्च 1985 में भोपाल गैस रिसाव अधिनियम पारित किया, जिसने इसे पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। • जून 2010 में, यूनियन कार्बाइड के सात पूर्व कर्मचारी, जो सभी भारतीय नागरिक थे, को लापरवाही से मौत का कारण बनने का दोषी ठहराया गया और दो साल की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। **फंगल संक्रमण:** • टिनिया नामक फंगल के कारण होने वाला दाद रोग बढ़ रहा है। • लाल खुजली वाले धब्बे कमर में, सिर पर या शरीर के विभिन्न स्थानों पर होते हैं। यदि उपचार नहीं किया जाय तो तो दाने फैल जाते हैं। • संभावना क्लिनिक में बची महिलाओं द्वारा यीस्ट संक्रमण कैंडिडा एल्बीकैंस के बारे में भी बताया जाता है। **मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) के बारे में:** • मिथाइल आइसोसाइनेट एक रंगहीन अत्यधिक ज्वलनशील तरल है जो हवा के संपर्क में आने पर जल्दी से वाष्पित हो जाता है। इसमें तीखी, तेज गंध होती है। • इसका उपयोग कीटनाशकों, पॉलीयूरेथेन फोम और प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है। • गर्मी के लिए रासायनिक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। पानी के संपर्क में आने पर, MIC में यौगिक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे गर्मी की प्रतिक्रिया होती है। • तत्काल स्वास्थ्य प्रभावों में अल्सर, फोटोफोबिया, श्वसन संबंधी समस्याएं, एनोरेक्सिया, लगातार पेट दर्द, आनुवांशिक समस्या, न्यूरोसिस, बिगड़ी हुई आवाज और विजुअल मेमोरी, बिगड़ी हुई तर्क क्षमता और बहुत कुछ शामिल हैं। • लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य प्रभावों में क्रोनिक नेत्रश्लेष्मलाशोथ, फेफड़ों के कार्य में कमी, गर्भावस्था में

	कमी, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, क्रोमोसोमल असामान्यताओं में वृद्धि और बहुत कुछ शामिल हैं।
महुआ का पेड़/मधुका लोंगिफोलिया	**संदर्भ:** महुआ का पेड़ मुंडा जनजाति के लोगों का अभिन्न अंग है। मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र की केंद्रीय भारतीय जनजाति हैं। मुंडा लोगों का जुड़ाव महुआ के पेड़ से उनके जन्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है। उनके होने वाली माताओं को महुआ के फूलों से बनी एक साधारण चटनी खिलाई जाती है जिसे स्वस्थ के लिए अच्छा माना जाता है। • महुआ भी शादी की रस्मों का एक हिस्सा है और समारोह में महुआ से बनी शराब परोसी जाती है। जन्म से लेकर शादी तक, अंतिम संस्कार तक महुआ इनके सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। **महुआ के पेड़ के बारे में:** • मधुका लोंगिफोलिया भारत के मूल निवासी उष्णकटिबंधीय वृक्ष की एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से देश के मध्य, दक्षिणी और उत्तरी भागों के मैदानी इलाकों और जंगलों के साथ-साथ नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका में भी पाई जाती है। • यह एक तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है जो लगभग 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जिसमें चिरस्थायी या अर्ध-सदाबहार पत्ते होते हैं। • यह अर्ध-सदाबहार जंगल, नदी के किनारे, और मध्य भारत में चरागाहों और फसल के खेतों में छिटपुट रूप से बढ़ता है। • इसमें 80 सेमी के व्यास के साथ एक छोटा, मोटा तना होता है। • इसकी मुकुट जैसी कई शाखाएँ होती हैं और यह गोलाकार होता है। • मूल पत्ती ब्लेड की लंबाई 10-25 सेमी और चौड़ाई 6-12 सेमी होती है, यह अंडाकार आकार का कठोर, मोटा होता है, नीचे का भाग ऊनी होता है, और टूटने पर दूधिया रस निकलता है। **मधुका लोंगिफोलिया का उपयोग:** • पेड़ के कई अलग-अलग हिस्सों, विशेष रूप से छाल का उपयोग उनके चिकित्सीय लाभों के लिए किया जाता है। नेपाल में मधुमेह के मरीजों को पेड़ की छाल से बना काढ़ा दिया जाता है। • महुआ मध्य भारत के आदिवासियों के दैनिक जीवन में भोजन से लेकर चारा, दावा से लेकर दारू (शराब) तक सर्वव्यापी है। इनके शब्दों में, 'महुआ पेड़ नहीं, हमारी जीवन पद्धति है'। • कुष्ठ रोग का इलाज अक्सर पेड़ की छाल से बने औषधीय अर्क का उपयोग करके किया जाता है। • बीजों से निकाले गए तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार की त्वचा स्थितियों के उपचार में किया जाता है। • तेल निकालने के बाद जो बीज केक बच जाते हैं ये उत्कृष्ट उर्वरक बनाते हैं। • माना जाता है कि फूल शांतिदायक, शक्तिवर्धक और शांतिदायक प्रभाव प्रदान करते हैं। ये अन्य स्थितियों के साथ खांसी, जुकाम और ब्रोंकाइटिस के उपचार में कार्यरत हैं। • रसीले, मीठे फूलों को ताजे या सूखे, आटे के साथ पाउडर और बेक किया जा सकता है, शराब बनाने के लिए किण्वित किया जा सकता है या स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। • इसकी गैर-विषाक्तता को देखते हुए, पश्चिमी ओडिशा के लोग पोषण के प्राथमिक स्रोत के रूप में महुआ फल पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं।
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल	**सन्दर्भ:** 2022 में, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) में 196 देशों के प्रतिनिधि मॉन्ट्रियल, कनाडा में 7-21 दिसंबर तक मिले, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए एक नया

बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क	वैश्विक समझौता तैयार करना था। • मॉन्ट्रियल में बैठक COP15 का दूसरा भाग था, पहला भाग 2021 में चीन के कुनमिंग में आयोजित किया गया था। • 2021 में कुनमिंग घोषणापत्र पर 100 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए ताकि एक प्रभावी वैश्विक जैव विविधता ढांचे के विकास, अंगीकरण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। • इस घोषणा की थीम थी पारिस्थितिक सभ्यता: पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। • COP 15 ने "कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" (GBF) को अपनाया। **COP15 के प्रमुख परिणाम:** • **30x30 डील:** 2030 तक विश्व स्तर पर (जमीन और समुद्र पर) 30% बिगड़े हुए पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करना। • 2030 तक 30% क्षेत्रों (स्थलीय, अंतर्देशीय जल, और तटीय और समुद्री) का संरक्षण और प्रबंधन करना। • **प्रकृति के लिए धन:** हस्ताक्षरकर्ताओं का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक और निजी स्रोतों से प्रति वर्ष USD200 बिलियन संरक्षण पहलों के लिए प्रसारित किया जाए। • अमीर देशों को 2025 तक हर साल कम से कम 20 अरब डॉलर और 2030 तक हर साल कम से कम 30 अरब डॉलर का योगदान देना चाहिए। • **बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट जैव विविधता पर प्रभाव:** कंपनियों को विश्लेषण करना चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए कि उनके संचालन कैसे प्रभावित होते हैं और जैव विविधता के मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं। • पार्टियों ने बड़ी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को उनके संचालन, आपूर्ति श्रृंखला और पोर्टफोलियो के बारे में खुलासा करने के लिए "आवश्यकताओं" के अधीन होने पर सहमति व्यक्त की। • **हानिकारक सब्सिडी:** वर्ष 2025 तक जैवविविधता को कम करने वाली सब्सिडी की पहचान करने और फिर उन्हें समाप्त करने, चरणबद्ध करने या सुधार करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। • वे 2030 तक उन प्रोत्साहनों को प्रतिवर्ष कम-से-कम 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम करने और संरक्षण के लिये सकारात्मक प्रोत्साहन बढ़ाने पर सहमत हुए। • निगरानी और रिपोर्टिंग प्रगति:सभी सहमत लक्ष्यों की भविष्य में प्रगति की निगरानी करने के लिये प्रक्रियाओं को सशक्त किया जाएगा, इस समझौते को आइची (जापान) समझौते, 2010 की तरह नहीं लिया जाएगा, जो कभी पूरे नही हुए। • जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले प्रयासों के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये उपयोग किये जाने वाले समान प्रारूप के बाद राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को निर्धारण एवं उनकी समीक्षा की जाएगी।
नेवादा वाइल्डफ्लावर' (Nevada wildflower)	**संदर्भ:** अमेरिकी वन्यजीव अधिकारियों ने नेवादा वाइल्डफ्लावर को एकमात्र स्थान पर लुप्तप्राय घोषित किया है जहां यह एक उच्च-रेगिस्तानी रिज पर मौजूद है, जहां इलेक्ट्रिक कार बैटरी की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करने के लिए लिथियम खदान की योजना बनाई गई है। **नेवादा वाइल्डफ्लॉवर के बारे में:**

- सिएरा नेवादा घास के मैदान वसंत और गर्मियों में खूबसूरत जंगली फूलों के साथ खिलते हैं।
- इंग्लिश मीडो में, नारंगी-लाल भारतीय तूलिका (जीनस कैस्टिलजा) लंबे, पीले-फूल वाले तीर के पत्तों के रैगवॉर्ट (सेनेशियो ट्रायंगुलरिस) के बीच उगता है।
- सिएरा नेवादा के बड़े पारिस्थितिक तंत्र में मैदानी जंगली फूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इनके फूल कीड़ों के लिए एक प्राथमिक भोजन स्रोत हैं, और कीड़े चमगादड़ तथा पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं।

सिएरा नेवादा के बारे में:

- सिएरा नेवादा, जिसे सिएरा नेवादास भी कहा जाता है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के पूर्वी किनारे पर लगी है।
- इसका बड़ा भाग पश्चिम में बड़े सेंट्रल वैली डिप्रेशन और पूर्व में बेसिन तथा रेंज प्रांत के बीच स्थित है।
- मोजावे रेगिस्तान से उत्तर की ओर 250 मील (400 किलोमीटर) से अधिक उत्तरी कैलिफ़ोर्निया और ओरेगन के कैस्केड रेंज तक फैला हुआ, सिएरा नेवादा झील ताहो में लगभग 80 मील चौड़ा से लेकर दक्षिण में लगभग 50 मील चौड़ा है।
- सिएरा नेवादा रेंज इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि मानव व्यवसाय और किसी क्षेत्र का उपयोग इसके परिदृश्य को कैसे संशोधित कर सकता है।

ओरण (Orans)

संदर्भ: जैसलमेर, राजस्थान के लगभग 40 गाँवों के निवासी 225 किलोमीटर पैदल चलकर समुदाय-संरक्षित पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए गए हैं जिन्हें 'ओरण' कहा जाता है। वर्तमान में, जैव विविधता हॉटस्पॉट को बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ओरान के बारे में:

- 'ओरान' सामुदायिक वन हैं जो जैव विविधता के भंडार के रूप में कार्य करते हैं, प्रभावी जल प्रबंधन को सक्षम करते हैं और समुदाय आधारित पुनर्जनन प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला और राजस्थान के महान भारतीय रेगिस्तान में ग्रामीणों द्वारा गैर-इमारती वन उपज (NTFPs) का स्थायी निष्कर्षण भी सुनिश्चित करता है।
- पवित्र उपवन वनों के साथ मनुष्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव की जीवंत अभिव्यक्ति रहे हैं।
- ये ग्रामीण समुदायों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एकजुट करते हैं। नियत समय में, प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारणों से वनों और वन संसाधनों का क्षरण और ह्रास हुआ है।
- राजस्थान में लगभग 25000 ओरान हैं जो 600,000 हेक्टेयर से अधिक को कवर करते हैं और अपने संबंधित समुदायों को एक बहुत ही आवश्यक जीवन रेखा और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

	• दो दशक पहले तक, उपेक्षा और गलत प्राथमिकताओं के कारण ओरानों को व्यापक गिरावट का सामना करना पड़ा है, हॉस्टिल एक्टर्स जैसे मुनाफाखोरी निगमों का विरोध, विदेशी वनस्पतियों और जीवों की शुरूआत जो जैव विविधता से समझौता करती है और बदलती जलवायु से, जिसके कारण ओरान की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आई है। • उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थापित, KRAPAVIS, स्थानीय लोगों का एक संगठन है, जो 21 वर्षों से रेगिस्तान और अरावली क्षेत्रों में शारीरिक और वैचारिक रूप से ओरान को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहा है। • ये ओरान बड़ी संख्या में रोहिड़ा, बोर्डी, कुम्भट और देसी बबूल जैसे पेड़ों और फूलों के साथ जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र हैं। • सीवान और मुरथ जैसी घासों की विभिन्न किस्में भी हैं, जो इन घास के मैदानों को पक्षियों और जानवरों की 250 से अधिक प्रजातियों का घर बनाती हैं, जिनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैकक्वीन बस्टर्ड, चिंकारा, इंडियन डेजर्ट कैट, डेजर्ट फॉक्स आदि शामिल हैं। **क्रापाविस के बारे में:** • कृषि एवं परिस्थितिकी विकास संस्थान (KRAPAVIS) राजस्थान के अलवर के बख़्तपुरा गाव में स्थित एक संगठन है जिसका शाब्दिक अर्थ "पारिस्थितिकी और कृषि / पशुधन के विकास के लिए संगठन" है। • यह संस्थान राजस्थान में ग्रामीण देहाती समुदाय के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने की दृष्टि से पारिस्थितिक, कृषि और पशुधन प्रथाओं की बेहतरी हेतु एक स्पष्ट मिशन के साथ काम करता है।
नीलगिरी तहर परियोजना	**संदर्भ:** हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरि तहर के संरक्षण के लिए एक पहल शुरू की है। **नीलगिरि तहर के बारे में:** • इस प्रजाति को स्थानीय रूप से वरैयाडु के नाम से जाना जाता है। • तमिल संगम साहित्य में 2,000 साल पुराने नीलगिरी तहर के कई संदर्भ हैं। • उत्तर मध्य पाषाण काल (10,000-4,000 ईसा पूर्व) के चित्र लोककथाओं, संस्कृति और जीवन में तहर के महत्व को उजागर करते हैं। • इसे इसके पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व की मान्यता में तमिलनाडु के राज्य पशु के रूप में नामित किया गया था। • **IUCN स्थिति:** इसे एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित है। • यह समुद्र तल से 300 मीटर और 2,600 मीटर की ऊँचाई पर खड़ी चट्टानों के साथ घास के मैदान में रहता है। • जनसंख्या: अनुमान है कि जंगल में 3,122 नीलगिरि तहर हैं। • E.R.C. डेविडर के सम्मान में 7 अक्टूबर को 'नीलगिरी तहर दिवस' के रूप में मनाया जाता है। • वह 1975 में नीलगिरी तहर पर पहले अध्ययनों में से एक का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार थे।
एशियाई विशालकाय कछुए	**संदर्भ:** हाल ही में 10 विशालकाय एशियाई कछुओं को संरक्षण के लिए नागालैंड में इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया। **एशियाई विशालकाय कछुओं के बारे में (मनोरिया एमिस):**

- इसमें दो उप-प्रजातियां शामिल हैं: मनौरिया एमीस फेरी और मनौरिया एमीस एमिस।
- ये मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़े कछुए हैं।
- ये एकमात्र कछुआ हैं जो अपने अंडे जमीन के ऊपर एक घोंसले में देते हैं, जिसे मादा पत्ती के ढेर से बनाती है।

प्राकृतिक आवास:

- सदाबहार वन, बाँस के जंगल सहित शुष्क सदाबहार वन।
- ये बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर (विलुप्त) में पाए जाने वाले दक्षिण एशिया के मूल निवासी हैं।
- भारत में, नेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य, उत्तरी कछार पहाड़ियों और नोंगखिलेम वन्यजीव अभयारण्य में कम अशांत आवासों में जंगली आबादी है।

संरक्षण की स्थिति:

- **आईयूसीएन रेड लिस्ट:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- **साइट्स:** परिशिष्ट II
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972:** अनुसूची IV

संरक्षण के प्रयास:

- नागालैंड और गैर-लाभकारी कछुआ जीवन रक्षा गठबंधन और वन्यजीव संरक्षण सोसायटी ने प्रजातियों को पुनर्जीवित करने के लिए किशोर कछुओं की सॉफ्ट रिलीज का आयोजन किया।
- सॉफ्ट रिलीज: यह कैद में पली-बढ़ी प्रजातियों को धीरे-धीरे जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया है।
- यह प्रजातियों को छोड़े गए व्यक्तियों के बीच साइट की निष्ठा विकसित करने में मदद करता है और अंततः रिलीज क्लोजर के आसपास रहने की आदत विकसित करता है।

सैंड बैटरी

संदर्भ: हाल ही में फिनलैंड की एक कंपनी यूरोप के ऊर्जा संकट के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने के लिए सैंड बैटरी लेकर आई है। वर्तमान में यह फ़िनलैंड के कंकनपा (Kankaanpää) शहर में परिचालित है।

सैंड बैटरी के बारे में:

- "सैंड बैटरी" एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है जो अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग करता है।
- लंबी अवधि तक ऊष्मा बनाए रखने के लिये रेत एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है, एक बार में यह महीनों तक की बिजली का भंडारण करता है।

	• इसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त पवन और सौर ऊर्जा के लिये उच्च शक्ति और उच्च क्षमता वाले संग्रह स्थान के रूप में काम करना है। • सैंड बैटरी नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित अतिरिक्त/अधिशेष ऊर्जा को संग्रहीत करने और बाद में उपयोग करने की अनुमति देकर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने में मदद कर सकती है। • स्टील साइलो: इसमें 100 टन रेत होती है जहां गर्मी संग्रहीत होती है। **काम करने की स्थिति:** • यह सौर और पवन जैसे सस्ते नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ग्रिड से बिजली प्राप्त करता है। • बिजली ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है और रेत में स्थानांतरित हो जाती है। • साइलो के अंदर करीकुलर (curricular) पाइप प्रणाली के माध्यम से एक पंखे के द्वारा हवा दी जाती है। • यह इलेक्ट्रिक एयर हीटर में प्रवेश करेगा, जहां यह अंदर स्थित प्रतिरोधक की मदद से गर्म हो जाता है। • गर्म वायु धातु संरचना (पाइप) के माध्यम से वायु से पानी हीट एक्सचेंजर द्वारा परिचालित की जाएगी। • वायु और पानी के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। 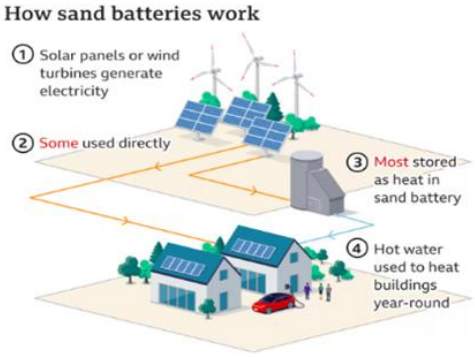
अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन (Emperor penguin)	**संदर्भ:** अंटार्कटिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए अधिक से अधिक संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है, और भूमि आधारित अंटार्कटिक प्रजातियों की 97 प्रतिशत तक की आबादी एम्परर पेंगुइन सहित 2100 तक विलुप्त हो सकती है, यदि हम इसे नहीं बदलते हैं, तो एक नया शोध पाया गया है। **एम्परर पेंगुइन के बारे में:** • एम्परर पेंगुइन सभी प्रजातियों में से सबसे बड़ी है और अंटार्कटिका की स्थानिक (देशज) प्रजाति है। • सभी पेंगुइन की तरह, यह उड़ान रहित है। • इनके आहार में मुख्य रूप से मछली होती है, लेकिन इसमें क्रस्टेशियन भी शामिल होते हैं। • शिकार करते समय, प्रजातियाँ लगभग 20 मिनट तक जलमग्न रह सकती हैं। • यह एकमात्र पेंगुइन प्रजाति है जो अंटार्कटिक सर्दियों के दौरान प्रजनन करती है। • आमतौर पर जंगल में इनका जीवनकाल 20 साल का होता है, हालांकि टिप्पणियों से पता चलता है कि कुछ 50 साल की उम्र तक जीवित रह सकते हैं। • आईयूसीएन स्थिति: निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)

डाइबैक रोग (Dieback Disease)

चर्चा में क्यों : नीम के पेड़ों के लिए खतरा पैदा करने वाले रोग की पहचान तेलंगाना में टहनी अंगमारी और डाईबैक रोग के रूप में की गई है।

नीम:

- नीम महोगनी परिवार मेलियासी का सदस्य है।
- नीम के पेड़ आकर्षक चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार होते हैं जो 30 मीटर तक लंबे और 2.5 मीटर की परिधि तक बढ़ सकते हैं।
- यह केरल के दक्षिणी सिरे से हिमालय की पहाड़ियों तक, उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अर्धशुष्क से आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और समुद्र तल से लगभग 700 मीटर की ऊँचाई तक उगाया जाता है।
- नीम में जीवाणुरोधी, एंटिफंगल और अन्य बहुमुखी गुण होते है।

डाइबैक रोग:

- डाइबैक रोग सभी उम्र के नीम के पेड़ों की पत्तियों, टहनियों और पुष्पक्रम को प्रभावित करता है।
- यह गंभीर रूप से संक्रमित पेड़ों में फलों के उत्पादन में लगभग 100% की कमी का कारण बनता है।
- डाइबैक रोग मुख्य रूप से फंगस फ़ोमोप्सिस एज़ेडेराचेस के कारण होता है।
- लक्षणों की उपस्थिति बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ शुरू होती है और बारिश के मौसम के बाद के हिस्से और शुरुआती सर्दियों में उत्तरोत्तर गंभीर हो जाती है।

नियंत्रण के उपाय:

- रोग से प्रभावित टहनियों को काट देना चाहिए और उन्हें हटाने के बाद कवकनाशी और कीटनाशक के मिश्रण का छिड़काव किया जा सकता है।
- वैकल्पिक रूप से, एक प्रभावित पेड़ के चारों ओर एक गड्ढा खोदा जाना चाहिए, और उसमें कवकनाशी और कीटनाशक मिलाकर पानी डालना चाहिए।

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

खानाबदोश मलमपदंद्रम जनजाति	**संदर्भ:** मलमपदंद्रम जनजाति नामक एक स्वदेशी समुदाय अधिकारियों को सबरीमाला जंगलों में वन सड़कों को साफ रखने में मदद कर रहा है। **मलमपदंद्रम जनजाति के बारे में:** • यह सुदूर जंगल में रहने वाले एक छोटे, खानाबदोश समुदाय का नाम है। • मछली पकड़ना और जंगल से फल और अन्य खाद्य पदार्थ इकट्ठा करना इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय है जो अपनी सभी जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर करता है। • मलाई पंडारम या जिसे पहाड़ी पंडारम कहा जाता है, एक अनुसूचित जनजाति है। • ये मुख्य रूप से कोल्लम और पठानमथिट्टा जिलों के उच्च श्रेणी क्षेत्रों में वितरित होते हैं। • वर्ष 2011 की जनगणना में इनकी जनसंख्या 2,422 दर्ज की गई थी। • ये रुद्राक्षमाला, तुलसीमाला, कांच के मोतियों का हार और चूड़ियाँ बनाने तथा बेचने के अपने पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। • इनमें से कुछ को हर्बल दवाओं का पारंपरिक ज्ञान है।
तलाक अधिनियम 1869	**चर्चा में क्यों:** केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक याचिका दायर करने के लिए एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि की शर्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और असंवैधानिक है। • सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक दंपति ने उच्च न्यायालय का रुख किया। • दंपति ने यह घोषित करने के लिए एक अन्य याचिका भी दायर की कि अधिनियम की धारा 10ए (1) के तहत निर्धारित एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि असंवैधानिक है। **तलाक अधिनियम 1869:** • यह ईसाई समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों को नियंत्रित करने वाला एकमात्र संहिताबद्ध कानून है। • इसमें विवाहों के विघटन, अशक्तता डिक्री, अभिरक्षा मुद्दों, वैवाहिक अधिकारों की बहाली आदि के प्रावधान शामिल हैं। • धारा 10 में वे आधार हैं जिन पर न्यायालय विवाह को भंग कर सकता है। • धारा 10-A, पक्षकार आपस में मिलकर जिला न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। • वे दो साल से अलग रह रहे हो और साथ रहने में असमर्थ हो।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

डार्क पैटर्न	**संदर्भ:** कुछ इंटरनेट-आधारित व्यावसायिक कंपनियां उपयोगकर्ताओं को कुछ शर्तों से सहमत होने या कुछ लिंक पर क्लिक करने के लिए बरगला (Tricking) रही हैं। इस तरह की स्वीकृति एवं क्लिक उपयोगकर्ताओं के इनबॉक्स में प्रचार ईमेल से भर रहे हैं जो वे कभी नहीं चाहते थे, जिससे सदस्यता समाप्त करना या हटाने का अनुरोध करना कठिन हो गया। ये "डार्क पैटर्न" के उदाहरण हैं, जिन्हें "भ्रामक पैटर्न" भी कहा जाता है। **डार्क पैटर्न के बारे में:** • ऐसे पैटर्न अनैतिक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस डिज़ाइन हैं जो सुविचारित रूप से उपयोगकर्ताओं के इंटरनेट अनुभव को कठिन बनाते हैं या उनका शोषण भी करते हैं। • बदले में, वे डिज़ाइनों को नियोजित करने वाली कंपनी या प्लेटफ़ॉर्म को लाभान्वित करते हैं। • डार्क पैटर्न का उपयोग करके, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जा रही सेवाओं एवं उनके ब्राउज़िंग अनुभव पर उनके नियंत्रण के बारे में पूरी जानकारी का अधिकार छीन लेते हैं। • इस शब्द का श्रेय UI/UX (उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस/उपयोगकर्ता अनुभव) के शोधकर्ता एवं डिज़ाइनर हैरी ब्रिग्नुल को दिया जाता है, जो लगभग 2010 से इस तरह के पैटर्न एवं उनका उपयोग करने वाली कंपनियों को सूचीबद्ध करने हेतु कार्य कर रहे हैं। **डार्क पैटर्न का उपयोग:** • सोशल मीडिया कंपनियां एवं बिग टेक फर्म जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, स्काइप, फेसबुक, लिंकडइन, माइक्रोसॉफ्ट एवं गूगल उपयोगकर्ता अनुभव को अपने लाभ के लिए डाउनग्रेड करने के लिए डार्क या भ्रामक पैटर्न का उपयोग करते हैं। • सोशल मीडिया में, लिंक्डइन उपयोगकर्ता प्रायः प्रभावशाली लोगों से अवांछित, प्रायोजित संदेश प्राप्त करते हैं।
विश्व एड्स दिवस	**खबरों में क्यों :** 1988 से हर साल 1 दिसंबर को 'वर्ल्ड एड्स डे' मनाया जाता है। • यह एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो एचआईवी संक्रमण के प्रसार के कारण होने वाली एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से मरने वालों का शोक मनाने के लिए समर्पित है। • इस साल यानि साल 2022 की थीम है 'EQUALIZE' है। **एड्स प्रगति के बारे में:** • 2021 तक, 38.4 मिलियन लोग HIV के साथ रह रहे थे, जिनमें से 1.7 मिलियन बच्चे थे। HIV के साथ रहने वाले सभी लोगों में से 54% महिलाएँ और लड़कियां थीं। • 2021 में, एचआईवी/एड्स पर संयुक्त संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) के अनुसार; • 2021 में AIDS से संबंधित बीमारियों से 6,50,000 लोगों की मौत हुई। • 5 मिलियन लोग नए संक्रमित हुए- हर दिन 4,000 नए संक्रमण • पिछले वर्षों में 2 मिलियन से अधिक लोगों की शुद्ध वृद्धि की तुलना में 2021 में एचआईवी उपचार पर लोगों की संख्या में केवल 1.47 मिलियन की वृद्धि हुई। • वैश्विक स्तर पर एचआईवी के साथ जी रहे सभी लोगों में से 85 प्रतिशत लोगों को 2021 में अपनी एचआईवी स्थिति पता थी। जो लोग अपनी स्थिति जानते थे, उनमें से 75 प्रतिशत उपचार तक पहुंच बना रहे थे। उपचार प्राप्त करने वाले लोगों में 68 प्रतिशत विषाणुजनित रूप से दब गए थे। **भारतीय संदर्भ:** यूएनएड्स के अनुसार, 2021 में अनुमानित 2.4 मिलियन लोग भारत में एचआईवी के साथ जी रहे थे (70,000 बच्चों सहित)।

	• इनमें से 19 लाख या 77 प्रतिशत को अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में पता था; 1.6 मिलियन (या 65 प्रतिशत) जीवन रक्षक एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी पर थे; और 1.3 मिलियन (55 प्रतिशत) ने वायरल लोड को दबा दिया था। • अधिक चिंताजनक रूप से भारत में 2021 में 63,000 लोग एचआईवी से नए संक्रमित थे, यानी हर दिन 173 नए संक्रमण या हर घंटे सात संक्रमित लोग मिल रहे थे। • UNAIDS के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में 42,000 एड्स से संबंधित मौतें हुईं यानी हर घंटे 5 मौतें।
ज्वारीय व्यवधान घटनाएं (TDE)	**संदर्भ:** इस साल की शुरुआत में ब्रह्मांड के आधे रास्ते से आने वाली एक रहस्यमयी और तीव्र चमकीली लाइट लाइट ने दुनिया भर के खगोलविदों को स्तब्ध कर दिया। तीव्र किरण के स्रोत को अब एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहचान की गई है, जो एक तारे को चीरता हुए सीधे पृथ्वी की ओर संकेत किया। **टाइडल डिसरप्शन इवेंट (TDE) के बारे में:** 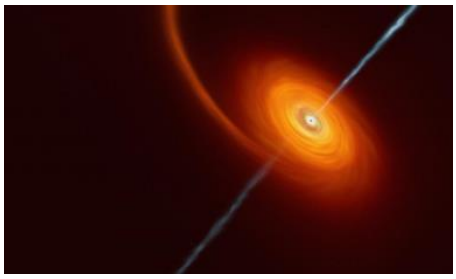 • खगोलविद निकट के तारों और गैस पर उनके प्रभावों को देखकर ब्लैकहोल का अध्ययन करते हैं। ये तारे तब बाधित होते हैं जब ब्लैक होल का ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण तारे के स्व-गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो जाता है, और इस घटना को ज्वारीय व्यवधान घटनाएँ (TDE) कहा जाता है। • ज्वारीय विघटन की घटनाएं शांत आकाशगंगाओं में सुपरमैसिव ब्लैक होल के द्रव्यमान का पता लगाने और भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी घटनाएं हैं। **ब्लैकहोल के बारे में:** 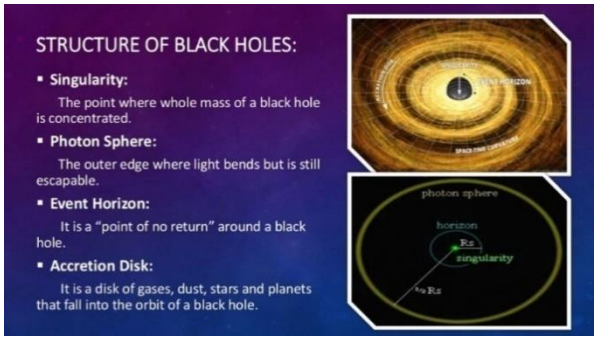 • गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावी होता है क्योंकि पदार्थ को एक छोटे से स्थान में निचोड़ा गया है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई तारा मर रहा हो। • दृश्यता: • क्योंकि वहाँ से कोई प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, वे अदृश्य होते हैं। • विशेष उपकरणों के साथ स्पेस टेलीस्कोप ब्लैक होल खोजने में मदद कर सकते हैं। • घूमते हुए गैस वास्तव में उनकी छवियों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। • उदाहरण: आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल को "Sagittarius A" कहा जाता है। • इसका द्रव्यमान लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर होता है और यह अपने अंदर कई मिलियन पृथ्वी को समा सकता है।

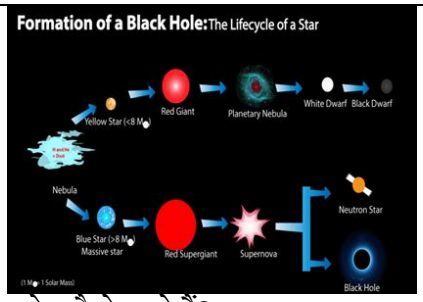

ब्लैक होल कैसे बनते हैं?

- वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे छोटे ब्लैक होल का निर्माण तब हुआ जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी।
- तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक बहुत बड़े तारे का केंद्र अपने आप में आ जाता है या ढह जाता है।
- जब ऐसा होता है, तो यह सुपरनोवा का कारण बनता है। एक सुपरनोवा एक विस्फोट करने वाला तारा है जो तारे के एक हिस्से को अंतरिक्ष में विस्फोट कर देता है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल उसी समय बने थे जब वे आकाशगंगा में थे।

भारत की पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना

संदर्भ: भारत पुणे में अपना पहला वेस्ट-टू-हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहा है, जो कचरे को ईंधन में बदलेगा।

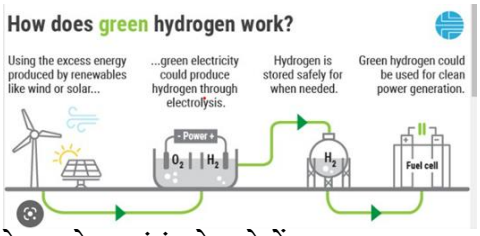

अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र के बारे में:

- पुणे नगर निगम (पीएमसी) और द ग्रीन बिलियन (टीजीबीएल) कचरे का उपयोग करेंगे और इसे प्रयोग करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में बदलेंगे ।
- कचरे में बायोडिग्रेडेबल, नॉन-बायोडिग्रेडेबल और घरेलू खतरनाक कचरा शामिल होगा।
- ऑप्टिकल सेंसर तकनीक का उपयोग करके कचरे को एक ही स्थान पर अलग किया जाएगा।
- प्लाज्मा गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कचरे से प्राप्त अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन (RDF) का उपयोग किया जाएगा।
- RDF एक ईंधन है जो विभिन्न प्रकार के कचरे जैसे नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW), औद्योगिक अपशिष्ट या वाणिज्यिक कचरे से उत्पन्न होता है।
- अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र तभी व्यवहार्य होते हैं जब संयंत्र कम से कम 300 टीपीडी (प्रति दिन टन) संसाधित कर सकता है।

विक्रम एस रॉकेट

खबरों में क्यों : 18 नवंबर, 2022 को हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लॉन्चपैड से रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला निजी भारतीय संगठन बनाकर इतिहास रचा।

विक्रम एस रॉकेट के बारे में :

- यह मिशन प्रारंभ (Mission Prarambh) का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ है शुरुआत।
- यह एक सिंगल स्टेज सब-आर्बिटल लॉन्च वेहिकिल है, सब आर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और फिर धरती पर गिर जाता है।
- इसकी पेलोड क्षमता 300 किलोग्राम तक की है।
- विक्रम-एस ठोस ईंधन-अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से हरित ईंधन नहीं है।
- विक्रम-2 के साथ, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का उपयोग करने की योजना है, जो पारंपरिक मिट्टी के तेल की तुलना में हरित है।

स्काईरूट एयरोस्पेस के बारे में:

	• यह एक भारतीय निजी एयरोस्पेस निर्माता और वाणिज्यिक लॉन्च सेवा प्रदाता है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। • इसका अगला प्रक्षेपण विक्रम-1 होगा, एक कक्षीय वाहन जो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करता है। विक्रम-2 की क्षमता विक्रम-1 से अधिक होगी। • स्काईरूट एयरोस्पेस रॉकेट के पुन: प्रयोज्य पर केंद्रित है।
एथिलीन ग्लाइकोल	**संदर्भ:** उज़्बेकिस्तान द्वारा एक भारतीय दवा निर्माता द्वारा निर्मित औषधीय सिरप के सेवन से समरकंद में 18 बच्चों की मौत का आरोप लगाने के एक दिन बाद, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने 29 दिसंबर को एथिलीन ग्लाइकॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 शीर्षक से एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। 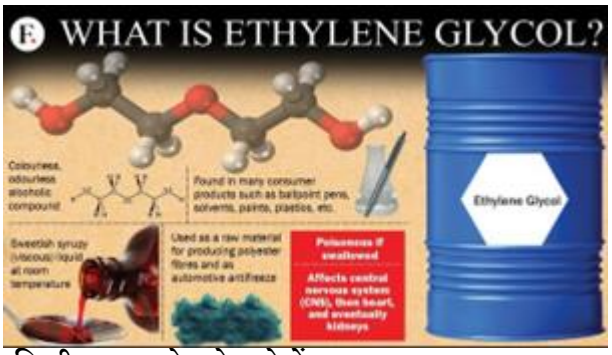 **एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में:** • एथिलीन ग्लाइकॉल एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक यौगिक है जिसका सेवन करने पर घातक हो सकता है। • यह ज्यादातर ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज़ के रूप में और पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। • डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल मिश्रण हैं जो कभी-कभी अवैध रूप से तरल दवाओं में सॉल्वैंट्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। • डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग फार्मा कंपनियों द्वारा गैर विषैले सॉल्वैंट्स जैसे ग्लिसरीन या प्रोपलीन ग्लाइकॉल के विकल्प के रूप में लागत में कटौती के लिए किया जा सकता है। • यह कई उत्पादों में भी पाया जाता है जैसे: I. हाइड्रोलिक ब्रेक तरल II. स्टाम्प पैड स्याही III. बॉलपॉइंट पेन IV. सॉल्वैंट्स, पेंट V. सौंदर्य प्रसाधन VI. प्लास्टिक **मैरियन बायोटेक के बारे में:** • मैरियन बायोटेक नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित एक दवा कंपनी है। • यह एक लाइसेंस प्राप्त निर्माता है और यूपी ड्रग कंट्रोल द्वारा दी गई निर्यात उद्देश्यों के लिए Dok-1 मैक्स सिरप और टैबलेट के निर्माण के लिए लाइसेंस रखता है। • मैरियन बायोटेक भारत में Dok-1 मैक्स की बिक्री नहीं करती है और इसका एकमात्र निर्यात उज्बेकिस्तान को किया गया है।
ओपन स्टैंडर्ड डिजिटल ट्रंकिंग रेडियो सिस्टम	**खबरों में क्यों :** दिल्ली पुलिस 'ओपन स्टैंडर्ड डिजिटल ट्रंकिंग रेडियो सिस्टम' (OS-DTRS) को डिजाइन, स्थापित और आपूर्ति करने के लिए तैयार है और वर्तमान टेट्रानेट वायरलेस नेटवर्क सेवाओं को समाप्त कर देगी। **नई प्रणाली के बारे में:**

	• यह दिल्ली पुलिस की एक आंतरिक संचार प्रणाली है। • यह अधिक कुशल है और इसका उद्देश्य सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान करना है। • यह ट्रंकिंग सिस्टम पुलिसकर्मियों के लिए कई चैनल और कॉमन समूह प्रदान करता है। इस तरह वे कम समूहों का उपयोग करके अधिक कर्मियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। • इसमें एक वॉयस लॉगर सिस्टम भी होगा, जिसका इस्तेमाल अपराध के दृश्य, पूछताछ के विवरण और साक्ष्य का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। • परियोजना की मास्टर साइट दिल्ली पुलिस मुख्यालय में होगी। • पुलिस 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड और माइक्रोवेव लिंक पर सिस्टम चलाने के लिए निजी कंपनियों की तलाश कर रही है।
SHE STEM 2022	**खबरों में क्यों :** स्वीडन भारत नोबेल मेमोरियल वीक के हिस्से के रूप में, SHE STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और स्थिरता के क्षेत्र में महिलाओं का जश्न मनाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम, 5 दिसंबर, 2022 को लगातार तीसरे वर्ष नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। **इवेंट्स के बारे में:** • वार्षिक कार्यक्रम भारत में स्वीडन के दूतावास द्वारा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार और जर्मन सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च (DWIH नई दिल्ली) की साझेदारी में आयोजित किया जाता है। **महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं:** • **मिशन शक्ति:** यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं और लड़कियों की संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच हो। • **नई रोशनी:** अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना पूरे भारत में लागू की जा रही है। • **जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI):** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यह एक पायलट परियोजना है। • **नॉलेज इन्वोल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग (KIRAN)-** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत फिर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने और पारिवारिक कारणों से महिला वैज्ञानिकों को शोध छोड़ने से रोकने के लिए यह योजना उल्लेखनीय है। • किरण के तहत 'महिला वैज्ञानिक योजना' बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को कैरियर के अवसर प्रदान करती है, विशेष रूप से जिनके करियर में ब्रेक था। • STEMM (WISTEMM) कार्यक्रम में महिलाओं के लिए भारत-अमेरिका फैलोशिप- इस द्विपक्षीय समझौते के तहत, भारतीय महिला वैज्ञानिक अब अमेरिका में अनुसंधान प्रयोगशालाओं में काम कर सकती हैं। • **महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (CURIE) कार्यक्रम-** इसका उद्देश्य महिला विश्वविद्यालयों में S&T में उत्कृष्टता पैदा करने के लिए R&D बुनियादी ढांचे में सुधार करना और अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना करना है। • **विज्ञान ज्योति कार्यक्रम-** इसमें कक्षा 9-12 की मेधावी छात्राओं को एसटीईएम क्षेत्र में उच्च शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
न्यूरालिंक	**खबरों में क्यों :** न्यूरालिंक, एलोन मस्क कंपनी अपने पशु परीक्षण कार्यक्रम पर एक संघीय जांच का टारगेट है। कंपनी एक ऐसी ब्रेन चिप विकसित करने की कोशिश कर रही है जो लकवाग्रस्त लोगों को चलने और नेत्रहीनों को देखने में सक्षम बनाएगी। **न्यूरालिंक के बारे में:** • वर्ष 2016 में एलोन मस्क और इंजीनियरों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया। • न्यूरालिंक एक ब्रेन चिप इंटरफ़ेस का निर्माण कर रहा है जिसे खोपड़ी (skull) के भीतर प्रत्यारोपित किया जा सकता है, जो यह कहता है कि अंततः अक्षम रोगियों को स्थानांतरित करने और फिर से संचार करने तथा दृष्टि बहाल करने में मदद कर सकता है। • न्यूरालिंक के डिवाइस में एक चिप होती है जो न्यूरल सिग्नल को प्रोसेस और ट्रांसमिट करती है जिसे कंप्यूटर या फोन जैसे डिवाइस में ट्रांसमिट किया जा सकता है।

	• इसे मानव परीक्षण के लिए अमेरिकी विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना अभी बाकी है।
ChatGPT	**चर्चा में क्यों:** हाल ही में OpenAI ने ChatGPT नामक एक नया चैटबॉट पेश किया है। **ChatGPT के बारे में:** • ChatGPT एक 'संवादात्मक' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है। • यह कंपनी के GPT 3.5 सीरीज़ के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल (LLM) पर आधारित है। • GPT का मतलब जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर-3 है। • यह एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर मानव-समान पाठ करने के लिये गहन शिक्षण तकनीकों पर निर्भर करता है। • मॉडल को यह भविष्यवाणी करने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है कि भविष्य में क्या होगा, और इसलिये तकनीकी रूप से ChatGPT के साथ 'बातचीत' की जा सकती है। • चैटबॉट को रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक (RLHF) का उपयोग करके भी प्रशिक्षित किया गया था। • OpenAI इन मॉडलों को चलाने के लिए Microsoft Azure के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है। • उपयोगकर्ताओं के पास प्रतिक्रिया को डाउनवोट या अपवोट करने का विकल्प होता है। **अनुप्रयोग :** • यह एक मानव की तरह ही प्रश्नों का उत्तर देगा। • जैसे कि जन्मदिन की पार्टी कैसे आयोजित करें, इस पर एक निबंध लिखें कि संसदीय लोकतंत्र बेहतर क्यों है, और यहां तक कि दो प्रसिद्ध हस्तियों के बीच एक काल्पनिक मुलाकात भी। • यह अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है, गलत परिसरों को चुनौती दे सकता है, और अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है। • इसे बेसिक ईमेल, पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवी और यहाँ तक कि कॉलेज निबंध और होमवर्क के प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है। • इसका उपयोग कोड लिखने, गणित के समीकरणों को हल करने और यहां तक कि कोड में त्रुटियों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है।
GAGAN (जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन)	**संदर्भ:** हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने GAGAN (जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन) पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बैठक की। **GAGAN के बारे में:** • GAGAN, GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन का संक्षिप्त रूप है। • यह एक अंतरिक्ष आधारित विस्तार प्रणाली (एसबीएएस) है जिसे इसरो और एएआई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है ताकि पड़ोसी देशों में विस्तार की क्षमता के साथ भारतीय हवाई क्षेत्र पर सर्वोत्तम संभव नौवहन सेवाएं प्रदान की जा सके।

	• गगन उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों की एक प्रणाली है जो जीपीएस सिग्नल सुधार प्रदान करती है, जिससे आपको बेहतर स्थिति सटीकता मिलती है। **गगन के तहत दी जाने वाली सेवाएं:** • विमानन, वन प्रबंधन, रेलवे सिग्नलिंग, वायुमंडलीय अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक संसाधन और भूमि प्रबंधन, स्थान आधारित सेवाएं, मोबाइल, पर्यटन। **यह कार्य किस प्रकार करता है?** • गगन में भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित ग्राउंड रेफरेंस स्टेशनों का सेट शामिल है, जिसे इंडियन रेफरेंस स्टेशन (INRES) कहा जाता है, जो GPS उपग्रह डेटा एकत्र करता है। • मास्टर स्टेशन, इंडियन मास्टर कंट्रोल सेंटर (आईएनएमसीसी) संदर्भ स्टेशनों से डेटा एकत्र करता है और जीपीएस सुधार संदेश बनाता है। • संशोधित अंतर संदेशों को भारतीय अपलिंक स्टेशन (INLUS) के माध्यम से अपलिंक किया जाता है और फिर तीन भू-स्थिर उपग्रहों (GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15) से सिग्नल पर प्रसारित किया जाता है। • इस सिग्नल की जानकारी बुनियादी जीपीएस सिग्नल संरचना के साथ संगत है, जिसका अर्थ है कि कोई भी एसबीएएस सक्षम जीपीएस रिसीवर इस सिग्नल को रीड कर सकता है। • दो GEO एक साथ अंतरिक्ष में GAGAN सिग्नल संचारित करते हैं। • GAGAN ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पैनल द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) मानकों और अनुशंसित प्रथाओं (SARPs) के अनुरूप एक नागरिक वैमानिकी नेविगेशन संकेत प्रदान करता है। • यह प्रणाली अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के साथ अंतःक्रियाशील है।
एंथ्रेक्स	**संदर्भ:** अंतर्राष्ट्रीय एंथ्रेक्स आयोग ने ब्रश बनाने, असबाब और कपड़ा उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले बालों और ऊन को औद्योगिक रूप से संभालने से पहले कीटाणुरहित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। 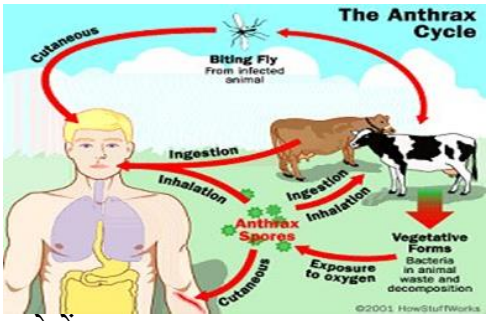 **एंथ्रेक्स के बारे में:** • एंथ्रेक्स एक जानलेवा संक्रामक रोग है जो बेसिलस एन्थ्रासिस (Bacillus Anthracis) जीवाणुओं के कारण होता है। • एंथ्रेक्स के जीवाणु मिट्टी में मौज़ूद होते हैं और कई वर्षों तक सुप्त (Latent) अवस्था में रहते हैं। • यह मानव के साथ-साथ कई जानवरों जैसे- घोड़ों, गायों, बकरियों और भेड़ों आदि को भी प्रभावित कर सकता है। • मानव संक्रमण आमतौर पर संक्रमित जानवरों या उनके उत्पादों के संपर्क से होता है। • **एंथ्रेक्स के प्रकार:** I. त्वचीय (त्वचा के माध्यम से), II. जठरांत्र, III. साँस लेना • त्वचीय (cutaneous), गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, या इनहेलेशनल एंथ्रेक्स के व्यक्ति-से-व्यक्ति संचरण की कोई पुष्टि नहीं हुई है। • विकासशील देशों में एंथ्रेक्स सबसे आम है। **इलाज:** • एंथ्रेक्स के सभी रूपों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। • सिप्रोफ्लोक्सासिन (सिप्रो) नामक एक एंटीबायोटिक को अगस्त 2000 में यू.एस. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा

	इनहेलेशनल एंथ्रेक्स के संपर्क में आने वाले लोगों के इलाज के लिए अनुमोदित किया गया था।
नाविक (NavIC)	**चर्चा में क्यों :**'भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन' (NavIC) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) नागरिक नेविगेशनल उपयोग के लिए अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में L1 आवृत्ति प्रस्तुत करेगा। 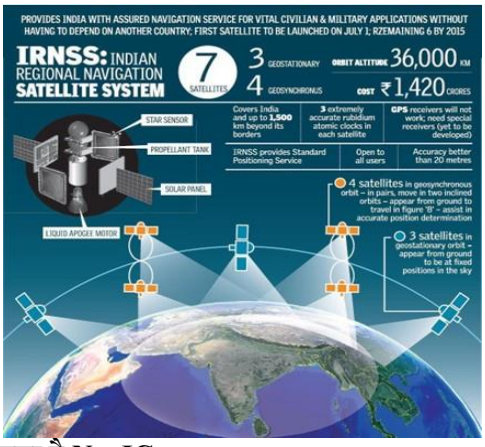 **क्या है NavIC:** • यह नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और जीपीएस का स्वदेशी विकल्प है। • इसरो द्वारा विकसित, इसे पहली बार 2006 में अनुमोदित किया गया था लेकिन यह 2018 तक ही चालू हो सका। • वर्तमान में, इसमें आठ उपग्रह शामिल हैं, जो पूरे भारत को कवर करते हैं और इसकी सीमाओं से 1,500 किमी तक हैं। • NavIC समूह में सात उपग्रह स्थिति निर्धारण डेटा प्रदान करने के लिए दो आवृत्तियों का उपयोग करते हैं - L5 और S बैंड। • इन उपग्रहों को बदलने के लिए बनाए गए नए उपग्रह NVS-01 के बाद भी L1 आवृत्ति होगी। • NavIC जीपीएस की तरह सटीक है। **L1 आवृत्ति क्या है:** • L1 सबसे पुराना और सबसे स्थापित जीपीएस सिग्नल है। • यहां तक कि कम परिष्कृत, स्मार्टवॉच जैसे उपकरण इसे प्राप्त कर सकते हैं। • इस प्रकार, इस बैंड के साथ नागरिक उपयोग के उपकरणों में NavIC का उपयोग बढ़ सकता है। • जीपीएस उपग्रह आम तौर पर दो आवृत्तियों-L1 (42 मेगाहर्ट्ज) और L2 (1227.60 मेगाहर्ट्ज) पर संचारित होते हैं। **NavIC के लाभ:** • चूंकि यह स्वदेशी है, इसलिए यह अन्य प्रणालियों की तुलना में अधिक सटीक होगा। • भारत के बाहर पूरी तरह से परिचालित समूह और ग्राउंड स्टेशनों के साथ - इसरो ने NavIC कवरेज के तहत पूरे क्षेत्र को बेहतर ट्रायंगल बनाने के लिए जापान और फ्रांस में ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है - यह सिस्टम जीपीएस की तुलना में अधिक सटीक होने की संभावना है। • यह भारत के ऊपर सीधे रखे गए उपग्रह GPS की तुलना में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संकेतों की बेहतर उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं, जो भारत को एक एंगल पर प्राप्त होता है, जिससे घने जंगलों या घाटियों में पहुँचना मुश्किल हो जाता है। **अन्य नेविगेशन सिस्टम:** • गैलीलियो - यूरोपीय संघ • ग्लोनास - रूस • बेइदौ (Beidou)- चीन • QZSS – जापान
सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बनेगा	**चर्चा में क्यों :** भारत उपग्रह संचार (सैटकॉम) के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। • ट्राई इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए एक मॉडल पर काम कर रहा है।

भारत	• विभिन्न मंत्रालयों सूचना और प्रसारण, अंतरिक्ष और दूरसंचार से उपग्रह संचार के लिए अनुमति प्राप्त करने पर काम करना ताकि क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी हो। **नोट:** जबकि दूरसंचार ऑपरेटरों ने उपग्रह संचार के लिए नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम के आवंटन का प्रस्ताव किया है, उपग्रह उद्योग के खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया है। **संचार उपग्रह क्या है?** • यह एक कृत्रिम उपग्रह है जो एक ट्रांसपोंडर के माध्यम से रेडियो दूरसंचार संकेतों को रिले और प्रवर्धित करता है; यह एक स्रोत ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के बीच पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर एक संचार चैनल बनाता है। • संचार उपग्रहों का उपयोग टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। • GSAT (जियोस्टेशनरी सैटेलाइट) उपग्रह भारत के स्वदेशी रूप से विकसित संचार उपग्रह हैं, जिनका उपयोग डिजिटल ऑडियो, डेटा और वीडियो प्रसारण के लिए किया जाता है।
पनडुब्बी 'वागीर'	**संदर्भ:** हाल ही में पांचवीं स्कॉर्पीन-श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बी, वागीर, नौसेना को सौंपी गई। **पनडुब्बी वागीर के बारे में:** • INS वागीर (S25) भारतीय नौसेना के लिए छह कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बियों के पहले बैच की पांचवीं पनडुब्बी है। • यह स्कॉर्पीन वर्ग पर आधारित एक डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसे फ्रांसीसी नौसेना रक्षा द्वारा डिजाइन किया गया है और मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। • पनडुब्बी को अपना नाम INS वागीर (S41) से विरासत में मिला है, जो 1973-2001 तक नौसेना में सेवा करता था, और इसका नाम सैंडफिश की एक प्रजाति वागीर के नाम पर रखा गया है। • **कलवरी श्रेणी:** ○ कलवरी-श्रेणी डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का एक वर्ग है जो भारतीय नौसेना के लिए बनाई जा रही स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। ○ इस श्रेणी और पनडुब्बियों का नाम भारतीय नौसेना में शामिल पहली पनडुब्बियों से लिया गया है। • स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों में से छठी और आखिरी, वाग्शीर को 2022 में पानी में लॉन्च किया गया था और इसके 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। • पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को 2017 में, दूसरी आईएनएस खंडेरी (INS Khanderi) को 2019 में, तीसरी आईएनएस करंज (INS Karanj) को 2021 में और चौथी आईएनएस वेला (INS Vela) को 2021 में कमीशन किया गया था।
कार्बनिक सौर सेल	**संदर्भ :** हाल ही में आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने जैविक सौर सेल विकसित किया है जो स्टील की छत को ऊर्जा उत्पादक उपकरण में बदल सकता है। इसे डीएसटी-आरसीयूके एपेक्स परियोजना के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से वित्त पोषण द्वारा समर्थित किया गया था।

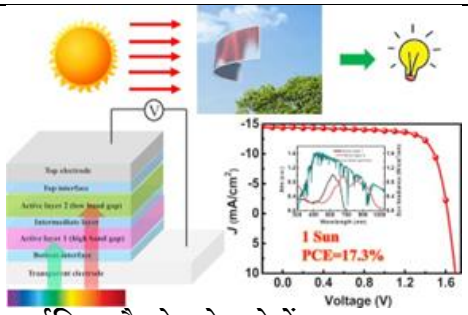

कार्बनिक सौर सेल के बारे में:

- जैविक सौर सेल जिसमें एक दाता के रूप में कार्बनिक बहुलक PTB7 और एक ग्राही के रूप में PCBM (एक कार्बनिक अर्धचालक) का संयोजन होता है।
- यह तीसरी पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकी है।

लाभ :

o केवल धात्विक इलेक्ट्रोड की तुलना में उच्च ऑप्टिकल ट्रांसमिशन।
o मल्टीलेयर इलेक्ट्रोड वाले डिवाइस ने गोल्ड के सिंगल-लेयर टॉप मेटल इलेक्ट्रोड की तुलना में 1.5 गुना बेहतर फोटोवोल्टिक प्रदर्शन दिखाया।

- जैविक सौर सेल को स्टील जैसी लचीली और अनुरूप सतहों पर एकीकृत किया जा सकता है।
- हालाँकि, इसके लिए नए, पारदर्शी संचालन वाले इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है जो अधिक टिकाऊ होते हैं और वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले इंडियम टिन ऑक्साइड की तुलना में बेहतर ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक दक्षता रखते हैं।

ग्रीन मेथनॉल

संदर्भ: हाल ही में, NTPC (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) ने ग्रीन मेथनॉल के उत्पादन का पता लगाने के लिए टेक्निमोंट (इटली) के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

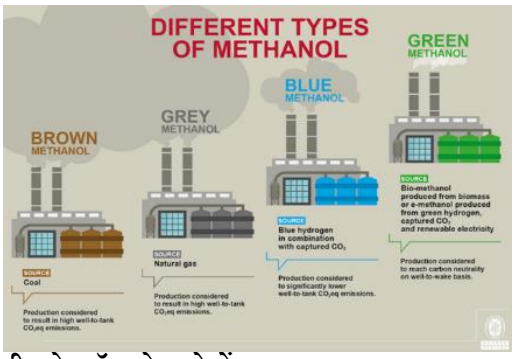

ग्रीन मेथनॉल के बारे में:

- ग्रीन मेथनॉल एक निम्न-कार्बन ईंधन है जिसे या तो बायोमास गैसीकरण या नवीकरणीय बिजली और कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) से उत्पादित किया जा सकता है।

अनुप्रयोग:

- ग्रीन मेथनॉल के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है:
  - रासायनिक उद्योग के लिए आधार सामग्री के रूप में कार्य करना
  - नवीकरणीय बिजली का भंडारण
  - परिवहन ईंधन
- **समुद्री ईंधन:** इसे समुद्री ईंधन अनुप्रयोगों के लिए एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में भी माना जाता है।
- **मोटर वाहन उद्योग:** मेथनॉल को कम मात्रा में गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है और मौजूदा सड़क वाहनों में उपयोग किया जा सकता है, या इसे उच्च अनुपात वाले मिश्रणों में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे फ्लेक्स-ईंधन वाहनों में M85 या इसके विकल्प के रूप में समर्पित मेथनॉल-ईंधन वाले वाहनों में M100 गैसोलीन या डीजल के लिए।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बारे में:

- एनटीपीसी 68,961.68 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है और 2032

	तक 130 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने की योजना है। • एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है। • 1975 में स्थापित एनटीपीसी का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बिजली कंपनी बनना है। • एनटीपीसी के पास व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन व कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीतियां हैं जो बिजली परियोजनाओं की स्थापना और बिजली उत्पादन के अपने मुख्य व्यवसाय के साथ अच्छी तरह से एकीकृत हैं। • कंपनी नवोन्मेषी पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ कई ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को अनुकूलित करके एक सतत् तरीके से प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर विश्वसनीय बिजली का उत्पादन करने के लिये प्रतिबद्ध है, इस प्रकार एनटीपीसी राष्ट्र के आर्थिक विकास और समाज के उत्थान में योगदान दे रहा है।
नेगलेरिया फाउलेरी या ब्रेन-ईटिंग अमीबा	**संदर्भ:** दक्षिण कोरिया ने नेग्लेरिया फाउलेरी या ब्रेन-ईटिंग अमीबा से संक्रमण के अपने पहले मामले की सूचना दी। 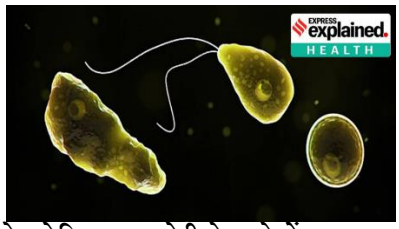 **नेगलेरिया फाउलेरी के बारे में:** • नेगलेरिया एक मुक्त-जीवित अमीबा (एकल-कोशिका वाला जीव) है। • यह इतना छोटा है कि इसे केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। • यह आमतौर पर गर्म मीठे पानी के निकायों, जैसे गर्म झरनों, नदियों और झीलों में पाया जाता है। • नेगलेरिया की केवल एक प्रजाति लोगों को संक्रमित करती है: नेगलेरिया फाउलेरी। • यह जीव 46°C तक उच्च तापमान में सबसे अच्छा बढ़ता है और कभी-कभी उच्च तापमान पर भी जीवित रह सकता है। • बहुत ही दुर्लभ उदाहरणों में, यह पूल, स्प्लैश पैड या सर्फ पार्क वाले पानी से संक्रमण हुआ है, जिसमें काफी क्लोरीन नहीं था। • इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नेगलेरिया फाउलेरी जल वाष्प या एरोसोल बूंदों (जैसे शॉवर मिस्ट या ह्यूमिडिफायर से वाष्प) के माध्यम से फैल सकता है। • दूषित पानी पीने से लोग नेगलेरिया फाउलेरी से संक्रमित नहीं हो सकते। • **उपचार:** वर्तमान में, डॉक्टर एम्फ़ोटेरिसिन बी, एज़िथ्रोमाइसिन, फ्लुकोनाज़ोल, रिफैम्पिन, मिल्टेफोसिन और डेक्सामेथासोन सहित दवाओं के संयोजन से इसका इलाज करते हैं।
सेप्सिस	**चर्चा में क्यों :** एक नया शोध स्पष्ट करता है कि कैसे सेप्सिस कोशिका मृत्यु का कारण बन सकता है। **सेप्सिस के बारे में :** 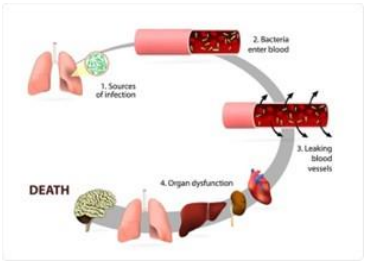 • सेप्सिस जीवन को जोखिम में डालने वाली एक स्थिति है, जो एक संक्रमण के खिलाफ शरीर की अत्यधिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है, जब यह अपने स्वयं के ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुंचाती है। • 'सेप्सिस' का पहला ज्ञात संदर्भ 2,700 साल से अधिक पुराना है, जब ग्रीक कवि होमर ने इसे 'सेपो' शब्द के व्युत्पन्न के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसका अर्थ है 'मैं सड़ा।' • जो अमेरिका में 750,000 लोगों को प्रभावित करती है और हर साल वैश्विक स्तर पर लगभग पांच करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। • साल 2017 में दुनिया भर में सेप्सिस से एक करोड़ 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और यह अमेरिका में सबसे महंगी

	चिकित्सा स्थिति है, जिसकी लागत सालाना अरबों डॉलर से अधिक है। **ऑटोइम्यूनिटी कैसे काम करती है?** • संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया तब शुरू होती है जब प्रतिरक्षा कोशिकाएं हमलावर रोगज़नक़ के घटकों से परिचित हो। • ये कोशिकाएं तब साइटोकिन्स जैसे अणुओं को छोड़ती हैं जो संक्रमण को खत्म करने में मदद करते हैं। • साइटोकिन्स छोटे प्रोटीन का एक व्यापक समूह है जो अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमण या चोट के स्थान पर लगाता है। • अत्यधिक और अनियंत्रित साइटोकिन उत्पादन सेप्सिस से जुड़े खतरनाक साइटोकिन स्टॉर्म का कारण बन सकता है। • साइटोकिन स्टॉर्म को पहली बार ग्राफ्ट बनाम मेजबान रोग के संदर्भ में देखा गया था, जो प्रत्यारोपण जटिलताओं से उत्पन्न हुआ था। वे कोविड-19 सहित वायरल संक्रमण के दौरान भी हो सकते हैं। • यह अनियंत्रित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बहु-अंग विफलता और मृत्यु का कारण बन सकती है। **ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर (TNF):** • ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, या टीएनएफ, सबसे शक्तिशाली होता है। • ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का नाम ट्यूमर कोशिकाओं को मरने के लिए प्रेरित करने की इसकी क्षमता पर आधारित है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली एक कोली बैक्टीरिया के अर्क से उत्तेजित होती है। • एलपीएस टीएनएफ का सबसे मजबूत ज्ञात ट्रिगर है, जो एक बार सतर्क होने पर, हमलावर बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए संक्रमण स्थल पर प्रतिरक्षा कोशिकाओं को लगाने में सहायता करता है। • सामान्य परिस्थितियों में, टीएनएफ सेल अस्तित्व और ऊतक पुनर्जनन जैसी लाभकारी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। • अनियंत्रित टीएनएफ उत्पादन रूमेटोइड गठिया और इसी तरह की प्रदाह की स्थिति के विकास का कारण बन सकता है। • जब टीएनएफ को संक्रमण के दौरान अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो इससे सेप्सिस हो सकता है। • संक्रमण की स्थिति में, टीएनएफ को प्रदाह से अत्यधिक ऊतक और अंग क्षति को रोकने और एक अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को रोकने के लिए भी कड़ाई से विनियमित किया जाना चाहिए। **उपचार :** • टीएनएफ गतिविधि को अवरुद्ध करने से रूमेटाइड गठिया, सोरियाटिक गठिया और आंत्र रोग सहित कई ऑटोइम्यून बीमारियों का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। • टीएनएफ को बेअसर करने से जीवाणु एलपीएस से जानवर की मौत को रोका जा सकता है। • अस्थि मज्जा, या माइलॉयड कोशिकाओं में बनी रक्त कोशिकाओं को टीएनएफ का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। • हमारे परिणाम सेप्सिस के संभावित उपचार लक्ष्य के रूप में टीआरआईएफ और सीडी14 का भी सुझाव देते हैं, जिसमें कोशिका मृत्यु और प्रदाह दोनों को कम करने की क्षमता होती है। • TNF ब्लॉकर्स साइटोकिन स्टॉर्म को रोकने में असफल रहे हैं जो COVID-19 संक्रमण और सेप्सिस से उत्पन्न हो सकता है।
दुर्लभ बीमारी 'जीएनबी1 इन्सेफेलोपैथी'	**चर्चा में क्यों :** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी (Indian Institute of Technology-IIT), मद्रास, इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय और अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता मस्तिष्क की दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी 'जीएनबी1 इन्सेफेलोपैथी' (GNB1 Encephalopathy) का अध्ययन कर रहे हैं और इसके प्रभावी इलाज के लिए दवा विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। **GNB1 इन्सेफेलोपैथी के बारे में** • यह एक प्रकार का मस्तिष्क रोग या तंत्रिका संबंधी विकार है जो भ्रूण अवस्था में व्यक्तियों को प्रभावित करता है। • अभी तक दुनिया भर में इसके 100 से भी कम मामले दर्ज किए गए हैं। • GNB1 उत्परिवर्तन के साथ पैदा होने वाले बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास में देरी, बौद्धिक अक्षमता, मिर्गी (मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि), चलने-फिरने की समस्या, मांसपेशियों में हाइपोटोनिया या हाइपरटोनिया का अनुभव करते हैं।

- G-प्रोटीन गेटेड इनवर्डली रेक्टिफाइंग के+ (जीआईआरके) चैनल (मस्तिष्क, हृदय और अंतःस्रावी ग्रंथियों में मौजूद) नामक एक पोटेशियम चैनल का कार्य महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है।
- चूंकि I80T म्यूटेशन GNB1 एन्सेफैलोपैथी रोगियों में सबसे प्रचलित प्रकार है।

यह कैसे होता है:

- GNB1 जीन में एक एकल न्यूक्लियोटाइड उत्परिवर्तन जो G-प्रोटीन में से एक बनाता है, "Gβ1 प्रोटीन," इस बीमारी का कारण बनता है।
- मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में विभिन्न प्रकार के सिग्नलिंग अणु और रास्ते होते हैं जो अन्य कोशिकाओं के साथ और अपने भीतर संचार करने में मदद करते हैं।
- कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख सिग्नलिंग तंत्र 'जी-प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर' (जीपीसीआर) सिग्नलिंग है।
- GPCR एक रिसेप्टर है जो कोशिका के बाहर से एक संकेत (जैसे एक हार्मोन, प्रकाश, न्यूरोट्रांसमीटर) प्राप्त करता है और इसे कोशिका के अंदर तक पहुंचाता है।
- GPCR कोशिका झिल्ली में मौजूद होता है और इसमें कोशिका के अंदर से G-प्रोटीन (αβγ) जुड़ा होता है।
- G-प्रोटीन तत्काल डाउनस्ट्रीम अणु हैं जो जीपीसीआर द्वारा प्राप्त सिग्नल को रिले करते हैं।
- ये G-प्रोटीन हर कोशिका में मौजूद होते हैं, और कोई भी खराबी बीमारी का कारण बन सकती हैं।

इलाज:

- चूंकि विकास संबंधी मुद्दे भ्रूण के अवस्था में शुरू होते हैं, उत्परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जीन थेरेपी सबसे विश्वसनीय विकल्प है।
- पूरे जीनोम अनुक्रमण, बच्चे के पूर्ण अनुवांशिक विश्लेषण की व्याख्या, बीमारी के प्रारंभिक निदान में बहुत सहायक हो सकती है।
- रोगी के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट दवाओं का उपयोग करके मिर्गी का इलाज किया जा सकता है।
- मिर्गी का इलाज करने के लिए, विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करनी होगी।
- ज्यादातर मिर्गी आयन चैनल के कार्य में बदलाव के कारण होती हैं।
- आयन चैनल (Ion channels) प्रोटीन होते हैं जो न्यूरॉन्स और हृदय कोशिकाओं की विद्युत गतिविधि को रेखांकित करते हैं।

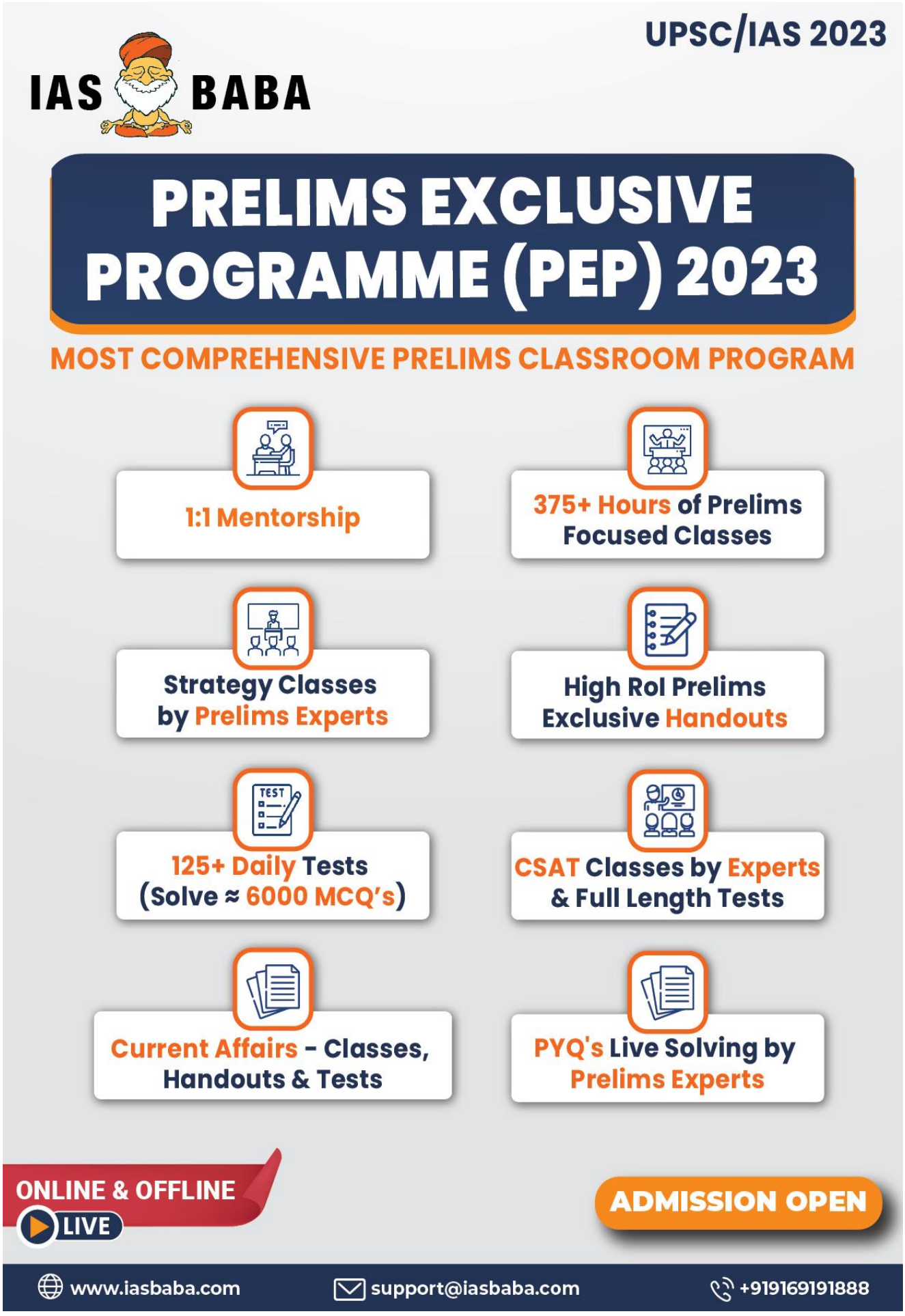
UPSC/IAS 2023
IAS BABA
PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAMME (PEP) 2023
MOST COMPREHENSIVE PRELIMS CLASSROOM PROGRAM
1:1 Mentorship
375+ Hours of Prelims Focused Classes
Strategy Classes by Prelims Experts
High RoI Prelims Exclusive Handouts
125+ Daily Tests (Solve ≈ 6000 MCQ's)
CSAT Classes by Experts & Full Length Tests
Current Affairs - Classes, Handouts & Tests
PYQ's Live Solving by Prelims Experts
ONLINE & OFFLINE
LIVE
ADMISSION OPEN
www.iasbaba.com
support@iasbaba.com
+919169191888

MAINS

राजव्यवस्था और शासन

जनजातीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करना

संदर्भ: हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'जनजाति अनुसंधान- अस्मिता, अस्तित्व एवं विकास' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) जिस पर वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वदेशी जनजातियों के ज्ञान को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।

- 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104 मिलियन है जो देश की जनसंख्या का 8.6% है। इन समुदायों की आवश्यक विशेषताएं हैं:
- पुराने लक्षण; भौगोलिक अलगाव; विशिष्ट संस्कृति; बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने से कतराते हैं; आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ।

जनजातीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करने के बारे में:

- जनजातीय ज्ञान प्रणाली सदियों के अनुभव और शिक्षाओं के माध्यम से वर्तमान समय में बैंड समाजों में अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है।
- वन, वनस्पति और जीवों से निरंतर निकटता के कारण जनजातीय समाजों को प्रकृति का समकालीन ज्ञान है।
- जनजातीय पद्धतियां ज्ञान के संरक्षण पर आधारित हैं।
    - उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार के आदिवासियों के बीच समुद्र की दीवार के बारे में जागरूकता ने उन्हें 2004 में सुनामी के खिलाफ मदद की।

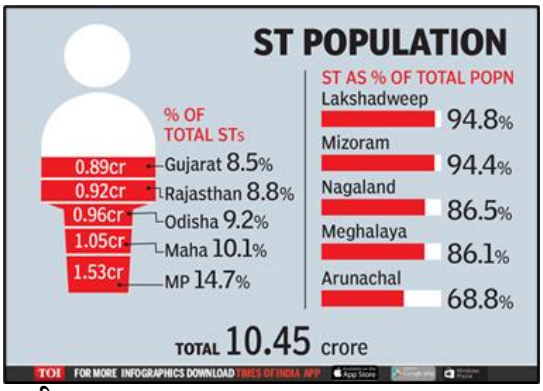

जनजातीय ज्ञान प्रणाली का महत्व:

- वनों, वनस्पतियों और जीवों से निरंतर निकटता के कारण जनजातीय समाजों को प्रकृति का समकालीन ज्ञान है। मुख्यधारा के समाज, समाज के कृषि के आधार पर चले गए हैं, और उनका सांस्कृतिक ज्ञान उनके आदिवासी अतीत की छापों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अब मौजूद नहीं है।
- मुख्यधारा की ज्ञान प्रणालियाँ चर्चाओं और वैज्ञानिक सत्यापन के माध्यम से विचारों के कठिन शोध और पूछताछ पर आधारित हैं, जबकि जनजातीय पद्धतियाँ ज्ञान के संरक्षण पर आधारित हैं।
- जनजातीय ज्ञान प्रणालियों को गीतों और कहानियों में संग्रहीत किया जाता है, जबकि मुख्यधारा के ज्ञान को पुस्तकों और रिकॉर्डिंग में संरक्षित किया जाता है।
- जनजातीय ज्ञान प्रणाली समुदाय के लिए एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देती है। मुख्यधारा समाज में, ज्ञान और परंपराएं विभाजित हो गई हैं, परंपराएं अध्ययन के तरीके के बजाय अध्ययन का विषय बन गई हैं।
- जनजातीय ज्ञान प्रणालियां गैर-बहिष्करणीय हैं और इक्विटी द्वारा चिन्हित हैं।
    - मुख्यधारा की ज्ञान प्रणालियाँ शिक्षा की लागत, पेटेंट सुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार आदि जैसी बाधाओं में उलझी हुई हैं।

जनजातीय कल्याण के लिए भारत सरकार की पहल

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय:

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।

ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केटप्लेस:

- ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केटप्लेस भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पादों का बाजार है।
    - इस पहल का उद्देश्य देश भर में विभिन्न हस्तकला, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की सोर्सिंग के लिए 5 लाख आदिवासी उत्पादकों को शामिल करना है और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ जनजातीय उत्पाद लाना है।
- आपूर्तिकर्ताओं में अलग-अलग जनजातीय कारीगर, जनजातीय एसएचजी और आदिवासियों के साथ काम करने वाले संगठन/एजेंसियां/एनजीओ शामिल हैं।

वनबंधु कल्याण योजना

- भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासियों के कल्याण के लिए वनबंधु कल्याण योजना (VKY) शुरू की है।
    - इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के आवश्यकता-आधारित और परिणाम-उन्मुख समग्र विकास के लिए सक्षम माहौल बनाना है।

लघु वनोपज

- लघु वनोपज (एमएफपी) अक्सर मांग और आपूर्ति की आत्मनिर्भर प्रक्रिया के बजाय व्यापारियों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है।
    - यह सुनिश्चित करने के लिए योजना लागू करना कि ऐसे वनवासी अपने हक से वंचित न हों।
- इस योजना के तहत एमएफपी के लिए अधिकतम बिक्री मूल्य शुरू में अनुसूची V राज्यों में लागू किया जा रहा है।
- इसके लिए एक वेब-आधारित पोर्टल भी विकसित किया गया है जो राज्यों की विभिन्न मंडियों में वास्तविक समय के आधार पर एमएफपी की वर्तमान कीमत को इंगित करता है।

वन धन योजना:

- वन धन योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड (TRIFED) की एक पहल है। इसे 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और यह जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करना चाहता है।
- इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड (TRIFED) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
    - राज्य स्तर पर, एमएफपी के लिए राज्य नोडल एजेंसी और जिला कलेक्टरों को जमीनी स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई है।

जनजातीय संग्रहालय:

- देश भर में 200 से अधिक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के रिकॉर्ड हैं जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लगभग 85 विद्रोहों और बगावतमें भाग लिया।
- इन्हें जानने के लिए 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय आंध्र प्रदेश (लंबासिंगी), छत्तीसगढ़ (रायपुर), गोवा (पोंडा), गुजरात (राजपीपला), झारखंड (रांची), केरल (कोझिकोड), मध्य प्रदेश (छिंदवाड़ा), मणिपुर (तामिंगलोंग), मिजोरम (केल्सी) और तेलंगाना (हैदराबाद) में आदिवासियों के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में

- अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A जोड़कर की गई थी।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
- इसकी भूमिका अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना या सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना है।
- संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।
- आयोग और उसके अधिकारी जनजातीय उप-योजना सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियों के निर्माण और विकासात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं।

न्यायपालिका में महिलाएं

संदर्भ: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में तीसरी बार केवल महिला जजों वाली बेंच मामलों की सुनवाई कर रही थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 2013 में एक महिला बेंच थी और दूसरा अवसर 2018 में आया था।

सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश:

- शीर्ष अदालत में 1989 में पहली महिला न्यायाधीश थी, जब न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- अपनी स्थापना के बाद से, भारत ने सर्वोच्च न्यायालय में केवल 11 महिला न्यायाधीशों को देखा है और उस मामले के लिए कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है।
- शीर्ष अदालत में वर्तमान में केवल तीन महिला न्यायाधीश हैं: जस्टिस कोहली, बी वी नागरत्ना और बेला.एम.त्रिवेदी।
- न्यायमूर्ति नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं।

भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की वर्तमान स्थिति:

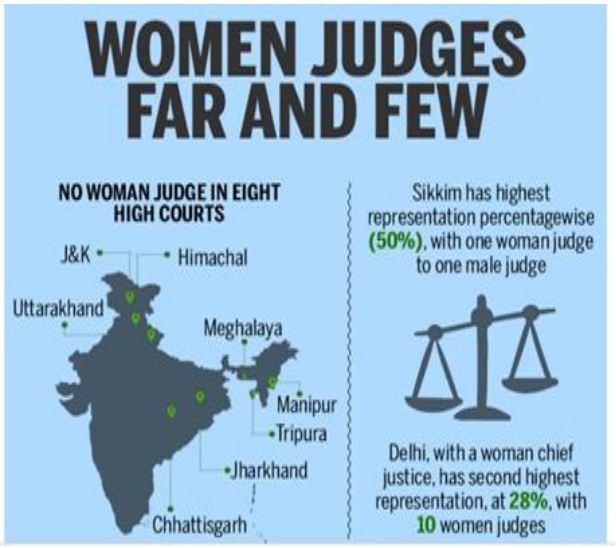

- **उच्च न्यायालय:**
  - उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या 11.5% है।
- **अधीनस्थ न्यायालय:**
  - अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 30 प्रतिशत महिला न्यायिक अधिकारी हैं।
- **अधिवक्ता:**
  - 1.7 मिलियन अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएँ हैं।
- **बार काउंसिल:**
  - राज्य बार काउंसिलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में से केवल 2% महिलाएं हैं।
  - बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई महिला सदस्य नहीं है।

न्यायपालिका में कम महिला प्रतिनिधित्त्व के कारण:

- **समाज में पितृसत्ता:** न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्त्व का प्राथमिक कारण समाज में पितृसत्ता है। महिलाओं को अक्सर न्यायालयों के भीतर अपमानजनक माहौल का सामना करना पड़ता है। उत्पीड़न, बार और बेंच के सदस्यों से सम्मान की कमी, उनकी राय को अनसुना किया जाना तथा कुछ अन्य दर्दनाक अनुभव हैं जो कई महिला वकीलों द्वारा बताए जाते हैं।
- **अपारदर्शी कॉलेजियम कार्यप्रणाली:** प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भर्ती की विधि के कारण प्रवेश स्तर पर अधिक महिलाएँ निचली न्यायपालिका में प्रवेश करती हैं।
- हालाँकि, उच्च न्यायपालिका में एक कॉलेजियम प्रणाली है, जो अधिक अपारदर्शी है और इसमें पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करने की अधिक संभावना है।
- **महिला आरक्षण नहीं होना:** कई राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिलाओं के लिये आरक्षण नीति है, जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है।
- असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों को इस तरह के आरक्षण का लाभ मिला है क्योंकि उनके पास अब 40-50% महिला न्यायिक अधिकारी हैं।
- पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ उम्र और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के कारक भी अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं से उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को प्रभावित करते हैं।

- **न्यायिक बुनियादी ढांचे की कमी:** न्यायिक बुनियादी ढाँचा या इसकी कमी, पेशे में महिलाओं के लिये एक और बाधा है। छोटे, भीड़ भरे कोर्ट रूम, टॉयलेट की कमी और चाइल्डकैअर सुविधाओं का आभाव जैसी बाधाएँ शामिल हैं।

न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का महत्व:

- **विविधीकरण की आवश्यकता:** विविधीकरण सकारात्मक संस्थागत परिवर्तन लाता है, और न्यायपालिका को और अधिक विविध होने की आवश्यकता है।
- **संतुलित न्याय वितरण प्रणाली:** न्यायाधीशों और वकीलों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति से न्याय वितरण प्रणाली में काफी सुधार होगा।
- **संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण:** न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार यौन हिंसा से संबंधित मामलों में अधिक संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की दिशा में एक लंबा मार्ग तय कर सकता है।
    - लैंगिक संवेदीकरण का मुद्दा कई बार उठाया गया है, विशेषकर उन मामलों में जहां पुरुष न्यायाधीश महिला पीड़ितों के लिए सहानुभूति दिखाने में विफल रहे।
- **वैधता:** न्यायपालिका पर भरोसा नहीं किया जाएगा अगर इसे अभिजात वर्ग, विशिष्टता और विशेषाधिकार के गढ़ के रूप में देखा जाए।

न्यायपालिका में और अधिक महिला न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए अपनाए जाने वाले सुझावात्मक उपाय:

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना के सुझाव:

- **50% प्रतिनिधित्व:** पिछले CJI ने भी न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व के लिए अपना समर्थन दिया।
- **कानूनी शिक्षा:** उन्होंने कानूनी शिक्षा में लैंगिक विविधता को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
    - विधि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निश्चित होनी चाहिए।
- **बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाना:** उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, को तुरंत चिन्हित करने की आवश्यकता है।
- **अलग इकाई की आवश्यकता:** उन्होंने अदालत परिसरों के लिए समावेशी डिजाइन पेश करने और उनमें अधिक स्वागत योग्य वातावरण बनाने के लिए एक अलग इकाई - राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम - बनाने की आवश्यकता पर बार-बार दबाव डाला।

लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्षम करना

संदर्भ: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला गतिशीलता महामारी के पिछले दो वर्षों में और हाल ही में यूक्रेनी संकट के भू-राजनीतिक झटकों से गंभीर रूप से बाधित हुई थी। इस प्रकार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को कोविड-19 महामारी जैसी एक और 'ब्लैक स्वान' घटना का सामना करने के लिए अधिक लचीला बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

आपूर्ति श्रृंखलाओं के बारे में:

- आपूर्ति श्रृंखला कच्चे माल और घटकों को एक तैयार उत्पाद में बदल देती है जिसे ग्राहक तक पहुँचाया जाता है।
- यह कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों जैसे संगठनों और गतिविधियों के एक जटिल नेटवर्क से बना है।
- आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों के उदाहरणों में डिजाइनिंग, खेती, निर्माण, पैकेजिंग, या परिवहन शामिल हो सकते हैं।

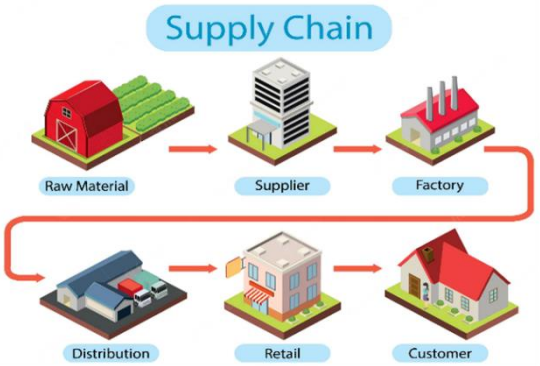

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का महत्व:

- उच्च क्षमता
- कम समग्र परिचालन लागत और जोखिम मूल्यांकन
- ग्राहक अनुभव बढ़ाना

- आपूर्ति और मांग का प्रबंधन करना
- **व्यापार चपलता (Business Agility):** आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन व्यवसायों को अधिक लचीला और अवसरों के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाता है। आपूर्ति श्रृंखला चपलता वास्तविक और अप्रत्याशित मांग परिवर्तनों को पूरा करती है क्योंकि यह नए युग की तकनीकों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और लॉजिस्टिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि को लागू करती है।

मजबूत जीएससी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल:

- राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी): व्यापक रसद कार्य योजना के रूप में जानी जाने वाली, राष्ट्रीय रसद नीति 2024 तक भारत के रसद परिदृश्य को बदलने का एक एजेंडा है।
    - नीति ऐसे समय में आई है जब देश बुनियादी ढांचे की योजना में पहले से ही बड़े बदलाव देख रहा है जैसे-
- **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी):** 'संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण' को अपनाकर 1,400 से अधिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना बनाई गई है जिसमें 2,00,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 65 से अधिक बंदरगाह, तीन राष्ट्रीय जलमार्ग, 100 से अधिक हवाई अड्डे और हेलीपैड शामिल हैं और अगले कुछ वर्षों में रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य साधित है।
    - राष्ट्रीय रसद नीति एक समान दृष्टिकोण अपनाती है और प्रस्तावों में मानव संसाधन विकास को बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण जैसे दक्षता चालक शामिल हैं।
    - नीति एक कुशल एक्जिम लॉजिस्टिक परिदृश्य बनाने के लिए विशिष्ट अध्यायों को समर्पित करती है।
- एनएमपी-एनएलपी पूरकता सरकार की चल रही पहलों को अधिक बढ़ावा देगी।
    - उदाहरण के लिए, सरकार की एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) और निर्यात हब के रूप में जिला (DEH) योजनाएँ जिलों में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रही हैं और उनका प्राथमिक ध्यान उत्पादों की पहचान, ब्रांडिंग और प्रचार करने पर रहा है। जिला स्तरीय प्रबंधन और उत्पादन के माध्यम से निर्यातकों के लिए प्रत्येक जिला।
- जबकि पीएम गतिशक्ति एनएमपी इन जिलों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकता है, एनएलपी अपनी क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में जिले के निर्यातकों की मदद कर सकता है।
- नीति के माध्यम से कुशल और जानकार कार्यबल के एक पूल के निर्माण के साथ एआई, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग जैसी नई युग की तकनीकों की शुरूआत से लचीलापन बढ़ेगा।
- पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति में मिलकर न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता में लचीलापन लाने की क्षमता है, जिससे भारत को जोड़ा जा सकता है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मानकीकृत, अनुमानित और लागत-कुशल भी बनाया जा सकता है।
- संयोजन मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल को सक्षम करेगा और रसद की दक्षता में वृद्धि करेगा।
- दोनों के बीच इस तरह की पूरकता देश के भीतर विनिर्माण आधार स्थापित करने में वैश्विक निवेश के जोखिम को भी कम करेगी और इस प्रकार भारत को चीन+ 1 रणनीति का लाभ उठाने में मदद करेगी।

आगे की राह

जीएससी भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा में सहायता करेगा और इसके वैश्विक व्यापार हिस्से को बढ़ाएगा। इस प्रयास में, ऐसे बुनियादी ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता है जो भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाए। जबकि भारत बाजार और विनिर्माण आधार दोनों के रूप में संभावित निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रतीत होता है, इसे व्यवसाय करने में आसानी और कौशल विकास के मामले में प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता है।

जैसे ही भारत जी20 की अध्यक्षता संभालता है, परिवर्तनकारी नीतिगत हस्तक्षेपों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से वांछित लचीलापन लाने में उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने के लिए भारत के लिए अवसर खुल गए हैं।

भारत के लिए प्रेषण

संदर्भ: अपने प्रवासन और विकास विवरण में, विश्व बैंक ने कहा है कि भारत का प्रेषण पिछले वर्ष के 7.5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढ़ जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप 2021 में 89.4 बिलियन डॉलर की तुलना में 100 बिलियन डॉलर का प्रवाह होगा।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: दक्षिण एशिया

- भारत और नेपाल में मजबूत प्रदर्शन के नेतृत्व में, डब्ल्यूबी ने भविष्यवाणी की है कि इस साल 3.5 प्रतिशत बढ़कर 2022 में 163 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
- भारत ने 12 प्रतिशत और नेपाल ने 4 प्रतिशत की वृद्धि की है, जबकि अन्य देशों ने 10 प्रतिशत की कुल गिरावट दर्ज की है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण 5% बढ़कर 626 अरब डॉलर हो जाएगा।

- हालाँकि, यह 2021 के 6.7 प्रतिशत लाभ से धीमा है, जो गंतव्य और स्रोत देशों में समान रूप से घरेलू कारकों के साथ-साथ बाहरी वैश्विक झटकों (मुद्रास्फीति, धीमी मांग) के मिश्रण के प्रभाव को दर्शाता है।

इस वृद्धि का कारण:

- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और पूर्वी एशिया में अपेक्षाकृत उच्च वेतन पाने वाले भारतीय प्रवासियों का बड़ा हिस्सा होना।
- भारतीय प्रवासियों के लिए गंतव्यों में धीरे-धीरे बदलाव आया है।
    - प्रवासियों द्वारा खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में बड़े पैमाने पर कम छोड़े गए, अनौपचारिक रोजगार से प्रवासी उच्च आय वाले देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और पूर्वी एशिया (सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड) में उच्च-कुशल नौकरियों के प्रमुख हिस्से में चले गए।
- योग्यता में एक संरचनात्मक बदलाव ने उन्हें विशेष रूप से नौकरियों में अधिक आय-अर्जित-श्रेणी में स्थानांतरित करने में मदद की।
- प्रेषण प्रवाह के प्रत्यक्ष प्रभाव के साथ उच्च शिक्षा को उच्च आय स्तरों पर मैप किया गया।
- कोविड-19 महामारी के दौरान, उच्च आय वाले देशों में भारतीय प्रवासियों को वर्क-फ्रॉम-होम और बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों से लाभ हुआ।
- महामारी के दौरान खाड़ी सहयोग परिषद में भारतीय प्रवासियों के भारत लौटने के बावजूद, मूल्य समर्थन नीतियों ने मुद्रास्फीति को काबू में रखा और तेल की उच्च कीमतों के साथ श्रम की मांग में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय मजदूरों के लिए प्रेषण में वृद्धि हुई।
- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्यह्रास - जनवरी और सितंबर 2022 के बीच यह 10 प्रतिशत गिर गया - यह भारतीय प्रवासियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ और प्रेषण प्रवाह में वृद्धि हुई।
- पिछले दो वर्षों में, टीकाकरण और यात्रा की बहाली ने प्रवासियों को काम फिर से शुरू करने में मदद की, जिससे देश में प्रेषण में वृद्धि हुई।

प्रेषण में वृद्धि का महत्व:

- प्रवासियों द्वारा घर भेजा गया पैसा विकासशील देशों के लिए सबसे बड़े वित्तीय प्रवाहों में से एक है।
- एफडीआई या अंतरराष्ट्रीय सहायता की तुलना में प्रेषण कई विकासशील देशों में विदेशी आय का एक अधिक स्थिर और विश्वसनीय रूप है।
- यह ऐसे देशों के भुगतान संतुलन (बीओपी) और ऋण संकट को कम करने में मदद करता है।
- प्रेषण विकासशील देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं के लिए एक स्थिर कारक हैं।
- प्रेषण परिवारों की आजीविका सहायता की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता हैं।
- जैसा कि COVID-19 अभी भी दुनिया भर के परिवारों को तबाह कर रहा है, प्रेषण गरीबों और कमजोर लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान करना जारी रखा है।

भारत में असमानता रिपोर्ट 2022: एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया द्वारा डिजिटल डिवाइड

संदर्भ: हाल ही में एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी 'इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022: डिजिटल डिवाइड' के अनुसार, भारतीय महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने की संभावना 15 फीसदी कम है और पुरुषों की तुलना में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की संभावना 33 फीसदी कम है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- रिपोर्ट जनवरी 2018 से दिसंबर 2021 तक आयोजित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण करती है।
- **भारतीय महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता:** पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने की संभावना 15 फीसदी कम है और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की संभावना 33 फीसदी कम है।
    - भारत में इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाएं केवल एक तिहाई हैं।
- **वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति:** अध्ययन में कहा गया है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, भारत 40.4 प्रतिशत के व्यापक लिंग अंतर के साथ सबसे खराब स्थिति में है।
- **ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन:** रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में 13 फीसदी की महत्वपूर्ण (डिजिटल) वृद्धि दर दर्ज करने के बावजूद, शहरी आबादी के 67 फीसदी की तुलना में केवल 31 फीसदी ग्रामीण आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है।
- **जाति-वार विभाजन:** ग्रामीण भारत में, औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने की प्रवृत्ति एसटी परिवारों के लिए सबसे कम है, इसके बाद एससी परिवारों और ओबीसी परिवारों का स्थान है।
    - एससी और एसटी आबादी की तुलना में सामान्य और ओबीसी समूहों के लिए कंप्यूटर तक पहुंच की संभावना अधिक है।
    - 2018 और 2021 के बीच सामान्य वर्ग और ST के बीच का अंतर सात से आठ प्रतिशत जितना अधिक है।

- **धर्म के लिहाज से:** सभी धर्मों में, सिखों के पास कंप्यूटर होने की सबसे अधिक संभावना है, जिसके बाद ईसाई, हिंदू और अंत में मुसलमान आते हैं।
- **शिक्षा के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच:** राष्ट्रीय सेवा योजना [एनएसएस (2017-18)] के अनुसार, किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों में से केवल 9 फीसदी के पास इंटरनेट के साथ कंप्यूटर तक पहुंच थी और नामांकित छात्रों में से 25 फीसदी के पास किसी भी प्रकार के उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच थी।
    - उच्च स्तर की शिक्षा के साथ-साथ आय के साथ कंप्यूटर होने की संभावना अधिक होती है।
    - रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में, महाराष्ट्र में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है, इसके बाद गोवा और केरल का स्थान है, जबकि बिहार में सबसे कम, इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड का स्थान है।
- महामारी और डिजिटल भुगतान का प्रभाव: महामारी द्वारा संचालित डिजिटल प्रभाव के परिणामस्वरूप भारत ने 2021 में 48.6 बिलियन में वास्तविक समय के डिजिटल लेनदेन की सबसे बड़ी संख्या का अनुभव किया।
    - हालांकि, सबसे अमीर 60 फीसदी द्वारा डिजिटल भुगतान की संभावना भारत में सबसे गरीब 40 फीसदी की तुलना में चार गुना अधिक है।

डिजिटल डिवाइड के बारे में:

- डिजिटल डिवाइड एक ऐसा शब्द है जो जनसांख्यिकी और उन क्षेत्रों के बीच की खाई को संदर्भित करता है जिनके पास आधुनिक जानकारी और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच है, और जिनके पास पहुंच नहीं है या जिनके पास प्रतिबंधित पहुंच है। इस तकनीक में टेलीफोन, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट शामिल हो सकते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले समुदायों के बीच डिजिटल असमानता स्पष्ट है; जिसमें सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच; कम आर्थिक रूप से विकसित देशों और अधिक आर्थिक रूप से विकसित देशों के बीच; शिक्षित और अशिक्षित आबादी के बीच आदि हो सकते है।

डिजिटल डिवाइड के परिणाम:

- **राजनीतिक:** सोशल मीडिया के युग में, डिजिटल कनेक्टिविटी के बिना राजनीतिक सशक्तिकरण और लामबंदी मुश्किल है।
- **स्वास्थ्य और शासन:** पारदर्शिता और जवाबदेही डिजिटल कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं। यह डिजिटल डिवाइड ई-गवर्नेंस की पहल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- **सामाजिक:** इंटरनेट की पैठ किसी राष्ट्र की अधिक सामाजिक प्रगति से जुड़ी है। इस प्रकार, डिजिटल डिवाइड एक तरह से किसी देश की सामाजिक प्रगति में बाधा डालता है।
    - डिजिटल डिवाइड के कारण ग्रामीण भारत सूचना गरीबी से पीड़ित है। यह केवल गरीबी, अभाव और पिछड़ेपन के दुष्चक्र को मजबूत करता है।
- **आर्थिक:** डिजिटल डिवाइड उन लोगों के बीच आर्थिक असमानता का कारण बनता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च उठा सकते हैं और जो नहीं करते हैं।
- **शैक्षिक:** डिजिटल डिवाइड बच्चों की सीखने और विकसित करने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहा है। इंटरनेट एक्सेस के बिना, छात्र आवश्यक तकनीकी कौशल का निर्माण नहीं कर सकते।

सतत विकास की सहायता में ग्रीन टैक्स

संदर्भ: जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सरकारों, नागरिक समाजों, कॉरपोरेट्स, व्यवसायों और यहां तक कि आम लोगों द्वारा शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। भारत इन प्रयासों में कार्य करने वाला मुख्य है और कर उत्सर्जन के एक नए आयाम का पता लगा सकता है जो सरकारी राजस्व में वृद्धि करेगा।

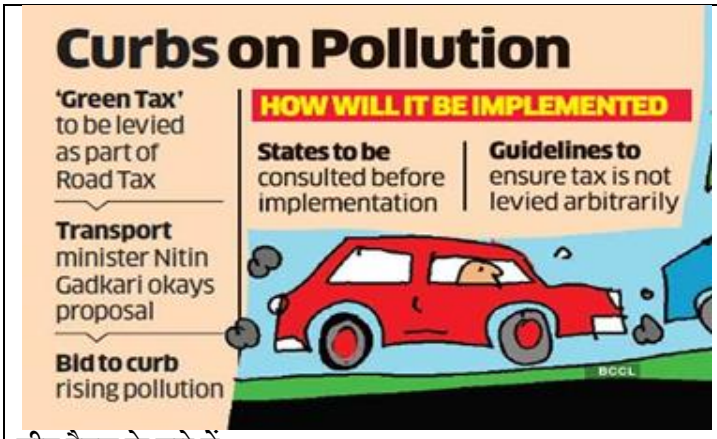

ग्रीन टैक्स के बारे में:

- ग्रीन टैक्स पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स है।
- ऐसा माना जाता है कि प्रदूषण का कारण बनने वाले उत्सर्जन पर कर लगाने से घरों और फर्मों में व्यवहारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करके लागत प्रभावी तरीके से पर्यावरणीय हानि कम हो जाएगी, जिससे उनके प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता होती है।
- ऐसे कर के माध्यम से एकत्रित राजस्व का उपयोग हरित ऊर्जा अवसंरचना बनाने, पर्यावरण प्रदूषण से निपटने, वनीकरण और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जो पर्यावरण के संरक्षण में मदद करते हैं।
- भारत में, कई राज्य सरकारों जैसे गोवा और गुजरात में हरित कर या उपकर का प्रावधान है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स/ईको टैक्स नामक एक समान कर पेश किया था।

भारत में ग्रीन टैक्सिंग के माध्यम से राजस्व सृजन की संभावना:

- भारत की शीर्ष 4,000 विषम कंपनियों का 2021-22 में लगभग 100 ट्रिलियन रुपए का संयुक्त कारोबार था।
- सहज रूप से, यदि प्रदूषण से जुड़ी इन कंपनियों की बिक्री पर थोड़ा हरित कर लगाया जाता है तो इससे बड़ा राजस्व प्राप्त हो सकता है।
    - उदाहरण के लिए टर्नओवर के 0.5% पर एक औसत ग्रीन टैक्स सरकार के लिए सालाना 50,000 करोड़ रुपए उत्पन्न करेगा।
    - इसका उपयोग बजट खर्च को वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है और यह पर्यावरण के अनुरूप परियोजनाओं के लिए ग्रीन बांड जारी करने के सरकार के प्रयासों का पूरक होगा।
    - जिन सेवाओं में कारखाने नहीं हैं, उनकी इमारतों (आधुनिक वाणिज्यिक परिसरों और शीतलन उत्सर्जन के फैंसी कांच के सामने की इमारतें) और सर्वर जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं, के साथ पारिस्थितिक शोष में योगदान करते हैं।
- हरित कर को समान रूप से लागू करने की आवश्यकता नहीं है, और संबंधित उद्योग के आधार पर इसकी दर 0.1% से 2% तक भिन्न हो सकती है।
- जैसे-जैसे इन कंपनियों/उद्योगों की बिक्री बढ़ेगी, सरकार को स्वत: ही अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

सभी व्यवसायों पर ग्रीन टैक्स लगाने की चुनौतियाँ:

- सटीक और आनुपातिक कर दर के साथ व्यक्तिगत फर्म के उत्सर्जन का आकलन करना एक कठिन प्रक्रिया है और वर्तमान में ऐसी कोई मजबूत तकनीक अस्तित्व में नहीं है।
- कंपनियां ग्राहकों पर कर की लागत डाल सकती हैं जिससे मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि हो सकती है, ऐसे कदम कमजोर वर्गों के लिए वांछनीय नहीं हैं।
- भ्रष्टाचार से ग्रस्त जमीनी स्तर पर प्रवर्तन की कमी इस तरह की पहलों को अन्यलोगों के बीच सिर्फ एक और कर देने के लिए प्रेरित कर सकती है।
- यह छोटे और स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई को बाधित कर सकता है क्योंकि उनकी लागत बढ़ जाएगी जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी।
- कुछ कंपनियों को केवल सीएसआर दायित्वों को पूरा करने के लिए 'ग्रीनवाशिंग' में लिप्त देखा गया है और ग्रीन टैक्सिंग के लिए भी ऐसी कमियां मिल सकती हैं।

आगे की राह

उत्सर्जन के लिए सिंगल टैक्सिंग की तर्ज पर एक ग्रीन टैक्स एक सही कदम हो सकता है लेकिन यह ग्राहकों पर लागत को पारित करने जैसी कई चुनौतियों का सामना करता है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा और इसे एब्जॉर्व (absorbed) किया जा सकता है। इसके अलावा, पर्यावरण की दृष्टि से अमित्र उत्पादों और सेवाओं के उपभोक्ताओं को भी बड़े पैमाने पर दुनिया के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। कुल मिलाकर लागत किसी

न किसी को वहन करनी होगी, लेकिन सरकार को निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा।

भारत में खाद्य सुरक्षा

संदर्भ: 2011 से जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली कवरेज का विस्तार करना कोई ब्रेनर नहीं है; भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करने के लिए सरकार का विरोध चौंकाने वाला है।

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2021 में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, वर्ष 2021-22 में खाद्य मूल्य सूचकांक में 30% की वृद्धि हुई है।

खाद्य सुरक्षा के बारे में:

- खाद्य सुरक्षा भोजन की उपलब्धता और इसे प्राप्त करने की व्यक्तियों की क्षमता का माप है; इसका अर्थ है कि सभी लोगों के पास हर समय, पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच है जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी भोजन की प्राथमिकताओं और आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

खाद्य सुरक्षा पर महामारी का प्रभाव: हाल ही में, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने विश्व 2021 रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति जारी की है। प्रमुख निष्कर्ष निम्न हैं,

- **आय में कमी और खाद्य कीमतों में वृद्धि:** सामर्थ्य में गिरावट का प्राथमिक कारण आय में कमी है। लेकिन खाद्य कीमतों में वृद्धि ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। 2020 के अंत तक, वैश्विक उपभोक्ता खाद्य कीमतें छह वर्षों में सबसे अधिक थीं। 2021 के पहले चार महीनों में इनमें वृद्धि जारी रही।
- **स्वस्थ भोजन की लोगों की सामर्थ्य में गिरावट:** आय में कमी के कारण स्वस्थ भोजन के लिए लोगों की सामर्थ्य में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। महामारी के कारण अतिरिक्त 141 मिलियन लोग अध्ययन किए गए देशों में स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ हो गए।
- **स्वस्थ आहार की लागत अधिक होना :** स्वस्थ आहार की लागत उस आहार की तुलना में 60% अधिक थी जो केवल "आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकताओं" को पूरा करता है और लगभग पांच गुना अधिक एक ऐसे आहार से है जो "स्टार्चयुक्त स्टेपल के माध्यम से न्यूनतम आहार ऊर्जा की आवश्यकता" को पूरा करता है।
- **अल्पपोषण:** महामारी के दौरान अल्पपोषित लोगों की संख्या में वृद्धि पिछले दो दशकों में अल्पपोषण में उच्चतम वृद्धि की तुलना में पांच गुना अधिक थी।

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए वर्तमान संरचना :

- **संवैधानिक प्रावधान:** हालांकि भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की जा सकती है, जिसमें भोजन का अधिकार और अन्य बुनियादी आवश्यकताएं अधिकार शामिल हो सकते हैं।
- **बफर स्टॉक:** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद और विभिन्न स्थानों पर अपने गोदामों में संग्रहीत करने की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम (FCI) की है और वहां से आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों को इसकी आपूर्ति की जाती है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** वर्षों से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेचर में पूरक है और इसका उद्देश्य किसी भी वस्तु की संपूर्ण आवश्यकता को उपलब्ध कराना नहीं है।
    - पीडीएस के तहत, वर्तमान में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वितरण के लिए गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं का आवंटन किया जाता है।
    - कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से दाल, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसालें आदि जैसे बड़े पैमाने पर उपभोग की अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण भी करते हैं।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए):** यह खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
- वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card-ONORC) योजना की शुरूआत एक ऐसा नवाचार है जो गेम-चेंजर हो सकती है, जिससे लाभार्थियों को देश में कहीं से भी अपने भोजन की पात्रता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

एनएफएसए में 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी शामिल है:

- **अंत्योदय अन्न योजना:** इसमें सबसे गरीब व्यक्ति शामिल है, जो प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार है।
- **प्राथमिकता वाले परिवार (PHH):** PHH श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
    - राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घर की सबसे बड़ी महिला को घर का मुखिया होना

अनिवार्य है।

- इसके अलावा, यह अधिनियम 6 महीने और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है, जो उन्हें एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसे आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में जाना जाता है।

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ:

- जलवायु परिवर्तन कृषि और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करना रहेगा, और इसका प्रभाव गरीबों और कमजोरों पर विनाशकारी होता है।
- कुल उत्पादित भोजन का एक तिहाई बर्बाद हो जाता है। खाद्य उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली खोई हुई या व्यर्थ ऊर्जा विश्व की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 10% है।
    - इसके अलावा, खाद्य नुकसान और खाद्य अपशिष्ट से जुड़ा वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन CO_2 समकक्ष के लगभग 3.5 गीगाटन तक पहुंच जाता है।
- भारत की सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली का पैमाना बहुत बड़ा है और निरंतर नेविगेशन और सुधार के माध्यम से चला गया है, जो सराहनीय है।
    - लेकिन अनुलपब्ध कमजोर आबादी के बीच पहुंच और समावेशन में सुधार के लिए अभी भी और अधिक किए जाने की आवश्यकता है।
    - जैसे एकल महिला नेतृत्व वाले परिवार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, एचआईवी प्रभावित व्यक्ति, विस्थापित व्यक्ति, शरणार्थी और अनाथ बच्चे आदि।
- व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-18 से पता चला है कि 40 मिलियन से अधिक बच्चे लंबे समय से कुपोषित हैं, और 15-49 वर्ष की आयु की आधी से अधिक भारतीय महिलाएं एनीमिक हैं।
- भारत में, 86% से अधिक किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 60% और देश के फलों और सब्जियों के आधे से अधिक का योगदान देते है।
- रसायनों के अत्यधिक उपयोग और अस्थिर कृषि पद्धतियों के साथ सघन खाद्य उत्पादन प्रणाली के कारण मिट्टी का क्षरण, भूजल तलिका का तेजी से क्षरण और कृषि-जैव विविधता का तेजी से नुकसान होता है।

आगे की राह

- **राशन कार्डों की आधार सीडिंग को पुनर्जीवित करना:**आधार को राशन कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, जमीनी निगरानी के उपाय किए जाने चाहिए जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके हिस्से के खाद्यान्न से कोई वैध लाभार्थी छूट न जाए जो जीरो हंगर (सतत विकास लक्ष्य- 2) के लक्ष्य को बल दे सके।
- **JAM के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** JAM ट्रिनिटी प्लेटफॉर्म (जन धन, आधार और मोबाइल) के माध्यम से पहचाने गए लाभार्थियों के खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है जो खाद्यान्नों के बड़े भौतिक संचलन को कम करेगा, लाभार्थियों को अपनी खपत बास्केट चुनने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा।
- **टिकाऊ खेती की ओर बढ़ते हुए:** भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में सुधार, वाटरशेड प्रबंधन को तेज करना, नैनो-यूरिया का उपयोग और सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच और सामूहिक दृष्टिकोण के माध्यम से राज्यों में फसल उपज अंतराल को कम करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
- **सटीक कृषि की ओर:** यह सुनिश्चित करने के लिए कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है कि फसलों और मिट्टी को ठीक वही मिले जो उन्हें इष्टतम स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए चाहिए।
- **खाद्य भंडार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** किसानों के साथ संचार चैनलों को बेहतर बनाने के लिए आईटी का उपयोग करने से उन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर सौदा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए नवीनतम तकनीक के साथ भंडारण घरों में सुधार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
    - इसके अलावा, खाद्यान्न बैंकों को ब्लॉक/ग्राम स्तर पर तैनात किया जा सकता है, जहां से लोगों को खाद्य कूपन के एवज में सब्सिडी वाला खाद्यान्न मिल सकता है (जो आधार से जुड़े लाभार्थियों को प्रदान किया जा सकता है)।
- **अम्ब्रेला एप्रोच के साथ मुद्दों को संबोधित करना:** असमानता, खाद्य विविधता, स्वदेशी अधिकार और पर्यावरणीय न्याय जैसे विभिन्न मुद्दों को एक सामान्य दृष्टि से देखकर, भारत एक स्थायी हरित अर्थव्यवस्था की आशा कर सकता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

संदर्भ: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश को प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाया है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में:

डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2015 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।

कार्यक्रम के निष्कर्ष:

- डिजिटल इंडिया ने सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया है।
- इसने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सीधे लाभार्थी को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने में भी मदद की है।
- इस प्रक्रिया में, भारत अपने नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए दुनिया के पूर्व-प्रतिष्ठित राष्ट्रों में से एक के रूप में उभरा है।

डिजिटल इंडिया अभियान का महत्व

- **पारदर्शिता:** डिजिटल इंडिया के कारण जो पारदर्शिता आई है, उससे विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:** पिछले आठ वर्षों में, लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 23 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण किया गया है।
- **जन धन, मोबाइल और आधार, या JAM की तिकड़ी:** इसने गरीबों और मध्यम वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाया है।
- **भ्रष्टाचार समाप्त करना:** डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले आठ वर्षों में 2.25 लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचाने में मदद की है।
- **मध्यस्था को खत्म करना:** डिजिटल इंडिया ने बिचौलियों के नेटवर्क को खत्म कर आम आदमी के पैसे बचाए हैं।
- **डिजिटल इंडिया ने सरकार को कोविड महामारी से उत्पन्न संकट से निपटने में मदद की:** कोविन और आरोग्य सेतु दो मोबाइल एप्लिकेशन हैं जिन्होंने 200 करोड़ वैक्सीन खुराक प्रदान करने में मदद की।
- **डिजिटल विभाजन को समाप्त करना:** डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण और शहरी भारत के बीच मौजूद डिजिटल विभाजन को भरने में भी मदद की है।

चुनौतियां:

- **लैंगिक अंतर:** पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने की संभावना 15 फीसदी कम है और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की संभावना 33 फीसदी कम है।
    - भारत में महिलाएं केवल एक-तिहाई इंटरनेट उपयोग करती हैं।
    - राज्यों में, महाराष्ट्र में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है, इसके बाद गोवा और केरल का स्थान है, जबकि बिहार में सबसे कम है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड का स्थान है।
- **भारत की वैश्विक रैंक:** संयुक्त राष्ट्र के ई-भागीदारी सूचकांक (2022) के अनुसार, जो कि ई-सरकार के तीन महत्वपूर्ण आयामों, अर्थात् ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान, दूरसंचार कनेक्टिविटी और मानव क्षमता का एक समग्र उपाय है, के अनुसार भारत 193 देशों में 105वें स्थान पर है।
- **ऑनलाइन सुरक्षा:** एक सर्वेक्षण के अनुसार, आधी से अधिक युवतियों ने ऑनलाइन हिंसा का अनुभव किया है, जिसमें यौन उत्पीड़न, धमकी भरे संदेश और सहमति के बिना निजी इमेज साझा करना शामिल है।

- महिला अधिकार रक्षकों और महिला पत्रकारों को सबसे अधिक दुर्व्यवहार के लिए निशाना बनाया गया।
- अपर्याप्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: तीसरा खतरा खराब तरीके से डिजाइन किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से आता है जो भेदभाव को दोहराता और बढ़ाता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत MeitY द्वारा की गई प्रमुख पहल:

- **आधार (Aadhaar):** आधार 12 अंकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय-आधारित पहचान प्रदान करता है जो अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रामाणिक है।
  - इसने आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के माध्यम से वैधानिक समर्थन भी दिया है।
  - इसमें 135.5 करोड़ से अधिक निवासियों का नामांकन किया गया है।
- **न्यू-एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग/UMANG):** यह नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए है। उमंग पर 1668 से अधिक ई-सेवाएं और 20,197 से अधिक बिल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
- **सामान्य सेवा केंद्र:** सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
  - इन सीएससी द्वारा 400 से अधिक डिजिटल सेवाओं की पेशकश की जा रही है।
  - अब तक, देश भर में 5.21 लाख सीएससी कार्यरत हैं (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित)।
- **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई):** यह अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। इसने 376 बैंकों को जोड़ा है और 11.9 लाख करोड़ रुपये के 730 करोड़ लेनदेन (मात्रा के हिसाब से) की सुविधा दी है।
- **डिजी लॉकर:** डिजिटल लॉकर डिजिटल रिपॉजिटरी में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए जारीकर्ताओं के लिए रिपॉजिटरी और गेटवे के संग्रह के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है।
  - डिजिटल लॉकर के 13.7 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता और 562 करोड़ से अधिक दस्तावेज हैं।
- **ई-साइन (e-Sign):** ई-हस्ताक्षर सेवा कानूनी रूप से स्वीकार्य रूप में नागरिकों द्वारा प्रपत्रों/दस्तावेजों पर तुरंत ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **MyGov:** यह एक नागरिक जुड़ाव मंच है जिसे सहभागी शासन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। वर्तमान में, MyGov के साथ 2.76+ करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं।
- **मेरी पहचान (MeriPehchaan):** मेरी पहचान नाम का नेशनल सिंगल साइन-ऑन (NSSO) प्लेटफॉर्म जुलाई 2022 में शुरू किया गया है, ताकि नागरिकों को सरकारी पोर्टलों तक आसानी से पहुंचा जा सके।
- **जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan):** जीवन प्रमाण में पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की परिकल्पना की गई है।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA):** सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है।

आगे की राह

समय की मांग है कि एक ऐसी सशक्त संस्था की स्थापना की जाए जो गुणवत्ता और समयबद्धता के लिए डिजिटल राजमार्गों और उनकी ग्रामीण शाखाओं को डिजाइन और निर्माण करने के लिए जवाबदेह हो और बुनियादी ढांचे को साझा करके इनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करे। डिजिटल कौशल, जो आज जीवन और आजीविका दोनों के लिए आवश्यक है, सरकारी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को कौशल मिशन में बदलकर और निजी क्षेत्र के माध्यम से आउटरीच का विस्तार करके युद्ध स्तर पर प्रदान किया जाना चाहिए।

सुरक्षा के मुद्दे से सक्रिय रूप से निपटने के लिए सोशल मीडिया साइटें अपनी "एल्गोरिदम शक्ति" का उपयोग कर सकती हैं। इस प्रकार, सरकार को उन कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है जो ऑनलाइन दुर्व्यवहारियों को खाते में रखते हैं, और जब भी वे ऑनलाइन दुर्व्यवहार देखते हैं तो जनता को बोलने की आवश्यकता होती है।

विरासत संरक्षण की आवश्यकता

संदर्भ: केरल में जनार्दन मंदिर, आगरा में आगा खान की हवेली और लद्दाख में गोनपा परिसर उन 14 प्राचीन स्थलों में शामिल हैं, जिन्हें पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है।

- इन स्मारकों और स्थलों की सूची को प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित घोषित किया गया है जिसे संस्कृति मंत्री ने राज्य सभा में साझा किया था।
- अन्य स्मारकों और स्थलों की सूची में शामिल हैं

- झारखंड के गुमला जिले का नवरत्नगढ़ का मंदिर परिसर।
- ओडिशा के बोलांगीर का स्मारकों का समूह।
- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का विष्णु मंदिर।
- जम्मू और कश्मीर के कठुआ का त्रिलोचननाथ मंदिर।
- उधमपुर ऐसे स्थल हैं जिन्हें संरक्षित घोषित किया गया है।
- नीमराना राजस्थान का बावड़ी और आसपास के पुरातात्विक अवशेष।
- बागपत, उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक अवशेष।
- बागपत, उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक अवशेष।
- देहरादून का वीरभद्र गाँव
- कारगिल, लद्दाख में रंगदुम मठ।
- आगरा का हाथी खाना।

- इसके अलावा, सरकार ने देश में सूक्ष्म संस्कृति को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक समितियों को अनुदान के रूप में पिछले तीन वर्षों में 15,622 लाख रुपये प्रदान किए हैं।
- जिसमें से वर्ष 2021-22 में 5,881.46 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (AMASR), 1958 के बारे में:

- यह अधिनियम 1958 में देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए पेश किया गया था।
- इस कानून का मुख्य उद्देश्य प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों की रक्षा करना है।
- यह अधिनियम पुरातात्विक खुदाई और मूर्तियों, नक्काशी और इसी तरह की अन्य वस्तुओं की सुरक्षा को भी नियंत्रित करता है।
- यह अधिनियम संरक्षित स्मारकों के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र में 'निषिद्ध क्षेत्रों' में निर्माण को प्रतिबंधित करता है।
- केंद्र सरकार निषिद्ध क्षेत्र को 100 मीटर से आगे बढ़ा सकती है।
- यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कार्य करता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के बारे में:

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)

- यह संस्कृति मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है।
- यह प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- यह पुरावशेष और कला निधि अधिनियम, 1972 को भी नियंत्रित करता है।
- इसकी स्थापना 1861 में एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।
- अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्व के पिता" के रूप में भी जाना जाता है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण

- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की स्थापना प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष AMASR (संशोधन और मान्यकरण) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार की गई है, जिसे मार्च, 2010 में लागू किया गया था।
- एनएमए को स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें केंद्रीय रूप से नामित स्मारकों के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्रों का नियंत्रण भी शामिल है।
- यह अधिनियम एनएमए को एक अध्यक्ष और अधिकतम 5 पूर्णकालिक और 5 अंशकालिक सदस्यों और एक सदस्य सचिव के साथ गठित करने का प्रावधान करता है।
- महानिदेशक एएसआई एक पदेन सदस्य होता हैं।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में:

- क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) की स्थापना 80 के दशक के मध्य में विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों को विकसित करने और स्वायत्त निकायों के रूप में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न तत्वों के संरक्षण और संवर्धन के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए की गई थी।
- ZCCs को लोक कला, नृत्य और संगीत पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी।
- जेडसीसी की स्थापना के पीछे का जनादेश राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से बांधना था, जबकि उन क्षेत्रों की विशेषता को बनाए रखना था जो

उनमें शामिल हैं।

AMASR अधिनियम का महत्व:

- जब किसी स्मारक को AMASR अधिनियम के तहत संरक्षित घोषित किया जाता है तो स्मारक के रखरखाव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिकार में ले लिया जाता है।
- स्मारक या स्थल के आसपास निर्माण गतिविधियों को विनियमित किया जाता है और संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होती है।
- स्मारक के चारों ओर सभी दिशाओं में 200 मीटर तक फैले क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र कहा जाता है।
- एएमएसएआर (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के अनुसार संरक्षित क्षेत्र की 100 मीटर की परिधि के भीतर निर्माण निषिद्ध है।

अर्थव्यवस्था

बड़े व्यवसायों पर न्यूनतम कर

संदर्भ: यूरोपीय संघ के सदस्य बड़े व्यवसायों पर न्यूनतम 15% कर लागू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए।

पिछले साल, 136 देशों ने क्षेत्राधिकारों में कर अधिकारों को पुनर्वितरित करने और बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों पर 15% की न्यूनतम कर दर लागू करने की योजना पर सहमति व्यक्त की थी।

बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) क्या है?

- आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर नियोजन रणनीतियों को संदर्भित करता है जो कर के भुगतान से बचने के लिए कर नियमों में अंतराल और बेमेल का लाभ उठाते हैं।
- हालाँकि उपयोग की जाने वाली कुछ योजनाएँ अवैध हैं, अधिकांश नहीं हैं।
- बीईपीएस प्रथाओं से देशों को सालाना 100-240 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है।
- BEPS पर OECD/G20 समावेशी ढांचे के अंदर एक साथ काम करते हुए, 135 से अधिक देश और क्षेत्राधिकार सहयोग कर रहे हैं।

बीईपीएस से क्या संबंधित हैं?

- **कम कर राजस्व:** विकासशील देशों की कॉर्पोरेट आय कर पर अधिक निर्भरता का मतलब है कि वे बीईपीएस से अनुपातहीन रूप से पीड़ित हैं।
- **घरेलू छोटी फर्मों पर प्रतिकूल प्रभाव:** इस तरह की टैक्स प्लानिंग रणनीतियाँ कर प्रणालियों की निष्पक्षता और अखंडता को कम करती हैं क्योंकि व्यवसाय जो सीमाओं के पार संचालित होते हैं, वे बीईपीएस का उपयोग उन उद्यमों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं जो घरेलू स्तर पर संचालित होते हैं।
- **गलत मिसाल कायम करना:** इसके अलावा, जब करदाता बहुराष्ट्रीय निगमों को कानूनी रूप से आयकर से बचते हुए देखते हैं, तो यह सभी करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को कमजोर करता है।

ओईसीडी की वैश्विक कर योजना क्या है?

- यूरोपीय संघ के सदस्य आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) 2021 द्वारा बनाए गए वैश्विक कर समझौते के स्तंभ 2 के अनुसार बड़े व्यवसायों पर 15% की न्यूनतम कर दर लागू करने पर सहमत हुए हैं।
- OECD की योजना के तहत, सरकारें अतिरिक्त कर लगाने के लिए तैयार होंगी, यदि कंपनियों को बहुत कम माने जाने वाले करों का भुगतान करते हुए पाया जाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वैश्विक परिचालन वाले बड़े व्यवसायों को कर बचाने के लिए टैक्स हेवन में रहने से लाभ न हो।
- दूसरी ओर, ओईसीडी की कर योजना का स्तंभ 1, कर अधिकारों के प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करता है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पारंपरिक रूप से अपने घरेलू देशों में करों का भुगतान किया है, भले ही उन्होंने अपना अधिकांश व्यवसाय विदेशों में किया हो।
- ओईसीडी योजना उन देशों की सरकारों को अधिक कर अधिकार देने की कोशिश करती है जहां बड़े व्यवसाय अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संचालित करते हैं।

- परिणामस्वरूप, बड़ी अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को विकासशील देशों की सरकारों को अधिक करों का भुगतान करना पड़ सकता है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि न्यूनतम कर की दर से वैश्विक कर राजस्व में सालाना 150 बिलियन डॉलर की वृद्धि होगी।

वैश्विक न्यूनतम कर की आवश्यकता क्यों है?

- अधिक से अधिक निजी निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में कॉर्पोरेट कर की दरें गिर रही हैं।
- वैश्विक कॉर्पोरेट कर की दरें 1980 के दशक में 40% से अधिक से गिरकर 2020 में 25% से कम हो गई हैं, वैश्विक कर प्रतियोगिता के लिए धन्यवाद जो कि 1980 के दशक में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा शुरू किया गया था।
- ओईसीडी की कर योजना इस "रेस टू बॉटम" को समाप्त करने की कोशिश करती है जिसने सरकारों के लिए अपने बढ़ते खर्च बजट को निधि देने के लिए आवश्यक राजस्व एकत्र करना कठिन बना दिया है।
- न्यूनतम कर प्रस्ताव विशेष रूप से ऐसे समय में प्रासंगिक हुआ है जब दुनिया भर में सरकारों की राजकोषीय स्थिति खराब हो गई है जैसा कि सार्वजनिक ऋण मेट्रिक्स की बिगड़ती स्थिति में देखा गया है।

आगे की राह

- कुछ सरकारें, विशेष रूप से पारंपरिक टैक्स हैवन्स की, असहमत हो सकती हैं और ओईसीडी की कर योजना के कार्यान्वयन को रोक सकती हैं।
- यूरोपीय संघ जैसे उच्च कर क्षेत्राधिकारों द्वारा न्यूनतम कर योजना को पूरी तरह अपनाने की अधिक संभावना है क्योंकि यह उन्हें कम कर क्षेत्राधिकारों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने से बचाता है।
- • दूसरी ओर, कम कर क्षेत्राधिकार, ओईसीडी की योजना का विरोध करने की संभावना हैं, जब तक कि उन्हें अन्य तरीकों से पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जाता।
- यह ध्यान देने की जरुरत है कि, यूरोपीय संघ के अंदर भी, पोलैंड जैसे देशों ने पहले ही विभिन्न गैर-आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए वैश्विक न्यूनतम कर प्रस्ताव को अपनाने से रोकने की कोशिश की है।
- चूंकि ओईसीडी की योजना अनिवार्य रूप से एक वैश्विक कर कार्टेल बनाने की कोशिश करती है, यह हमेशा कार्टेल के बाहर कम कर वाले न्यायालयों को खोने और कार्टेल के सदस्यों द्वारा धोखा देने के जोखिम का सामना करेगी।
- आखिरकार, कार्टेल के अंदर और बाहर दोनों देशों के पास व्यवसायों को कम कर दरों की पेशकश करके अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन होगा। यह एक संरचनात्मक समस्या है जो तब तक बनी रहेगी जब तक वैश्विक टैक्स कार्टेल मौजूद रहेगा।

ओईसीडी की कर योजना के निहितार्थ क्या हैं?

- OECD की कर योजना के समर्थकों का मानना है कि यह वैश्विक "रेस टू बॉटम" को समाप्त कर देगा और सरकारों को सामाजिक खर्च के लिए आवश्यक राजस्व एकत्र करने में मदद करेगा।
- कई लोगों का मानना है कि यह योजना टैक्स हेवन सेवाओं का लाभ उठाकर बड़े व्यवसायों के लिए कम करों का भुगतान करना कठिन बनाकर बढ़ती वैश्विक असमानता का मुकाबला करने में भी मदद करेगी।
- ओईसीडी के प्रस्ताव के आलोचक, हालांकि, वैश्विक न्यूनतम कर को एक खतरे के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि सरकारों के बीच कर प्रतिस्पर्धा के बिना, दुनिया पर वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक कर लगाया जाएगा, इस प्रकार वैश्विक आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- दूसरे शब्दों में, इन आलोचकों का मानना है कि यह कर प्रतिस्पर्धा का खतरा है जो सरकारों पर नियंत्रण रखता है जो अन्यथा अपने नागरिकों पर भारी कर लगाती हैं।

ई-रूपी (E-Rupee)

संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 दिसंबर से खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए भारत की बहुप्रतीक्षित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), ई-रुपया, एक प्रकार की आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है।

- RBI CBDC को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी करेंसी नोटों के डिजिटल रूप के रूप में परिभाषित करता है। यह देश की मौद्रिक नीति के अनुसार केंद्रीय बैंक (इस मामले में, आरबीआई) द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है।

खुदरा ई-रे क्या है?

- ई-रुपया (ई-रे) सीबीडीसी या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा से जुड़ा सामान्य नाम है। जो कानूनी निविदा या मुद्रा का एक डिजिटल रूप है।
- ई-रे थोक और खुदरा हो सकता है। होलसेल के लिए एक पायलट 1 नवंबर को लॉन्च किया गया था, जबकि रिटेल वर्जन के लिए 1

दिसंबर को लॉन्च किया गया था।

- चार बैंक (एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक) पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में भाग लेंगे, और चार अन्य बैंक (एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक) को बाद में जोड़ा जाएगा। योजना चरणबद्ध तरीके से 13 शहरों को कवर करेगी।
- जिस तरह टेलीकॉम ऑपरेटर उत्पाद लॉन्च करते हैं, ठीक उसी तरह ई-रू का भी क्लोज्ड यूजर ग्रुप या सीयूजी पर परीक्षण किया जाएगा।
- पायलट चरण का उद्देश्य उन बैंकों के ग्राहक हैं जो इस परियोजना से जुड़े हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य उत्पाद की प्रभावकारिता का परीक्षण करना है।
- आखिरकार, ई-रे के खुदरा संस्करण का उपयोग व्यक्तियों द्वारा सभी लेनदेन के लिए किया जा सकता है, जहां वे नकदी का उपयोग चीजें खरीदने, दोस्तों या रिश्तेदारों को देने, कर्ज चुकाने आदि के लिए करते हैं।
- जबकि मूल्य या मात्रा के संदर्भ में कोई विशिष्ट लेन-देन सीमा नहीं है, प्रारंभिक चरणों में, ई-रे कम-टिकट उपयोगों तक सीमित हो सकता है।

कैसे कार्य करता है ई-रुपया?

- भौतिक वॉलेट के बजाय डिजिटल वॉलेट से नकद खर्च करने पर विचार करना; इस तरह से ई-रे कार्य करेगा और इस पर सॉवरेन मुहर लगेगी।
- प्रायोगिक चरण में, ई-रे एक पुश उत्पाद होगा। बैंक ईमेल या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से पहचाने गए ग्राहकों को एक लिंक भेजेंगे, जिससे ई-री ऐप डाउनलोड किया जा सकता है।
- मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए, ग्राहक सत्यापन या केवाईसी पूरा करेगा और केवाईसी के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, डिजिटल वॉलेट का उपयोग करना अच्छा होगा।
- इसके बाद उपयोगकर्ता बैंक खाते से वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकेगा। सीधे शब्दों में कहें तो एटीएम से पैसे निकालने के बजाय आप डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं।
- स्थानांतरित की गई राशि भौतिक नकदी के सटीक मूल्यवर्ग के बराबर होगी और ई-वॉलेट में रखे जाने पर उस पर ब्याज नहीं मिलेगा।
    - आरबीआई ब्याज सहित ई-रुपये के पक्ष में नहीं है। क्योंकि लोग बैंकों से पैसा निकाल सकते हैं और इसे डिजिटल रुपये में बदल सकते हैं - जिससे बैंक विफल हो सकते हैं।
- इसलिए, कितना गैर-ब्याज पैदा करने वाला पैसा एक उपयोगकर्ता समायोजित करने के लिए तैयार रहता है, यह ई-रे की स्वीकृति को मापने के लिए एक निर्धारित कारक होगा।

आरबीआई ई-रे की ओर क्यों बढ़ रहा है?

- ई-रे आधिकारिक सिक्के के विकास में एक स्वाभाविक अगला कदम प्रतीत होता है (मेटल-आधारित मुद्रा से, मेटल-समर्थित बैंक नोटों से, भौतिक फिएट मनी से)
- मुद्राओं और सिक्कों की छपाई, परिवहन और भंडारण में लागत आती है जिसे ई-रे के माध्यम से युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।
- ई-रे उन लोगों पर भी लक्षित होता है जिनके पास बैंक खाता नहीं है, लेकिन वे प्री-पेड मोबाइल रिचार्ज कार्ड के समान डिजिटल मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह, यह सिर्फ स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास मोबाइल फोन है।
- ई-रे को किसी भी वाणिज्यिक बैंक के पैसे या नकदी में बदला जा सकता है। यह एक वैकल्पिक कानूनी निविदा होगी जिसके लिए धारकों के पास बैंक खाता नहीं होना चाहिए - इसलिए, वित्तीय समावेशन के कारण को मजबूत करना होगा। इसलिए, ई-रे पैसे की डिजिटल खपत को औपचारिक रूप देने में मदद करेगा।
- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आम जनता को अनियमित क्रिप्टोकरेंसी और उनसे जुड़े जोखिमों का विकल्प प्रदान करेगा।
- यह निपटान प्रणाली में दक्षता को जोड़ेगा और सीमा पार भुगतान स्थान में नवाचार को बढ़ावा देगा और जनता को उन उपयोगों के साथ प्रदान करेगा जो किसी भी निजी आभासी मुद्रा से संबंधित जोखिमों के बिना प्रदान कर सकते हैं।
- सीबीडीसी जारी करने से केंद्रीय बैंकों को परिचालन दक्षता, वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति प्रभावशीलता और वित्तीय अखंडता सहित सार्वजनिक नीति के लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने की अनुमति मिलती है।
    - आरबीआई के अनुसार, भारत में सीबीडीसी जारी करने की तलाश के लिए प्रमुख प्रेरणाओं में भौतिक नकदी प्रबंधन में शामिल परिचालन लागत में कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता और नवीनता लाना शामिल है।

खुदरा ई-रुपये से क्या चुनौतियाँ हैं?

- ग्राहक के दृष्टिकोण से, यूपीआई ने उपयोग में सरलता हासिल की है। इसलिए, ई-रे को यह साबित करने की जरूरत है कि यह उपयोगकर्ताओं को लुभाने के लिए ध्वनि प्रौद्योगिकी और डेटा गोपनीयता प्रावधानों के साथ समान रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल है।
- उपयोगकर्ताओं को हैकिंग और वायरस हमलों जैसी डिजिटल चोरी का भी सामना करना पड़ता है, जो कुछ लोगों को डरा सकता है।
- देश में सांस्कृतिक और सामाजिक मानसिकता, जो भौतिक मुद्रा के अधिक उपयोग की ओर ले जाती है, भी एक बाधा है।

भारत का सहकारी क्षेत्र

संदर्भ: बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) अधिनियम, 2002 में संशोधन करने वाला विधेयक, 07 दिसंबर 2022 को शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया गया था।

भारत के सहकारी आंदोलन का इतिहास क्या है?

- भारत के सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि और संबंधित क्षेत्रों में किसानों के लिए साहूकारों द्वारा शोषण को रोकने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के साधन के रूप में हुई।
- कृषि ऋण बैंकों के जर्मन मॉडल से प्रेरित होकर 19वीं शताब्दी के अंत में भारत के सहकारी आंदोलन को औपचारिक रूप दिया गया।
- स्वतंत्रता के बाद, संविधान निर्माताओं ने सहकारी समितियों को राज्य सूची में रखा। उन्हें सामाजिक-आर्थिक विकास का उपकरण माना जाने लगा और प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं का एक अनिवार्य केंद्र बन गया। परिणामस्वरूप, राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए अपने स्वयं के कानून बनाए।
- 97वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में कहा गया है कि "राज्य स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे"।
- सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियाँ हैं, जिनसे लगभग 1.3 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं।
    - केंद्र सरकार ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए 2021 में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है।
- आज, भारत में सहकारी समितियों से लेकर उर्वरक, दूध, चीनी और मछली जैसे उत्पादों का उत्पादन, खरीद या विपणन करने वालों को ऋण प्रदान करते हैं।
    - भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति (Indian Farmers Fertilisers Cooperative-IFFCO) के पास उर्वरकों में लगभग एक तिहाई बाजार हिस्सेदारी है, जबकि गुजरात की अमूल अत्यधिक लाभदायक डेयरी सहकारी है।

बहु-राज्य सहकारी समितियां क्या हैं?

- सहकारिता राज्य का विषय है, लेकिन कई समितियां हैं जैसे चीनी और दूध, बैंक, दुग्ध संघ आदि जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं।
- उदाहरण के लिए, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित जिलों की अधिकांश चीनी मिलें दोनों राज्यों से गन्ना खरीदती हैं। ये समितियां दोनों राज्यों से अपनी सदस्यता प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार ये बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (2002 में संशोधित) के तहत पंजीकृत हैं।
- इनके निदेशक मंडल में उन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है जिनमें वे संचालन करते हैं।
    - निदेशक मंडल सभी राज्यों से होते हैं, ये समूह सभी वित्त और प्रशासन कार्यों को संचालित और नियंत्रित करते हैं।
- इन सोसायटियों का प्रशासनिक और वित्तीय विनियमन तथा निगरानी केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास होता है, कानून यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी उन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है।
- कानून बनने के बाद से ऐसी 1,479 सोसायटियां पंजीकृत की गई हैं, जिनमें से 9 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
- महाराष्ट्र में सबसे अधिक 567, इसके बाद उत्तर प्रदेश (147) और नई दिल्ली (133) का स्थान है।
- क्रेडिट सोसाइटी 610 में पंजीकृत सोसाइटियों का बड़ा हिस्सा हैं, इसके बाद 244 पर कृषि आधारित (जिसमें चीनी मिलें, कताई मिलें आदि) शामिल हैं। 96 बहुराज्य सहकारी डेयरी और 66 बहुराज्य सहकारी बैंक हैं।

सहकारी क्षेत्र के साथ क्या मुद्दे हैं?

- जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कल्पना की गई है, सहकारी समितियों का स्वतंत्र और स्वायत्त चरित्र उनके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण था।
- हालांकि, जैसे-जैसे सहकारी समितियों पर सरकार और विधायी नियंत्रण में वृद्धि हुई, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की रिपोर्टें बढ़ती गईं।
- विकास के साधनों के रूप में नियोजन प्रक्रिया में उनके समावेश ने इस क्षेत्र को सत्ताधारी राजनीतिक दलों के समर्थकों को संरक्षण प्रदान करने का एक माध्यम बना दिया, या तो गवर्निंग बोर्ड में नामांकन के माध्यम से या सहकारी समितियों के लिए विशिष्ट योजनाओं को मंजूरी देकर।
- इसके अलावा, वित्तीय सहायता के विभिन्न रूपों को प्रदान करने से राज्य सरकारें, "सार्वजनिक हित के नाम पर", कानूनी रूप से स्वायत्त

सहकारी समितियों के कामकाज में सीधे हस्तक्षेप करने में सक्षम हो गई।

- इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अमूल, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) जैसी सबसे सफल भारतीय सहकारी समितियां सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं।

- विश्व स्तर पर, संपत्ति के आकार के आधार पर शीर्ष 10 सहकारी समितियों में से 7 वित्तीय क्षेत्र से हैं। संपत्ति के आकार के लिहाज से भारतीय वित्तीय क्षेत्र इस मामलें में कहीं नहीं है।
- जब एक सहकारी बैंक का आकार बढ़ता है, तो उसकी सहकारिता को बनाए रखना एक चुनौती होती है। सहकारी समितियां विनियामक अंतरपणन, ऋण देने में बाधा डालने और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विनियमों के लिए भी मार्ग बन गई हैं।
- MSCS विश्वास के संबंध में मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जो सहयोग का आधार है। इसलिए, MSCS को 2018 में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत लाया गया, और सभी शहरी तथा MSCS बैंकों को 2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक के रडार पर लाया गया।
- इन घटनाक्रमों ने MSCS को केंद्र के कई नियंत्रणों में ला दिया है, जिससे यह डर उत्पन्न हो गया है कि निगरानी जमीनी स्तर के बजाय ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अपनाएगी।
- सहकारी बैंकिंग को ऊपर से नीचे की गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। शहरी सहकारी समितियों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन और केंद्र में एक नया सहकारिता मंत्रालय जैसी हाल की पहल सुरक्षा उपायों के अभाव में इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की चेतावनी देती है।

प्रस्तावित बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- MSCS अधिनियम में "कमियों" को दूर करने के लिए, केंद्र ने अधिक "पारदर्शिता" के लिए 2002 के कानून में संशोधन करने और "व्यापार करने में आसानी" बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश किया।
- प्रशासन में सुधार, चुनावी प्रक्रिया में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए संशोधन पेश किए गए हैं।
- यह बिल MSCSs के चुनावी कार्यों की निगरानी के लिए एक केंद्रीय सहकारी चुनाव प्राधिकरण के निर्माण का प्रावधान करता है।
- बिल MCSCs में धन जुटाने को सक्षम करने के अलावा, बोर्ड की संरचना में सुधार करने और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है।
- यह कमजोर MSCSs के पुनरुद्धार के लिए एक सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष के निर्माण की परिकल्पना करता है, जो मौजूदा लाभदायक MSCSs द्वारा वित्तपोषित है, जिसे अपने शुद्ध लाभ का 1 करोड़ रुपये या 1% जमा करना होता है।
- इन सोसायटियों के शासन को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए, विधेयक में एक सहकारी सूचना अधिकारी और एक सहकारी लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान है।
- इक्विटी और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, MSCS बोर्डों में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- बिल केवल सदस्यों को बोर्ड के लिए या सहकारी समिति के पदाधिकारियों के रूप में चुने जाने के योग्य बनाता है।
- बिल कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये और संभावित कारावास को छह महीने से बढ़ाकर एक साल करता है।

भारत की ब्लू कार्बन क्षमता

संदर्भ: पर्यावरण विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यदि भारत वैश्विक जलवायु लीडर के रूप में उभरना चाहता है तो उसे ब्लू-कार्बन समाधान अपनाना चाहिए। अपने 2070 नेट-ज़ीरो लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इस बात पर जोर देती है कि उसे सभी ब्लू कार्बन हस्तक्षेपों का पूरी तरह से पता लगाना चाहिए।

ब्लू कार्बन के बारे में:

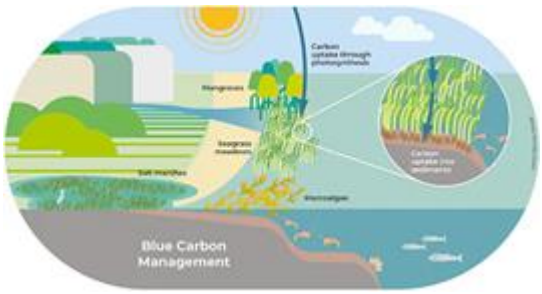

- "ब्लू कार्बन" शब्द तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहीत कार्बन को संदर्भित करता है।
- तथाकथित ब्लू कार्बन पारिस्थितिक तंत्र मैंग्रोव, ज्वारीय और नमक दलदल, और समुद्री घास अत्यधिक उत्पादक तटीय पारिस्थितिक

तंत्र हैं जो विशेष रूप से पौधों के भीतर और नीचे तलछट में कार्बन को स्टोर करने की उनकी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- वैज्ञानिक आकलन से पता चलता है कि वे स्थलीय वनों की तुलना में दो से चार गुना अधिक कार्बन का पृथक्करण कर सकते हैं और इस प्रकार उन्हें जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों का एक प्रमुख घटक माना जाता है।

जलवायु परिवर्तन को कम करने में ब्लू कार्बन का महत्व:

- **विशाल 7,500+ किलोमीटर लंबी तटरेखा:** भारत में वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ग किमी मैंग्रोव, 500 वर्ग किमी समुद्री घास और लगभग 300 से 1400 वर्ग किमी नमक दलदल हो सकते हैं।
- मैंग्रोव, समुद्री घास और नमक के दलदल बोरियल (boreal) और उष्णकटिबंधीय जंगलों सहित किसी भी अन्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में 20 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) ग्रहण कर सकते हैं।
- तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की कुल कार्बन पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगभग 700 मिलियन टन CO_2 है, जो भारत के वार्षिक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 22 प्रतिशत है।

भारत की ब्लू कार्बन क्षमता के उपयोग में चुनौतियाँ:

- 'नेचर' पत्रिका में भारत को ब्लू कार्बन 'दाता' के बजाय 'ब्लू कार्बन धन प्राप्तकर्ता देश' के रूप में उल्लेखित किया गया है।
- यह पत्रिका भारत में ब्लू कार्बन संसाधनों के कम उपयोग का सुझाव देती है।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत भारत की 'दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति' दस्तावेज़ नीले कार्बन अवसर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है।
- ब्लू कार्बन भंडारण संपत्तियों की बहाली के लिए एक स्पष्ट मार्ग का अभाव भविष्य में कार्बन उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है।

आगे की राह

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ ब्लू कार्बन पर राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता है:

- यह'मिशन देश के सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने वाले ज्ञान, जनशक्ति, धन और सामग्री प्राप्त करने के लिए मूल्य-श्रृंखला विकास के लिए चरण-वार रणनीतियों को परिभाषित कर सकता है।
- मिशन इस क्षेत्र में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए प्रमुख संबलों को स्थापित करने पर जोर देते हुए ब्लू कार्बन दायित्वों जैसे संभावित मांग सृजन कार्यों की पहचान कर सकता है।
- ब्लू-कार्बन क्षेत्र में वित्तीय और नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ तकनीकी विकास को कारगर बनाना।
- मिशन प्रासंगिक क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य तय कर सकता है जो एक ब्लू-कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान करते हैं।
- मिशन देश में एक मजबूत कार्बन बाजार स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- उपयुक्त निगरानी, अनुपालन और जोखिम कम करने के दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करते हुए मिशन निजी क्षेत्र/एनजीओ/थिंक टैंक के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है।

भारत में कपड़ा उद्योग

संदर्भ: कपड़ा उद्योग अधिक पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (ईएसजी) जांच के दायरे में आ रहा है। आपूर्ति श्रृंखला में पता लगाने की क्षमता और कपड़ा कचरे का पुनर्चक्रण आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में कपड़ा उद्योग के बारे में:

- भारतीय कपड़ा और परिधान बाजार वर्तमान में $150 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें से निर्यात $40 बिलियन से अधिक है।
- एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक कपड़ा और परिधान व्यापार 2025-26 तक 1,000 अरब डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार है और इसी अवधि में भारतीय कपड़ा और परिधान बाजार 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
- भारत के पास 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक कपड़ा और परिधान बाजार का 4% हिस्सा है, और यह पांचवें स्थान पर है।
- यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 7%, भारत की निर्यात आय में 12% का योगदान देता है और कुल रोजगार के 21% से अधिक को रोजगार देता है।
- भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दुनिया का 95% हाथ से बुने हुए कपड़े भारत से आते हैं।
- भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्र का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है।

- तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक कपड़े हैं जिनका ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित विभिन्न उद्योगों में उपयोग होता है।

क्षेत्र का महत्व:

- **किफायती:** 2019-20 में, घरेलू कपड़ा और परिधान बाजार $150.5 बिलियन का था।
- **व्यापार:** भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 में 41 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात दर्ज किया, जो वैश्विक औसत से मामूली अधिक सीएजीआर (2.7) है।
- **रोजगार:** भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता, कपड़ा और परिधान क्षेत्र सीधे 45 मिलियन श्रमिकों के अलावा सहायक क्षेत्रों में 100 मिलियन लोगों को रोजगार देता है।
- **अन्य क्षेत्रों के लिए कच्चा माल:** तकनीकी वस्त्र उपयोगी सामग्री हैं जिनका उपयोग ऑटोमोटिव, सिविल इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, व्यक्तिगत सुरक्षा और निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।

कपड़ा क्षेत्र के सामने चुनौतियां:

- **अत्यधिक खंडित:** असंगठित क्षेत्र और छोटे तथा मध्यम आकार के व्यवसाय भारत के कपड़ा उद्योग पर हावी हैं, जो अत्यधिक खंडित है।
- **अप्रचलित प्रौद्योगिकी:** बाजार प्रतिस्पर्धा और पहुंच के मुद्दों के कारण, भारतीय कपड़ा क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह छोटे पैमाने के व्यवसायों के लिए विशेष रूप से सही है।
- **कर संरचना से संबंधित मुद्दे:** जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कर संरचना घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में कपड़ों को महंगा और अप्रतिस्पर्धी बनाती है। बढ़ते श्रम और श्रमिकों के वेतन का खतरा एक और हिस्सा है।
- **निर्यात स्थिर:** पिछले छह वर्षों से, इस क्षेत्र का निर्यात 40 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर स्थिर रहा है।
- **स्केल की कमी:** बांग्लादेश में औसतन प्रति फैक्ट्री कम से कम 500 मशीनें हैं, जबकि भारत में कपड़ा इकाइयों का औसत आकार केवल 100 है, जो काफी छोटा है।
- **विदेशी निवेश की कमी:** एक चिंता यह है कि ऊपर बताए गए मुद्दों के कारण कपड़ा व्यवसाय में विदेशी निवेश की कमी है।

कपड़ा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल:

- **नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन:** यह राष्ट्र को क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करते हुए घरेलू तकनीकी टेक्सटाइल खपत को बढ़ाने का प्रयास करता है। 2024 तक, यह घरेलू बाजार के आकार को $40 बिलियन और $50 बिलियन अमरीकी डालर के बीच बढ़ाने की उम्मीद करता है।
- **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS):** कपड़ा उद्योग की प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 2015 में "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)" को मंजूरी दी।
- **इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्कीम (SITP)** का उद्देश्य छोटे और मध्यम आकार के टेक्सटाइल व्यवसाय के मालिकों को टेक्सटाइल पार्कों में निवेश करने में मदद करना है, इसके लिए पार्कों के शीर्ष बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **SAMARTH (कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना):** सरकार ने प्रशिक्षित लोगों की कमी को दूर करने के लिए कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना (SCBTS) शुरू की है।
- **नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम (NERTPS)** एक ऐसा कार्यक्रम है जो बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता के साथ कपड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों का समर्थन करता है।
- **पावर-टेक्स इंडिया:** इसमें अभिनव पावर-लूम वस्त्र अनुसंधान और विकास, नए बाजार, ब्रांडिंग, सब्सिडी और श्रमिक कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं।
- **रेशम समग्र योजना** घरेलू स्तर पर उत्पादित रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाकर आयातित रेशम पर देश की निर्भरता को कम करना चाहती है।
- **ICARE जूट:** यह पायलट पहल, जिसे 2015 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य जूट उत्पादकों को रियायती कीमतों पर प्रमाणित बीजों की पेशकश करके और जल-प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में हाल ही में विकसित कई तकनीकों को लोकप्रिय बनाकर उनकी चुनौतियों से उबरने में मदद करना है।
- **पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क:** इसका उद्देश्य कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना है।

आगे की राह

भारत को एक उपयुक्त नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग हमारी ऊर्जा परिवर्तन प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में योगदान दे

सके। स्थायी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अच्छी नियामक प्रथाओं को अपनाना और गुणवत्ता, अनुपालन और निवेश पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। इस भाग के रूप में, हमें फेंके गए वस्त्रों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों की आवश्यकता है। यह देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आय असमानताओं को देखते हुए महत्वपूर्ण है। हाल ही में, बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स ने ऊर्जा, पानी और संसाधनों के संरक्षण में मदद करने के लिए 'ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग' प्रथा की शुरुआत की। कपड़ा उद्योग की स्थिरता से निपटने के लिए भारत इस तरह की पहल कर सकता है। कपड़ा उद्योग को टिकाऊ बनाने के लिए पुनर्योजी जैविक खेती, टिकाऊ विनिर्माण ऊर्जा (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग किया जाता है) और चक्रीयता को अपनाने की आवश्यकता है। भारत सरकार परियोजना के सतत संकल्प के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय समावेशन में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की भूमिका

संदर्भ: हाल के दिनों में, माइक्रोफाइनेंस संस्थान परिचालन दक्षता बढ़ाने, अंडरराइटिंग मॉडल में सुधार करने और खर्चों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को तेजी से अपना रहे हैं।

माइक्रोफाइनेंस के बारे में:

- यह एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो बेरोजगार या निम्न-आय वाले व्यक्तियों या ग्रुप को प्रदान की जाती है, जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं की कोई पहुंच नहीं होती है।
- माइक्रोफाइनेंस लोगों को उचित लघु व्यवसाय ऋण सुरक्षित रूप से लेने की अनुमति देता है, और इस तरीके से जो नैतिक उधार प्रथाओं के अनुरूप हो।
- "माइक्रोफाइनेंसिंग" शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1970 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान किया गया था, जिसकी स्थापना मुहम्मद यूनुस ने की थी।
- आज, भारत के लगभग 85 प्रतिशत जिलों में माइक्रोफाइनेंस उपलब्ध है, जिसमें दो लाख से अधिक फ्रंटलाइन कर्मचारी क्रेडिट और संबंधित सेवाओं का वितरण कर रहे हैं।

माइक्रोफाइनेंस के लाभ:

- **वित्तीय समावेशन:** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोफाइनेंस सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक के रूप में उभरा है।
    - यह गरीब और कम आय वाले परिवारों को गरीबी से बाहर आने में सक्षम बनाता है, महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनने में मदद करता है , निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ जाती है और सामूहिक भलाई की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगती है।
- **समांवेशी विकास:** माइक्रोफाइनेंस अंतिम व्यक्ति तक ऋण उपलब्ध कराकर समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए, पिरामिड के निचले भाग में रहने वालों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है।
    - माइक्रोफाइनेंस ऋण सबसे गरीब लोगों को वित्तीय पहुंच प्रदान करते हैं जो उनमें से कई को नए व्यवसाय शुरू करने, मौजूदा व्यवसायों को विकसित करने, खराब मौसम और बीमारी के कारण होने वाले झटकों के खिलाफ बीमा करने और सुचारू उपभोग करने की अनुमति देता है।
- **तकनीक को अपनाना:** एमएफआई (माइक्रोफाइनेंस संस्थान) परिचालन दक्षता बढ़ाने, अंडरराइटिंग मॉडल में सुधार करने और ग्राहक-केंद्रितता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खर्चों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को तेजी से अपना रहे हैं।
- स्थानीय भाषाओं में ऑडियो-विजुअल सामग्री का व्यापक रूप से वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- **अंडरराइटिंग मॉडल में सुधार:** माइक्रोफाइनेंस के लिए एक अलग क्रेडिट ब्यूरो लगभग एक दशक पहले स्थापित किया गया था।
    - एमएफआई और क्रेडिट ब्यूरो के गहन प्रयासों से मजबूत डेटाबेस का विकास हुआ है और क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट अब अंडरराइटिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है।
- **माइक्रोफाइनेंस की पहुंच का विस्तार:** पहुंच के संदर्भ में, माइक्रोफाइनेंस संचालन 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को कवर करता है।
    - क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का सबसे बड़ा हिस्सा 37 प्रतिशत है, इसके बाद दक्षिण का 27 प्रतिशत और पश्चिम का 15 प्रतिशत है।
    - इस प्रकार, जीवन और आजीविका को प्रभावित करने में माइक्रोफाइनेंस की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। जबकि माइक्रोफाइनेंस देश के लगभग सभी नुक्कड़ और कोनों में मौजूद है , भौगोलिक वितरण के संदर्भ में, ऋण पोर्टफोलियो का 82 प्रतिशत केवल दस राज्यों में केंद्रित है।
- **मजबूत ग्राहक सुरक्षा:** माइक्रोफाइनेंस के लिए आरबीआई के नियम ग्राहक सुरक्षा के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करते हैं।

- यह ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त, स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) द्वारा समर्थित है।
- एसआरओ विनियमों के कार्यान्वयन में एमएफआई का समर्थन करता है, क्षमता निर्माण के लिए पहल करता है, नियमित मार्गदर्शन और निगरानी के माध्यम से शासन में सुधार करता है और क्षेत्र स्तर की चुनौतियों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

- **डिजिटलीकरण पहल:** डिजिटलीकरण की पहल को स्मार्टफोन के तेजी से प्रसार और लेन-देन के डिजिटल मोड के साथ उधारकर्ताओं की बढ़ती सुविधा के साथ जोड़ा गया है।
  - आज, लगभग 100 प्रतिशत ऋण डिजिटल रूप से सीधे उधारकर्ताओं के बैंक खाते में वितरित किए जाते हैं और भुगतान की बढ़ती संख्या भी डिजिटल रूप से की जा रही है।

सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की चुनौतियाँ:

- **खंडित आंकड़े (Fragmented Data):** समग्र ऋण खाते बढ़ रहे हैं, जबकि ग्राहकों के गरीबी-स्तर पर इन ऋणों का वास्तविक प्रभाव स्पष्ट नहीं है क्योंकि एमएफआई ग्राहकों के सापेक्ष गरीबी-स्तर में सुधार के आंकड़े खंडित हैं।
- **कोविड-19 का प्रभाव:** इसने एमएफआई क्षेत्र को प्रभावित किया है, संग्रह पर प्रारंभिक प्रभाव पड़ा है और संवितरण पर अभी तक कोई सार्थक जोर नहीं दिया गया है।
- **सामाजिक उद्देश्य की अनदेखी:** विकास और लाभप्रदता की अपनी खोज में, एमएफआई का समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के जीवन में सुधार लाने का सामाजिक उद्देश्य धीरे-धीरे क्षीण होता जा रहा है।
- **गैर-आय सृजित उद्देश्यों के लिए ऋण:** गैर-आय सृजित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए ऋणों का अनुपात आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि से बहुत अधिक हो सकता है जो एमएफआई के कुल ऋणों का 30% है।
  - इन ऋणों की अवधि कम होती है और ग्राहकों की आर्थिक रूपरेखा को देखते हुए, यह संभावना है कि वे जल्द ही पहले भुगतान के लिए एक और ऋण लेने के दुष्चक्र (vicious debt trap) में खुद को पाते हैं।

आगे की राह

माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम में, पिछले दशक में भारत में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। हालाँकि, अधिकांश माइक्रोफाइनेंस सेवा प्रदाताओं का ध्यान वित्तीय सेवाओं की गहराई, गुणवत्ता और व्यवहार्यता पर कम ध्यान देने के बजाय माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने पर रहा है। आरबीआई को सभी संस्थानों को 'सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड' के माध्यम से समाज पर उनके प्रभाव की निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

कार्बन ट्रेडिंग

चर्चा में क्यों: संसद ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक -2022 पारित किया जो केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना स्थापित करने और निर्दिष्ट ऊर्जा उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैर-जीवाश्म स्रोतों की न्यूनतम मात्रा निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाता है।

संदर्भ :

- जब ऊर्जा परिवर्तन की बात आई तो भारत ने नेतृत्व किया था।
- UNFCCC के तहत भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार, जैसा कि पिछले साल COP-26 में पीएम द्वारा दिया गया था, लक्ष्य उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती करना और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 50% हासिल करना है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक-2022

- यह बिल ऊर्जा संरक्षण एक्ट-2001 में संशोधन करता है।
- इसमें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) नियामक होगा और कार्बन मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- ऊर्जा संरक्षण और स्थिरता कोड के अनुपालन के लिए विधेयक में बड़ी बिल्डिंग्स को शामिल किया गया है - जो 100 किलोवाट और उससे अधिक के जुड़े भार के साथ हैं।
- राज्यों को भवनों के एक व्यापक खंड को शामिल करने के लिए सीमा को कम करने का अधिकार दिया गया था।
- विधेयक में 100 किलोवाट की सीमा के तहत उन लोगों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है जो स्वेच्छा से ऊर्जा संरक्षण तंत्र को प्रस्तुत करना चाहते हैं।

कार्बन ट्रेडिंग क्या है?

- कार्बन ट्रेडिंग परमिट और क्रेडिट खरीदने व बेचने की बाजार आधारित प्रणाली है। यह परमिट धारक को कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है।
- यह एक बाजार आधारित प्रणाली है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली ग्रीनहाउस गैसों को कम करना है, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड।
- एक उत्सर्जन व्यापार योजना (कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम) योजना के तहत विनियमित किए जा रहे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर एक नियामक

सीमा या 'कैप' निर्धारित करती है।

- एक टन कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन के अधिकार को अक्सर कार्बन 'क्रेडिट' या कार्बन 'भत्ता' कहा जाता है।
- मोटे तौर पर दो प्रकार के कार्बन बाज़ार हैं: अनुपालन और स्वैच्छिक।
- उदाहरण - यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS)
- वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) अपनाया गया।
- विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं ने कार्बन क्रेडिट उत्पन्न किया है जिसका उपयोग औद्योगिक देशों द्वारा उनके उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है।

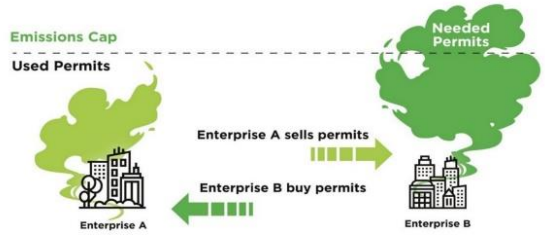

महत्व:

- मौजूदा बाजारों का दोहन करके वर्तमान और भविष्य की जलवायु महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद करना।
- विकास सह-लाभ लाना: वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड परमिट का व्यापार अमेरिका में अम्ल वर्षा को सीमित करने में मदद करता है।
- महंगे प्रत्यक्ष नियमों और अलोकप्रिय कार्बन करों की तुलना में कार्बन ट्रेडिंग को लागू करना बहुत आसान है।
- यदि क्षेत्रीय कैप और व्यापार योजनाओं को विश्व स्तर पर मजबूत कार्बन मूल्य के साथ जोड़ा जाता है, तो यह दुनिया को डीकार्बोनाइज करने में मदद करने के लिए अपेक्षाकृत कष्ट-मुक्त (pain-free) और तेज़ तरीका हो सकता है।
- फंसी हुई संपत्तियों के जोखिम को कम करके व्यवसायों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ावा देना।

चुनौतियां:

- कार्बन डाईआक्साइड जैसे किसी आंतरिक मूल्य के बिना बाजार बनाना मुश्किल है।
- कमी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है - और आपको उत्सर्जन के अधिकार को सख्ती से सीमित करना होगा ताकि इसका व्यापार किया जा सके।
- दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग योजना, ईयू ईटीएस, में राजनीतिक हस्तक्षेप ने परमिटों की अधिकता उत्पन्न कर दी है।
- भ्रष्टाचार के कारण, कार्बन क्रेडिट अक्सर मुफ्त में दिए जाते हैं, जिसके कारण कीमत में गिरावट आई है और उत्सर्जन में कोई प्रभावी कमी नहीं आई है।
- एक अन्य समस्या यह है कि गरीब देशों में प्रदूषण में कमी के भुगतान से प्राप्त ऑफसेट परमिट को व्यापार करने की भी अनुमति है।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इन परमिटों का महत्व संदिग्ध है और समग्र कैप और व्यापार योजना की प्रभावशीलता भी कम हो गई है।
- ग्रीनवॉशिंग- जिसमें कंपनियां अपने ग्रीन क्रेडेंशियल्स का झूठा प्रचार करती हैं, उदाहरण के लिए, जलवायु-तटस्थ उत्पादों या सेवाओं की गलत व्याख्या शामिल है।
- जीएचजी उत्सर्जन में कमी की दोहरी गणना।

आगे की राह

- आईपीसीसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों को 2030 तक 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक की आवश्यकता होगी, ताकि वे अपने जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों (जैसा कि उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, या एनडीसी में सूचीबद्ध है) के आधे से भी कम वित्त पोषण कर सकें।
- एनडीसी के कार्यान्वयन के लिए कार्बन वित्त महत्वपूर्ण होगा, और पेरिस समझौता अनुच्छेद 6 के माध्यम से ऐसे बाजार तंत्र के उपयोग को सक्षम बनाता है।
- एनडीसी के 83 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तंत्र का इस्तेमाल करने की मंशा जताते हैं।

भारत में उर्वरक क्षेत्र

चर्चा में क्यों : उर्वरक विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान यूरिया की बिक्री में पिछले वर्ष के इसी सात

महीनों की तुलना में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे भी अधिक, 16.9 प्रतिशत, डीएपी की बिक्री में वृद्धि रही है।

SALE OF FERTILISERS IN LAKH TONNES

	APR-OCT 2021	APR-OCT 2022	% GROWTH
Urea	186.273	193.112	3.67
DAP	55.612	65.032	16.94
MOP*	16.877	8.792	-47.91
NPKS	71.875	57.553	-19.93
SSP	34.815	31.678	-9.01

*For direct application

संदर्भ:

- लंबे समय से, भारत का उर्वरक क्षेत्र यूरिया के अत्यधिक उपयोग से विकृतियों से भरा हुआ है।
- लेकिन अब, एक दूसरा उर्वरक है - डाय-अमोनियम फॉस्फेट या डीएपी - जो कम मूल्य निर्धारण के कारण अधिक आवेदन की एक समान घटना प्रदर्शित कर रहा है।
- इसलिए, जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन में उर्वरकों के संतुलित उपयोग की आवश्यकता है।

उर्वरक क्षेत्र:

- तीन बुनियादी प्रकार के उर्वरकों का उपयोग किया जाता है- यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी)।
- यूरिया सबसे अधिक उत्पादित (86 प्रतिशत), सबसे अधिक खपत (74 प्रतिशत हिस्सा), और सबसे अधिक आयातित (52 प्रतिशत) है।
- यह सबसे अधिक फिजिकली नियंत्रित उर्वरक है और सबसे बड़ी सब्सिडी (कुल उर्वरक सब्सिडी का लगभग 70 प्रतिशत) प्राप्त करता है।
- डीएपी और एमओपी उत्पादकों और आयातकों को 4:2:1 अनुपात में N, P और K के फार्मूले के आधार पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy-NBS) प्राप्त होती है।
- चीन के बाद भारत विश्व में उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- 2022 में भारतीय उर्वरक बाजार 28.56 अरब अमेरिकी डॉलर था और 2028 में 41.08 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए 6.25% सीएजीआर दर्ज करने का अनुमान है।
- यूरिया और डीएपी की बिक्री बढ़ रही है जबकि अन्य उर्वरकों की बिक्री घट रही है।

इस क्षेत्र में मुद्दे:

- उच्च सरकारी सब्सिडी जैसे कि यूरिया और डीएपी पर जीडीपी का 5 प्रतिशत, यह खाद्य पदार्थ के बाद दूसरी सबसे अधिक है।
- कंपनियां एमआरपी पर बेचने के लिए बाध्य हैं, उनके उत्पादन की उच्च लागत या केंद्र द्वारा सब्सिडी के रूप में आयात की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भारी आयात निर्भरता:

- संपूर्ण पोटाश आवश्यकता, लगभग 90 प्रतिशत फॉस्फेटिक आवश्यकता और 20 प्रतिशत यूरिया आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।
- देश में नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी) और पोटेशियम (के) का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में 4:2:1 के आदर्श NPK उपयोग अनुपात से तेजी से विचलित हुआ है।
- इससे मिट्टी की गुणवत्ता बिगड़ती है।
- **अनुप्रयोग में असंतुलन:** MOP, जिसमें 60% पोटेशियम होता है, की MRP अधिक होती है, इसलिए किसानों के पास इसे लागू करने के लिए वर्तमान में कोई प्रोत्साहन नहीं है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** इनके उपयोग के कारण पोषक तत्व असंतुलन - अन्य, अधिक महंगे उर्वरकों के अनुपात में नहीं - मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए निहितार्थ हो सकते हैं, अंततः फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकते हैं।
- भारतीय उर्वरक बाजार खंडित है, जिसमें शीर्ष पांच कंपनियों का 28.93% हिस्सा है।

काला बाजारी और भ्रष्टाचार:

- यूरिया अत्यधिक विनियमित है और इसे केवल कृषि के लिए सब्सिडी दी जाती है।
- यह ब्लैक मार्केट में बनायी जाती है जो छोटे किसानों पर असमान रूप से बोझ डालता है; इसकी उत्पादन अक्षमता को प्रोत्साहित करता है, इसका अति-उपयोग, मिट्टी की गुणवत्ता को कम करने और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।

आगे की राह

- उर्वरक सब्सिडी बहुत महंगी होती है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.8 प्रतिशत है।
- ये यूरिया के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, ग्रामीण आय, कृषि उत्पादकता को कम करता

है, और इस प्रकार आर्थिक विकास होता है।

- उर्वरक क्षेत्र में सुधार से न केवल किसानों को मदद मिलेगी और क्षेत्र में दक्षता में सुधार होगा। इससे यह भी पता चलेगा कि भारत बाहर निकलने की उन बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार है, जो अन्य क्षेत्रों में सुधारों में बाधक हैं।

पुनर्योजी कृषि

संदर्भ: पुनर्योजी खेती के तरीकों का पालन करने वाले मध्य प्रदेश के किसानों का मानना है कि इससे उनकी लगातार सिंचाई की आवश्यकता कम होती जा रही है तथा पानी और ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है।

Promising numbers

Trials of regenerative agriculture in Madhya Pradesh and Maharashtra have saved 14.5 billion litres of water

Activities followed under regenerative agriculture	Water saved across farms (billion litres)	Share (%) in total saving
Change in cropping pattern	5.53	37.0
Dry sowing	4.01	26.8
Soil fertility interventions	3.03	20.2
Drip irrigation	1.16	7.7
Change in crop variety	0.99	6.6
System of wheat intensification, Line sowing	0.21	1.4
Sprinkler	0.03	0.3
Total	14.5	100

Source: Samaj Pragati Sahyog

पुनर्योजी कृषि के बारे में:

- यह एक कृषि और चराई प्रथा है जो जलवायु परिवर्तन को उलट कर, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों के पुनर्निर्माण और खराब मिट्टी की जैव विविधता को बहाल करके लाभान्वित करती है।
- इसका उद्देश्य मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाकर भविष्य में बेहतर कृषि के लिए मिट्टी और पानी में सुधार करना है।
- यह प्राकृतिक आदानों, खाद, मल्चिंग और कृषि के तरीकों जैसे फसल रोटेशन, विविधीकरण, बहु-फसल, विविध और देशी किस्मों की बुवाई के द्वारा रासायनिक-मुक्त खेती के तरीकों का उपयोग करता है।
- प्राकृतिक आदान मिट्टी की संरचना और इसकी जैविक कार्बन सामग्री को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
- एक साथ या बारी-बारी से पानी की खपत करने वाली और पानी की कम खपत वाली फसलें लगाने से सिंचाई की आवृत्ति और तीव्रता कम हो जाती है।

भारत में पुनर्योजी कृषि की आवश्यकता:

- **मिट्टी का क्षरण:** खाद्य उत्पादन को अधिक करने के लिए भारी मशीनरी, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग सहित कृषि आज मिट्टी के क्षरण और नुकसान में योगदान दे रही है।
    - पुनर्योजी कृषि संगठन रीजनरेशन इंटरनेशनल के अनुसार, 50 वर्षों के भीतर, दुनिया को खिलाने के लिए पर्याप्त मिट्टी नहीं बची होगी।
- **जलवायु परिवर्तन:** सघन खेती भी मिट्टी में प्राकृतिक रूप से जमा CO_2 को मंथन करती है और इसे वातावरण में छोड़ती है। यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है जो जलवायु परिवर्तन को चला रहा है।
    - संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अनुसार वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कृषि का योगदान एक तिहाई से अधिक है।
- **चरम घटनाएँ:** क्षतिग्रस्त मिट्टी और अपरदित भूमि वातावरण को बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है, जो कि पृथ्वी के गर्म होने के साथ-साथ आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ रही हैं।

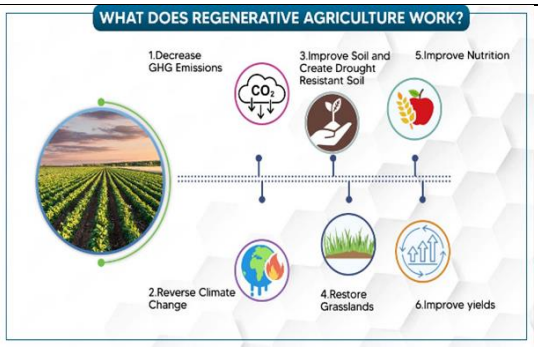

कृषि से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत हर साल 251 क्यूबिक किमी. या दुनिया की भूजल निकासी का एक-चौथाई से अधिक जल निकालता है, इसके 90% का उपयोग कृषि के लिये किया जाता है।
- **उत्पादन में कोई वृद्धि न होना :** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के एक अध्ययन से पता चला है कि देश में 39 मिलियन हेक्टेयर (हेक्टेयर) से अधिक क्षेत्र में गेहूं, चावल और मक्का के तहत पिछले एक दशक में कोई सुधार नहीं हुआ है।
- **भूजल:** 1960 के दशक की हरित क्रांति ने भारत को भुखमरी के कगार से उबार लिया लेकिन इस क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा भूजल का उपयोग करने वाला देश बना दिया।
    - लेकिन क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा भूजल निकालने वाला भी बना दिया।
- **मृदा स्वास्थ्य में गिरावट:** दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई), स्टेट ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया की 2022 की रिपोर्ट भारतीय मिट्टी में जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की गंभीर और व्यापक कमी को दर्शाती है।
- **वैज्ञानिक अध्ययन का अभाव:** नागरिक समाज संगठनों और किसानों के पास दीर्घकालिक अध्ययन करने की क्षमता नहीं है।

आगे की राह

भारत में, केंद्र सरकार पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा दे रही है जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग और लागत को कम करना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और गुजरात जैसे राज्यों ने भी इसे बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, स्वस्थ मिट्टी बेहतर जल भंडारण, संचरण, फ़िल्टरिंग और कृषि अपवाह को कम करने में मदद करती है। अध्ययनों ने स्थापित किया है कि प्रति 0.4 हेक्टेयर मृदा कार्बनिक पदार्थ (मृदा स्वास्थ्य का एक संकेतक) में एक प्रतिशत की वृद्धि से जल भंडारण क्षमता 75,000 लीटर से अधिक बढ़ जाती है।

इस प्रकार, पानी बचाने में पुनर्योजी कृषि की भूमिका को समझने के लिए ठोस शोध की आवश्यकता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष आगे नीतिगत उपायों और भविष्य की पहलों को सूचित करने में मदद करेंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कृषि कमोडिटी पर व्यापार प्रतिबंध का विस्तार किया

संदर्भ: हाल ही में, सेबी ने दो उत्पादों के डेरिवेटिव सहित सात कृषि जिंसों में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध को लगा दिया है, जो 20 दिसंबर, 2021 से लागू है।

- सेबी ने गैर-बासमती धान, गेहूं, चना, सरसों के बीज और इसके डेरिवेटिव, सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव, कच्चे पाम तेल और मूंग के व्यापार पर प्रतिबंध को इस चिंता पर बढ़ा दिया कि प्रतिबंध हटाने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में:

- वस्तु बाजार (commodity market) उस बाजार को कहते हैं जिसमें प्राथमिक अर्थव्यवस्था की वस्तुएँ खरीदी-बेची जाती हैं न कि निर्मित वस्तुएँ।
- सॉफ्ट वस्तुएं कृषि उत्पाद हैं जैसे कि गेहूं, कॉफी, कोको और चीनी।
- हार्ड वस्तुओं का खनन किया जाता है, जैसे सोना और तेल।

- कमोडिटी मार्केट में स्पॉट कीमतों, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और फ्यूचर्स पर ऑप्शंस का उपयोग करके फिजिकल ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग शामिल हो सकती है।
    - किसानों ने मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए सदियों से वस्तु बाजार में व्युत्पन्न व्यापार के एक सरल रूप का उपयोग किया है।
- वस्तुओं के व्यापार की मात्रा और भौतिक रूप में वस्तुओं के वास्तविक मूल्य में बहुत बड़ा अंतर है - यह कई प्रतिभागियों द्वारा की गई हेजिंग (hedging) के कारण है।

भारत में कमोडिटी मार्केट:

- **कमोडिटी मार्केट:** किसी अन्य मार्केट के समान, कमोडिटीज़ मार्केट या तो भौतिक या आभासी स्थान है, जहां इच्छुक पार्टियां वर्तमान या भविष्य की तिथि पर कमोडिटी (कच्चे या प्राथमिक उत्पाद) को ट्रेड कर सकती हैं। मूल्य आपूर्ति और मांग के आर्थिक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- **रेगुलेटर:** 2015 तक, बाजार को फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन द्वारा विनियमित किया गया था, जिसे अंततः वाणिज्यिक निवेश के लिए एकीकृत नियामक वातावरण बनाने के लिए सेबी के साथ विलय कर दिया गया था।
- कमोडिटी मार्केट के प्रकार: आमतौर पर, कमोडिटी ट्रेडिंग या तो डेरिवेटिव मार्केट या स्पॉट मार्केट में होती है-
    - स्पॉट मार्केट को "कैश मार्केट" या "फिजिकल मार्केट" के रूप में भी जाना जाता है जहां व्यापारी भौतिक वस्तुओं का आदान-प्रदान करते हैं, और वह भी तत्काल डिलीवरी के लिए।
    - भारत में डेरिवेटिव बाज़ार में दो प्रकार के कमोडिटी डेरिवेटिव शामिल हैं: फ़्यूचर्स और फ़ॉरवर्ड्स; ये डेरिवेटिव अनुबंध अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में उपस्थित बाजार का उपयोग करते हैं और भविष्य में उस मूल्य के लिए ओनर को नियंत्रण देते हैं जिस पर वर्तमान में सहमति हुई है।
        - जब अनुबंध समाप्त हो जाते हैं, वस्तु या संपत्ति भौतिक रूप से वितरित की जाती है।

इन वस्तुओं पर प्रतिबंध के कारण:

- केंद्र, विशेष रूप से और सेबी ने मुद्रास्फीति पर चिंताओं पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है।
- जहां पिछले साल खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण प्रतिबंध लगाया गया था, वहीं इस साल चावल और गेहूं की ऊंची कीमतों ने केंद्र को इसे बढ़ाने के लिए मजबूर किया है।
- पिछले एक साल में चावल की कीमतों में 7.5 फीसदी और गेहूं की कीमतों में 15.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- हालांकि उपभोक्ता मुद्रास्फीति पिछले महीनों में छह प्रतिशत से अधिक के उच्च स्तर से नवंबर में घटकर 5.9 प्रतिशत हो गई, लेकिन आरबीआई को लगता है कि यह "नीचे लेकिन बाहर नहीं" है।

बाजार में नोटबंदी का असर:

- सरसों के बीज और इसके डेरिवेटिव, सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव, और कच्चे पाम तेल की कीमतों में गिरावट आई है।
- दूसरी ओर, मूंग और चना की कीमतें साल भर पहले की अवधि की तुलना में वर्तमान में चावल और गेहूं की कीमतों की तुलना में अधिक चल रही हैं।
- तिलहन की कीमतों में मुख्य रूप से गिरावट आई है क्योंकि खाद्य तेल की आपूर्ति अब चिंता का विषय नहीं रही है।

कमोडिटी ट्रेडिंग के लाभ और आवश्यकता:

- महंगाई, स्टॉक मार्केट क्रैश आदि से सुरक्षा
- पारदर्शिता और उचित मूल्य खोज
- हाई लिवरेज फैसिलिटी
- कोई इनसाइडर ट्रेडिंग न होना
- मौसमी पैटर्न और विविधीकरण
- कोई प्रतिपक्ष जोखिम नहीं (चूंकि क्लीयरिंग हाउस है)
- कार्टेलाइजेशन के जोखिम को कम करना

कमोडिटी ट्रेडिंग के नुकसान:

- **मुद्रास्फीति के लिए जरूरी प्रतिरक्षा न होना :** कीमत की अस्थिरता का मतलब है कि जब कीमत बढ़ती या घटती है, तो वस्तु की आपूर्ति अपरिवर्तित रहती है।
- **उच्च अस्थिरता:** वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक अस्थिर होती हैं और मांग तथा आपूर्ति कारकों पर निर्भर करती हैं। वस्तुओं की आपूर्ति और मांग मूल्य अयोग्य रहती हैं।
- **विविधीकरण के लिए आदर्श न होना :** आम सहमति यह है कि वस्तुओं की कीमतों और शेयरों की कीमतों के बीच एक नकारात्मक

या निम्न सहसंबंध है।

आगे की राह

इसलिए, कभी-कभी ये प्रतिबंध भारतीय कमोडिटी बाजारों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जिससे देश में व्यापार करने में सरल धारणा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है और इस तरह के विस्तार के लिए शोध किया जाना चाहिए।

कमोडिटी डेरिवेटिव किसानों, प्रोसेसर, मिलर्स, भौतिक बाजारों में व्यापारियों और किसान उत्पादक संगठनों में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन पर महत्वपूर्ण संकेत देते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता

संदर्भ: भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (IndAus ECTA) हाल ही में प्रभाव में आया है। ईसीटीए पर 2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और 21 नवंबर, 2022 को इसकी पुष्टि की गई थी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार के बारे में:

- भारत 2017-18 में कुल ऑस्ट्रेलियाई व्यापार के 3.6% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए $ 29 बिलियन के माल और सेवाओं में व्यापार के साथ ऑस्ट्रेलिया का 5 वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जिसमें निर्यात $ 8 बिलियन और आयात $ 21 बिलियन है।
- **भारतीय निर्यात:** ऑस्ट्रेलिया को भारत के मुख्य निर्यात में रिफाइंड पेट्रोलियम, दवाएं, होवर-ट्रेन सहित रेलवे वाहन, मोती और रत्न, आभूषण और बने-बनाए वस्त्र लेख शामिल हैं।
- **भारतीय आयात:** आयात में कोयला, तांबा अयस्क और सांद्र, सोना, सब्जियां, ऊन और अन्य पशु बाल, फल और मेवे, दाल और शिक्षा संबंधी सेवाएं शामिल हैं।

इंडो-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के बारे में:

भारत के लिए लाभ:

- ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनी टैरिफ लाइनों के 100% पर तरजीही बाजार पहुंच से भारत को लाभ होगा, जिसमें भारत को निर्यात हित के सभी श्रम-गहन क्षेत्र शामिल हैं, जैसे रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, फर्नीचर अन्य, वाणिज्य मंत्रालय ने कहा।

ऑस्ट्रेलिया के लिए लाभ:

- दूसरी ओर भारत ऑस्ट्रेलिया को अपनी 70% से अधिक टैरिफ लाइनों पर अधिमान्य पहुँच की पेशकश करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की निर्यात हेतु ब्याज दरें शामिल हैं जो मुख्य रूप से कच्चे माल जैसे- कोयला, खनिज अयस्क तथा वाइन और और बिचौलिये आदि हैं।

कुछ उत्पादों के लिए सुरक्षा:

- कृषि उत्पादों और डेयरी क्षेत्र जैसे उत्पाद - जो भारत के लिए बहुत संवेदनशील थे और जिनके बिना ऑस्ट्रेलिया ने पहले कभी समझौता नहीं किया - को संरक्षित किया गया है।

रोजगार सृजन:

- अनुमान है कि ईसीटीए के तहत भारत में अतिरिक्त 10 लाख नौकरियां सृजित होंगी।

वीजा कोटा:

- भारतीय योग शिक्षक और रसोइया वार्षिक वीज़ा कोटा के साथ लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

अध्ययन के बाद का वर्क वीजा:

- ईसीटीए के तहत 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को अध्ययन के बाद के कार्य वीजा (18 महीने से 4 साल के लिए) का लाभ मिलेगा।

दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए):

- ऑस्ट्रेलियाई संसद ने दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, यह एक ऐसा कदम है जो भारतीय आईटी क्षेत्र को उस बाजार में काम करने में मदद करेगा।
- यह ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों की अपतटीय आय पर कराधान को रोक देगा।

चुनौतियां:

- भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते के कारण ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार घाटा 2001-02 से बढ़ रहा है।

आगे की राह

- साझा मूल्य, साझा हित, साझा भूगोल और साझा उद्देश्य भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को गहरा करने का आधार हैं तथा हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग एवं समन्वय ने गति पकड़ी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की दृष्टि साझा करते हैं।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करके और एकतरफा या जबरदस्त कार्रवाई के बजाय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के द्वारा समुद्र के सहकारी उपयोग में विश्वास करते हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ और सामरिक संबंधों को बढ़ाएगा।

भारत और G20 अध्यक्षता

संदर्भ: 1 दिसंबर को, भारत ने इंडोनेशिया से पदभार ग्रहण करते हुए G20 फोरम की अध्यक्षता ग्रहण की। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे "भारत के लिए एक बड़ा अवसर" कहा।

G20 का इतिहास क्या है?

- G20 फोरम की स्थापना 1999 में वाशिंगटन डीसी में एक बैठक के बाद सात देशों - कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा की गई थी।
- एकजुट करने वाला कारक 1997-98 का दक्षिण-पूर्व एशिया वित्तीय संकट और उसके परिणाम थे।
    - गौरतलब है कि जी-20 की स्थापना एशिया महाद्वीप में 1997-98 के दौरान शुरू हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए हुई थी। उस दौरान जब थाईलैंड ने अपनी मुद्रा को अमेरिकी डालर की तुलना में नियंत्रित करने की कोशिश की, तो उसके दुष्प्रभाव फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आदि देशों पर पड़े थे।
- G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- समूह की पहली वार्षिक बैठक के लिए प्रतिनिधि बर्लिन, जर्मनी में मिले। G20 नेताओं की पहली बैठक 1999 में हुई थी, और इसे 2008 में सरकार / राज्य के प्रमुखों के स्तर तक बढ़ा दिया गया था।
- G20 का प्राथमिक उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना था।
- 2009 में, G20 को "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच" नामित किया गया था।
- फोरम ने शुरुआत में मैक्रोइकॉनॉमिक्स से संबंधित मामलों को निपटाया, लेकिन वर्षों से, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों से संबंधित मुद्दों को कवर करने के लिए इसका विस्तार हुआ है।
- G20 को अधिक "अभिजात्य" G-7 (तब रूस के कारण G-8), और अधिक बोझिल 38-सदस्यीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के बीच एक स्वीकार्य माध्यम माना जाता था।
- पिछले दो दशकों में, वैश्विक आर्थिक संतुलन बदल गया है, और G-20 को वैश्विक नेतृत्व के एक अधिक प्रतिनिधि और समतावादी समूह के रूप में देखा गया है, और 2008 के वैश्विक वित्त संकट और बैंकिंग पतन के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने में विशेष रूप से उपयोगी था।
- वर्ष 2009 के अपने शिखर सम्मेलन में, G20 ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए प्राथमिक स्थान घोषित किया। इस समूह का मान बाद के दशक के दौरान बढ़ा है, और विश्लेषकों द्वारा इसे काफी वैश्विक प्रभाव के रूप में मान्यता दी गई है।
- वर्तमान समय में G20 सदस्य दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और ग्रह की 60% आबादी के लिए जिम्मेदार हैं।

G20 कैसे काम करता है?

- इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
- G20 के तहत प्रक्रियाओं को दो समानांतर ट्रैक्स में विभाजित किया गया है - फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्रियों और सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा किया जाता है, जो साल भर मिलते हैं।
- शेरपा, जो नेताओं के निजी दूत होते हैं, शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। वे साल भर चर्चा की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा मदों पर चर्चा करते हैं और जी20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं।
- शिखर सम्मेलनों और शेरपा बैठकों (जो बातचीत और आम सहमति बनाने में मदद करते हैं) के अलावा, पूरे वर्ष कई अन्य कार्यक्रम और समूह बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।
- विशिष्ट विषयों के आसपास तैयार किए गए कार्यकारी समूह दोनों ट्रैकों के भीतर काम करते हैं। इनमें सदस्य राष्ट्रों के संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि और आमंत्रित/अतिथि देश भी शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कार्यकारी समूहों में भाग लेते हैं।
- इस वर्ष के कार्यकारी समूह वित्तीय समावेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण और जलवायु स्थिरता जैसे विषयों को कवर करते

हैं।

G20 अध्यक्षता कैसे काम करती है?

- G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्यों के बीच घूमती है, और अध्यक्षता करने वाला देश, पिछले और अगले अध्यक्ष-धारक के साथ मिलकर G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 'ट्रोइका' बनाता है।
- भारत 1 दिसंबर को मौजूदा अध्यक्ष, इंडोनेशिया से शक्तिशाली जी20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और एक वर्ष के लिए पद धारण करेगा।
- भारत की अध्यक्षता के दौरान, भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील तिकड़ी बनाएंगे।
- यह पहली बार होगा जब तिकड़ी में तीन विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी।
- अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान, भारत पूरे भारत में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा।

G20 अध्यक्षता-राष्ट्र के रूप में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- भारत की G20 अध्यक्षता पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर है।
- G20 अध्यक्षता पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी, इस प्रकार हमारे देश के प्रत्येक भाग की विशिष्टता को सामने लाएगी।
- शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने और थीम तय करने के अलावा, G20 अध्यक्षता किसी औपचारिक शक्ति के साथ नहीं आती है।
- हालाँकि, भारत वसुधैव कुटुम्बकम (एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य), और LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के अपने दर्शन को विषय और घटना के लोगो के माध्यम से प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है।
- एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत की जी20 अध्यक्षता "दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास के लिए प्रयास कर रही है, जैसा कि हम इस अशांत समयों के माध्यम से एक स्थायी, समग्र, जिम्मेदार और समावेशी तरीके से नेविगेट करते हैं।"
- भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले आगंतुकों को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने और उन स्थानों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बड़ी संभावना है जहां G20 बैठकें आयोजित होगी।
- G20 प्रेसीडेंसी भी भारत को एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में अपनी साख को मजबूत करते हुए देखेगा जो भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों के लाभ के लिए अपने अद्वितीय डिजिटल सार्वजनिक सामान का लाभ उठा सकता है।
- लोगों के बेहतर जीवन के निर्माण के लिए G20 को जन-नेतृत्व वाले आंदोलन में बदलना संभावित रूप से भारत की G20 अध्यक्षता की एक स्थायी विरासत बन सकता है।
- चीन के साथ भारत की अपनी समस्याएं, जो G20 समूह का भी हिस्सा हैं, परस्पर विरोधी मुद्दों के प्रभावी निवारण के लिए एक संभावित मंच प्रदान करती हैं।
- भारत की G20 अध्यक्षता की दीर्घकालिक स्थायी विरासत G20 एजेंडे पर विकासशील दुनिया और ग्लोबल साउथ के हितों की प्राथमिकता होगी।
    - वैश्विक वित्तीय शासन संस्थानों को अधिक लोकतांत्रिक बनाना और विश्व व्यवस्था में चल रहे बदलावों का प्रतिनिधि बनाना भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक प्रमुख प्राथमिकता होगी।
    - विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएँ पश्चिम का गढ़ बनी हुई हैं और प्रासंगिक बने रहने के लिए उभरते और विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व और दायित्व प्रदान करने की आवश्यकता है।
    - चूंकि भारत बढ़ते वैश्विक तनाव के समय G20 का नेतृत्व कर रहा है, इसलिए इसके मूल में सुधारित बहुपक्षवाद के साथ एक समावेशी और न्यायसंगत विश्व व्यवस्था बनाने का नेतृत्व करना होगा।
- भारत की G20 अध्यक्षता कार्बन पदचिह्न को कम करने और परिवर्तनकारी परिवर्तनों के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में हरित ऊर्जा और डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के पक्ष में वैश्विक आख्यान को आकार देने का एक अभूतपूर्व अवसर है।
- भारत की G20 अध्यक्षता का उपयोग अपने विचार नेतृत्व की भूमिका और ध्रुवीकरण को कम करने के व्यापक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, संसाधनों को समावेशी तरीके से चैनलाइज़ करना, और विकासात्मक प्राथमिकताओं के पक्ष में ऑप्टिक्स को मजबूत करना।

मुक्त व्यापार समझौता शासन

संदर्भ: हाल के दिनों में, भारत सरकार सक्रिय रूप से देशों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का पालन कर रही है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के बारे में:

- यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है।
- एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिये बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किये जाते हैं।
- मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है।

विभिन्न प्रकार के आर्थिक जुड़ाव:

- **तरजीही व्यापार समझौता (पीटीए):** पीटीए में, दो या दो से अधिक भागीदार टैरिफ लाइनों की एक सहमत संख्या पर टैरिफ कम करने के लिए सहमत होते हैं। उन उत्पादों की सूची जिन पर भागीदार शुल्क कम करने के लिए सहमत होते हैं, सकारात्मक सूची कहलाती है। इंडिया मर्कोसुर पीटीए इसका एक उदाहरण है। हालांकि, सामान्य तौर पर पीटीए सभी व्यापारों को पर्याप्त रूप से कवर नहीं करते हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए):** एफटीए में, भागीदार देशों के बीच पर्याप्त द्विपक्षीय व्यापार को कवर करने वाली वस्तुओं पर शुल्क समाप्त कर दिया गया है; हालाँकि, प्रत्येक गैर-सदस्यों के लिए एक व्यक्तिगत टैरिफ संरचना बनाए रखता है।
    - उदाहरण के लिए भारत - श्रीलंका एफटीए।
- **कॉमन मार्केट:** कॉमन मार्केट द्वारा प्रदान किया गया एकीकरण सीमा शुल्क संघ द्वारा प्रदान किए गए एकीकरण से एक कदम गहरा है।
    - कॉमन मार्केट एक सीमा शुल्क संघ है जिसमें श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही की सुविधा, सदस्यों में तकनीकी मानकों का सामंजस्य आदि के प्रावधान हैं।
    - उदाहरण के लिए यूरोपियन कॉमन मार्केट एक उदाहरण है।
- **आर्थिक संघ:** आर्थिक संघ राजकोषीय/मौद्रिक नीतियों और साझा कार्यकारी, न्यायिक और विधायी संस्थानों के आगे सामंजस्य के माध्यम से विस्तारित एक कॉमन मार्केट है।
    - यूरोपीय संघ (ईयू) एक उदाहरण है।
- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए): ये शर्तें उन समझौतों का वर्णन करती हैं जिनमें आईपीआर, प्रतिस्पर्धा आदि सहित अन्य क्षेत्रों के साथ माल, सेवाओं और निवेश पर एक एकीकृत पैकेज शामिल है।
    - भारत कोरिया सीईपीए ऐसा ही एक उदाहरण है और इसमें व्यापार सुगमता और सीमा शुल्क सहयोग, निवेश, प्रतिस्पर्धा, आईपीआर आदि जैसे अन्य क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- **सीमा शुल्क संघ:** एक सीमा शुल्क संघ में, भागीदार देश आपस में जीरो शुल्क पर व्यापार करने का निर्णय ले सकते हैं, हालांकि वे शेष विश्व के विरुद्ध सामान्य टैरिफ बनाए रखते हैं।
    - दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, नामीबिया, बोत्सवाना और स्वाज़ीलैंड के बीच दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) का उदाहरण है।
    - यूरोपीय संघ भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

एफटीए का महत्व:

- एफटीए व्यवसायों और उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी मूल्य वाली वस्तुओं और सेवाओं, नई तकनीकों और नवीन प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक बेहतर पहुंच प्रदान करते हैं।
- एफटीए विदेशी निवेश से अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करते हैं।
- एफटीए क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं और व्यापारिक भागीदारों के बीच व्यापार और निवेश के लिए साझा दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं।

- एफटीए उन्नत व्यापार और निवेश के अवसर प्रदान कर सकते हैं जो कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।
- एफटीए मजबूत लोगों से लोगों (people-to-people) और व्यापार से व्यापार (business-to-business) संबंधों का समर्थन करते हैं जो एफटीए भागीदारों के साथ समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाते हैं।
- एफटीए समय के साथ व्यापार भागीदारों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करना जारी रखते हैं, जिसमें अंतर्निर्मित एजेंडा के माध्यम से चल रहे घरेलू सुधार और व्यापार उदारीकरण को प्रोत्साहित करना शामिल है।

एफटीए को अपनाने में प्रमुख चुनौतियां:

- **संरक्षणवादी प्रवृत्तियाँ:** "गैर-आवश्यक वस्तुओं" पर आयात शुल्क बढ़ाने की योजना जैसे कदम सरकार पर केवल संरक्षणवादी होने के आरोप को उजागर करेंगे।
  - 1991-92 के बाद पहले दो दशकों में टैरिफ दरों में भारी गिरावट देखी गई।
  - हालांकि, प्रवृत्ति को सत्तारूढ़ सरकार के तहत उलट दिया गया है, और औसत लागू आयात शुल्क वास्तव में बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** ये गैर-टैरिफ मुद्दे भारत के लिए अपने तुलनात्मक श्रम लाभ का फायदा उठाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **ध्यान में बदलाव:** ये एफटीए वार्ता जल्द ही समाप्त हो सकती है क्योंकि भारत का ध्यान भारत की जी20 अध्यक्षता से जुड़ी घटनाओं की श्रृंखला में बदल जाएगा।
- **प्रभावशाली लॉबियां का देरी होना:** किसान यूनियनों और ऑटो सेक्टर जैसे प्रभावशाली लॉबी समूहों से राजनीतिक पैरवी तेज हो सकती है।
- **गैर-टैरिफ मुद्दों को प्राथमिकता:** वर्तमान में चर्चा के तहत अधिकांश वार्ताओं में, जलवायु कार्रवाई, कार्बन उत्सर्जन और श्रम मुद्दों को व्यापार के मुद्दों पर प्राथमिकता दी जा रही है।
- **GSP (वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली):** वर्तमान में हम जीएसपी से लाभान्वित हो सकते हैं लेकिन यदि वे श्रम या पर्यावरण का हवाला देकर गैर-टैरिफ बाधा में आते हैं, तो यह मानकों, समायोजन, बाल श्रम का हवाला देते हुए एक मुद्दा बन जाता है।
  - भारत नवंबर 1975 से अमेरिका के जीएसपी कार्यक्रम का लाभार्थी रहा है, जिसके तहत लाभार्थी देशों को शुल्कों के अतिरिक्त बोझ के बिना अमेरिका को हजारों उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति है।
- **मंदी की स्थिति:** ये संभावित रूप से साझेदार देशों को गैर-टैरिफ संरक्षणवादी उपायों को ट्रिगर करने की पेशकश कर सकते हैं क्योंकि विकसित राष्ट्र मंदी की स्थिति में हैं।
- **पर्यावरणीय मुद्दे:** अमेरिका जैसे विकसित देशों ने गैर-टैरिफ-संबंधित मुद्दे के रूप में पिघले हुए स्टील के निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे को उठाया है।
  - भारत ज्यादातर लौह अयस्क से उत्पन्न इस्पात का उत्पादन करता है जो खनन से आता है।
  - अधिकांश विकसित देशों ने इसे स्क्रैप से उत्पन्न करने के तरीकों का सहारा लिया है जिसके परिणामस्वरूप कम कार्बन उत्सर्जन होता है। इस प्रकार, कार्बन समायोजन कर लगाया जा सकता है।
- **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र:** यूरोपीय संघ ने 2026 से लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और बिजली उत्पादन जैसे कार्बन-गहन उत्पादों पर कर लगाने के लिए CBAM का प्रस्ताव दिया है।
  - यूरोपीय संघ के आयातक उस कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन प्रमाणपत्र खरीदेंगे जिसका भुगतान यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के तहत किया गया था।

आगे की राह

व्यापार नीति के ढाँचे के साथ आर्थिक सुधार होने चाहिए जिसके परिणामस्वरूप एक खुली, प्रतिस्पर्धी और तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था हो। इसलिए, एफटीए की तलाश कर रहे देश को वैश्विक आर्थिक नेटवर्क में उद्यमियों को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए जो उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा का अनुशरण करने की अनुमति देता है। वाणिज्य समिति को एफटीए की जांच करने, समझौतों और वार्ताओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने, इस प्रकार विधायिका के लिए कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम सौंपा जाना चाहिए।

इतिहास, कला और संस्कृति

बी आर अम्बेडकर और महिला अधिकारिता

संदर्भ :

- मनु के पागलपन में, नारीवादी समाजशास्त्री शर्मिला रेगे का तर्क है कि पिछड़े वर्ग और दलित समुदायों के सदस्यों के रूप में फुले (माली जाति) और अंबेडकर (महार जाति) के जीवन के बीच अंतर को समझने में मुख्यधारा का नारीवाद कम पड़ता है।
- अधिकार, संसाधनों और स्थानों तक पहुंच, गरीबी और अपमान उन लोगों के लिए अलग हैं जो गांव की सीमाओं के बाहर रहने के लिए नियत हैं और जिन्हें भार ढोने वाले के रूप में माना जाता है।
- इसलिए, जाति-विरोधी संघर्ष और महिला सशक्तिकरण में अम्बेडकर की भूमिका का नजदीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए।

नारीवाद का अर्थ:

- नारीवाद राजनैतिक आन्दोलनों विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है जो राजनीतिक आर्थिक व्यक्तिगत और सामाजिक लैंगिक समानता को परिभाषित करने स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है।
- नारीवाद का रेखांकित आधार जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की समानता और न्याय की तलाश करना है और महिलाओं के लिए उन संसाधनों तक समान पहुंच के अवसर पैदा करना है जो पुरुषों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं।

भारत में नारीवादी आंदोलन:

चिपको आंदोलन (मार्च 1974)

- उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में गौरा देवी के नेतृत्व में 28 महिलाओं का एक समूह पेड़ों को गिरने से बचाने के लिए उनसे चिपक गया।
- आंदोलन ने अहिंसक विरोध की गांधीवादी सत्याग्रह शैली का अनुसरण किया और भविष्य के कई पर्यावरण आंदोलनों के लिए एक बेंचमार्क बन गया।

नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985)

- यह नर्मदा नदी पर बांधों से जुड़ी बहु-करोड़ की परियोजना के निर्माण के कारण 250,000 लोगों के विस्थापन पर केंद्रित था।
- नर्मदा बचाओ आंदोलन ने 1991 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त है।

रमाबाई अंबेडकर की भूमिका:

- रमाबाई अम्बेडकर को बाबा पिता के रूप में अम्बेडकर के साथ "रमाई" राम के साथ "आई" (मराठी में माँ) के रूप में जाना जाता है।
- वह उस सख्त मां की प्रतिनिधि हैं जिसे मजदूर वर्ग के परिवार जानते हैं।
- जब अंबेडकर कोलंबिया चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने घर चलाया, मजदूरी की और कभी-कभी भुखमरी का सामना किया।
- उसने जो किया वह केवल एक पत्नी का कर्तव्य नहीं था, बल्कि यह उसके समुदाय के लिए योगदान और सामाजिक परिवर्तन में साझेदारी थी।

अम्बेडकर - एक नारीवादी के रूप में:

- अम्बेडकर ने लोगों से मनुस्मृति को जलाने का आग्रह किया, जिसने महिलाओं और शूद्रों को अपमानित किया।
- वर्ष 1936 में एक भाषण में, जोगिनियों और देवदासियों के समुदायों के लिए - जो आम तौर पर दलित समुदाय से संबंधित थे - अम्बेडकर ने इन महिलाओं से आग्रह किया कि वे मंदिरों में यौवन लड़कियों को देवताओं को चढ़ाने की प्रतिगामी धार्मिक प्रथा से लड़ें।

नीति-निर्माता के रूप में:

द हिंदू कोड बिल

- इसने महिलाओं को पसंद से और जाति की सीमाओं से परे शादी करने का अधिकार देकर, उन्हें तलाक का अधिकार, और विरासत में संपत्ति का अधिकार देकर हिंदू घरेलू क्षेत्र में क्रांति ला दी।
- यह विधेयक हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि के रूप में एक खंडित, कमजोर अवतार (diluted avatar) में कानून बन गया।
- उच्च जाति के रूढ़िवादियों द्वारा विधेयक को रोके जाने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

- उनके प्रभाव ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, और 1961 के दहेज निषेध अधिनियम जैसे कई अन्य महिला-समर्थक अधिनियमों को पारित किया, क्रमशः महिलाओं को समान वेतन और दहेज के अपराधीकरण के लिए कानूनी रूप से हकदार बनाया।

महिला अधिकारों के कार्यकर्ता के रूप में:

- अंबेडकर का मानना था कि महिलाएं, एक बार अपने भाग्य की एजेंट बन जाने के बाद, जातिगत पितृसत्ता को समाप्त कर देंगी।
- उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न पर व्यापक रूप से लिखा और 'मूक नायक' और 'बहिष्कृत भारत' जैसे समाचार पत्रों की स्थापना की, जिनमें विशेष रूप से महिला-केंद्रित मुद्दों को शामिल किया गया था।
- अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए परिवार नियोजन के उपायों पर जोर दिया, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिनियमन को सुनिश्चित किया, जिससे महिलाओं और कई अन्य अल्पसंख्यकों और हाशिए के लोगों के लिए मतदान के अधिकार को वैध बनाया।
- मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की उनकी आलोचना में अम्बेडकर का महिलाओं की मुक्ति में योगदान परिलक्षित होता है।

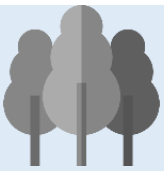

पर्यावरण

अमेज़न बेसिन में वनों की कटाई

संदर्भ: हाल ही में, मैपबायोमास के सहयोग से भू-संदर्भित सामाजिक-पर्यावरणीय सूचना के अमेज़ॅन नेटवर्क द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेज़ॅन क्षेत्र ने लगभग चार दशकों में अपनी मूल वनस्पति का 10% खो दिया है। खोया हुआ वन क्षेत्र ज्यादातर उष्णकटिबंधीय वर्षावन है और मोटे तौर पर टेक्सास के आकार का है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **वनों की कटाई वाले क्षेत्र का विस्तार:** 1985 से 2021 तक, वनों की कटाई का क्षेत्र 490,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1,250,000 वर्ग किलोमीटर हो गया।
    - इस अवधि में कुल वनों की कटाई में ब्राजील का योगदान 84% था।
- सबसे अधिक नुकसान के साथ ब्राजील सबसे आगे: ब्राजील, जिसके पास अमेज़ॅन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है, विनाश का भी नेतृत्व करता है।
    - लगभग चार दशकों में, ब्राजील के वर्षावन का 19% नष्ट हो गया है।
    - ब्राजील का लगभग आधा कार्बन उत्सर्जन वनों की कटाई से होता है।
    - वनों की कटाई मुख्य रूप से सड़कों के खुलने से समर्थित पशुपालन के विस्तार के कारण हुआ है।

कार्बन उत्सर्जन पर प्रभाव:

- कम से कम लगभग 75 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन पूरे अमेज़न में संग्रहित है।

- यदि वह सारा कार्बन वातावरण में तुरंत समाप्त हो जाता है, तो यह वैश्विक वार्षिक उत्सर्जन का लगभग सात गुना होगा।

अमेज़न वर्षावनों और अमेज़न बेसिन के बारे में:

अमेज़न वर्षावन

- ये विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन के सहारे स्थित हैं।
- 2021 तक, अमेज़ॅन का 74% क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और 9% अन्य प्राकृतिक वनस्पति प्रकारों से आच्छादित था।
- ये विश्व की भूमि प्रजातियों का लगभग पांचवां हिस्सा और 45 मिलियन से अधिक लोगों का घर हैं।
- अमेज़ॅन का वर्षावन 400-500 स्वदेशी अमेरिंडियन जनजातियों (Amerindian tribes) का घर है।
- यह ग्रह द्वारा उपयोग की जाने वाली 20% ऑक्सीजन का स्रोत है।
- उष्णकटिबंधीय वर्षावन बंद कैनोपी वन होते (Closed-Canopy Forests) हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं।
- यह बहुत गीला स्थान हैं, यहाँ या तो मौसमी रूप से या पूरे वर्ष में प्रतिवर्ष 200 सेमी. से अधिक वर्षा होती है।
- तापमान समान रूप से उच्च होता है जो 20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है।

अमेज़न बेसिन

- अमेज़न बेसिन 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के साथ विस्तृत है, यह भारत के आकार का लगभग दोगुना है।
- ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज़ पर्वत, दक्षिण में ब्राज़ील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।
- यह बेसिन दुनिया के ताज़े पानी के प्रवाह का लगभग 20% महासागरों से प्राप्त करता है।

बेसिन देशों में अमेज़न वर्षावनों का महत्व:

- **समृद्ध जैव विविधता का स्रोत:** अमेज़ॅन के जंगल अत्यधिक जैव विविधता वाले हैं और दुनिया के किसी भी अन्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अमेज़ॅन में वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों की एक विस्तृत श्रेणी पाई जाती है।
  - इसमें सभी प्रजातियों के 30 प्रतिशत तक होने का अनुमान है।
- **वर्षा और जलवायु नियंत्रण:** अमेज़ॅन वर्षावन वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से दुनिया की 50 से 75 प्रतिशत वर्षा का उत्पादन करता है।
  - पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य अमेरिका में वर्षा अमेज़ॅन से नमी से प्रभावित होती है।
  - हाइड्रोलॉजिकल चक्र जो जंगलों पर निर्भर करते हैं, अमेज़ॅन का कैनोपी आवरण तापमान और आर्द्रता को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।
- **कार्बन सिंक क्षमता और एक प्राकृतिक वायु शोधक:** लगभग 350 बिलियन पेड़ों द्वारा भारी मात्रा में कार्बन का पृथक्करण किया जाता है जो अमेज़ॅन वर्षावन बनाते हैं।
  - 85 बिलियन टन से अधिक कार्बन जंगलों में संग्रहित है जो दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय वनों द्वारा संग्रहीत कार्बन के एक तिहाई से अधिक है।
- **स्थानीय और क्षेत्रीय लाभ:** अमेज़ॅन बेसिन में लाखों लोग वन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और लॉगिंग, गैर-इमारती वन उत्पादों

के संग्रह जैसी गतिविधियों पर निर्भर हैं।

- **औषधीय मूल्य और खाद्य सुरक्षा:** अमेज़ॅन 70% पौधे प्रदान करता है जो कैंसर कोशिकाओं के विरुद्ध प्रभावी होता हैं।
- दुनिया भर में हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में से 80 फीसदी की जड़ें अमेज़न वर्षावन में हैं।

अमेज़न के जंगलों की चिंताएँ और खतरे:

- अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) के साथ मिलकर वैश्विक तापमान में वृद्धि ने लैटिन अमेरिकी जलवायु परिवर्तनशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्षावन केवल 100 वर्षों में नष्ट हो जाएंगे।
- जंगल में आग लगने, सूखे और अरक्षणीय कृषि पद्धतियों की बढ़ती घटनाओं ने वन वनस्पति को भारी नुकसान पहुंचाया है।
- अवैध शिकार, वाणिज्यिक मछली पकड़ने, जैव-चोरी (bio-Piracy) और तस्करी के कारण वनस्पतियों और जीवों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। अमेज़ॅन रिवर टर्टल "पैचे" सहित कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं।
- बड़े वन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियाँ, औद्योगिक और खनन गतिविधियाँ कुल वनों की कटाई वाले क्षेत्र के कम से कम 10% के लिए जिम्मेदार हैं।
- सोया तेल और पशुपालन के लिए जंगलों को साफ करने से वनस्पति की भारी मात्रा में हानि हुई है - प्रति सेकंड 1.5 एकड़ का नुकसान होता है।

आगे की राह

अमेज़न कार्यात्मक विनाश के कगार पर है; केवल अमेज़ॅन वर्षावन ही नहीं, बल्कि अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई वन भी पिछले कुछ वर्षों में वृक्षारोपण और आग के परिणामस्वरूप कार्बन स्रोतों में बदल गए हैं। वनों की कटाई की प्रवृत्ति को उलटने और ग्रह को बचाने के लिए एक आसन्न आवश्यकता है जिसमें मिशन मोड में सरकारों, नागरिक समाज, उद्योगों और निगमों सहित सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

मृदा संरक्षण और प्रबंधन का महत्व

संदर्भ: विश्व मृदा दिवस (WSD) प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 2022 का विषय 'मृदा: जहां भोजन की शुरुआत होती है' (Soils: Where food begins) है। इसका उद्देश्य स्थायी मृदा प्रबंधन के माध्यम से स्वस्थ मृदा, पारिस्थितिक तंत्र और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

परिचय:

- मृदा संरक्षण नए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के लिए सतत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है:
    - **एसडीजी 6 - स्वच्छ जल और स्वच्छता:** जल निकासी और शुद्धिकरण के माध्यम से, मृदा पीने और खेती के लिए स्वच्छ जल प्रदान करने में मदद करती है।
    - **एसडीजी 13 - जलवायु कार्रवाई:** पृथक्करण के माध्यम से, वायुमंडलीय कार्बन को कम करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में मृदा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
    - **एसडीजी 15 - भूमि पर जीवन:** वनों के स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण से लड़ने और भूमि क्षरण को उलटने के लिए स्वस्थ मिट्टी आवश्यक है।

एक स्वस्थ मृदा पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता:

- जीवित रहने के लिए स्वस्थ मृदा आवश्यक है। ये भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए हमारे पोषण और जल रिसाव दोनों को बढ़ाने के लिए स्वस्थ पौधों के विकास का समर्थन करते हैं।
- मृदा कार्बन का भंडारण करके ग्रह की जलवायु को विनियमित करने में मदद करती है और महासागरों के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है।
- ये एक स्वस्थ परिदृश्य को बनाए रखने में मदद करते हैं जो सूखे और बाढ़ के प्रभावों के प्रति अधिक लचीले है। चूंकि मिट्टी खाद्य प्रणालियों का आधार है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्वस्थ खाद्य उत्पादन के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है।

मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार की पहल:

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना:** इसका उपयोग मृदा स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है, और जब समय के साथ उपयोग किया जाता है, तो मृदा स्वास्थ्य में परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है।
    - मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा स्वास्थ्य संकेतक और संबंधित वर्णनात्मक शब्द प्रदर्शित करता है, जो किसानों को आवश्यक मृदा संशोधन करने के लिए मार्गदर्शन करता है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** इस पहल का उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, वर्षा जल संचयन और भूजल तालिका का पुनर्भरण करना है।

- **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन:** इसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जैसी पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हैं, जिससे रसायनों और अन्य कृषि-इनपुट पर निर्भरता कम हो जाती है और छोटे किसानों पर मौद्रिक बोझ कम हो जाता है।

मृदा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए मृदा संरक्षण में भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कई गतिविधियाँ करता है जैसे-

- **पूर्वानुमान उपकरणों का विकास:** एफएओ डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके पूर्वानुमान उपकरण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) के साथ सहयोग करता है, जो कमजोर किसानों को विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में फसल विकल्पों पर सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा।
- **टिकाऊ और लचीली प्रथाओं को अपनाने के लिए क्षमता निर्माण:** एफएओ, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से, दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का समर्थन करता है ताकि स्थायी और लचीली प्रथाओं, जैविक प्रमाणीकरण और कृषि-पोषक-उद्यान को अपनाने के लिए ऑन-फार्म आजीविका का समर्थन करने की दिशा में उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके।
- **राज्यों के साथ काम करना:** एफएओ फसल विविधीकरण और लैंडस्केप-स्तरीय योजना को बढ़ावा देने के लिए आठ लक्षित राज्य, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब में कार्य करता है।
- आंध्र प्रदेश में, एफएओ राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि किसानों को कृषि-पारिस्थितिक दृष्टिकोण और जैविक खेती के लिए स्थायी बदलाव में सहायता मिल सके।

आगे की राह

अवक्रमित मिट्टी की पहचान, प्रबंधन और बहाली के साथ-साथ अग्रिम उपायों को अपनाने के लिए शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और समाज के बीच संचार चैनलों को मजबूत करने की आवश्यकता है। ज्ञान की उपलब्धता, सफल प्रथाओं को साझा करने और स्वच्छ तथा टिकाऊ प्रौद्योगिकियों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक सहयोग और साझेदारी केंद्रीय हैं, जिससे कोई भी पीछे न छूटे।
टॉपसॉइल की रक्षा के लिए घर/किचन गार्डन विकसित करने और बनाए रखने के लिए पेड़ लगाकर और मुख्य रूप से स्थानीय रूप से प्राप्त और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग करके उपभोक्ता और नागरिक योगदान कर सकते हैं। बदलती जलवायु की चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारे पारिस्थितिक तंत्र का लचीलापन बनाना महत्वपूर्ण है।

आर्कटिक महासागर का गर्म होना और इसके प्रभाव

संदर्भ: हाल ही में फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में अपना अध्ययन प्रकाशित किया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि आर्कटिक बाकी ग्रह की तुलना में चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है।

- वार्मिंग आर्कटिक के यूरेशियन भाग में ज्यादा केंद्रित है, जहां रूस और नॉर्वे के उत्तर में बैरेंट्स सागर खतरनाक दर से गर्म हो रहा है - वैश्विक औसत से सात गुना तेज।
- 11 देशों के लगभग 150 विशेषज्ञों ने इस साल के आर्कटिक स्थितियों (आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड) के आकलन को संकलित किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने 2006 से तैयार किया है।

आर्कटिक क्षेत्र के बारे में:

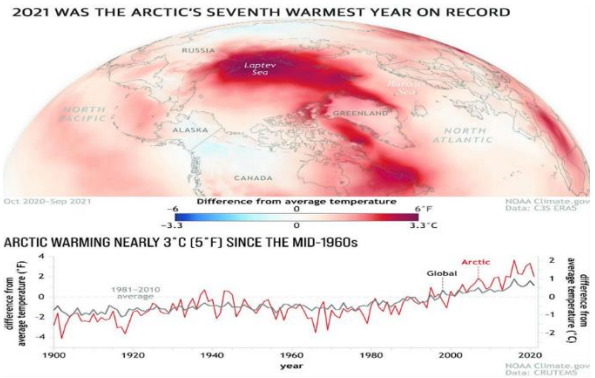

- इसे आमतौर पर 66° 34′ N अक्षांश के उत्तर में आर्कटिक सर्कल के ऊपर के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए समझा जाता है, जिसमें इसके केंद्र में उत्तरी ध्रुव के साथ आर्कटिक महासागर शामिल है।
- आठ आर्कटिक राज्य: कनाडा, डेनमार्क साम्राज्य, फ़िनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका आर्कटिक परिषद

बनाते हैं।

- आर्कटिक लगभग चार मिलियन निवासियों का घर है, जिनमें से लगभग दसवां हिस्सा स्वदेशी लोगों के रूप में माना जाता है।
- आर्कटिक महासागर और इसके आस-पास का भूभाग वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के साथ-साथ नीति निर्माताओं के लिए अत्यधिक रुचि और अनुसंधान का एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है।
- आर्कटिक पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के वायुमंडलीय, महासागरीय, और जैव-भू-रासायनिक चक्रों को प्रभावित करता है।

आर्कटिक वार्मिंग से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- **जलवायु परिवर्तन:** उन्होंने बताया कि कैसे गर्म हवा का तापमान, पिघलती समुद्री बर्फ, बर्फ की छोटी अवधि, जंगल की आग में वृद्धि और वर्षा के बढ़ते स्तर ने इस क्षेत्र में वन्यजीवों और स्वदेशी लोगों को अनुकूल होने के लिए मजबूर किया है।
- **ग्रीनलैंड में गर्मी की लहर:** यह चार दशकों से अधिक समय तक लगातार उपग्रह निगरानी में द्वीप की बर्फ की चादर को वर्ष के उस समय के लिए सबसे गंभीर पिघलने का कारण बना।
    - वर्ष 2021 में, अगस्त की गर्मी की लहर के कारण पहली बार बर्फ की चोटियों के शिखर पर बारिश हुई थी।
- बढ़ता तापमान इस क्षेत्र की जलवायु को समुद्री बर्फ, बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट से कम और खुले जल, बारिश और हरे-भरे परिदृश्यों द्वारा परिभाषित जलवायु में बदल रहा है।
- पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने से दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, महासागरों में गर्मी और जल केबढ़ने का तरीका बदल रहा है, और गर्मी की लहरों तथा आंधी-तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाओं को भी प्रभावित कर रहा है।
- **परिवर्तन की दर:** पिछले चार दशकों में, यह क्षेत्र वैश्विक औसत दर से चार गुना अधिक गर्म हुआ है। आर्कटिक के कुछ हिस्से वैश्विक दर से सात गुना तक गर्म हो रहे हैं।
- **हरित आवरण में वृद्धि:** बढ़ते तापमान ने आर्कटिक टुंड्रा के कुछ हिस्सों में पौधों, झाड़ियों और घासों को बढ़ाने में मदद की है।
    - वर्ष 2022 में हरित वनस्पति का स्तर देखा गया जो विशेष रूप से कनाडाई आर्कटिक द्वीपसमूह, उत्तरी क्यूबेक और मध्य साइबेरिया में 2000 के बाद से चौथा उच्चतम स्तर था।
- **बर्फ का कम आवरण:** उत्तरी अमेरिकी आर्कटिक में बर्फ का आवरण रिकॉर्ड में दूसरा सबसे कम था। यूरेशियन आर्कटिक में, यह तीसरा सबसे कम था।
- ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर ने पिछले 25 वर्षों से बर्फ खो दी है।
- **समुद्री जहाज यातायात:** वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि समुद्री बर्फ में गिरावट के साथ आर्कटिक में समुद्री जहाज यातायात बढ़ रहा है, बेरिंग जलडमरूमध्य और ब्यूफोर्ट सागर के माध्यम से प्रशांत महासागर से यात्रा करने वाले जहाजों के बीच होने वाले यातायात में सबसे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

महत्वपूर्ण निहितार्थ:

- **मानवता के लिए खतरा:** हमारे घरों, आजीविका और भौतिक सुरक्षा को तेजी से पिघलने वाली बर्फ, पिघलते पर्माफ्रॉस्ट, बढ़ती गर्मी, जंगल की आग और अन्य परिवर्तनों से खतरा है।
- **खनिज संसाधन:** आर्कटिक क्षेत्र में कोयले, जिप्सम और हीरे के समृद्ध भंडार हैं और जस्ता, सीसा, प्लेसर गोल्ड और क्वार्ट्ज के पर्याप्त भंडार हैं। ग्रीनलैंड अकेले दुनिया के दुर्लभ मृदा भंडार का लगभग एक चौथाई हिस्सा रखता है।
- **हाइड्रोकार्बन:** आर्कटिक में भी हाइड्रोकार्बन संसाधनों का भंडार है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग करने वाला देश है। इसलिए आर्कटिक संभावित रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सकता है।
- **मानसून:** भारत में बदलते आर्कटिक और मानसून के प्रभाव के बीच की कड़ी मौसम की चरम घटनाओं और जल तथा खाद्य सुरक्षा के लिए वर्षा पर भारी निर्भरता के कारण महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है।

भारत की आर्कटिक नीति:

- सरकार और शैक्षणिक, अनुसंधान और व्यावसायिक संस्थानों के भीतर संस्थागत और मानव संसाधन क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा।
- आर्कटिक में भारत के हितों की खोज में अंतर-मंत्रालयी समन्वय।
- भारत की जलवायु, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा पर आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समझ को बढ़ाना।
- वैश्विक शिपिंग मार्गों, ऊर्जा सुरक्षा और खनिज संपदा के दोहन से संबंधित भारत के आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक हितों पर आर्कटिक में बर्फ के पिघलने के प्रभावों पर बेहतर विश्लेषण, भविष्यवाणी और समन्वित नीति निर्माण में योगदान।
- ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमालय के बीच संबंधों का अध्ययन।
- विभिन्न आर्कटिक मंचों के तहत भारत और आर्कटिक क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को गहरा करना, वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान से

विशेषज्ञता प्राप्त करना।

- आर्कटिक परिषद में भारत की भागीदारी बढ़ाना और आर्कटिक में जटिल शासन संरचनाओं, प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों और क्षेत्र की भू-राजनीति की समझ में सुधार करना।

भारत की आर्कटिक नीति देश को भविष्य के लिए तैयार करने में एक आवश्यक भूमिका निभाएगी जहां मानव जाति की सबसे बड़ी चुनौतियों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, को सामूहिक इच्छा और प्रयास के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।

आगे की राह

समस्या यह है कि हम उन कारकों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं जो नियंत्रित करते हैं कि बर्फ कितनी तेजी से बहती है और इस प्रकार समुद्र में गिरती है। प्रक्रिया को न समझने की समस्या से निपटने का एक तरीका यह अध्ययन करना है कि अतीत में समुद्र का स्तर कैसे बदला। पृथ्वी अब लगभग उतनी ही गर्म है जितनी कि लगभग 125,000 साल पहले अंतिम इंटरग्लेशियल अवधि के दौरान थी। दुनिया को ग्लेशियरों पर मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कार्य करना चाहिए।

राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के बारे में:

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अंदर एक अमेरिकी वैज्ञानिक और नियामक एजेंसी है जो मौसम की भविष्यवाणी करती है, समुद्री और वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी करती है, समुद्रों का चार्ट बनाती है, गहरे समुद्र की खोज करती है, र अमेरिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री स्तनधारियों और लुप्तप्राय प्रजातियों के मछली पकड़ने और संरक्षण का प्रबंधन करती है।
- NOAA's की पांच मूलभूत गतिविधियां हैं:
  I. उपकरणों और डेटा संग्रह नेटवर्क के साथ पृथ्वी प्रणालियों की निगरानी और निरीक्षण करना।
  II. डेटा के अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी प्रणालियों को समझना और उनका वर्णन करना।
  III. समय के साथ इन प्रणालियों में परिवर्तनों का आकलन और भविष्यवाणी करना।
  IV. प्रासंगिक जानकारी के साथ जनता और भागीदार संगठनों को शामिल करना, सलाह देना और सूचित करना।
  V. पर्यावरण संसाधनों की अभिरक्षा।

क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)

संदर्भ: हाल ही में, केंद्र सरकार ने कहा कि अफ्रीकी चीतों को भारत लाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के साथ-साथ क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority-CAMPA) के धन का उपयोग परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था।

कैम्पा फंड के बारे में:

- वर्ष 2004 में स्थापना, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित क्षतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) की देखरेख और प्रबंधन के लिए क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) का गठन किया।
- CAMPA अधिनियम या प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम एक भारतीय कानून है जो केंद्र और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों में एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र प्रदान करना चाहता है।
  - गैर-वन प्रयोजन के लिए परिवर्तित की गई वन भूमि के एवज में जारी की गई राशियों का कुशल और पारदर्शी तरीके से शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करना, जो ऐसी वन भूमि के विपथन के प्रभाव को कम करता है।

कैम्पा का उद्देश्य:

- निधियां वनीकरण और पुनर्जनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हैं, जो गैर-वन उपयोगों के लिए परिवर्तित वन भूमि की क्षतिपूर्ति के उपाय के रूप में हैं।
- राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद की स्थापना निम्नलिखित अधिदेश के साथ की गई है:
  - राज्य कैम्पा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
  - राज्य कैम्पा द्वारा आवश्यक वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य सहायता की सुविधा प्रदान करना।
  - राज्य कैम्पा को उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के आधार पर सिफारिश करना।
  - अंतर-राज्य या केंद्र-राज्य चरित्र के मुद्दों को हल करने के लिए राज्य CAMPA को एक तंत्र प्रदान करना।

प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में:

- यह वर्ष 1973 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बंगाल के बाघों की आबादी उनके प्राकृतिक आवासों में अच्छी तरह से बनी रहे, यह परियोजना बाघ की रक्षा और बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती है।

बाघ सुरक्षा बल:

- सरकार ने एक बाघ सुरक्षा बल भी स्थापित किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार का अवैध शिकार या मानव-बाघ संघर्ष न हो।
- यह निश्चित रूप से बाघों को विलुप्त होने से रोकने में मदद करेगा।

बाघों की संख्या बढ़ाना:

- वर्ष 2006 में, सर्वेक्षणों ने सुझाव दिया कि बाघों की संख्या केवल 1,411 थी जो दुनिया भर में चिंता का कारण था।
- एक दशक से भी अधिक समय में, भारत में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है।

टाइगर रिजर्व:

- भारत में 18 टाइगर रेंज राज्यों में 53 टाइगर रिजर्व हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि बाघों के आवासों में कमी लाने वाला कोई भी कारक सीमित है।
- इन आवासों को हुए किसी भी नुकसान की मरम्मत की जानी चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहे।
  - व्यवहार्य बाघ आबादी बनाए रखना।

प्रोजेक्ट चीता के बारे में:

- भारत में चीतों का परिचय प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जा रहा है।
- यह दुनिया की पहली अंतरमहाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी ट्रांसलोकेशन परियोजना है।
- सह-अस्तित्व दृष्टिकोण:
  - भारत ने इस दृष्टिकोण को चुना है।
  - यह और भी अनोखा है क्योंकि यह पहली बार है जब चीतों को बिना बाड़ वाले संरक्षित क्षेत्र (पीए) में फिर से रखा जाएगा।
- **सह-अस्तित्व दृष्टिकोण का महत्व:**
  - सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सह-अस्तित्व के दृष्टिकोण को अधिक अनुकूल माना जाता है।
  - बाड़ लगाना दक्षिण अफ्रीका और मलावी में व्यापक दूरी पर चीता की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है, इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की अनुमति देता है।
  - कूनो राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य संरक्षण क्षेत्र काफी हद तक मानवजनित खतरों से स्वतंत्र है।

सह-अस्तित्व के दृष्टिकोण से जुड़ी चुनौतियाँ:

- कूनो राष्ट्रीय उद्यान अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यह संलग्न/बाड़ से घिरा हुआ नहीं है।
- बिना बाड़ वाले सिस्टम में चीता का कोई सफल रीइन्ट्रडक्शन (reintroductions) नहीं हुआ है।
- चीते के जीवित रहने के लिए मानवजनित खतरों में फँसना जैसे जंगली मांस और पशुओं के शिकार के कारण जवाबी हत्याएं शामिल है।
- यह उन्हें मानव-संबंधित मृत्यु दर के जोखिम में डालता, जिसमें पशुपालकों द्वारा जालसाज़ी और जवाबी हत्याएं शामिल हैं।

आगे की राह

CAMPA फंड वनों की बहाली के लिए हैं, विशेष रूप से वे जो औद्योगिक उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किए गए हैं। ऐसी मांग की जाती रही है कि यह फंड ग्राम सभाओं को दिया जाना चाहिए ताकि वनों को बहाल करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। देश भर के स्वदेशी और वन-निवासी समुदाय स्थायी वित्त के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, इस धन का उपयोग उन्हें सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

स्वास्थ्य एक अधिकार के रूप में: राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक

संदर्भ: सितंबर 2022 में, राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य विधान सभा में राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पेश किया। विधान सभा में इस पर अभी भी बहस हो रही है और यह स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ-साथ विभिन्न हित समूहों के बीच सार्वजनिक चर्चा का एक प्रमुख हिस्सा बना है।

- राज्य सरकार की ओर से इस तरह की पहली विधायी कार्रवाई होने के नाते, निर्णय में नवीनता दोनों हैं और इस प्रकार इसके कानूनी आयामों, इसके कार्यान्वयन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।

स्वास्थ्य का अधिकार कहाँ स्थित हो सकता है?

- संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है और उसे स्थिर रखता है। स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार के दायरे का विस्तार करने में न्यायालयों ने अक्सर एक प्रगतिशील रुख अपनाया है।
- पंजाब राज्य और अन्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला (1996) में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के दायित्वों को भी इंगित किया।
- अदालतों ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में राज्य के दायित्वों को विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 38, 41, 42 और 47 के माध्यम से उजागर करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी सहारा लिया है।
    - अनुच्छेद 38 अनुसार, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करता है।
    - अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य कार्य पाने ,शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता और अन्य अयोग्य अभाव के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है।
    - अनुच्छेद 42 के अनुसार, राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करता है।
    - अनुच्छेद 47 पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य से संबंधित है।
- पंजाब राज्य बनाम राम लुभया बग्गा (1998) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रत्येक अधिकार का एक समान कर्तव्य था, और इस मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए अनुच्छेद 47 में उल्लिखित राज्य के कर्तव्य को आकर्षित किया।
- पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) में, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के हित में, चिकित्सा सहायता प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है।
- संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची के आइटम 6 के तहत आने वाली, राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और चिकित्सा सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करें।
    - स्वास्थ्य विधेयक के अधिकार को सामने लाने में, राजस्थान सरकार ने अतीत में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित मूल्यों को बरकरार रखते हुए, राज्य के निवासियों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करके अपने संवैधानिक जनादेश पर कार्य किया है।

विधेयक में निर्धारित अधिकार और कर्तव्य क्या हैं?

- शुरुआत में बिल की प्रस्तावना सरकार के इरादों को स्पष्ट करती है - बिना किसी विनाशकारी आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय के स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।
- विधेयक में राज्य के निवासियों के लिए निर्धारित 20 अधिकारों में, हम इक्विटी, न्याय और अच्छे गुण के सिद्धांतों को देखते हैं, जैसा कि पहले संदर्भित निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया था।
- बिल निजी और सार्वजनिक दोनों अस्पतालों में मुफ्त और किफायती स्वास्थ्य जांच और सर्जरी का प्रावधान करता है। यह निवासियों के लिए विभिन्न बीमा योजनाओं में निर्धारित मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार देता है।
    - जबकि यह उन चीजों को संहिताबद्ध करने में एक लंबा रास्ता तय करता है जिन्हें पहले केवल अपेक्षाओं के रूप में माना जाता था, राज्य निवासियों को पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का वजन उठाता है।

- चिकित्सा प्रतिष्ठानों में चिकित्सा सूचना के अधिकार के एक और पेचीदा मुद्दे से निपटने में बिल एक कदम आगे रहता है। विधेयक निवासियों को निदान और उपचार के संबंध में जानकारी मांगने का अधिकार देता है, साथ ही, विधेयक ऐसी सभी सूचनाओं को गोपनीय प्रकृति बनाये रखता है।
- विधेयक ने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए अधिकार भी प्रदान किए हैं जैसे कि प्रामाणिकता में उत्तरदायित्व से छूट, एक सुरक्षित कार्य वातावरण, और सुरक्षात्मक उपकरणों तक पहुंच।
- विधेयक, हितधारकों के दोनों समूहों को अधिकार और कर्तव्य देने में, उन प्रतिदावों को संतुलित करने की मांग करता है जो स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को समस्याग्रस्त बना सकते थे।
- जबकि निवासियों के पास चिकित्सा देखभाल और उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और सुरक्षा है, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को अपना कर्तव्य निभाने में कोई नुकसान नहीं करता है।
- यदि अन्य राज्यों में इसका पालन किया जाता है, तो अधिकारों और कर्तव्यों का यह संतुलन एक मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाने और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तरों में सुधार करने में मदद करता।

विधेयक में प्रदान किए गए सरकारी दायित्व क्या हैं?

- अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं, और यह बिल में दिखाई देता है। करने के लिए सरकार बाध्य होगी-
  - धन प्रदान करना
  - संस्थानों की स्थापना
  - शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना
- पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता के लिए विभिन्न विभागों और कार्यालयों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी सरकार की है।
- विधेयक ने नैदानिक, चिकित्सा और सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए योजना तैयार करने, तैयारियों का आकलन करने और प्रणाली विकसित करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए एक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन की स्थापना की है।
- जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण इन योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी भूमिका निभाता है।
- इस सीमांकन को बनाने में, बिल विकेंद्रीकरण के पुराने तर्क पर निर्भर करता है जहां स्थानीय उपाय और रणनीतियाँ समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक होंगी और उसी के लिए समाधान प्रदान करने में सक्षम होंगी।

सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार पर विधेयक की रोक विवादास्पद क्यों है?

- जनता से काफी प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाले इस विधेयक का प्रावधान खंड 14 है, जो किसी भी सिविल न्यायालय को उन मामलों में अधिकार क्षेत्र रखने से मना करता है जहां अपीलीय प्राधिकरण, जैसा कि बिल में उल्लिखित है, मामलों को तय करने की शक्ति है।
- यह तर्क दिया गया है कि इन अपीलीय अधिकारियों के पास जटिल मामलों को तय करने के लिए पर्याप्त संसाधन या कानूनी विशेषज्ञता नहीं होगी, और इस तरह का एक व्यापक प्रतिबंध न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा।
- यह बिल के तहत की गई कार्रवाइयों के खिलाफ किसी भी अदालत से निषेधाज्ञा की मांग को भी अस्वीकार करता है। यह अदालत जाने के अधिकार पर एक मनमाना प्रतिबंध प्रतीत होता है।
- सरकार के हस्तक्षेप की किसी गुंजाइश के अभाव में, कार्यपालिका के अतिरेक या मनमानी के खतरे से बचना अत्यंत कठिन हो जाता है।
- हालांकि सांसदों की मंशा अदालती प्रक्रिया की लागत और देरी के बिना मामलों को जल्दी से निपटाने की अनुमति देना सद्भावना में हो सकती है, इसे न्यायिक कार्यवाही के लिए किसी भी तरह का सहारा नहीं लेना चाहिए।

विधेयक से प्रमुख टेकअवे क्या है?

- हालांकि बिल के कुछ पहलुओं पर अभी भी स्पष्टता का अभाव है, जिसके लिए बाद में जारी किए जाने वाले नियमों और विनियमों के आधार पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, जहां तक सभी निवासियों को सस्ती चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का संबंध है, सरकार का समग्र जनादेश स्पष्ट प्रतीत होता है।
- न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक जैसे कुछ समस्याग्रस्त प्रावधानों के अलावा, विधेयक स्वास्थ्य के अधिकार को अधिक प्राप्य और मूर्त मौलिक अधिकार बनाने के लिए एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु प्रतीत होता है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

संदर्भ: हाल ही में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट जारी की गई।

- भारत की सुंदरता की सराहना करने और पर्यटन के महत्व तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है।

- इस वर्ष की थीम: राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के लिए 'ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन' है।
- केंद्र सरकार हैदराबाद के बाहरी इलाके में बुनकरों की बस्ती तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में मुख्य कार्यक्रम आयोजित की।
- यह हाथ से बुनी अपनी प्रसिद्ध इकत साड़ियों के लिएजाना जाता है, पोचमपल्ली को 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया था।

भारत में पर्यटन क्षेत्र

- भारत में यात्रा और पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग था: और 2018 में इसका मूल्य $234 बिलियन था।
- द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) के अनुसार: भारत में पर्यटन उद्योग ने 2019 में $194 बिलियन या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% उत्पन्न किया।
- भारत में पर्यटन क्षेत्र: 2028 तक 6.9% की वार्षिक दर से $460 बिलियन तक बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है जो सकल घरेलू उत्पाद का 9.9% है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति के बारे में:

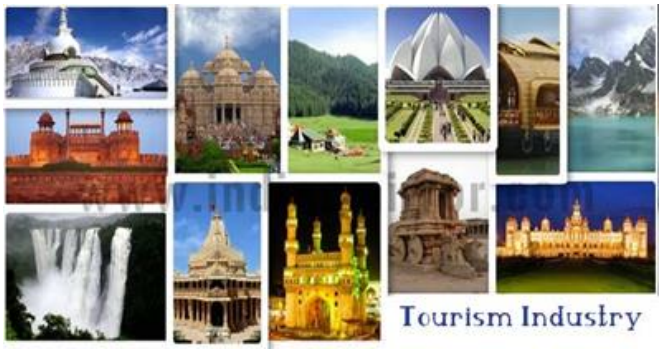

- राष्ट्रीय पर्यटन नीति के मसौदे के अनुसार, अगले 10 वर्षों में पांच प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो हैं:

I. हरित पर्यटन
II. डिजिटल पर्यटन
III. गंतव्य प्रबंधन
IV. आतिथ्य क्षेत्र को कुशल बनाना और
V. पर्यटन से संबंधित एमएसएमई को समर्थन देना।
VI. इसमें 'सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित धारणाएं' और केंद्र तथा राज्यों के बीच कमजोर जुड़ाव शामिल हैं।
VII. सरकार ने उन कारकों की भी पहचान की है जो देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास को बाधित करते हैं।
VIII. यह अन्य कारकों के रूप में 'दलालों के खतरे' और 'स्वच्छता एवं स्वच्छता के निम्न मानकों' का भी उल्लेख करता है जो उद्योग को अपनी पूरी क्षमता का लाभ उठाने से रोकते हैं।
IX. पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मसौदे में होटलों को औपचारिक रूप से बुनियादी ढांचे का दर्जा देने के साथ-साथ इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का उल्लेख है।
X. मसौदा नीति विशेष रूप से महामारी के मद्देनजर इस क्षेत्र की मदद करने के लिए रूपरेखा शर्तों की पेशकश करती है।

समिति की प्रमुख सिफारिशें:

- **राष्ट्रीय पर्यटन परिषद (एनटीसी):** सरकार को जीएसटी परिषद के मॉडल पर राष्ट्रीय पर्यटन परिषद (एनटीसी) बनाना चाहिए।
- **उद्देश्य:** पर्यटन क्षेत्र और इसके हितधारकों के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को सिफारिश करना चाहिए।

पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र:

- 25 करोड़ रुपये से अधिक के कैपेक्स खर्च करने से बिजली और पानी के शुल्क, संपत्ति कर, विकास कर आदि की रियायती दरों के माध्यम से आतिथ्य खिलाड़ियों के लिए परिचालन लागत कम हो जाएगी।
- यह क्षेत्र में निवेश को भी आकर्षित करेगा।
- यह आठ राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड की प्रशंसा करता है जिन्होंने आतिथ्य परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा दिया है।

समवर्ती सूची में पर्यटन:

- इसने पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की।
- यह महामारी से प्रभावित भारतीय पर्यटन क्षेत्र के मुद्दों को सरल बनाने में मदद करेगा क्योंकि पर्यटन एक बहु-क्षेत्रीय गतिविधि है।
- इसने परियोजना में अंतिम यूसी (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) जमा करने में देरी पर चिंता जताई।
- इसमें PRASHAD योजना के "पुरी में बुनियादी ढांचा विकास, मेगा सर्किट के तहत देउली में श्री जगन्नाथ धाम-रामचंडी-प्राची रिवर फ्रंट" जैसी परियोजनाएं शामिल हैं और विशिष्ट विषयों (स्वदेश दर्शन) के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास 2015 से लंबित है।
- यह मंत्रालय को आईटीडीसी (भारतीय व्यापार विकास निगम) के साथ विभिन्न व्यय मदों के भुगतान में देरी के कारणों की पहचान करने की सिफारिश करती है।

भारत सरकार की हालिया पहल:

विशिष्ट विषयों (स्वदेश दर्शन) के आसपास पर्यटक सर्किट का विकास:

- मंत्रालय को पर्यटन के मोर्चे पर अब तक पूर्वोत्तर राज्यों में विकसित क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का लाभ उठाना चाहिए।
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके बजटीय आवंटन के अनुसार बिल्कुल समान राशि दी जानी चाहिए।
- पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन (IITFC) पोर्टल लॉन्च किया है।
- यह एक ऑनलाइन कार्यक्रम है जहां व्यक्ति अपने समय, स्थान, पथ और गति से पर्यटन के बारे में सीख सकता है।
- इस कार्यक्रम के सफल समापन से शिक्षार्थी पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमाणित पर्यटक सहायक बनने में सक्षम होगा।
- सुविधाजनक वीज़ा व्यवस्था अंतर्गामी पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है।
- पर्यटन मंत्रालय इसे प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ पहल करता है।
- मंत्रालय का "अतुल्य भारत 2.0" अभियान दुनिया भर में किए जा रहे सामान्य प्रचार से बाजार विशिष्ट प्रचार योजनाओं और सामग्री निर्माण के लिए एक बदलाव का प्रतीक है।
- हाल ही में, संस्कृति मंत्रालय ने रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में आम आगंतुकों के लिए 10 ऐतिहासिक स्मारकों को रात 9 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है।
- इसके अलावा, यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपने महत्वपूर्ण स्मारकों को आगंतुकों के लिए देर रात तक खोलने का आग्रह किया।
- सरकार राज्यों को अपने-अपने राज्यों में सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि यह समझा जा सके कि विदेशी पर्यटक भारत को कैसे देखते हैं और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए।
- इससे विदेशी पर्यटकों के मन में भारत के प्रति धारणा बदलेगी जिससे हमें पर्यटन को बढ़ावा देने के अच्छे परिणाम मिलेंगे।

आगे की राह

यात्रा गंतव्य के रूप में, कुछ अन्य देश भारत में पाए जाने वाले उत्पादों और अनुभवों की विविधता की पेशकश कर सकते हैं। यात्रा और पर्यटन उद्योग देश के सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन सहित प्रमुख राष्ट्रीय विकास अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, और इस क्षेत्र में विकास देश में समग्र आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है। हालाँकि, भारत में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, फिर भी इस क्षेत्र में कई चुनौतियों के कारण अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं हो पाया है। उद्योग को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए इन चुनौतियों का उन्मूलन करना आवश्यक है।

भारत की भाषाएँ

चर्चा में क्यों : केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली राजभाषा समिति की रिपोर्ट का 11वां खंड हाल ही में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था।

- समिति ने तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा और परीक्षाओं की भाषा के रूप में हिंदी की सिफारिश की।
- इसने तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों की ओर से गुस्से वाली प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर किया है, जिन्होंने रिपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का प्रयास बताया है।

भारत की भाषाएँ:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 123 प्रमुख भाषाएँ हैं, जिनमें से 30 एक मिलियन से अधिक देशी वक्ताओं द्वारा बोली जाती हैं।
- भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण - 19,500 "मातृभाषाएँ" हैं - जिनमें 103 विदेशी मातृभाषाएँ शामिल हैं।
- अंग्रेजी का उपयोग उच्च शिक्षा और भारत सरकार के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है।
- हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली मातृभाषा या प्राथमिक भाषा (43.6%) है और यह उत्तर तथा मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भाषा के रूप में कार्य करती है।
- हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है, बंगाली 7वें और पंजाबी 10वें स्थान पर है।
- बंगाली दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा (8%) है, जिसके बोलने वालों की संख्या पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में काफी अधिक है।
- मोटे तौर पर, 12% भारतीय स्थानीय, कम मान्यता प्राप्त भाषाएं बोलते हैं।
- भारत की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है।
- भारत इंडो-आर्यन और द्रविड़ भाषा परिवारों का घर है, जो दुनिया के दो सबसे बड़े हैं।

भाषा पर संवैधानिक प्रावधान:

- **संविधान सभा:** भाषाई रूप से विविध समाज में राष्ट्रीय पहचान को अभिव्यक्त करने के सवाल पर संविधान निर्माताओं ने बहस की और इसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से भी जोड़ा।
- आठवीं अनुसूची में देश भर की 22 भाषाएं शामिल हैं।
- अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की अनुमति देता है। व्यावहारिक रूप से, कई राज्यों ने अंग्रेजी को चुना है।
- अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों, विधेयकों, अधिनियमों, संशोधनों, अध्यादेशों, नियमों आदि में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य करता है, जब तक कि संसद कानून द्वारा दूसरी प्रदान नहीं करती।
- अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान है कि भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य होगा।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके नियम संघ के आधिकारिक उद्देश्यों और संसद में उपयोग के लिए अंग्रेजी भाषा को जारी रखने का प्रावधान करते हैं।

एकल भाषा की चुनौतियाँ:

- **शिक्षा क्षेत्र में:** पाठ्यक्रम सामग्री की उपलब्धता और इसे पर्याप्त रूप से संप्रेषित करने के योग्य शिक्षकों के संदर्भ में निहितार्थ और व्यावहारिकता शामिल है।
- हिंदी भाषा में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की योग्यता और हिंदी भाषा की मातृभाषा वालों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करना।
- उचित पाठ्यक्रम का अभाव।

- **एकता में:** 1948 में गठित एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार के खिलाफ तर्क दिया, क्योंकि इससे और विभाजन हो सकता है।
- भाषाई उग्रवाद अर्थात एक भाषा की शक्ति और दूसरों पर श्रेष्ठता का प्रयोग करना या अपनी खुद की भाषा में अत्यधिक गर्व करना जो असंतोष और विभाजन को जन्म दे सकता है।
- **आर्थिक निहितार्थ:** यह जॉब मार्केट में प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है क्योंकि अंग्रेजी वैश्विक भाषा है।

आगे की राह

- भारतीय संघ जातीय भाषाई राष्ट्रीयताओं का समूह है जिनकी अपनी भाषाएं और संस्कृतियां हैं।
- क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की स्वीकृति से भारत की एकता मजबूत होगी।
- भारत की सभी भाषाएँ और मातृभाषाएँ इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भंडार हैं और इन्हें समान रूप से प्रोत्साहित और विकसित किया जाना चाहिए।

ST सूची में जनजातियों को जोड़ना

संदर्भ: हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों में लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes-STs) की सूची में कुछ अन्य समुदायों को शामिल करने की मंज़ूरी दी है, जिससे इन राज्यों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा किया जा सके, जिसके कारण संसद में बहस हुई।

नए जोड़े गए जनजातीय समूहों के बारे में:

नारिकोरावन और कुरीविक्करन(तमिलनाडु): नारिकुरवा और कुरुविकार (सियार पकड़ने वाले और पक्षी खाने वाले) जैसी खानाबदोश जनजातियाँ शिकार तथा संग्रहण करने के अपने पारंपरिक व्यवसायों पर गर्व करती हैं।

गोंड समुदाय (उत्तर प्रदेश): कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 ज़िलों में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

- इसमें गोंड समुदाय की पाँच उपश्रेणियाँ (धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड) शामिल हैं।

'बेट्टा-कुरुबा' (कर्नाटक): कर्नाटक के कडू कुरुबा के पर्याय के रूप में बेट्टा-कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया।

- बेट्टा-कुरुबा समुदाय पिछले 30 वर्षों से इस वर्ग में शामिल करने की मांग कर रहा है।

हट्टी जनजाति (हिमाचल प्रदेश): हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय हैं, जिन्होंने कस्बों में 'हाट' नामक छोटे बाज़ारों में घरेलू सब्जियों, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से यह नाम प्राप्त किया।

- यह समुदाय वर्ष 1967 जब उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया गया तब से इसकी मांग कर रहा है, जिसकी सीमा सिरमौर ज़िले से लगती है।
- वर्षों से विभिन्न महा खुंबलियों में पारित प्रस्तावों के कारण आदिवासी दर्जे की उनकी मांग को बल मिला।

बिंझिया (छत्तीसगढ़): बिंझिया को झारखंड और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं।

- बिंझिया, मांसाहारी हैं और कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वे गोमांस एवं सूअर का मांस नहीं खाते हैं, लेकिन हंडिया (चावल की बीयर) सहित मादक पेय का सेवन करते हैं।

एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया:

- एसटी सूची में जनजातियों को शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश के साथ शुरू होती है, जिसे फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और भारत के महापंजीयक को अनुमोदन के लिए भेजता है।
- इसके बाद अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट को सूची भेजने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मंजूरी मिलती है।

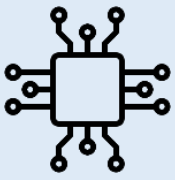

सुरक्षा समस्याएं

भारत में साइबर हमले

संदर्भ: हाल ही में, देश का प्रमुख चिकित्सा संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (AIIMS) एक बड़े साइबर हमले का निशाना बना गया था।

साइबर हमले के बारे में:

- साइबर हमले कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत पहुंच के माध्यम से जानकारी को चुराने, उजागर करने, बदलने, निष्क्रिय करने या नष्ट करने के अवांछित प्रयास हैं।
- आमतौर पर, डेटा को एन्क्रिप्ट करने के बाद नेटवर्क को काम करने से रोकने के लिए हमलों के ऐसे रूप, रैंसमवेयर चाहने वाली संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं और संगठनों को मांगें भेजी जाती हैं, जिन्हें अक्सर कानून प्रवर्तन को सूचित किए बिना बातचीत और भुगतान किया जाता है।
- **साइबर आतंकवाद:** इसे अक्सर सूचना प्रणाली, कार्यक्रमों और डेटा के खिलाफ किसी भी पूर्व-निर्धारित, राजनीतिक रूप से प्रेरित हमले के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हिंसा की धमकी देता है या हिंसा का परिणाम होता है।

भारत में साइबर अटैक बढ़ने के कारण

- **प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता:** जैसे-जैसे हम तेजी से बढ़ रहे हैं, अधिक से अधिक प्रणालियों को वर्चुअल स्पेस में स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि पहुंच और उपयोग में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके।
  - हालांकि, इस प्रवृत्ति का नकारात्मक पक्ष साइबर हमलों के लिए ऐसी प्रणालियों की बढ़ती भेद्यता है।
  - उदाहरण के लिए, यदि हैकर्स किसी देश की परमाणु, वित्तीय या ऊर्जा प्रणालियों में घुसपैठ करने में सक्षम होते हैं तो व्यापक क्षति और भारी नुकसान की चिंता है।
  - कोविड के बाद के युग में बढ़ती डिजिटल निर्भरता ने डिजिटल असमानताओं को उजागर किया है जिसे क्षमता निर्माण के माध्यम से पाटा जाना चाहिए।
- आतंकवादियों द्वारा अपने प्रचार को व्यापक बनाने और नफरत फैलाने के लिए साइबरस्पेस का परिष्कृत उपयोग किया जाता है।
- मजबूत कानून प्रवर्तन तंत्र का अभाव: साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का दृष्टिकोण अब तक तदर्थ और अव्यवस्थित रहा है।
  - कई एजेंसियों, नीतियों और पहलों के बावजूद, इसका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है।
- **चीन के साथ प्रतिकूल संबंध:** सूचना प्रौद्योगिकी में चीन को दुनिया के लीडरों में से एक माना जाता है। इसलिए, किसी दूसरे देश में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को अक्षम या आंशिक रूप से बाधित करने की क्षमता होने की उम्मीद रहती है।
  - दोनों देशों की सेनाओं के बीच हालिया सीमा गतिरोध और हिंसक घटनाओं के साथ संयुक्त रूप से, संबंधों में प्रतिकूलता एक दूसरे की महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे पर फैलने की उम्मीद है।
- **असममित और गुप्त युद्ध (Asymmetric and covert warfare):** जानमाल के नुकसान और आईबॉल टू आईबॉल वाली स्थितियों (eyeball to eyeball situations) के साथ पारंपरिक युद्ध के विपरीत, साइबर युद्ध प्रशंसनीय खंडन के दायरे के साथ गुप्त युद्ध है, यानी सरकारें इनके पकड़े जाने पर भी इनके शामिल होने से इनकार कर सकती हैं।
  - इसी प्रकार, उन्नत प्रणालियों और कुशल संसाधनों वाला एक छोटा राष्ट्र भी भारी नुकसान के डर के बिना एक बड़ी शक्ति पर हमला कर सकता है।
  - इसलिए, साइबर युद्ध तेजी से राष्ट्रों के बीच संघर्ष के लिए चुना गया स्थान बन गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का अभाव: इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आम सहमति का अभाव है।
  - आम जनता के बीच कम डिजिटल साक्षरता और राष्ट्रों के बीच डिजिटल अंतराल साइबर डोमेन में एक अस्थिर वातावरण बनाते हैं।
  - अक्सर यह बताया जाता है कि लोगों को दिलचस्प सामग्री पर क्लिक करने के लिए क्लिक-बेट करके आसानी से धोखा दिया जाता है, जिसमें अक्सर मैलवेयर जुड़ा होता है।

साइबर सुरक्षा के लिए प्रमुख सरकारी पहलें:

- **CERT-In:** यह भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संगठन है।
- **साइबर सुरक्षित भारत पहल:** यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में

एक मजबूत साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के सहयोग से था।

- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र:** NCIIPC एक केंद्र सरकार की स्थापना है, जिसका गठन हमारे देश की महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा के लिए किया गया है, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** गृह मंत्रालय ने एक समन्वित और कुशल पद्धति के माध्यम से देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए इस I4C भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत की।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर):** यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक स्थापना है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** 2000 का IT अधिनियम 09 जून 2000 को भारत में प्रभाव में आया। IT अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि कानून का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को कानूनी मान्यता प्रदान करना है।

आगे की राह

मानव संसाधन महत्वपूर्ण है और साइबर योद्धाओं की एक अनौपचारिक भारतीय टीम बनाने की तत्काल आवश्यकता है। महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रबंधकों को भी साइबर युद्ध में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और वायरस तथा हमलों को अलग करने के लिए सभी तकनीकों से सुसज्जित होना चाहिए। व्हाइट हैकर्स के लिए एक इनाम होना चाहिए जो उनकी कमियों को उजागर कर सके। प्रबंधकों और आम जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। इस तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ-साथ आम जनता के सामान्य जागरूकता स्तर को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। यूएस की तर्ज पर साइबर कमांड के रूप में सेना या नौसेना के तहत अलग विंग को एक भविष्यवादी राष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा नीति के साथ स्थापित करने की आवश्यकता है जो पर्याप्त संसाधनों का आवंटन करती है और हितधारकों की चिंताओं को दूर करती है। इसी तरह, मौजूदा बुनियादी ढांचे के तेजी से उन्नयन की आवश्यकता है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है और प्रतिस्पर्धा से आगे रहने की जरूरत है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति

संदर्भ: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का एक मसौदा तैयार किया है जो राष्ट्रीय साइबर स्पेस की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में:

- भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित के मामलों पर प्रधान मंत्री कार्यालय को सलाह देने का काम सौंपा गया है।
- इसकी स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 नवंबर 1998 को ब्रजेश मिश्रा के साथ पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में की थी।
- एनएससी के गठन से पहले, इन गतिविधियों की देखरेख पूर्व प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा की जाती थी।

सदस्य:

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के अलावा, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार के रक्षा, विदेश, गृह, वित्त मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं।

संगठनात्मक संरचना

- NSC भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना का शीर्ष निकाय है।
- तीन स्तरों में सामरिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और संयुक्त खुफिया समिति का सचिवालय शामिल हैं।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के बारे में:

- **उद्देश्य:** यह साइबर स्पेस के लिए एक अलग विधायी ढांचे और खतरों, प्रतिक्रियाओं और शिकायतों को दूर करने के लिए एक शीर्ष निकाय के निर्माण का प्रस्ताव करता है।
- **आवश्यकता:** मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचे साइबर घटनाओं से निपटने के लिए उभरते खतरे के परिदृश्यों या प्रक्रियाओं को संबोधित नहीं करते हैं।
- वर्तमान में साइबर सुरक्षा की देखभाल करने के लिए कोई समर्पित निकाय नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप जवाबदेह ठहरा सकें।
- वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत साइबर सुरक्षा खतरों का जवाब दिया जा सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

डीपफेक तकनीक और चीन

संदर्भ: चीन का साइबरस्पेस प्रशासन 10 जनवरी से प्रभावी होने के लिए नए नियमों को लागू कर रहा है, ताकि डीप सिंथेसिस तकनीक के उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सके और गलत सूचना पर अंकुश लगाया जा सके।

- डीप सिंथेसिस को वर्चुअल सीन बनाने के लिए टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो जेनरेट करने के लिए डीप लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी सहित तकनीकों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।
- प्रौद्योगिकी के सबसे प्रसिद्धअनुप्रयोगों में से एक डीपफेक है, जहां सिंथेटिक मीडिया का उपयोग एक व्यक्ति के चेहरे या आवाज को दूसरे व्यक्ति से बदलने के लिए किया जाता है।
- प्रौद्योगिकी के विकास के साथ डीपफेक का पता लगाना कठिन होता जा रहा है। इसका उपयोग सेलिब्रिटी अश्लील वीडियो बनाने, फर्जी समाचार बनाने और अन्य गलत कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है।

डीपफेक क्या है?

- डीपफेक मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम के साथ गलत सूचना फैलाने और वास्तविक व्यक्ति की उपस्थिति, आवाज या दोनों को समान कृत्रिम समानता या आवाज के साथ बदलने के लिए कृत्रिम छवियों और ऑडियो का संकलन है।
- यह ऐसे लोगों को बना सकता है जो मौजूद नहीं हैं और यह वास्तविक लोगों को ऐसा कहने और करने का नक़ल कर सकता है जो उन्होंने नहीं कहा या नहीं किया।
- डीपफेक शब्द की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब एक अज्ञात Reddit उपयोगकर्ता ने खुद को "डीपफेक" कहा था। इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए Google की ओपन-सोर्स, डीप-लर्निंग तकनीक में हेरफेर किया।
    - वीडियो को चेहरे की अदला-बदली नामक तकनीक से संपादित किया गया था।
    - उपयोगकर्ता "डीपफेक" ने असली चेहरों को सेलिब्रिटी चेहरों से बदल दिया।
- यह फेक न्यूज़, स्पैम/फिशिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड, कैटफिशिंग और एकेडमिक फ्रॉड के साथ-साथ साइबरस्पेस के आधुनिक फ्रॉड में से एक बन गया है।
- डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, फेसबुक प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉम क्रूज जैसे उल्लेखनीय व्यक्तित्वों को लागू करने के लिए किया गया है।

डीप फेक क्यों तेजी से समाज के लिए खतरा बन रहा हैं?

- तकनीक में सुधार के साथ, डीप फेक भी बेहतर हो रहे हैं। शुरू में, मशीन लर्निंग के उन्नत ज्ञान और पीड़ित के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल तक पहुंच रखने वाला व्यक्ति केवल डीप फेक बना सकता था।
- हालाँकि, ऐप्स/सॉफ्टवेयर की आसान उपलब्धता ने कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए भी इस तरह के फेक बनाना संभव बना दिया है। इस तरह के संपादन में सक्षम ऐप्स और वेबसाइटों का विकास अधिक बार और एक औसत उपयोगकर्ता के लिए आसानी से सुलभ हो गया।
- दूसरे शब्दों में, कमोडिटी क्लाउड कंप्यूटिंग, एल्गोरिदम और प्रचुर मात्रा में डेटा तक पहुंच ने मीडिया निर्माण और हेरफेर का लोकतंत्रीकरण करने के लिए एकदम सही तूफान खड़ा कर दिया है।
- डीपफेक का उपयोग अब बड़े पैमाने पर और तेजी से कम्प्यूटेशनल प्रचार और गलत सूचना फैलाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
- इससे सामाजिक कलह पैदा करने, ध्रुवीकरण बढ़ाने, और कुछ मामलों में, चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए दुष्प्रचार आदि के रूप में विकसित हुआ है।

डीप फेक को लेकर क्या चिंताएं हैं?

ऐसी प्रौद्योगिकियां लोगों को एक आवाज, उद्देश्य और बड़े पैमाने पर और तेजी से प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान कर सकती हैं। लेकिन किसी भी नई नवीन तकनीक की तरह, इसे नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार बनाया जा सकता है।

- **व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान:** डीपफेक में एक व्यक्ति को असामाजिक व्यवहार में लिप्त और गंदी बातें कहते हुए दिखाया जा सकता है। ये उनकी प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं, उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद कर सकते हैं।

  - इसका उपयोग नकली अश्लील वीडियो बनाने और राजनेताओं को ऐसी बातें कहने के लिए किया जा सकता है जो उन्होंने नहीं की, इसलिए व्यक्तियों, संगठनों और समाज को नुकसान की संभावना बहुत अधिक है।
- **महिलाओं को लक्षित करना:** डीपफेक का दुर्भावनापूर्ण उपयोग पोर्नोग्राफी में देखा जा सकता है, जो भावनात्मक, प्रतिष्ठापूर्ण और कुछ मामलों में व्यक्ति के प्रति हिंसा का कारण बनता है।
- **निर्विवादित तथ्य का मुद्दा (Issue of Fait Accompli):** भले ही पीड़ित डीप फेक को खारिज करता हो, प्रारंभिक नुकसान का समाधान करने में बहुत देर हो सकती है।
- **ब्लैकमेलिंग टूल:** इसके अलावा, डीपफेक का उपयोग धन, गोपनीय जानकारी, या व्यक्तियों से सटीक लाभ लेने के लिए किया जा सकता है।
- **समाज को अस्थिर करना:** ध्रुवीकरण के बीज बोने, समाज में विभाजन को बढ़ाने और असहमति को दबाने के लिए डीपफेक एक बहुत प्रभावी उपकरण बन सकता है।
- **सार्वजनिक युद्ध:** डीपफेक एक राष्ट्र-राज्य द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा को कमजोर करने और लक्षित देश में अनिश्चितता और अराजकता पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। भू-राजनीतिक आकांक्षाओं, वैचारिक विश्वासियों, हिंसक चरमपंथियों और आर्थिक रूप से प्रेरित उद्यमों वाले राष्ट्र-राज्य अभिनेता डीपफेक का उपयोग करके मीडिया की कहानियों में हेरफेर कर सकते हैं।
- **राज्य-विरोधी भावना:** भू-राजनीतिक आकांक्षाओं, वैचारिक विश्वासियों, हिंसक चरमपंथियों और आर्थिक रूप से प्रेरित उद्यमों वाले राष्ट्र-राज्य अभिनेता डीपफेक का उपयोग करके मीडिया आख्यानों में हेरफेर कर सकते हैं। इसका उपयोग विद्रोही समूहों और आतंकवादी संगठनों द्वारा भड़काऊ भाषण देने या लोगों के बीच राज्य विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए उत्तेजक कार्यों में संलग्न होने के रूप में अपने विरोधियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है।
- **लोकतंत्र को कमजोर करना:** डीप फेक भी लोकतांत्रिक प्रवचन को बदलने और संस्थानों में विश्वास को कम करने और कूटनीति को कम करने में मदद कर सकता है। संस्थानों, सार्वजनिक नीति और डीपफेक द्वारा संचालित राजनेताओं के बारे में गलत जानकारी का उपयोग कहानी को घुमाने और विश्वास में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है।
  - राजनीतिक उम्मीदवार का डीप फेक उनकी छवि और प्रतिष्ठा को खराब कर सकता है।
  - नेता लोग इसका उपयोग लोकलुभावनवाद बढ़ाने और सत्ता को मजबूत करने के लिए भी कर सकते हैं।
- **लायर्स डिविडेंड (Liar's Dividend):** यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक अवांछित सच्चाई को डीप फेक या फेक न्यूज़ के रूप में खारिज कर दिया जाता है। यह सार्वजनिक हस्तियों को उनके वास्तविक हानिकारक कार्यों को फेक बताते हुए डीपफेक और फेक समाचारों की आड़ में उनके अनैतिक कार्यों को छिपाने में भी मदद कर सकता है।
- **सोशल मीडिया में इको चेम्बर्स का निर्माण:** असत्य लाभदायक है, यह सोशल प्लेटफॉर्म पर सच्चाई से ज्यादा वायरल होता है। अविश्वास के साथ संयुक्त, मौजूदा पक्षपात और राजनीतिक असहमति समाज में विवाद पैदा करने, इको चैम्बर और फ़िल्टर बबल्स बनाने में मदद कर सकती है।
- **निजता के अधिकार को बाधित करना:** स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती सामर्थ्य को देखते हुए, किसी भी देश की बड़ी आबादी की एक या अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल उपस्थिति है। डीपफेक बनाने के लिए इन प्लेटफार्मों पर साझा की गई सामग्री का दुरुपयोग किया जा सकता है जो निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

क्वांटम कम्प्यूटिंग

संदर्भ : क्वांटम कंप्यूटरों (QC) का आकर्षण क्वांटम भौतिकी का लाभ लेने की उनकी क्षमता है, जो क्लासिकल भौतिकी का उपयोग करने वाले कंप्यूटरों के लिए बहुत जटिल समस्याओं को हल करने के लिए है।

- भौतिकी के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार ऐसे कार्य के लिए दिया गया, जिसने ऐसे ही एक 'अनुभव' का कड़ाई से परीक्षण किया और कंप्यूटिंग में इसके अनुप्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो QCs के समकालीन महत्व को बताता है।
- केवल 2021 में, भारत सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया; सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम रिसर्च फैसिलिटी खोली; और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पुणे में एक और सुविधा शुरू की।
- अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए, यह समझना कि QCs वास्तव में क्या है, इसके आसपास की गलत सूचनाओं को दूर करने और वास्तविकता के करीब होने वाली अपेक्षाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

कंप्यूटर भौतिकी का उपयोग कैसे करता है?

- एक मैक्रोस्कोपिक वस्तु - जैसे गेंद, कुर्सी या लोग - एक समय में केवल एक ही स्थान पर हो सकते है; इस स्थान का सटीक अनुमान

लगाया जा सकता है; और इसके परिवेश पर वस्तु का प्रभाव प्रकाश की गति से अधिक तेजी से प्रसारित नहीं किया जा सकता है। यह वास्तविकता का क्लासिकल 'अनुभव' है।

- उदाहरण के लिए, आप एक गेंद को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और न्यूटन के नियमों के अनुसार उसके प्रक्षेपवक्र की योजना बनाते हैं। आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि निश्चित समय पर गेंद कहाँ होगी। यदि गेंद जमीन से टकराती है, तो आप इसे ऐसा करते हुए उस समय देखेंगे जब तक कि यह प्रकाश को वातावरण से होते हुए आपके पास आने में समय नहीं लेता।
- क्वांटम भौतिकी उप-परमाणु पैमाने पर वास्तविकता का वर्णन करती है, जहाँ वस्तुएँ इलेक्ट्रॉन जैसे कण हैं। इस दायरे में, आप एक इलेक्ट्रॉन के स्थान को इंगित नहीं कर सकते।
- आप केवल यह जान सकते हैं कि यह किसी दिए गए स्थान के आयतन में मौजूद होगा, तो आयतन के प्रत्येक बिंदु से जुड़ी संभावना के साथ जैसे बिंदु A पर 10% और बिंदु B पर 5%। जब आप इस आयतन को अधिक मज़बूती से जाँच करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु B पर मिल सकता है। यदि आप बार-बार इस आयतन की जाँच करते हैं, तो आप समय के 5% बिंदु B पर इलेक्ट्रॉन पाएंगे।
- क्वांटम भौतिकी के नियमों की कई व्याख्याएँ हैं। एक 'कोपेनहेगन व्याख्या' है, जिसे इरविन श्रोडिंगर ने 1935 में तैयार किए गए एक विचार-प्रयोग का उपयोग करके लोकप्रिय बनाया।
    - एक बंद डिब्बे में एक बिल्ली के पास जहर का कटोरा है। बॉक्स को खोले बिना यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि बिल्ली जिंदा है या मर गई है। इस स्थिति में, बिल्ली को दो अवस्थाओं के सुपरपोजिशन में मौजूद कहा जाता है: जीवित और मृत।
    - जब आप बॉक्स खोलते हैं, तो आप सुपरपोज़िशन को एक अवस्था में ढहने के लिए बाध्य करते हैं। जिस अवस्था में यह गिरता है वह प्रत्येक स्थिति की संभावना पर निर्भर करता है।
    - इसी तरह, जब आप वॉल्यूम की जांच करते हैं, तो आप प्रत्येक स्थिति की संभावना के आधार पर इलेक्ट्रॉनों के सुपरपोज़िशन को एक से गिरने के लिए मजबूर करते हैं।
- क्वांटम-कंप्यूटिंग से संबंधित अन्य 'अनुभव' उलझाव भरे है। जब दो कण आपस में उलझ जाते हैं और फिर एकपक्षीय दूरी से अलग हो जाते हैं, तो एक कण की जांच करना, और इस तरह इसकी सुपरपोज़िशन को ढहने का कारण बनता है, दूसरे कण के सुपरपोज़िशन को भी तुरंत ढहने का कारण बनता है।
    - यह घटना इस धारणा का उल्लंघन करती प्रतीत होती है कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड की अंतिम गति सीमा है।
    - अर्थात, दूसरे कण का सुपरपोजिशन एक सेकंड के तीन सौवें हिस्से से भी कम समय में एक अवस्था में ढह जाएगा, यह प्रकाश के 1,000 किमी की यात्रा करने में लगने वाला समय है।

कंप्यूटर सुपरपोजिशन का उपयोग कैसे करता है?

- बिट क्लासिकल कंप्यूटर की मूलभूत इकाई है। इसका मान 1 है यदि संबंधित ट्रांजिस्टर ऑन है और यदि 0 है तो ट्रांजिस्टर ऑफ है।
- ट्रांजिस्टर एक समय में दो अवस्थाओं में से एक में हो सकता है - चालू या बंद - इसलिए बिट में एक समय में दो में से एक मान हो सकता है, 0 या 1।
- क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग की मूलभूत इकाई है। यह आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉन जैसा कण होता है।
    - Google और IBM को ट्रांसमन्स का उपयोग करने के लिए जाना जाता है, जहां बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों के जोड़े दो सुपरकंडक्टर्स के बीच दो राज्यों को नामित करने के लिए दोलन करते हैं।
- कुछ जानकारी सीधे क्यूबिट पर एन्कोड की जाती है: यदि इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब 1 है; जब स्पिन नीचे की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब 0 है।
- लेकिन या तो 1 या 0 होने के बजाय, जानकारी एक सुपरपोजिशन में एन्कोड की गई है: मान लीजिए, 45% पर 0 + 55% पर 1 है। यह पूरी तरह से 0 और 1 के दो अलग-अलग स्थितियों के विपरीत है और यह एक तीसरी तरह की स्थिति है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक साथ काम करते हैं, क्यूबिटस को उलझा दिया जाता है। यदि इसकी स्थिति को प्रकट करने के लिए एक क्यूबिट की जांच की जाती है, तो गणना की जा रही गणना के आधार पर कुछ या सभी अन्य क्यूबिटस भी होंगे। कंप्यूटर का अंतिम आउटपुट वह अवस्था है जिससे सभी क्विट नष्ट हो गए हैं।
- एक क्यूबिट दो स्थितियों को सांकेतिक शब्दों में बदल सकता है। पाँच क्यूबिटस 32 स्थितियों को कूटबद्ध कर सकते हैं। N क्यूबिटस वाला एक कंप्यूटर 2N अवस्थाओं को कूटबद्ध कर सकता है जबकि N ट्रांजिस्टर वाला एक कंप्यूटर केवल 2 × N अवस्थाओं को कूटबद्ध कर सकता है।
- इसलिए एक क्विबिट-आधारित कंप्यूटर एक ट्रांजिस्टर-आधारित कंप्यूटर की तुलना में अधिक अवस्थाओं तक पहुंच सकता है, और इस प्रकार अधिक कम्प्यूटेशनल मार्ग और अधिक जटिल समस्याओं के समाधान तक पहुंच सकता है।

क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन (एनएम-क्यूटीए) पर भारत का राष्ट्रीय मिशन क्या है?

- मिशन संचार, कंप्यूटिंग, सामग्री विकास और क्रिप्टोग्राफी के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास की निगरानी करेगा।
- मिशन समग्र दृष्टिकोण अपनाने के माध्यम से उन बाधाओं (ऊपर सूचीबद्ध) को संबोधित करता है जिसके कारण क्वांटम क्षेत्र में देश की धीमी प्रगति हुई है।
- बजट 2020 में घोषित
- **अवधि:** पांच वर्ष (2020-25)
- **कुल फंड्स:** 8000 रुपये वर्ष में
- **कार्यान्वयन निकाय:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)

मिशन का महत्व:

- मिशन अंततः एक सुपर-सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क के निर्माण की ओर ले जा सकता है।
- यह अगली पीढ़ी के कुशल जनशक्ति को तैयार करने में मदद करेगा, ट्रांसलेशनल रिसर्च को बढ़ावा देगा और उद्यमिता और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।
- यह कंप्यूटिंग, संचार, संवेदन, रसायन विज्ञान, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग और मैकेनिक के क्षेत्र में जटिल समस्याओं का समाधान खोजने में उपयोगी साबित होगा।
- यह मिशन भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में बढ़ते निवेश और फोकस के माध्यम से क्षेत्र में वैश्विक लीडर के रूप में उभरने में सक्षम करेगा।

नीति शास्त्र

भारत में भ्रष्टाचार

संदर्भ: हाल ही में CBI द्वारा 'विकास और सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास' पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस -2022 का आयोजन किया गया था।

भ्रष्टाचार के बारे में:

- भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग करने को संदर्भित करता है। यह एक निर्वाचित राजनेता, सिविल सेवक, पत्रकार, स्कूल के प्रशासक, या प्राधिकरण में किसी के द्वारा किया जा सकता है।
- सार्वजनिक भ्रष्टाचार के अलावा, हमारे पास व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच निजी भ्रष्टाचार भी है।

वैश्विक सर्वेक्षण और सूचकांक:

- ग्लोबल सिविल सोसाइटी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार, एशिया में भारत में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए रिश्वतखोरी और व्यक्तिगत लिंक के उपयोग की उच्चतम दर है।
- भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, 2021 में 180 देशों में 85वें स्थान पर है।

भ्रष्टाचार के कारण:

- **विरासत के मुद्दे:** स्वतंत्रता के शुरुआत में अत्यधिक गरीबी और सरकार के खाली खजाने के कारण सरकारी अधिकारियों का वेतन बहुत कम हो गया
    - पूर्व उदारीकरण लाइसेंस परमिट राज ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।
    - आर्थिक स्वतंत्रता की कमी के कारण व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ।
    - विकास की आवश्यकताएं सतर्कता प्रक्रियाओं पर हावी हो गईं।
- **राजनीतिक व्यवस्था:** चुनावों में किसी भी कीमत पर जीतने के लिए काले धन का उपयोग कदाचार के माध्यम से उस लागत की रिकवरी की आवश्यकता उत्पन्न करता है।
    - चुनावी फंडिंग पारदर्शी नहीं है, जिससे यह काले धन के उपयोग के लिए प्रवृत्त होता है और फंडिंग क्विड प्रो क्वो के आधार पर होती है।
    - यह क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर ले जाता है, जो राजनेताओं और कॉरपोरेट्स के बीच एक अपवित्र गठजोड़ है।
    - राजनीति का अपराधीकरण- जब नियम तोड़ने वाले नियम निर्माता बन जाते हैं, तो कानून का शासन हताहत होता है।
- **आर्थिक संरचना:** अर्थव्यवस्था के निम्न स्तर की औपचारिकता (केवल 10%) काले धन को जन्म देती है।
    - व्यवसायों के लिए प्रवेश और निकास के कड़े अनुपालन नियमों के परिणामस्वरूप रिश्वतखोरी होती है।
    - धन का असमान वितरण - ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल डेटा बताता है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्र में आर्थिक अंतर के सीधे अनुपात में है।
- **कानूनी कमियां:** आईपीसी 1860 जैसे पुरातन कानून प्रशासन की जटिलताओं को पकड़ नहीं पाते हैं और गलत काम करने वालों से बच निकलते हैं।
    - लोकपाल अधिनियम में कमियां और राज्य तथा केंद्रीय दोनों स्तरों पर नियुक्तियों में देरी
    - आरटीआई अधिनियम को कमजोर करना और सीबीआई तथा अन्य एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग।
- **प्रशासनिक कमियां:** कमियां अधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियां देती हैं जिससे कामकाज भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख हो जाता है।
    - सतर्कता संस्थानों में संसाधनों, वित्त पोषण, बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की कमी।
    - बैंकों, खेल संगठनों जैसे संगठनों द्वारा मानक प्रथाओं को शामिल करने में कमी जिसके परिणामस्वरूप अरबों रुपये के घोटाले होते हैं।
    - पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला।
- **न्यायिक विलंब:** नेक लोगों को सुरक्षा का अभाव
    - ईमानदार और गैर-भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाना और भ्रष्ट अधिकारियों को इनाम देना।
    - लगभग न के बराबर मुखबिर संरक्षण

- **सामाजिक समस्याएं:** नागरिकों की वह मानसिकता जो समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती और उसे व्यवस्था का एक आवश्यक अंग भी मान लेती है।
    - नए मध्य वर्ग में बढ़ता उपभोक्तावाद जो कार्य करवाने के लिए रिश्वत देने को तैयार है।
    - सामाजिक नैतिकता की विफलता, मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षा प्रणाली

भ्रष्टाचार के प्रभाव:

- **विकासात्मक प्रक्रिया में बाधाएँ:** भ्रष्टाचार और करदाताओं के पैसे की हेराफेरी के कारण धन की हानि सामाजिक क्षेत्र में खर्च करने के लिए बहुत कम बचता है।
- पीडीएस, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से जनसांख्यिकीय नुकसान होता है।
- आर्थिक नुकसान: व्यापार करने में सरलता को कमजोर करता है।
    - सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार अच्छा कारोबार करने के लिए उच्च जोखिम वहन करता है।
    - कंपनियों को किसी भी प्रक्रिया या सौदों को अंतिम रूप देने के लिए अवांछित लालफीताशाही, छोटे-मोटे भ्रष्टाचार, रिश्वत की संभावना है।
    - गलत आवंटन नीतियों के परिणामस्वरूप कोयला ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं, स्पेक्ट्रम आवंटन जैसे संसाधनों का अवमूल्यन होता है। उदा. 2G घोटाला, कोलगेट।
    - संसाधनों के इस कुप्रबंधन से पर्यावरण का क्षरण और शोषण होता है।
    - बैंक, शेयर बाजार जैसे वित्तीय क्षेत्र के अधिकारियों का भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था की मजबूती को खत्म कर देता है। उदा. पीएनबी घोटाला, पीएमसी घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला।
- **सामाजिक क्षेत्र के नुकसान:** समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को लक्षित करने वाली सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार अमीर और गरीब के बीच आर्थिक अंतर को बढ़ाता है।
- भ्रष्ट व्यवस्था गरीबों को अपनी स्थिति सुधारने का मौका नहीं देती है, जिससे वे हमेशा के लिए गरीब हो जाते हैं।

भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानूनी ढांचा:

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में दंड का प्रावधान करता है और उन लोगों के लिए भी जो भ्रष्टाचार के लिए उकसाने में शामिल हैं।
    - 2018 के संशोधन ने लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने और किसी भी व्यक्ति द्वारा रिश्वत देने दोनों को आपराधिक बना दिया।
- मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाओं को रोकना और भारत में 'अपराध की आय' के उपयोग पर रोक लगाना है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रदान करता है।
    - 'धोखाधड़ी' शब्द को एक व्यापक परिभाषा दी गई है और यह कंपनी अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 उन प्रावधानों को निर्धारित करता है जिनकी व्याख्या रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामलों को कवर करने के लिए की जा सकती है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से संबंधित अपराध शामिल हैं।
- विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 व्यक्तियों और निगमों द्वारा विदेशी योगदान और आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है।

नियामक ढांचा:

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 केंद्र और राज्य सरकारों (क्रमशः लोकपाल और लोकायुक्त) के लिए एक लोकपाल की स्थापना का प्रावधान करता है।
- इन निकायों को सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता है और लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग को सतर्कता प्रशासन की देखरेख करने और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में कार्यपालिका को सलाह देने और सहायता करने का अधिकार है।

सुझावात्मक उपाय:

- **शिक्षा:** शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। यह सही व्यवसाय प्रथाओं को सुदृढ़ करने में मदद करती है।
    - मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी जैसे अनिवार्य शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
- **जवाबदेही:** जवाबदेही तंत्र भी भ्रष्टाचार को रोकने में मदद कर सकता है।

- **कुशल रिपोर्टिंग:** इसके अलावा, यदि रिपोर्टिंग सरल हो जाए तो भ्रष्टाचार को कम करना आसान हो सकता है।
- **श्रेष्ठ प्रथाओं का नेतृत्व करना:** प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ कर्मचारियों को उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए और एक खुली तथा पारदर्शी संस्कृति विकसित करनी चाहिए।
- **नैतिक संस्कृति को प्रोत्साहित करना:** इसी तरह, लोगों को नैतिक संस्कृति विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।
- **अभिनव भ्रष्टाचार-रोधी समाधानों की आवश्यकता:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वास्तविक समय पर जानकारी साझा करने की आवश्यकता है।

इस खतरे से लड़ने के लिए व्यवस्था के प्रत्येक वर्ग में अप्रत्याशित सुधारों की आवश्यकता है। दक्षता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता के लिए शासन के हर पहलू में सुधार किया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस (IACD) के बारे में:

- यह 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पारित होने के बाद से 9 दिसंबर को वार्षिक रूप से मनाया जाता है।

2022 IACD का महत्व:

- 2022 IACD भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन - UNCAC की बीसवीं वर्षगांठ की शुरुआत भी करता है।
- यह इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम 'यूएनसीएसी एट 20: यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन' से परिलक्षित होता है।
- यह भ्रष्टाचार विरोधी और शांति, सुरक्षा और विकास के बीच महत्वपूर्ण कड़ी को उजागर करना चाहता है।

PRACTICE QUESTIONS

Q.1) भारतीय जलवायु के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल के वर्षों में अल नीनो के कारण दक्षिणी प्रायद्वीप में अत्यधिक वर्षा हुई है।
2. अरब सागर में समुद्र का गर्म होना बहुत तीव्र है क्योंकि यह वायुमंडलीय सुरंगों और पुलों के माध्यम से अतिरिक्त गर्मी प्राप्त करता है।

नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) 'INS विक्रांत' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत का पहला 100% स्वदेशी विमानवाहक पोत है।
2. इसका निर्माण मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था।
3. यह लगभग 80MW ऊर्जा पैदा करने वाली परमाणु ऊर्जा है।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) 1, 2 और 3
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.3) भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) जनजातीय कल्याण मंत्रालय के तहत एक इनोवेटिव सेल है।
2. यह कला और साहित्य, कृषि, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में हमारे देश की समृद्ध विरासत और पारंपरिक ज्ञान को फैलाने में सक्रिय रूप से संलग्न होगा।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का गठन 2008 में हुआ था।
2. भारत का पहला इको ब्रिज ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (Tadoba-Andhari Tiger Reserve) में बनाया गया था।

नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (फेमा) अधिनियम के तहत, विदेशी मुद्रा से संबंधित अपराध आपराधिक अपराध हैं।
2. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध दीवानी अपराध हैं।
3. प्रवर्तन निदेशालय का गठन फेमा अधिनियम के तहत किया गया था।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.6) भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें:

1. वाणिज्यिक बैंक
2. मर्चेंट बैंकर्स
3. स्टॉक ब्रोकर्स
4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

उपरोक्त में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है?

a) केवल 1 और 3
b) केवल 2 और 4
c) केवल 1 और 4
d) ऊपर के सभी

Q.7) निम्नलिखित पर विचार करें:

1. सल्फर डाइऑक्साइड
2. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
3. पारा
4. पार्टिकुलेट मैटर

उपरोक्त में से कौन सा प्रदूषक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा छोड़ा जा सकता है?

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 3 और 4
d) ऊपर के सभी

Q.8) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक स्वायत्त संगठन है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

2. इसकी स्थापना रघु राम राजन आयोग की सिफारिशों पर की गई थी।

3. आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य और एक पदेन सदस्य होता है।

उपरोक्त में से कौन से सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.9) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी।

2. यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

3. इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 2
d) केवल 1 और 3

Q.10) "राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका गठन 2008 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अधिनियम के तहत किया गया था।

2. यह भारत में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एकमात्र ऑडिट नियामक है।

3. यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

Q.11) हाल ही में खबरों में रहा, "वासनार अरेंजमेंट (Wassenaar arrangement)" निम्नलिखित में से किससे संबंधित है:

a) जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन और हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए।
b) परमाणु हथियारों और इसकी प्रौद्योगिकियों के प्रसार को रोकने के लिए।
c) हानि और विनाश के लिए जवाबदेही और मुआवजा स्थापित करना।
d) पारंपरिक हथियारों के हस्तांतरण पर सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए।

Q.12) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी।

2. इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

3. भारत और विदेशों में सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन के अलावा, ICCR पूरे भारत में कई सांस्कृतिक संस्थानों का वित्तीय समर्थन करता है, और व्यक्तिगत कलाकारों को प्रायोजित करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.13) जिन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज: व्हाट आर राइट्स एंड हाउ टू सिक्योर देम इन द कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ रुपी: इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन लिखा। वे थे -

a) बिपिन चंद्र पाल
b) लाला लाजपत राय
c) बी आर अम्बेडकर
d) मोतीलाल नेहरू

Q.14) "मिशन प्रारंभ (Mission Prarambh)" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा लॉन्च किया गया पहला निजी रॉकेट है।

2. यह एक कक्षीय रॉकेट है जिसकी पेलोड क्षमता 300 किलोग्राम तक है।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.15) राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डीआरआई भारत की सर्वोच्च तस्करी विरोधी एजेंसी है, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करती है।

2. इसका मुख्यालय मुंबई में है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.16) भारत की काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. इनमें पोटाश और चूना प्रचुर मात्रा में होता है
2. इनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है
3. वे राजस्थान और यूपी में अच्छी तरह से विकसित हैं।

4. सूखने पर इनमें दरारें पड़ना इनकी विशेषता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

a) 1, 2 और 4
b) 2, 3 और 4
c) 1 और 4
d) केवल 2 और 3

Q.17) "डिजि यात्रा (Digi Yatra)" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह बोर्डिंग पास को पूरी तरह से बदल देता है।
2. इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.18) राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह राहत उपायों और कार्यों के प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन के लिए प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है।
2. इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) ChatGPT के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. चैटजीपीटी एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा मॉडल है जो गहन शिक्षण तकनीकों पर आधारित है।
2. चैटजीपीटी, अन्य बातों के अलावा, फिक्शन लिखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. चैटजीपीटी को एलोन मस्क की टेस्ला ने विकसित किया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) 1 और 2
d) 2 और 3

Q.20) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वोट डाले जाने के बाद एग्जिट पोल कराए जाते हैं, जबकि ओपिनियन पोल पहले किए जाते हैं।
2. एग्जिट पोल मतदाताओं से पूछते हैं कि उन्होंने किस राजनीतिक दल को वोट दिया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.21) निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें:
1. कर्नाटक
2. असम
3. तमिलनाडु
4. केरल
उपरोक्त में से कितने सामान्यतः कॉफी उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं?

a) केवल एक राज्य
b) केवल दो राज्य
c) केवल तीन राज्य
d) सभी चार राज्य

Q.22) राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद यानी राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं।
2. संविधान की चौथी अनुसूची प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23) कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य (Koundinya Wildlife Sanctuary) अक्सर खबरों में चर्चा में रहता है-

a) तेलंगाना
b) कर्नाटक
c) ओडिशा
d) आंध्र प्रदेश

Q.24) कृषि उड़ान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह योजना 2014 में किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करने के लिए शुरू की गई थी ताकि उनकी मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके।
2. यह एक अभिसरण योजना है जहां तीन मंत्रालय/विभाग अर्थात् नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग कृषि-उत्पादन के परिवहन के लिए रसद को मजबूत करने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाएं।
2. ई-कुशल (स्थायी समग्र कृषि-रसद के लिए कृषि उड़ान) मंच को सभी हितधारकों को सूचना प्रसार में सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया जाएगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q.25) भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 236 उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26) बहु-किश्त वित्तपोषण (Multi-tranche financing) सुविधा शब्द का अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है, यह एक पहल है-

a) विश्व बैंक
b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
c) एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
d) एशियाई विकास बैंक

Q.27) निम्नलिखित पर विचार करें:
1. ई-ग्रीन वॉच पोर्टल भारत में जंगल की आग से संबंधित जानकारी के लिए एकल बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करता है।
2. वन अग्नि जियो-पोर्टल एक उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे कैम्पा फंड के तहत किए गए कार्यों के स्वचालन, सुव्यवस्थित और प्रभावी प्रबंधन की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. PARIVESH पोर्टल केंद्र सरकार से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी के लिए सिंगल विंडो एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q.28) "काजा/KAZA" शब्द अक्सर समाचारों में सुना जाता है जो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है?

a) भूमध्य सागर के पास गाजा पट्टी की सीमा के साथ क्षेत्र
b) अंगोला से जिम्बाब्वे तक फैला दक्षिणी अफ्रीका के साथ क्षेत्र
c) फारस की खाड़ी और अफ्रीका के हॉर्न के साथ क्षेत्र
d) भूमध्य सागर के सभी तटीय क्षेत्र।

Q.29) कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित "पटवा (Patwa)" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक औषधीय झाड़ी है।
2. यह पश्चिमी घाट में उगता है।
3. यह एक स्ट्रांग एंटी-ऑक्सीडेंट है जिसका उपयोग दवा उद्योगों में किया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से है/हैं

a) केवल 1
b) केवल 3
c) 1 और 3
d) 2 और 3

Q.30) 'वैश्विक पर्यावरण सुविधा' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) एक बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है जो विकासशील देशों को जैव विविधता से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान और मिश्रित वित्त प्रदान करता है।
2. इसकी स्थापना 1972 के रियो अर्थ समिट से पहले की गई थी।
3. यह ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का भी समर्थन करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 2
d) 1, 2 और 3

Q.31) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

दर्रा	क्षेत्र
1. माना दर्रा	पुराना सिल्क मार्ग
2. नाथू ला पास	नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व
3. सेला पास	तवांग

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) 1 और 3
d) केवल 3

Q.32) "नाविक/NavIC" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वर्तमान में इसके 7 उपग्रह हैं।
2. इसके नए उपग्रह आवृत्ति के S और L2 बैंड का उपयोग करते है।
3. अन्य बातों के अलावा, यह मछुआरों के लिए मौसम की भविष्यवाणी में मदद करता है।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2

c) केवल 3
d) केवल 2

Q.33) नीचे दिए गए जोड़े में से कौन सा सही रूप से मिलान करता है / हैं?

चंद्र मिशन	देश
1. आर्टेमिस 1	नासा
2. बेरेशीट	जापान
3. होप	यूएई

सही कूट चुनें:
a) 1 और 3
b) 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) केवल 1

Q.34) टी लिम्फोसाइट्स (T lymphocytes) (टी कोशिकाओं) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उम्र के साथ टी-सेल ब्लड कैंसर के मामले बढ़ते जाते हैं।
2. ये अस्थिमज्जा की मूल कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.35) हाल ही में समाचारों में देखा गया, "द 3200 फेथॉन (The 3200 Phaethon)" है
a) एक उल्का शॉवर
b) एक क्षुद्रग्रह
c) एक प्राकृतिक उपग्रह
d) एक नई आकाशगंगा

Q.36) निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972 के तहत गठित है / हैं
1. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
3. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
सही कूट चुनें:
a) 1, 2 और 3
b) केवल 3
c) 1 और 3
d) 2 और 3

Q.37) स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ADC का गठन संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 के तहत किया जाता है।
2. एडीसी केवल चार राज्यों पर लागू होते हैं।
3. एडीसी सामाजिक रीति-रिवाजों पर कानून बना सकता है।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:
a) केवल 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1
d) केवल 1 और 2

Q.38) निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन के कारक हैं:
1. अचल संपत्ति
2. गिग वर्कर
3. उद्यमिता
4. एंजेल निवेशक
5. प्रबंधन सूचना प्रणाली
6. ट्रेड यूनियन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1, 2,3 और 4
b) 1, 2, 3 और 6
c) 1, 2, 3 और 5
d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

Q.39) फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस (PTUAS) योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों को पूरा करने के लिए सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले एमएसएमई को सुविधा प्रदान करना है।
2. इसमें उनके पूंजी ऋणों पर ब्याज सबवेंशन या पूंजी सब्सिडी शामिल है।
सही कथनों का चयन करें:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.40) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्थापित किया गया है
a) संबंधित राज्य सरकारें
b) ग्रामीण विकास मंत्रालय
c) नीति आयोग
d) पंचायती राज मंत्रालय

Q.41) भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति खातों में दिखाए गए धन की जाँच करती है, जो कि वितरित किए जाने के रूप में कानूनी रूप से उपलब्ध थे, और उस सेवा या उद्देश्य के लिए लागू थे, जिसके लिए आवेदन किया गया था या चार्ज किया गया था और वह व्यय उस प्राधिकरण के अनुरूप है जो इसे नियंत्रित करता है?
a) प्राक्कलन समिति
b) सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
c) सरकारी आश्वासनों पर समिति
d) लोक लेखा संबंधी समिति

Q.42) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के आधार पर 2020 में स्थापित एक नियामक संस्था है।
2. सीसीपीए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.43) सौर मंडल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. शनि का वातावरण अधिकतर आणविक हाइड्रोजन और हीलियम से बना है।
2. बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
3. शनि के 79 स्थायी मून हैं।
4. टाइटन बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 4
c) केवल 2 और 3
d) केवल 2 और 4

Q.44) स्तनधारियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मोनोट्रीम या प्रोटोथेरियन अंडे देने वाले (ओविपेरस) स्तनधारी हैं।
2. कंगारू, वॉलबीज, कोआला, पॉसम, ओपॉसम, वॉम्बैट मार्सुपियल्स के उदाहरण हैं।
3. ह्वेल और डॉल्फ़िन सिटासियन के उदाहरण हैं, ये बिना पश्च अंगों वाले जलीय स्तनधारी हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.45) भारत में चमड़ा उद्योग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत दुनिया में जूते और चमड़े के कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक है।
2. यह दुनिया में चमड़े के कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.46) 'आईएनएस मोरमुगाओ ' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसे कोचिन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।
2. यह पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें अत्याधुनिक स्टील्थ क्षमताएं हैं
3. यह केवल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल वेपन सिस्टम से लैस है।

सही कथन का चयन कीजिए

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 1
d) कोई नहीं

Q.47) स्वास्थ्य क्षेत्र में सिनॉच थेरेपी (synNotch therapy) के उपयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित कर सकता है।
2. यह ट्यूमर कोशिकाओं के बाहर साइटोकिन्स का निर्माण करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.48) निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें:

1. राम प्रसाद बिस्मिल
2. अशफाक उल्ला खान
3. चंद्रशेखर आजाद
4. सचिन्द्र बख्शी

उपरोक्त में से कौन काकोरी षड़यन्त्र से सक्रिय रूप से जुड़ा था/थे?

a) केवल 1 और 3
b) केवल 2 और 4
c) केवल 1, 2 और 4
d) ऊपर के सभी

Q.49) डीपफेक और डीप सिंथेसिस तकनीक के बारे में कुछ चिंता है। क्यों?

1. इनका इस्तेमाल स्कैम और पोर्नोग्राफी जैसी आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है।
2. वे ऐसे लोगों को बना सकते हैं जो मौजूद नहीं हैं।
3. वे किसी भी ऑनलाइन सामग्री को बदल सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 3
b) 1, 2 और 3
c) केवल 1
d) केवल 2 और 3

Q.50) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की जाती है।
2. सिक्किम राज्य क्षेत्रीय परिषदों में शामिल है।
3. सभी क्षेत्रीय परिषदों का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Key Answers

1	b	21	D	41	d
2	d	22	C	42	a
3	b	23	D	43	a
4	b	24	C	44	d
5	d	25	A	45	b
6	c	26	D	46	d
7	d	27	C	47	a
8	b	28	B	48	d
9	a	29	C	49	b
10	b	30	A	50	c
11	d	31	D		
12	c	32	C		
13	c	33	A		
14	d	34	B		
15	a	35	B		
16	a	36	A		
17	b	37	B		
18	a	38	A		
19	a	39	C		
20	a	40	D		

IAS BABA

UPSC/IAS 2023

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAMME (PEP) 2023

MOST COMPREHENSIVE PRELIMS CLASSROOM PROGRAM

- 1:1 Mentorship
- 375+ Hours of Prelims Focused Classes
- Strategy Classes by Prelims Experts
- High RoI Prelims Exclusive Handouts
- 125+ Daily Tests (Solve ≈ 6000 MCQ's)
- CSAT Classes by Experts & Full Length Tests
- Current Affairs - Classes, Handouts & Tests
- PYQ's Live Solving by Prelims Experts

ONLINE & OFFLINE

LIVE

ADMISSION OPEN

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888